



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2018/पौष 6, 1940

No. 406]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2018/PAUSHA 6, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2018

अंतिम जांच परिणाम

**विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लोरोलस्टोमर्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।**

1. **फा. सं. 6/25/2017/डीजीएडी.**—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

2. और जबकि, मैसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे "याचिकाकर्ता", अथवा "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लोरोलस्टोमर्स", जिसे एफकेएम के रूप में भी जाना जाता है (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के पाटित आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा उन पर उपयुक्त शुल्क लगाने के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है), व्यापार उपचार महानिदेशालय के समक्ष वर्तमान मामले में आवेदन दायर किया।

3. और जबकि, प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य बनाते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन की तथाकथित मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जांच करने तथा निर्धारित करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क, जो यदि लगाया जाता है और जो घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की राशि की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार दिनांक 02 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 6/25/2017-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

**क. प्रक्रिया**

4. प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच की शुरुआत अधिसूचित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास/प्रतिनिधियों को अधिसूचित किया।
- ii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार घरेलू उद्योग को जांच की शुरुआत की एक प्रति भेजी और जांच की शुरुआत की अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अनुरोध किया।
- iii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास को तथा ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- iv. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों सहित दूतावास को भी भेजी गई थी।
- v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली तथा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली भेजी:

- क. मैसर्स डेक्सिन फ्लोरोकार्बन्स, चीन जन. गण.
- ख. मैसर्स शानडोंग डोंग्यु केमिकल कं. लि., चीन जन. गण.
- ग. मैसर्स चांगझोऊ जियांटोंग केमिकल कं. लि., चीन जन. गण.
- घ. मैसर्स तेझैऊ मीलन रेसिन प्रोसेस, चीन जन. गण.
- ङ. मैसर्स शानडोंग डोंग्यु पॉलीमर, चीन जन. गण.
- च. मैसर्स डुपोंट (चांगशु) फ्लोरो टेक्नोलॉजी कं. लि., चीन जन. गण.
- छ. मैसर्स सिचुआन चेंगुआंग इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, चीन जन. गण.
- ज. मैसर्स जियांगसु मीलन केमिकल कं. लि., चीन जन. गण.
- झ. मैसर्स शंघाई 3एफ न्यू मैटेरियल्स कं. लि.
- ञ. मैसर्स फुक्सिन हेंगटोंग फ्लोरीन, चीन जन. गण.
- ट. चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, चीन जन. गण.
- ठ. द केमर्स केमिकल (शंघाई) कं. लि., चीन जन. गण.
- ड. डेकन फ्लोरोकेमिकल्स (चाइना) कं. लि., चीन जन. गण.
- ढ. फ्लोरोकेमिकल्स शंघाई फ्लोरोटीएम केमिकल्स, चीन जन. गण.
- ण. चेंगडु डोहोन इंडस्ट्रियल, चीन जन. गण.
- त. सॉल्वे, चीन जन. गण.
- थ. गुआंगझोऊ पोलेन केमिकल टेक्नोलॉजी कं. लि., चीन जन. गण.
- द. शानडोंग हुआक्सिया शेनझोऊ, चीन जन. गण.
- ध. जियांगसु मीलन केमिकल कं. लि., चीन जन. गण.
- न. शंघाई हेचांग फ्लोरोकार्बन कं. लि., चीन जन. गण.
- प. वुक्सी फुडा फ्लोरोप्लास्टिक्स कं. लि., चीन जन. गण.
- फ. बीजिंग रूईचेंग कं. लि., चीन जन. गण.

- ब. कम पिन पेंट वर्क्स लि., चीन जन. गण.  
 भ. हुबेई दनचांग चाइना कं. लि., चीन जन. गण.  
 म. वुक्सी टा टांग कंपाउंड मैटेरियल कं. लि., चीन जन. गण.  
 य. शंघाई किनेरिंग कं. लि., चीन जन. गण.  
 र. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन पॉलीमर कं. लि., चीन जन. गण.
- vi. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया और प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए:
- क) सॉल्वे (शंघाई) कं. लि., चीन जन. गण.  
 ख) मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं., चीन जन. गण.  
 ग) उनी-एलियांस लिमिटेड, चीन जन. गण.  
 घ) डेकन फ्लोरोकेमिकल्स (चाइना) कं. लि., चीन जन. गण.  
 ङ) झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि., चीन जन. गण.  
 च) चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टमर्स कं. लि., चीन जन. गण.  
 छ) शंघाई 3एफ, चीन जन. गण.  
 ज) इनर मंगोलिया 3एफ, चीन जन. गण.
- vii. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कंपनी लि., चीन जन. गण. ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली का उत्तर भी दायर किया है।
- viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:
- क. मीन बीन एलास्टमर्स  
 ख. जेएमएफ सिंथेटिक  
 ग. पॉलमन इंडिया लि.  
 घ. बीपी केमिकल्स  
 ङ. निशिगंधा पॉलीमर्स  
 च. हिंद एलास्टमर्स  
 छ. जयाश्री पॉलीमर्स  
 ज. विकास एलास्टोकेम एजेंसीज प्रा. लि.  
 झ. दिवेकर डब्ल्यूएंडएस प्रेसीसन सील्स पी. लि.  
 ञ. देवाशीष पॉलीमर्स प्रा. लि.  
 ट. नु-कॉर्क प्रोडक्ट्स (पी) लि.  
 ठ. एस. जे. रबड़ इंडस्ट्रीज लि.  
 ड. एम. के. मार्केटिंग  
 ढ. जेनिथ इंडस्ट्रियल रबड़  
 ण. रावत इंजी. टेक. प्रा. लि.  
 त. कोकोकु इंटेक इंडिया  
 थ. बीडीएस पॉलीकेम

- ix. अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया और प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए:
- क) सॉल्वे स्पेशियलिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ख) ईस्टकॉर्प इंटरनेशनल
- ग) निशिंगंधा पॉलीमर्स प्रा. लि.
- x. इसके अतिरिक्त, ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जेएम ऑटो इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और रूप पॉलीमर्स लिमिटेड ने प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा के भीतर याचिका की और जांच की शुरुआत का विरोध करते हुए कुछ अनुरोध दायर किए।
- xi. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- xii. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की अवधि और विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xiii. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन की इष्टतम लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xiv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए 29 मई, 2018 को एक मौखिक सुनवाई की जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था। उन सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोधों को एकत्रित करें और उसके बाद अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।
- xv. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन 30-31 मई, 2018 को आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। केवल आवश्यक संशोधन के साथ सत्यापित सूचना, जहां भी लागू थी, पर विश्वास किया गया है।
- xvi. विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर की गई प्रश्नावली के व्यस्त अध्ययन के मापद्वयम से आंकड़ों का सत्यापन किया गया था।
- xvii. मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी इंडिया प्रा. लि. के परिसरों में सॉल्वे (शंघाई) कंपनी लि., चीन जन. गण. और मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशू) कं. लि., चीन जन. गण. द्वारा दायर उत्तरों से उनके आंकड़ों का यथासंभव सहसंबंध बनाने के लिए स्थल सत्यापन किया गया था।
- xviii. वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) जुलाई, 2016 – जून, 2017 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2014-15, 2015-16, 2016-17 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल हैं।
- xix. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहां भी संगत पाए गए हैं, इस जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा हल कर दिए गए हैं।
- xx. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करें।

- xxi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अड़चनें डाली हैं, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां रिकार्ड की हैं।
- xxii. प्राधिकारी ने 28 नवंबर, 2018 को नियम 16 के तहत प्रकटन विवरण जारी किया और 7 दिसंबर, 2018 तक प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान किया।
- xxiii. इस दस्तावेज में \*\*\* किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं। इस अंतिम जांच परिणाम में कोष्ठक ( ) नकारात्मक अंक/रैंज दर्शाता है।
- xxiv. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग एवं विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर भी इस जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- xxv. जांच की अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 67.40 रुपए है।

#### क. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

##### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

#### उत्पाद के संबंध में

- i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "फ्लोरोलस्टोमर्स (एफकेएम)" है। एफकेएम बहुत उच्च तापमान के प्रचालन के लिए बनाये गए सिंथेटिक रबड़ की एक श्रेणी है। उत्कृष्ट समग्र गुणधर्मों से युक्त इसे "रबड़ किंग" कहा जाता है। इसमें अपूर्ण फ्लोरोनेटेड मॉर्क्यूलर संरचना होती है और इसकी मुख्य एवं बगली जंजीरों में फ्लोरिन एटम्स की सख्त इलेक्ट्रो निगेटिविटी होती है। इसकी भारी ऊर्जा (सी-एफ बांड ऊर्जा 485 केजे/111 मोल.) के कारण सी-एफ बांड स्थिर होता है। इसके अतिरिक्त, फ्लोरिन एटम्स कोवालेंट रेडियस 0.072 एनएम. होता है जो लगभग एक हाइड्रोजन एटम के दोगुने आकार का होता है, 0.131 एनएम. की सी-सी बांड लंबाई के आधे के बराबर होता है, फ्लोरिन एटम्स सी-सी बांड की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन चैन की मुख्य चैन को अच्छी तरह से सुरक्षित रखने में सक्षम होता है ताकि एफकेएम में अन्य रबड़ों की तुलना में प्रमुख बेहतर निष्पादन रहे।
- ii. फ्लोरोलस्टोमर्स (एफकेएम) के हाइड्रोलिक ओ-रिंग सील्स, चीक वाल्व वाल्व्स, मिलिट्री फेयर बाइंडर्स, डायफ्राम्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, फ्लू डकट, एक्सपी. ज्वाइंट्स, वाल्व लाइनर्स, रोल कवर्स, सीट स्टॉक/कट गास्केट्स में औद्योगिक प्रयोग; शाफ्ट सील्स, वाल्व स्टम सील्स, फ्यूल इंजेक्टर ओ-रिंग, फ्यूल होज में स्वचालित प्रयोग, टैंक और क्लिक कनेक्ट फ्यूल सिस्टम्स सील्स में, गास्केट (वाल्व और मिनीफोल्ड), चेक वाल्व्स के लिए बेल्स, लेथ कट गास्केट; और फ्यूल, लुब्रीकेंट्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स, मैनीफोल्ड गास्केट और फ्यूल टैंक ब्लाडर, फायर वाल्व सील्स, इंजन, ल्यूव, सिफोन होज, जेट इंजनों के लिए क्लिप, टायर वाल्व, स्टैमसील में ओ-रिंग सील्स में एयरोस्पेस प्रयोग जैसे विभिन्न अनुप्रयोग हैं।
- iii. फ्लोरो पॉलीमर रबड़ों का एक परिवार फ्लोरोलस्टोमर्स उनकी फ्लोरिंग मात्रा द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है और क्रमशः 66 प्रतिशत, 68 प्रतिशत और 70 प्रतिशत (अनुमति योग्य सहायता) हो सकती है। अधिक फ्लोरिन मात्रा वाले फ्लोरोलस्टोमर्स में बढ़ते हुए फ्लोरिन के स्तरों से निकाली गई बढ़ती हुई फ्लूड प्रतिरोधकता होती है। पैरोक्साइड क्योर्ड फ्लोरोलस्टोमर्स में अंतर्निहित रूप से बेहतर जल, भाप और एसिड प्रतिरोधकता होती है। एफकेएम को व्यापक रूप से दो सेटों में वर्गीकृत किया जाता है – कोपोलाइमर और टर्पोलाइमर। कोपोलाइमर (एफ 66 प्रतिशत) पूर्व के मिश्रण हैं और टर्पोलाइमर (67-70 प्रतिशत) कच्चा गोंद होते हैं। एफकेएम के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। यद्यपि, याचिकाकर्ता ने इन उत्पाद श्रेणियों के लिए विशिष्ट मूल्य दिए हैं। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ये उत्पाद सामान्य रूप से अनुमत सहायता के अंतर्गत उत्पादित किए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से संबंधित विभिन्न तकनीकी साहित्यों द्वारा यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी "विशिष्ट मूल्यों" के रूप में ही इन विशेष मूल्यों पर विचार कर सकते हैं।
- iv. मुख्य फ्लोरोलस्टोमर्स के सम्मिश्रण नीचे दिए गए हैं:
  - क. कोपॉलीमर फ्लोरो एलास्टमर्स: (सीएफ2-सीएफ)-(सीएच2-सीएफ2)-सीएफ3
  - ख. टेरपॉलीमर फ्लोरो एलास्टमर्स: (सीएफ2-सीएफ)-(सीएच2-सीएफ2)-(सीएफ2-सीएफ2)- टीएफई स्तर अलग-अलग फ्लोरिंग मात्राओं सीएफ3 के लिए अलग-अलग हो सकता है।

- ग. उन्नत कम तापमान वाला फ्लोरो एलास्टोमर टरपोलाइमर - (सीएफ2-सीएफ)-(सीएच2-सीएफ2)-(सीएफ2-सीएफ2)-एचएफपी के स्थान पर फ्लोरो ईथर ओ-सीएफ3 रखा गया।
- घ. नॉन-वीएफ2 फ्लोरो एलास्टोमर टरपोलाइमर - (सीएफ2-सीएफ)-(सीएच2-सीएच2)-(सीएफ2-सीएफ2)-वीएफ2 के स्थान पर एथिलीन रखा गया, आधार/अमाइन प्रतिरोधकता ओ-सीएफ3 प्रदान करता है।
- v. उपर्युक्त संयोजनों के आधार पर एफकेएम को प्रमुख रूप से दो किस्मों में श्रेणीकृत किया जा सकता है:
- क. कोपोलाइमर एफकेएम विनाइलीडीन फ्लोराइड (वीडीएफ) और हेक्सा फ्लोरो प्रोपीलीन (एचएफपी) से तैयार किया जाता है। इसमें काफी तापमान प्रतिरोधकता, ऑक्सीडेशन प्रतिरोधकता, तेल प्रतिरोधकता और रासायनिक प्रतिरोधकता तथा अच्छे यांत्रिक गुणधर्म होते हैं। 66 प्रतिशत फ्लोराइड मात्रा से एफकेएम सर्वोत्तम तापमान प्रतिरोधकता वाला रबड़ होता है और इसका प्रयोग अल्पकाल के लिए 300 डिग्री सेल्सियस पर तथा लम्बे समय के लिए 250 डिग्री सेल्सियस पर किया जा सकता है।
- ख. टरपोलाइमर एफकेएम विनाइलीडीन फ्लोराइड (वीडीएफ), टेट्रा फ्लोरोथीन (टीएफई) और हेक्सा फ्लोरो प्रोपीलीन (एचएफपी) से तैयार किया जाता है। टरपोलाइमर्स को सुरक्षित और सुरक्षा योग्य टरपोलाइमरों में श्रेणीकृत किया जा सकता है। इसकी सुरक्षा अमाइन/विस्फेनल और पैरॉक्साइड सुरक्षा प्रणाली से किया जा सकता है। इसमें अत्यधिक रासायनिक प्रतिरोधकता और दीर्घकालिक ताप प्रतिरोधकता वाले गुणधर्म होते हैं तथा पैरॉक्साइड सुरक्षा प्रणाली से एफकेएम कम तापमान वाले प्रतिरोधकता गुणधर्म भी दर्शाता है। 67-70 प्रतिशत फ्लोरीन मात्रा से एफकेएम टरपोलाइमरों में अधिक एसिड कीटोन और कोपोलाइमर्स के बजाए अधिक ईस्टर प्रतिरोधकता होती है।
- vi. याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, घरेलू उद्योग, बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत की उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए पीसीएन प्रणाली को माना है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि, याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद को चार किस्मों में श्रेणीकृत किया है, तथापि, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इन श्रेणियों को विशिष्ट उत्पाद किस्मों में और उप विभाजित करना आवश्यक समझते हैं तो याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी को संगत सूचना देगा।
- vii. उत्पाद में विशिष्ट वर्गीकरण नहीं है। विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 3904, 390469 और 39046990 के तहत अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह अनुरोध किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

#### अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अलग किए जाने के दावों के संबंध में अनुरोध

- viii. वर्तमान याचिका यह विचार करने के लिए है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी हो रही है। चूंकि, घरेलू उद्योग यहां तक कि पूरी तरह से स्थापित नहीं है, इसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की सभी उत्पाद किस्में पेश नहीं की हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पाद विशिष्ट की किस्म का अभाव का अर्थ यह नहीं है कि उसे अलग किए जाने की आवश्यकता है।
- ix. इस पर भी याचिकाकर्ता ने चीन से आयात किए जा रहे सभी उत्पाद स्वरूपों की समान वस्तु पहले ही पेश की है। संगत ब्यौरे पहले ही दे दिए गए हैं।
- x. विचाराधीन उत्पाद की एक किस्म की नगण्य मात्रा के संबंध में तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आयातों की मात्रा को समग्र रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए देखा जाना चाहिए न कि एक या कुछ उत्पाद किस्मों के लिए। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने सुनवाई के समय स्वयं ही स्वीकार किया कि आयातों की वास्तविक मात्रा बहुत ही अधिक है। निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया निर्यातकों से रिकार्ड में प्रश्नावली के उत्तरों पर विचार करें।

#### अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मात्रा संबंधी चिंताओं के संबंध में अनुरोध

- xi. घरेलू उद्योग के उत्पाद की मात्रा के संबंध में चिंताओं का उत्तर देते हुए आरंभ में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. विचाराधीन उत्पाद, उसके क्षेत्र और उसे कैसे परिभाषित/निर्धारित किया जाना चाहिए, के मुद्दे से संबंधित कानून के तहत कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है। तथापि, इस विषय में डब्ल्यूटीओ पैनल/अपीलीय निकाय तथा माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों में काफी मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकार है जिस पर घरेलू उद्योग हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उचित साक्ष्य से समर्थित पर्याप्त दावों के साथ अपने तर्क पर कार्रवाई किए जाने की स्थिति में विश्वास करना चाहेंगे।

- ख. वे सभी उत्पाद जो समान उत्पाद की योग्यता पूरी करते हैं, विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में रहते हैं। यह अपेक्षित साध्य के साथ सिद्ध करने के लिए निष्कासन का दावा करने वाले पक्षकार पर है कि घरेलू उद्योग ने भारत में आयातित किसी विशेष उत्पाद किस्म की समान वस्तु पेश नहीं की है।
- ग. घरेलू उद्योग ने उन विभिन्न उपभोक्ताओं के व्यौरे भी दिए हैं जिनको घरेलू उद्योग ने सामग्री बेची है। ये उपभोक्ता सामूहिक रूप से जहां तक चीन तथा भारतीय उत्पादकों द्वारा आपूर्तियों का संबंध है, भारत में विचाराधीन उत्पाद की अधिकतम खपत करते हैं। यदि किसी उपभोक्ता ने चीन के उत्पाद की कीमत जैसे अन्य कारकों के कारण याचिकाकर्ता का उत्पाद खरीदना बेहतर नहीं माना तो केवल इस कारण कि एक उपभोक्ता याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित तथा आपूर्ति किए गए सामानों का प्रयोग नहीं कर पाता है, जब उसी क्षेत्र में अन्य उपभोक्ताओं ने उस अंतिम उत्पाद का प्रयोग किया है और उत्पादित किया है तो उत्पाद किस्म को अलग करना औचित्यपूर्ण नहीं है।
- घ. आयात आंकड़े तीसरे देशों से चीन को आयातों की काफी मात्रा होना दर्शाते हैं। यह परिवर्तन तकनीकी आधारों के कारण नहीं हुआ था बल्कि वाणिज्यिक आधारों और उस कम कीमत के कारण हुआ था जिस पर चीनी उत्पादक उत्पाद बेचना चाह रहे हैं।
- ङ. यह तर्क देते समय कि याचिकाकर्ता के उत्पाद की गुणवत्ता खराब है, हितवद्ध पक्षकारों ने गुणवत्ता के अर्थ का भी उल्लेख नहीं किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी तकनीकी और वाणिज्यिक मापदंडों पर विचार करते हैं। हितवद्ध पक्षकारों ने उन तकनीकी मापदंडों की पहचान की होती जो याचिकाकर्ता के उत्पाद में भिन्न हैं जो कि उसे आयातित उत्पाद में अप्रतिस्थापनीय बनाते हैं।
- च. गुणवत्ता समान उत्पाद निर्धारण के विचार में पाटनरोधी जांचों में संगत मानदंड नहीं हैं, विशेष रूप से जब कम गुणवत्ता का दावा न तो सिद्ध है और न मात्रायुक्त है।
- छ. विगत कई जांचों (यथा यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, बस और रेडियल टायर, कास्ट एल्युमीनियम अलोंग व्हील्स अथवा अलोंग रोड व्हील्स, फिनोल और ईपीडीएम) में माननीय प्राधिकारी ने सतत रूप से यह माना है कि समान उत्पाद के निर्धारण के लिए मात्रा संगत मानदंड नहीं है। यही माननीय सेसेटेट ने डीएसएम इजेनिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माना है।
- ज. विगत में लगभग 44 प्रतिशत एफकेएम बाजार की आपूर्ति गैर-चीनी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की जाती थी। चीनी आपूर्तिकर्ताओं का हिस्सा 2014-15 में 32 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में 43 प्रतिशत हो गया जबकि दूसरी ओर गैर-चीनी आपूर्तिकर्ताओं का हिस्सा 2014-15 में 68 प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि में 44 प्रतिशत हो गया। गैर-चीनी स्रोतों से चीनी स्रोतों में यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से चीनी और गैर-चीनी आपूर्तिकर्ताओं के बीच कीमत में काफी अंतर के कारण हुआ है।
- झ. गुणवत्ता का मुद्दा घरेलू उद्योग पर उनकी कीमतें कम करने के लिए दबाव बनाने हेतु आयातकों तथा प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया गया केवल एक बहाना है, अतः गुणवत्ता के मुद्दे से संबंधित तर्कों को उसके औचित्य, कानूनी दायरे और निर्दिष्ट प्राधिकारी की सतत परिपाटी, जैसा कि प्लेथोरा के निर्णयों में दर्शाया गया है, के आधार पर प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।
- ञ. इस संदर्भ में एआईआरआईए ने घटिया गुणवत्ता की घरेलू आपूर्तियों के प्रयोग के कारण उनके परिष्कृत सामानों को रद्द किए जाने के संबंध में केवल खोखले दावे किए हैं। वह वास्तविक रूप से गलत और भ्रामक है। किसी भी तरह, गुणवत्ता के मुद्दे के कारण घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त आय भी बेची गई मात्रा की तुलना में बहुत कम है।
- ट. बिक्री वसूली से संबंधित तर्कों के संबंध में यद्यपि घरेलू उद्योग के सामानों के घटिया गुणवत्ता के दावों को हल कर दिया गया है। तथापि, संबद्ध सामानों का उत्पादन करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के रूप में भी प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है और कंपनी द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी के समान है। जीएफएल के पास उन्नत प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण वाली विश्वस्तरीय विनिर्माण सुविधा है। इसमें अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला से समर्थित एफकेएम नए ग्रेड के विकासों के लिए पृथक अग्रणी संयंत्र है। इसके अतिरिक्त, उनकी एफकेएम गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला पूर्णतः वैश्विक रूप से विख्यात परीक्षण उपस्करों से युक्त है जो परीक्षण परिणामों में उच्चस्तरीय परिशुद्धता, निर्धारण और विश्वसनीयता प्रदान करने में सक्षम है। अतः नकारात्मक बिक्री वसूली के लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार एक मात्र कारक चीनी उत्पादकों द्वारा भारी पाटन है।
- xii. चीनी आपूर्तिकर्ताओं की कीमतें औसतन जांच की अवधि में गैर-चीनी आपूर्तिकर्ताओं से केवल 908 प्रति किलोग्राम तक कम रही हैं। यह अपने-आप में चीनी आपूर्तिकर्ताओं के पाटन व्यवहार को सिद्ध करता है, परंतु वस्तुतः

याचिकाकर्ता का इरादा उस कीमत को लगाने का नहीं है जो गैर-चीनी आपूर्तिकर्ता लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने वस्तुतः उस कीमत का लक्ष्य बनाया है जो कि उस कीमत के बीच की ही कीमत है जिस पर चीनी और गैर-चीनी आपूर्तिकर्ताओं ने भारतीय बाजार में सामग्री की आपूर्ति की है।

- xiii. यह तथ्य कि चीनी उत्पादकों ने वास्तविक रूप से उत्पाद की इस श्रेणी में पाटन का सहारा लिया है, काफी पाटन सिद्ध करता है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों द्वारा पाया गया है। यद्यपि, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों ने भारतीय आपूर्तिकर्ताओं अर्थात् गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लि. (जीएफएल) के संबंध में 18.49 प्रतिशत पाटन मार्जिन निर्धारित किया। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों ने चीनी आपूर्तिकर्ताओं अर्थात् डेकिन फ्लोरो केमिकल्स (चीन) कंपनी लि. के संबंध में 84.75 प्रतिशत पाटन मार्जिन पाया। जहां तक जीएफएल का संबंध है, यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीय उत्पादक केवल इस कारण कम कीमत पर अमेरिकी बाजार में बिक्री करने पर मजबूर थे क्योंकि चीनी उत्पादकों ने भारतीय बाजार में बहुत ही कम कीमत पर अपने उत्पादों का निर्यात किया।
- xiv. इसके अतिरिक्त, यदि कोई अन्य कारक हो सकता है तो चीन से पाटन आयातों के कारण कोई क्षति न होने का निष्कर्ष निकालने के लिए घरेलू उद्योग को क्षति तथा चीन से पाटन के बीच कारणात्मक संपर्क को क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों की मौजूदगी कम नहीं करती अथवा रोकती नहीं। याचिकाकर्ता थाइलैंड-लौह के एंगलों, आकारों और खंडों अथवा नॉन-अलॉय स्टील और पौलेंड से एच-बीम्स के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट का उल्लेख करता है और उस पर विश्वास करता है।

### अन्य उत्पाद मुद्दों से संबंधित अनुरोध:

- xv. भारत सरकार ने विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई निर्धारण अधिदेशित नहीं किए हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को केवल उन निर्धारणों पर विचार करना चाहिए जो देश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए हैं और उन पर विचार नहीं करना चाहिए जो निर्धारण मानदंडों में हैं। नियमों के तहत घरेलू उद्योग के लिए समान वस्तु पेश करना अपेक्षित है। केवल इस कारण कि निर्यातक द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद पेटेंटयुक्त है, इसका मतलब यह नहीं है कि घरेलू उद्योग समान वस्तु की आपूर्ति नहीं करता।
- xvi. याचिकाकर्ता ने प्रयुक्त कच्ची सामग्री और उसकी लागत के संबंध में सभी संगत सूचनाएं दी हैं। यद्यपि, खरीदी गई कच्ची सामग्री का मूल्य सुपुर्दगी लागत पर है, तथापि, कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्ची सामग्री उत्पादन लागत पर अंतरित की जाती है। केवल दो कच्ची सामग्री अर्थात् हेक्सा फ्लोरो प्रोपीलीन (एचएफपी) और टीएफई का प्रयोग एफकेएम के उत्पादन के लिए कैप्टिव रूप से किया जाता है जिसे कंपनी विचाराधीन उत्पाद की लागत पर अंतरित करती है।
- xvii. यह वास्तव में सही है कि एफकेएम अत्यधिक विशेषीकृत अनुप्रयोगों में प्रयुक्त विशेष उत्पाद हैं और इसके गुणवत्ता आश्वासन के लिए जीएफएल के पास उन्नत प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण वाली विश्वस्तरीय विनिर्माण सुविधा है। जीएफएल में अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला से समर्थित एफकेएम नए ग्रेड के विकासों के लिए पृथक अग्रणी संयंत्र है। इसके अतिरिक्त, उनकी एफकेएम गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला पूर्णतः वैश्विक रूप से विख्यात परीक्षण उपस्करों से युक्त है जो परीक्षण परिणामों में उच्चस्तरीय परिशुद्धता, निर्धारण और विश्वसनीयता प्रदान करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, चूंकि पीटीएफई और एफकेएम के अंतिम प्रयोग पूर्णतः भिन्न हैं, अतः अंतिम प्रयोक्ता भी भिन्न है। अतः यह कहना सही नहीं है कि पीटीएफई उपभोक्ता आधार एफकेएम के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

### समान वस्तु

- xviii. किसी भी चीनी निर्यातक ने अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद किस्म को घोषित नहीं किया है। याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे कृपया उन उत्पाद किस्मों को प्रकट करें जो प्रत्येक उत्तरदाता निर्यातक द्वारा संगत अवधि के दौरान भारत को निर्यात किए गए हैं ताकि उस वस्तु की पहचान की जा सके जो कि आयातित उत्पाद की प्रतिस्पर्द्धा में याचिकाकर्ता द्वारा पेश की जा रही है। याचिकाकर्ता ऐसे आयातित उत्पाद की समान वस्तु की पहचान करेगा। जहां तक भारत को निर्यात किए गए उत्पाद किस्म का संबंध है, कुछ भी गोपनीय नहीं हो सकता।
- xix. चीन जन. गण. से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। वर्तमान मामले में, आयातित और घरेलू उत्पाद, दोनों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण आदि जैसे मानदंडों के संदर्भ में तुलनीय विशेषताएं हैं। उपभोक्ता दोनों का प्रयोग कर सकते हैं और परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।



**निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निष्कासन के संबंध में किया गया दावा**

- i. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों के अनुसार केवल दो श्रेणियों अर्थात् कोपोलाइमर प्री-कंपाउंड और कोपोलाइमर रॉ गम का आयात किया जाता है। टरपोलाइमर श्रेणी भारत में आयातित नहीं की जाती है और इस उत्पाद किस्म के लिए अंतिम उत्पाद की अपेक्षाएं भी भिन्न हैं।
- ii. अनुरोध है कि प्राधिकारी एक स्पष्टीकरण यथाशीघ्र जारी करे कि एफकेएम सम्मिश्रण और परफ्लोरोएस्टोमर (सामान्य रूप से "एफएफकेएम" के रूप में ज्ञात) वर्तमान जांच के क्षेत्र में शामिल नहीं है। याचिका में यह उल्लेख किया गया था कि भारत में आयातित एफकेएम में केवल दो किस्में (रॉ गम तथा प्री-कंपाउंड) हैं। याचिकाकर्ता एफकेएम कंपाउंड और एफएफकेएम का विनिर्माण नहीं कर रहा है। वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। दूसरी ओर, रॉ गम तथा प्री-कंपाउंड मध्यवर्ती उत्पाद हैं और एफकेएम कंपाउंड तथा एफएफकेएम अंतिम उत्पाद हैं, अतः वे "समान उत्पाद" नहीं हैं।
- iii. याचिका के अगोपनीय रूपांतर के पृष्ठ सं. 47 में आयात विवरण यह दर्शाता है कि चीन जन. गण. से केवल 6 मी. टन कोपोलाइमर रॉ गम का आयात किया जाता है। 6 मी. टन की यह नगण्य मात्रा घरेलू उद्योग को क्षति कैसे पहुँचा सकती है।

**गुणवत्ता और ग्रेड**

- iv. उत्पादक आवश्यकता के अनुसार, एफकेएम के चुनिंदा ग्रेडों का उत्पादन करते हैं। दो उत्पादकों के बीच एक-एक करके ग्रेड-वार तुलना संभव नहीं है। प्रत्येक विनिर्माता का अपने विशेषता वाले ग्रेड होते हैं जो अन्य विनिर्माताओं द्वारा आसानी से बदले नहीं जा सकते। ग्रेड का प्रतिस्थापन कठिन है और केवल तभी संभव है जब कोई उच्च स्तर का ग्रेड विकसित किया जाए।
- v. नए ग्रेड को चुनते समय और ग्रेड प्रतिस्थापन के लिए कीमत कोई बड़ा कारक नहीं है। ग्रेड का विकल्प गुणवत्ता, प्रक्रिया, स्वीकार्यता, अंतिम प्रयोक्ता की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है न कि कीमत के आधार पर।
- vi. आयातित सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान की अपेक्षा बेहतर गुणवत्ता के हैं जो कि असंगत भी हैं। घरेलू उद्योग ने एक नया प्रवेशक होने के नाते ऑटोमोबाइल कंपनियों सहित भारतीय उद्योग द्वारा अपेक्षित सभी ग्रेडों का अभी तक विकास नहीं किया है। इस प्रकार, भारत में रबड़ के प्रसंस्करणकर्ता अपनी मांग को पूरा करने के लिए जीएफएल पर विश्वास नहीं कर सकते। गुणवत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि एफकेएम का प्रयोग करते हुए विनिर्मित उत्पादों का प्रयोग वाहन में महत्वपूर्ण सुरक्षा उत्पादों के रूप में किया जाता है।
- क. एआईआरआईए के कई सदस्यों ने घरेलू उद्योग के उत्पादों का परीक्षण किया है और उसे घटिया गुणवत्ता का पाया है तथा उत्पादन विभाग द्वारा कुछ ग्रेडों को रद्द किया गया था।
- ख. एफकेएम आधारित उत्पादों के अंतिम उपभोक्ता बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो महंगे आयातित उत्पादों को खरीदने के लिए रबड़ प्रसंस्करणकर्ताओं को मजबूर करते हुए अपने उत्पादों में कोई गुणवत्ता संबंधी विचलन स्वीकार नहीं करेंगे।
- vii. अधिकतर अंतिम प्रयोक्ता बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए अपने प्रत्येक उत्पाद के लिए एक विशेष विनिर्माता से प्रयुक्त किए जाने के लिए एफकेएम के ग्रेड का सामान्यतः उल्लेख करते हैं।
- viii. घरेलू उद्योग की बिक्री वसूली में गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई घटिया प्रौद्योगिकी के कारण उत्पाद की घटिया गुणवत्ता के कारण हो सकती है।
- ix. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया यह दावा कि समान उत्पाद के निर्धारण में पाटनरोधी जांच में गुणवत्ता संगत मानदंड नहीं है, विशेष रूप से जब कमजोर गुणवत्ता का दावा सिद्ध न हो, गलत दिया गया है। याचिकाकर्ता ने जिन मामलों का उल्लेख किया है, वे सभी क्षति के हैं न कि वास्तविक मंदी के। वास्तविक मंदी के मामले में गुणवत्ता एक बड़ी चिंता है क्योंकि ऐसे मामलों में घरेलू उद्योग को उसके उत्पादों की घटिया गुणवत्ता के कारण क्षति हो सकती है।
- x. याचिकाकर्ता एक नया उद्योग है और उसका उत्पाद घटिया गुणवत्ता का है। संबद्ध सामानों का प्रयोग एयरोस्पेस, ऑयल रिफाइनरीज और अन्य उद्योगों में किया जाता है। एफकेएम का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पादों का प्रयोग

महत्वपूर्ण सुरक्षा उत्पादों के रूप में किया जाता है और इसीलिए संबद्ध सामानों की गुणवत्ता के साथ में कोई समझौता करने से प्रयोक्ता उद्योग के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

- xi. यदि संबद्ध सामानों की गुणवत्ता वास्तव में चीन से आयातों की गुणवत्ता के समान थी तो उसे अपने प्रत्याशित और वांछित बाजार हिस्से को लेने में सक्षम होना चाहिए था। घरेलू उद्योग ने यह तर्क देने के लिए अन्य देशों से गिरते हुए आयातों का भी उल्लेख किया है कि घरेलू बाजार कीमत संवेदनशील है और इसलिए चूंकि चीन से कीमतें कम हो गई हैं, अतः प्रयोक्ता चीन से संबद्ध सामान लेने की ओर चले गए। तथापि, यह अनुरोध गलत रखा गया है, जैसा कि घरेलू उद्योग की उपर्युक्त धारणा सही होती तो भारत में संबद्ध सामानों के घरेलू बाजार में उसका प्रभाव होता क्योंकि वह निरंतर अपने उत्पाद उस कीमत पर बेचता रहा है जो कि चीन की कीमतों से काफी कम है।
- xii. अधिकतर प्रमुख ऑटो ओईएम ने गुणवत्ता मुद्दे के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामग्री को अस्वीकार किया है। हाइटेक अराई ने जिसका भारत की एफकेएम मांग में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है, अपनी शिकायत आगे रखने के लिए मौखिक सुनवाई में भाग लिया।
- xiii. याचिकाकर्ता यह सूचित करने में विफल रहे कि पिछले तीन वर्षों से एफकेएम के विनिर्माण के बावजूद उन्होंने अपने उत्पाद के लिए एक भी ऑटो ओईएम (सुजूकी, हीरो और टोयोटा आदि जैसे कंपनियों से) अनुमोदन क्यों नहीं लिया। जीएफएल ग्रेड ऑटो कंपनियों की सख्त अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, रबड़ कंपनियों को उनके स्तर पर अनुमत ग्रेड/विनिर्माता के किसी विचलन के बिना निर्धारित ग्रेडों का प्रयोग करना होता है। इस प्रकार, कोई अतिरिक्त शुल्क लगाना उत्पादन विरोधी ही होगा क्योंकि भारतीय रबड़ कंपनियां अधिक कीमत पर विशेष आयातित ग्रेड खरीदने के लिए मजबूर होंगी।
- xiv. संबद्ध उत्पाद का विनिर्माता जानता है कि रबड़ उद्योग के पास विशेष ऑटो कंपोनेंट के लिए उनके ग्रेड का प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है (जैसा कि ग्रेड के साथ विनिर्माता का नाम ऑटो कंपनी द्वारा जारी घटक आरेख में उल्लिखित है), इस प्रकार विनिर्माता का कम लागत पर सामग्री पाटित करने का कोई कारण नहीं है।
- xv. एफकेएम जैसे उत्पाद के मामले में गुणवत्ता ध्यान दिए जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एफकेएम उत्पादों का प्रयोग बहुत नाजुक है और उसका प्रयोग सुरक्षा उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है, किसी को भी कोई जोखिम लिए बिना ग्रेडों का चयन करते समय अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। उत्पाद की घटिया गुणवत्ता के प्रयोग से अंतिम उत्पाद का प्रयोग करने वाले लोगों के जीवन का जोखिम हो सकता है। एफकेएम आधारित उत्पादों के अंतिम उपभोक्ता बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं।

## अन्य मुद्दे

- xvi. झोंघाओ चेंगुआंग का सम्पूर्ण अस्तित्व फ्लोरोलस्टोमर प्रौद्योगिकी के निमित्त नई प्रौद्योगिकी के विकास और सशक्त अनुसंधान एवं विकास पर आधारित है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोप और दक्षिण कोरिया में प्रमुख रूप से विश्वव्यापी 20 से अधिक पेटेंट लेने में सहायता की है। ये बहुत से पेटेंट रेट और प्रौद्योगिकियां विशिष्ट रूप से झोंघाओ चेंगुआंग की हैं और जीएफएल में उपलब्ध नहीं हैं।
- xvii. याचिकाकर्ता ने फ्लोरोलस्टोमर के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री का कोई संकत नहीं दिया है। गुजराता फ्लोरोकेमिकल्स लि. जैसी बहु-उत्पाद कंपनियों में कच्ची सामग्री का कैप्टिव रूप से उत्पादन किया जाता है तथा विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के लिए खरीद की जाती है। याचिकाकर्ता ने कच्ची सामग्री की लागत के वितरण के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। घरेलू उद्योग को कृपया यह सलाह दी जाए कि वे उस अंतरण कीमत के ब्यौरे प्रस्तुत करें जिस पर फ्लोरोलस्टोमर्स के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत हेतु कच्ची सामग्री अंतरित की गई थी।
- xviii. एफकेएम का प्रयोग अत्यधिक विशेषीकृत अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है और इसमें कठोर परीक्षण किया जाता है तथा स्वीकार किए जाने से पूर्व प्रयोक्ता उद्योग द्वारा कठोर अनुमोदन प्रक्रियाएं होती हैं। जीएफएल, पीटीएफई के उत्पादन की तरह अपने स्थापित बाजार नियंत्रण के कारण कठोर शर्तों के बावजूद बाजार हिस्सा ले पाया जिससे वे अपना मौजूदा ग्राहक आधार बढ़ा पाए।
- xix. घरेलू उद्योग के अनुसार, एफकेएम को दो किस्मों को-पॉलीमर और टरपोलाइमर में श्रेणीकृत किया जाता है। को-पॉलीमर के निर्माण में प्रयुक्त मोनोमर एचएफपी और वीडीएफ है जबकि टरपोलाइमर के लिए वह एचएफपी, वीडीएफ और टीएफई है। वीडीएफ, पीवीएमई और क्योर साइट मोनोमर (चौथा मोनोमर) टरपोलाइमर एफकेएम, को-पॉलीमर एफकेएम, निम्न तापमान की प्रतिरोधकता वाले एफकेएम और पैरॉक्साइड क्योरोबल एफकेएम का विनिर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण मोनोमर है, परंतु घरेलू उद्योग जीएफएल उसका विनिर्माण नहीं कर रहा है और आयातों पर निर्भर है जो उसे केवल कीमत में ही प्रमुख घाटा नहीं देता बल्कि गुणवत्ता की निरंतरता में भी हानिकारक है। इसके अतिरिक्त, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके पास अत्यधिक अंतिम

पैराॅक्साइड क्योरोबल एफकेएम बनाने की प्रौद्योगिकी नहीं है जो नवीनतम बीएसवीआई मानदंडों को पूरा करने में प्रमुख बाधा है और ऑटोमोबाइल सुरक्षा की अपेक्षाओं को बढ़ाता है।

- xx. फ्लोरस्पर एफकेएम के उत्पादन के लिए दूसरी प्रमुख कच्ची सामग्री है। विश्व में चीन कुछ कंपनियों में से एक है जिसके पास बहुत अधिक शुद्धता वाले फ्लोरस्पर की भारी मात्रा में उपलब्धता है जिसके कारण झोंघाओ चेंगुआंग, सॉल्वे, डेकिन जैसे अधिकतर वैश्विक विनिर्माताओं ने चीन में अपने संयंत्र स्थापित किये हैं। इससे इन कंपनियों का न केवल प्रतिस्पर्द्धी कीमत पर ही फ्लोरस्पर प्राप्त होता है बल्कि उच्चतम गुणवत्तायुक्त एफकेएम का विनिर्माण भी सुनिश्चित होता है।
- xxi. एफकेएम प्री-कंपाउंडों का निर्माण करने के लिए क्यूरेटिव्स महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है जिसका विनिर्माण भारत में नहीं किया जाता है। क्यूरेटिव के विनिर्माण में प्रयुक्त रसायनों का उत्पादन भारत में नहीं किया जा रहा है। अतः घरेलू उद्योग क्यूरेटिव खरीदने के लिए आयातों पर निर्भर है जबकि चीन में क्यूरेटिव रसायनों के कई विनिर्माता हैं। इससे चीन में एफकेएम प्री-कंपाउंडों का विनिर्माण करने के लिए दूसरा लाभ मिलता है।
- xxii. अनुरोध है कि पैरा 43 में दी गई तालिका में अन्य देशों और चीन की औसत पहुँच कीमत दर्शाते समय घरेलू उद्योग ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से इन देशों द्वारा निर्यातित एफकेएम की किस्म वर्गीकृत नहीं की है। चीन केवल को-पॉलीमर प्री-कंपाउंड और को-पॉलीमर गम का ही निर्यात नहीं कर रहा है बल्कि अन्य देशों से प्रमुख रूप से आधारभूत टर-पॉलीमरों के अत्यधिक अंतिम विशेषता के ग्रेडों का भारत में निर्यात कर रहा है। अन्य देशों से 70 प्रतिशत से अधिक निर्यातित सामग्री टर-पॉलीमर और विशेषता वाले ग्रेड हैं। को-पॉलीमर ग्रेडों और विशेषता वाले टर-पॉलीमर ग्रेडों की कीमतों में भारी अंतर है जिसकी घरेलू उद्योग ने जान-बूझकर उपेक्षा की है। वस्तुतः निर्यातित कुछ ग्रेड बहुत ही विशेष ग्रेड हैं, यथा – अत्यधिक कम तापमान वाले ग्रेड, अत्यधिक उच्च तापमान वाले प्रतिरोधक ग्रेड जो कई गुना अधिक महंगे हैं। इससे अन्य देशों से औसत निर्यात कीमत में वृद्धि हुई है, इस प्रकार अन्य देशों की कीमत और चीन की निर्यात कीमत के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। कोई तुलना किए जाने के लिए चीन से निर्यातित केवल को-पॉलीमर प्री-कंपाउंड की तुलना अन्य देशों से को-पॉलीमर प्री-कंपाउंड से की जानी चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करें।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद 02 जनवरी, 2018 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना में व्यापक रूप से निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है।

*"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) फ्लोरोलस्टोमर्स (एफकेएम) हैं। फ्लोरोलस्टोमर्स (एफकेएम) बहुत अधिक तापमान पर प्रचालन के लिए बनाए गए सिंथेटिक रबड़ की श्रेणी हैं। उत्कृष्ट समग्र गुणधर्म वाले फ्लोरोलस्टोमर्स (एफकेएम) को "रबड़ किंग" कहा जाता है। इसमें पूर्णतः फ्लोरोनीटेड मॉर्क्युलर संरचना नहीं होती है और इसकी मुख्य एवं बगली चेनों में फ्लोरीनएटम्स की सख्त इलेक्ट्रो निगेटिविटी होती है। "फ्लोरोलस्टोमर्स" फ्लोरोपॉलीमर रबड़ों का परिवार है न कि एकल कंपनी। इसे उनकी फ्लोरीन मात्रा क्रमशः 66 प्रतिशत, 68 प्रतिशत और 70 प्रतिशत द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। एफकेएम को व्यापक रूप से दो सेटों कोपोलाइमर और टर्पोलाइमर में वर्गीकृत किया जाता है।*

*फ्लोरोलस्टोमर्स (एफकेएम) के हाइड्रोलिक ओ-रिंग सील्स, चेक वाल्व वाल्व्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स में औद्योगिक प्रयोग; शाफ्ट सील्स, फ्यूल इंजेक्टर ओ-रिंग, और फ्यूल लुब्रीकेंट्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स, मैनीफोल्ड गार्स्केट और फ्यूल टैंक ब्लाडर में ओ-रिंग सील्स में एयरोस्पेस प्रयोग जैसे विभिन्न अनुप्रयोग हैं।"*

8. मोनोमर्स फ्लोरिंग कंटेन्ट्स और क्यूरेटिव्स पर आधारित दो मुख्य फ्लोरोलस्टोमर्स श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

#### **क) कोपोलाइमर फ्लोरोलस्टोमर्स (एफ 66 प्रतिशत):**

इनको विनाइलीडीन फ्लोराइड (वीडीएफ) और हेक्साफ्लोरो प्रोपीलीन (एचएफपी) से तैयार किया जाता है। को-पॉलीमर एफकेएम दो रूपों अर्थात् राँ-गम और प्री-कंपाउंड में हो सकता है। इसमें काफी तापमान, ऑक्सीडेशन, ऑयल और रासायनिक प्रतिरोधकता तथा अच्छा यांत्रिक गुणधर्म होते हैं। 66 प्रतिशत फ्लोरीन मात्रा से एफकेएम एक सर्वोत्तम तापमान प्रतिरोधक रबड़ होता है और इसका प्रयोग लम्बे समय के लिए 250 डिग्री सेल्सियस पर और कम समय के लिए 300 डिग्री सेल्सियस पर किया जा सकता है।

#### **ख) टरपोलाइमर फ्लोरोलस्टोमर्स (67-70 प्रतिशत):**

इनको विनाइलीडीन फ्लोराइड (वीडीएफ), टेट्रा फ्लोरोथीन (टीएफई) और हेक्सा फ्लोरो प्रोपीलीन (एचएफपी) अथवा प्रोपीलीन अथवा परफ्लोरोमिथाइलविनाइलीथर (पीएमवीई) का प्रयोग करके तैयार किया जाता है। टरपोलाइमर्स (एफकेएम) दो रूपों अर्थात् राँ गम और प्री-कंपाउंड में हो सकता है। को सुरक्षित और सुरक्षा योग्य टरपोलाइमरों में श्रेणीकृत किया जा

सकता है। इसको क्यूरेटिव अर्थात् अमीन बिसफेनल और पैरॉक्साइड से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें अत्यधिक रासायनिक प्रतिरोधकता और दीर्घकालिक ताप प्रतिरोधकता वाले गुणधर्म होते हैं। 67-70 प्रतिशत फ्लोरीन मात्रा से एफकेएम टरपोलाइमर्स एफकेएम में अधिक एसिड कीटोन और कोपोलाइमर्स के बजाए अधिक ईस्टर प्रतिरोधकता होती है।

9. प्राधिकारी उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न अनुरोधों तथा पहलुओं को नोट करते हैं।

1) घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में उनके द्वारा विनिर्मित उत्पाद रेंज के क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित पीसीएन, जांच की शुरुआत के बाद दिए हैं।

क्र. सं.	उत्पाद किस्म का नाम	पीसीएन	पीसीएन का विवरण
1	कोपोलाइमर रॉ गम	एफसीपी#आरजी0001	फ्लोरोलस्टोमर्स (एफकेएम) को-पॉलीमर रॉ गम
2	कोपोलाइमर प्री-कंपाउंड	एफसीपी#पीसी0004	फ्लोरोलस्टोमर्स (एफकेएम) को-पॉलीमर प्री-कंपाउंड
3	टरपोलाइमर बिसफेनल क्यूरेबल रॉ गम	एफटीपीबीआरजी 0002	फ्लोरोलस्टोमर्स (एफकेएम) टरपोलाइमर बिसफेनल क्यूरेबल रॉ गम
4	टरपोलाइमर पैरॉक्साइड क्यूरेबल रॉ गम	एफटीपीपीआरजी 0003	फ्लोरोलस्टोमर्स (एफकेएम) टरपोलाइमर पैरॉक्साइड क्यूरेबल रॉ गम

2) उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर में "टरपोलाइमर प्री-कंपाउंड" का निर्यात भी शामिल है।

3) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने एफकेएम कंपाउंडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने का अनुरोध किया है।

10. प्राधिकारी उपर्युक्त के मद्देनजर यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद अर्थात् फ्लोरोलस्टोमर्स में कोपोलाइमर और टरपोलाइमर दोनों कच्चे गोंद के रूप में तथा विभिन्न किस्मों में प्री-कंपाउंड रूप में हैं। कंपाउंड और एफकेएम विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अलग किए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा अपने अनुरोध में उल्लिखित किस्मों (पीसीएन) पर विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न किस्मों (पीसीएन) के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का अलग-अलग मूल्यांकन करने के लिए विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास टर्पोलाइमर कच्चे गोंद के अलावा टरपोलाइमर प्री-कंपाउंड का उत्पादन करने की भी क्षमता है। यद्यपि, टरपोलाइमर प्री-कंपाउंड का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया है, और उसका उत्पादन जांच की अवधि के बाद किया गया है और घरेलू उद्योग ने टरपोलाइमर श्रेणी के लिए प्री-कंपाउंड में कच्चे गोंद के लिए मूल्य अभिवृद्धि के संबंध में सूचना दी है।

#### ख. घरेलू उद्योग और आधार

#### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- यह याचिका मैसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे "जीएफएल" भी कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। घरेलू उद्योग संबंधित उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है। इस प्रकार, उत्पादक का कुल भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है।
- याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और नियम 2(ख) के अभिप्राय से भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा प्रयोक्ता अथवा चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध नहीं है।
- याचिकाकर्ता का नियमावली के अभिप्राय से पर्याप्त आधार है और वह घरेलू उद्योग है।

#### उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गए अनुरोध

12. वर्तमान जांच में आवेदक के आधार के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

14. यह आवेदन पत्र घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लि. द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक कंपनी के उत्पादन में घरेलू उत्पादन का “प्रमुख अनुपात” है; वस्तुतः वह घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है।

15. यह भी नोट किया जाता है कि उन्होंने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध हैं।

16. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि ये आवेदन पत्र घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया है और आवेदन पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के तहत “आधार” की अपेक्षाओं को पूरा करता है। याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार “घरेलू उद्योग” है।

**ग. गोपनीयता****घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

17. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. उत्तरदाता निर्यातकों ने किसी समुचित औचित्य के बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। सूचीबद्ध सूचना के अभाव में भी घरेलू उद्योग अपने हितों की रक्षा करने और इन अत्यधिक कमी वाले उत्तरों पर अपनी टिप्पणियाँ देने में पूर्णतः असमर्थ हैं।
- ii. निर्यातक शेरधारकों और संबंधित पक्षकारों से संबंधित सूचना को पूरी तरह गोपनीय रखते हैं। यहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह सूचना सार्वजनिक पटल पर है और इसमें कोई गोपनीयता नहीं है।
- iii. याचिकाकर्ता ने केवल उस सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है जो सार्वजनिक पटल पर नहीं है और जिसके लिए देश में प्रकटन के लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।
- iv. याचिकाकर्ता के घरेलू उद्योग के संबंध में वास्तविक सूचना का प्रकटन भी इस उत्पाद में भावी बिजनेस को क्षतिग्रस्त कर सकता है। वर्तमान उत्पादकों के वास्तविक वर्तमान निष्पादन के संबंध में कोई निश्चयात्मक सूचना न रखने वाले भारत में संयंत्र स्थापित करने का प्रयास करने वाले भावी भारतीय उत्पादक के लिए यह सूचना सोने की खान जैसी सूचना हो सकती है।
- v. खंड VI में दी गई सूचना घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए संबद्ध सामानों की लागत और कीमत से संबंधित है और इसमें से कोई भी सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है।
- vi. याचिकाकर्ता ने गोपनीय आधार पर प्राधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट सहित निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी सूचना दी है।
- vii. याचिकाकर्ता ने सभी स्रोतों से घरेलू बिक्री और आयातों की मात्रा के रूप में भारत में उत्पाद की स्पष्ट खपत अथवा मांग, वर्तमान याचिका के प्रयोजन के लिए परिभाषित की है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना अत्यधिक गोपनीय है, जिसके प्रकटन से घरेलू उद्योग को गंभीर पूर्वाग्रह होगा। घरेलू उद्योग का यह दावा कानून और डीजीएडी की विगत परिपाटी के अनुरूप है।
- viii. जहां तक कीमत प्रभाव से संबंधित सूचना प्रकट न किए जाने का संबंध है, कानून के तहत ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय की है जिसके लिए सूचना पहले ही दे दी गई है।

**निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

18. निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और इस प्रकार रक्षा का अधिकार पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। यह याचिका पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में और 9 दिसंबर, 2013 की व्यापार सूचना संख्या 01/2013 में उल्लिखित मानकों को पूरी करने में विफल रहती है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में है।
- ii. आवेदन पत्र के भाग VI के उत्तर में याचिकाकर्ता ने कोई भी सूचना नहीं दी है।
- iii. भाग VI के कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है – "वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार" तथा जीएफएल एक बहु उत्पाद कंपनी होने के नाते यह उत्तर भ्रामक है।
- iv. मांग, कीमत प्रभाव से संबंधित सूचना अकारण ही गोपनीय रखी गई है।
- v. उत्तरदाता ने केवल उसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है जो व्यापार संवेदनशील है और सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने उत्पादन, घरेलू बिक्री और मांग तथा भारतीय मांग में याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से जैसे कई मानदंडों पर स्वयं ही गोपनीयता का दावा किया है। चीन जन. गण. से शीट ग्लास के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच में जांच परिणाम का संदर्भ दिया जाता है (फा. सं. 14/22/2013-डीजीएडी दिनांक 19 दिसंबर, 2016)।
- vi. उत्तरदाताओं द्वारा दावा की जा रही अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे केवल अस्पष्ट नहीं हैं क्योंकि उन्होंने यह सही-सही उल्लेख नहीं किया है कि उत्तरदाताओं द्वारा पहले ही दिए गए कारणों को छोड़कर कारणों का समुचित विवरण क्या हो सकता है, परंतु पूरी तरह से विरोधाभासी भी है क्योंकि घरेलू उद्योग की अपनी याचिका के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होगा कि गोपनीयता का दावा करते समय उसके द्वारा दिया गया कारण उसके संबंध में अन्य कारणों के बिना "सारांश के असंवेदी व्यापार स्वामित्व सूचना" के रूप में संक्षेप में उल्लिखित किया गया है।
- vii. चुनाव सिद्धांत की वजह से घरेलू उद्योग एक ही समय में समर्थ और आक्षेप करने का कार्य नहीं कर सकता और यह तर्क देने से अस्वीकृत किया जाता है कि चीन में निर्यातकों और उत्पादकों को जो सूचना पहले दी गई है, उससे अधिक गोपनीयता का दावा करने के लिए अन्य किसी कारणों के विवरण अथवा उनके आंकड़ों की सूचीबद्ध संख्या देनी है। इस संबंध में इन लिसेंडन बनाम बोस लि., 1940 एसी 412 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाता है।
- viii. घरेलू उद्योग ने चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों के संबंध में दावा किया है जिनमें उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ दिए जा रहे हैं। अतः एआईआरआईए अनुरोध करता है कि घरेलू उद्योग ने उपर्युक्त दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। याचिकाकर्ता प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे असंगत हैं तथा पर्याप्त नहीं हैं।
- ix. झोंघाओ चेंगुआंग ने नियमों के अनुसार पूरी सूचना दी है और गोपनीयता का दावा करने के लिए कारण स्पष्ट करते हुए औचित्य की तालिका भी संलग्न की है।
- x. डेकिन और यूनी एलाइंस लि. ने उपर्युक्त नियम के अनुसार पूरी सूचना दी है और गोपनीयता का दावा करने के लिए कारण स्पष्ट करते हुए औचित्य की तालिका भी संलग्न की है। घरेलू उद्योग के ये दावे कि अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है, असंगत हैं, तथापि, डेकिन और यूनी एलाइंस लि. वर्तमान जांच के निष्कर्ष निकालने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित अन्य सूचना देने के लिए भी तैयार है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

19. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता जिन्हें संगत माना गया था, के संबंध में अनुरोधों की जाँच और तदनुसार उसका समाधान कानूनी प्रावधानों और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सतत प्रथाओं के आलोक में किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जाँच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे, जहाँ भी संभव हुआ, को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोई भी सूचना जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है, को गोपनीय के रूप में नहीं माना गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की कुल निर्यात बिक्री का प्रकटन के संबंध में कुछ उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। चूँकि ऐसे अनेक पीसीएन हैं जिन्हें प्राधिकारी ने सभी सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की कुल बिक्री और इस

जाँच परिणाम में संचयी रूप से सभी पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता और घरेलू बिक्री को भी प्रकट किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीजीसीआई एंड एस लेन देन वार आँकड़ों में उत्पाद संबंधित विवरण कमोवेश विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के स्रोत को प्रकट करते हैं।

## घ. विविध अनुरोध

### घरेलू उद्योग

20. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चीन सरकार द्वारा कोई सब्सिडी न होने के संबंध में प्रभावली के उत्तर में निर्यातकों द्वारा झूठे और भ्रामक विवरण दिए गए हैं क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई पूरी सूची है जिसमें उन कार्यक्रमों का उल्लेख है जो चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जिनमें निर्यातकों को लाभ दिए जा रहे हैं।
- ii. याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए क्षति संबंधी अनुरोध घरेलू बिक्री के आधार पर हैं न कि निर्यातों के आधार पर। प्राधिकारी सत्यापन कर सकते हैं।
- iii. इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना "तोड़ी-मरोड़ी गई है और गलत है" तथा यह आरोप जीएफएल के निर्यात के संबंध में "उनके पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार" के आधार पर है। उत्तरदाता केवल इस आधार पर उनके तर्कों को आधार नहीं बना सकते क्योंकि उपर्युक्त आँकड़े कहीं प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी को कुछ गोपनीय आधार पर दिया गया है तो वह याचिकाकर्ता को प्रकट किया जाना चाहिए।
- iv. जहां तक इस आरोप का संबंध है कि वास्तविक मंदी दर्शाने के लिए वार्षिक रिपोर्ट किसी तरीके से बनाई गई है, जीएफएल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी अपने व्यापारिक क्रियाकलापों में बहुत ही सजग है और वे ऐसी गलत परिपाटियों का सहारा नहीं लेते।
- v. अन्य उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का यहां कोई संबंध नहीं है। आवेदक एक बहु उत्पाद कंपनी है और यदि सरकार ने जांच के बाद के उनके कुछ उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है तो उन्हें वे कानून के अनुसार संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए प्राधिकारी के पास जाने के लिए अटकाया नहीं जा सकता। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना ही संगत है।
- vi. वार्षिक रिपोर्ट में सार्वजनिक विवरण इस निष्कर्ष को नहीं बदलते कि उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- vii. निर्दिष्ट प्राधिकारी का संबंध संबद्ध सामानों के घरेलू प्रचालनों से है जबकि वार्षिक रिपोर्टें कंपनी के समग्र प्रचालनों से संबंधित हैं।
- viii. अनुमान उपयुक्त थे। निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच कर सकते हैं। याचिकाकर्ता का डीलरों/वितरकों का व्यापक नेटवर्क है। यह वह मामला नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता कंपनी कोई नई कंपनी हो। जीएफएल देश में एक सुप्रसिद्ध, सुस्थापित और प्रतिष्ठित नाम और अपने उत्पादों पर गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। यदि याचिकाकर्ता कंपनी अपने व्यापार का प्रबंधन करने में अदक्ष अथवा अक्षम होती तो वह अपने अन्य व्यापारों में सफल न हुई होती।
- ix. उत्तरदाता निर्दिष्ट प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए बिना किसी सामग्री के सुपुर्दगी न किए जाने के संबंध में उसे सिद्ध करने के लिए आधारहीन दावे कर रहे हैं।
- x. यह अब एक निर्धारित कानून का सिद्धांत है कि पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने के लिए मांग-आपूर्ति का अंतराल आधार नहीं है। पाटनरोधी शुल्क निर्यातकों द्वारा अपनाई जा रही अनुचित व्यापार परिपाटी के विरुद्ध है और घरेलू उद्योग को उचित व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से है। यह आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता।
- xi. अनुचित संरक्षण उपाय से संबंधित तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनुरोध पूरी तरह अवधारणाओं और अनुमानों पर हैं, किसी अध्ययन से समर्थित नहीं है और खुद याचिकाकर्ता के मामले में प्राप्त अनुभव के विपरीत हैं जहां याचिकाकर्ता केवल पीटीएफई में ही नहीं बढ़ा है बल्कि उपभोक्ता भी बढ़े हैं और याचिकाकर्ता अधिक प्रतिस्पर्धी बना है। यदि हितबद्ध पक्षकारों के तर्क सही होते तो उद्योग के पास विकास करने का और पाटन के क्षतिकारक प्रभाव के कारण क्षति होने के मामले में प्राधिकारी के पास जाने का स्तर नहीं होता, डब्ल्यूटीओ द्वारा तथा विश्व स्तर पर मानी गई वास्तविक मंदी की कोई संकल्पना नहीं होती।

- xii. आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और अलग से आंकड़ों का कोई सेट नहीं दिया गया है। अंतर केवल यह है कि क्षमता, सकल उत्पादन, निवल उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में तिमाही आंकड़े सुनवाई से पूर्व के अनुरोधों में दिए गए हैं जबकि याचिका में केवल वार्षिक आंकड़े दिए गए हैं। प्राधिकारी सत्यापन करें।
- xiii. यह पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है कि त्रुटि याचिका में किए गए विश्लेषण में है और याचिका में दायर की गई सूचना/आंकड़ों में कोई त्रुटि नहीं है। प्राधिकारी कृपया याचिका में निहित आंकड़ों तथा सुनवाई से पूर्व लिखित अनुरोधों में विश्लेषण और उसके बाद किए गए अनुरोधों पर विचार करें। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि याचिका में निहित आंकड़े/सूचना ही जांच की शुरुआत का आधार बनते हैं।
- xiv. याचिकाकर्ता ने निवल उत्पादन पर विचार करते हुए क्षमता उपयोग के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। प्राधिकारी कृपया सत्यापन करें।
- xv. यदि संबद्ध सामान भारत में पाटित किए जा रहे हैं और घरेलू उद्योग को इस सीमा शुल्क के बावजूद भी क्षति हो रही है तो 7.5 प्रतिशत के मूल सीमा शुल्क की मौजूदगी से संबंधित तर्क असंगत है। दोनों केवल संकल्पना और सार में ही भिन्न नहीं हैं बल्कि प्रयोजन और प्रचालन में भी भिन्न है।
- xvi. एफकेएम का उत्पादन वैश्विक रूप से भारत, चीन, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और रूस में किया जाता है। प्रमुख वैश्विक उत्पादकों की एफकेएम की क्षमता 49,560 मी. टन है जिसमें चीन की क्षमता 22,500 मी. टन है।

### **एकाधिकार से संबंधित मुद्दे**

- xvii. उत्तरदाताओं का यह मानना कि शुल्क लगाए जाने से एकाधिकार की स्थिति बनेगी, आधारहीन है। पाटनरोधी कानून किसी उत्पादक को घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने से प्रतिबंधित नहीं करता।
- xviii. कई पाटनरोधी जांचें हुई हैं जिनमें घरेलू उद्योग भारत में संबंधित उत्पाद का एक मात्र उत्पादक था और प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।
- xix. पाटनरोधी शुल्क देश में आयात करने के लिए बाधक नहीं है। इसकी बजाए वह विदेशी अनुचित परिपाटी को रोकने का प्रयास करता है।
- xx. पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन एकाधिकार की स्थितियां पैदा करना नहीं है। पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप से घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी कानून का प्रयोजन अन्य देशों से उत्पादकों की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों के विरुद्ध सामानों के घरेलू उत्पादन की सुरक्षा कर भारतीय बाजार में सामानों के उत्पादन और खपत के लिए एक उचित व्यापारिक क्षेत्र तैयार करना है। सामान्य आर्थिक विकास के लिए घरेलू उद्योग आधार की मौजूदगी और संधारणीयता महत्वपूर्ण है जिसकी क्षतिकारक पाटन के विरुद्ध सुरक्षा की जानी है।

### **अन्य उत्पादों/उद्योगों एवं जनहित पर प्रभाव के संबंध में अनुरोध**

- xxi. जहां तक कमी पैदा करने वाले बल-उपाय के तर्क का संबंध है, यह आधारहीन है और पाटनरोधी जांच में असंगत है। जिन दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, वे किसी ऐसे कार्य का औचित्य बनाने के लिए आधार नहीं हो सकते जो कि मानव के नियंत्रण में है अर्थात् पाटन परिपाटी अपनाना।
- xxii. कार्बन ब्लैक के ये मुद्दे इस मामले में संगत नहीं हैं। किसी अन्य उत्पाद की कमी पाटनरोधी जांच में संगत नहीं है। विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना ही संगत है।
- xxiii. उत्तरदाता ने एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि पर प्रभाव दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। फिर भी घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उससे हुए क्षति के लिए कानून के तहत राहत की मांग कर रहा है।
- xxiv. पाटनरोधी उपाय प्रकृति में संरक्षणवादी नहीं हैं। पाटनरोधी व्यवस्था इस अनुचित व्यापारिक परिपाटी से ग्रस्त उद्योगों के लिए राहत प्रदान करने हेतु तैयार की गई है। पाटनरोधी कानून उन आयातों को हटाने अथवा सीमित करने के लिए तैयार नहीं किए गए हैं जो कि घरेलू उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके बजाए, वे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने के लिए भेद-भाव पूर्ण कीमत परिपाटियों का प्रयोग करने से विदेशी उत्पादकों को रोकने के लिए बनाए गए हैं।



- xxv. जहां तक उत्पाद लागतों में वृद्धि से संबंधित तर्क का संबंध है, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से छोटे समय के लिए भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लगाने से कम नहीं होगी।
- xxvi. अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता उपलब्ध नहीं होगी। उपभोक्ता आपूर्ति के विविध स्रोत बनाए रख सकते हैं।
- xxvii. पाटनरोधी शुल्क न लगाने से पाटनरोधी शुल्क की अपेक्षा देश पर और क्षतिग्रस्त प्रभाव पड़ेंगे। शुल्क न लगाए जाने से भारत में इस महत्वपूर्ण उत्पाद का उत्पादन कम होगा। ऐसे पाटित आयातों का प्रभाव घरेलू उद्योग पर पहले ही देखा जाता है। निचले उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा।
- xxviii. पाटनरोधी उपाय उचित व्यापार सुनिश्चित करने और घरेलू उद्योग को उचित व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए हैं। वे आयात को प्रतिबंधित करने और उत्पादन की लागत में अनौचित्यपूर्ण वृद्धि करने के उपाय नहीं हैं। वर्तमान स्थिति का प्रयोजन कोई अनुचित लाभ लेना नहीं है। याचिकाकर्ता केवल अनुचित पाटन पर रोक लगाना चाहता है ताकि याचिकाकर्ता बाजार में खुद को पूरी तरह से स्थापित कर सके और किए गए निवेश पर उचित आय अर्जित करते हुए उचित कीमत पर उपभोक्ताओं को आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह अधिक औचित्यपूर्ण है क्योंकि वह देश में एक मात्र उत्पादक है।
- xxix. एमएसएमई क्षेत्र का पक्ष लेने से संबंधित तर्क वास्तविक रूप से गलत और भ्रामक है। वस्तुतः जैसा कि उल्लेख किया गया है, विगत में 90 प्रतिशत एफकेएम मांग गैर-चीनी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पूरी की जा रही थी जबकि 2016-17 में 48 प्रतिशत मांग और जांच की अवधि में 44 प्रतिशत मांग चीनी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संगत अवधि में उस कीमत पर पूरी की जा रही थी जो कि लगभग उस कीमत से दोगुनी थी जिस पर चीनी आपूर्तिकर्ता बाजार में बिक्री कर रहे थे। यदि ये एमएसएमई उपभोक्ता इतनी अधिक कीमत पर गैर-चीनी स्रोतों से खुश होकर सामग्री खरीद सकते हैं और केवल बने ही नहीं रह सकते बल्कि बढ़ भी सकते हैं तो इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि इन चीनी आपूर्तिकर्ताओं को पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप क्षति होगी।
- xxx. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को पीटीएफई में वही अनुभव हुआ है जहां उत्पादन पुनः एमएसएमई क्षेत्र में है। कुछ समय के लिए पीटीएफई पर पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पीटीएफई बाजार 2005-06 में 1729 मी. टन से बढ़कर 2016-17 में 6800 मी. टन हो गया। पीटीएफई बाजार पाटनरोधी शुल्क के बावजूद बढ़ा है। यह तथ्य यहां स्पष्ट रूप से बताता है कि विचाराधीन उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र को प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप नुकसान नहीं होगा। किसी भी स्थिति में याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि उपभोक्ताओं ने उनके दावों को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य अथवा सत्यापनीय सूचना नहीं दी है।
- xxxi. यह उल्लेख करना भी संगत है कि तर्क एमएसएमई क्षेत्र के नाम पर दिए जा रहे हैं जबकि तथ्य यह है कि विचाराधीन उत्पाद के कई उपभोक्ता वस्तुतः काफी कारोबार वाली कंपनियां हैं।

### एनआईपी दावों के संबंध में अनुरोध

- xxxii. प्राधिकारी अपनी सतत परिपाटी के अनुसार, नियोजित पूंजी पर आय प्रदान करे, यद्यपि, घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर अधिक आय की मांग की है।
- xxxiii. निर्दिष्ट प्राधिकारी की सभी स्थितियों में 22 प्रतिशत आय देने की परिपाटी है और इसीलिए समानता का सिद्धांत यह मांग करता है कि सभी स्थितियों में उसे लागू किया जाए। निर्दिष्ट प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों की लो और चुनो की नीति तथा दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- xxxiv. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि प्राधिकारी जब कोई पाटन नहीं था तो उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय पर विचार किए बिना पिछले कई वर्षों से लगभग प्रत्येक मामले में 22 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर आय की अनुमति देते रहे हैं।
- xxxv. वर्तमान मामला वह मामला है जिसमें देश में घरेलू उद्योग की स्थापना को पाटन से वास्तविक मंदी हो रही है। इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा डीजीएडी की नीति और परिपाटी से संबंधित होने के नाते प्राधिकारी उचित रूप से वह निर्धारित करें जो उपयुक्त माना जाए।

### **निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

21. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

#### **विविध मुद्दे**

- i. घरेलू उद्योग द्वारा दायर पत्र में यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात काफी बढ़े हैं। उत्तरदाताओं के पास उपलब्ध आंकड़े संबद्ध सामानों के निर्यात में काफी भारी गिरावट दर्शाते हैं।
- ii. जीएफएल द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने वास्तविक मंदी दर्शाने के लिए उसमें जानबूझकर बनावट की हो।
- iii. जीएफएल विभिन्न आयातित उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए एक आदततन याचिकाकर्ता है।
- iv. जीएफएल का वित्तीय विवरण उनके घाटा होने के दावे पर विवाद करते हुए जांच की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित अच्छा लाभ दर्शाता है।
- v. घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की अनुमानों से तुलना करते समय यह अनिवार्य है कि घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट में उसके द्वारा की गई अवधारणाओं की उपयुक्तता की जांच की जाए क्योंकि याचिकाकर्ता इस उद्योग में नया है।
- vi. देश में मांग एवं आपूर्ति का अंतराल है। घरेलू उद्योग निर्यातों पर जोर दे रहा है। कई बार वह संबद्ध सामानों के उपलब्ध न होने के कारण आपूर्ति करने में विफल रहा।
- vii. अनुपयुक्त संरक्षण उपाय केवल घरेलू उद्योग की ही सुरक्षा नहीं करते बल्कि उसके दीर्घावधिक और मौलिक हित को भी क्षति पहुँचा सकते हैं। यह घरेलू उद्योग को उत्पादन प्रौद्योगिकी और दक्षता में सुधार लाने में उदासीन बना सकता है।
- viii. दो याचिकाएं दायर की गई हैं और याचिकाकर्ता का दावा है कि मूल याचिका में दायर सूचना अथवा आंकड़ों में कोई त्रुटि नहीं है। परंतु वस्तुतः याचिका में तथा क्षमता, कुल उत्पादन एवं निवल उत्पादन तथा क्षमता उपयोग के लिए सुनवाई पूर्व अनुरोध में आंकड़ों के अलग-अलग सेट दिए गए हैं।
- ix. याचिकाकर्ता क्षति की गैर-मौजूदगी दर्शाने के लिए वास्तविक क्षमता उपयोग को करने के उद्देश्य से निवल उत्पादन पर विचार करते हुए क्षमता उपयोग के ब्यौरे दे सकते थे।
- x. उत्तरदाता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे आधार वर्ष के रूप में 2015-16 पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता के आंकड़ों और आयात, दोनों की तुलना करें क्योंकि घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2015 से उत्पादन आरंभ किया और वर्तमान जांच की क्षति अवधि 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जांच की अवधि है।
- xi. मूल सीमा शुल्क पहले ही 7.5 प्रतिशत है और किसी भी अतिरिक्त शुल्क से चीन जन. गण. से निर्यात रुकेंगे ही।
- xii. दिनांक 28 फरवरी, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 5/2018 के अनुसार सूचना दायर करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों को निर्देश देने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारी से किया गया अनुरोध गलत है क्योंकि व्यापार सूचना सं. 5/2018 उस जांच पर लागू है जिसकी शुरुआत 28 फरवरी, 2018 के बाद की गई। उत्तरदाता ने सही लागू प्रपत्र में उत्तर दायर किया है।
- xiii. याचिकाकर्ता व्यापार सुधारात्मक उपायों आदततन प्रयोक्ता है और उसे उसके उत्पादन की घटिया गुणवत्ता, अदक्षताओं और बाजार प्रवेश नीति के कारण क्षति हो रही है। यह इस तथ्य से सिद्ध है कि याचिकाकर्ता को निर्यात बाजार में भारी हानियां हुई हैं।
- xiv. याचिकाकर्ता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्धारण के संबंध में दिया गया संदर्भ यहां असंगत है। पूरे ब्यौरे याचिकाकर्ता के पास दायर कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों के जांच परिणामों के अनुसार याचिकाकर्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में भी संबद्ध सामानों का पाटन किया है।
- xv. याचिकाकर्ता ने याचिका, सुनवाई पूर्व लिखित अनुरोधों तथा लिखित अनुरोधों में वर्ष 2016-17 के लिए आंकड़ों के अलग-अलग सेट दिए हैं। यह क्षति की गैर-मौजूदगी का आरोप लगाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आंकड़ों की सत्यता के संबंध में गंभीर संदेह उठाता है।
- xvi. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने पहले ही अधिसंख्या उपभोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति की है। वह पिछले लगभग 3 वर्षों से प्रचालन में है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता एक सुस्थापित उद्योग है। अतः उत्तरदाता

प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे जांच को पूरी तरह से रद्द करें क्योंकि वास्तविक मंदी का उपाय केवल उस उद्योग के लिए है जो अभी तक स्थापित न हुआ हो।

- xvii. घरेलू उद्योग का पाटनरोधी शुल्कों में पूर्व अनुभव निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस तथ्य की चेतावनी देने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा उल्लिखित किया गया है कि परियोजना रिपोर्ट और बाजार संभाव्यता परीक्षण वर्तमान मामले में विश्वास किए जाने के लिए सुरक्षित नहीं होंगे क्योंकि घरेलू उद्योग पाटनरोधी जांच में शामिल स्थितियों से सुपरिचित होने के नाते यह दर्शाने के लिए अपना वास्तविक निष्पादन निर्धारित करने हेतु अपने अनुमानों में छेड़-छाड़ करने की स्थिति में होगा कि वह अपना प्रत्याशित निष्पादन पूरा करने में समर्थ नहीं रहा है जो अन्यथा वास्तविक नहीं हो सकता और जो उसकी स्थापना को वास्तविक मंदी दर्शाए। घरेलू उद्योग ने जानबूझकर अपने सामानों की कीमत उस कीमत से काफी कम कीमत पर रखी है जो चीन से आयातों की कीमत थी ताकि वह अपनी बहियों में उसे क्षति दर्शाने के प्रयोजन के लिए हानियां दर्शा सके।
- xviii. पाटनरोधी जांच में यूएसडीओसी द्वारा निर्धारण पर यह दर्शाने के लिए किया गया विश्वास कि चीनी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन 84.75 प्रतिशत तक था, असंगत है क्योंकि वह पीटीएफई से संबंधित है न कि एफकेएम से संबंधित।
- xix. घरेलू उद्योग ने पीटीएफई के बाजार निष्पादन की तुलना एफकेएम से की है। यह तर्क अपने आप में घरेलू उद्योग द्वारा तथ्यों के गलत निर्माण को सिद्ध करता है जिसके कारण निम्नलिखित हैं:
- क. भारत में जीएफएल सहित पीटीएफई के दो विनिर्माता हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय अंतिम प्रयोक्ताओं को एक घरेलू आपूर्तिकर्ता पर विश्वास नहीं करना है। साथ ही, चूंकि केवल दो ही विनिर्माता हैं, इसलिए एक कोई भी एक विनिर्माता अंतिम प्रयोक्ताओं पर अधिक प्रभार नहीं लगा सकता।
  - ख. इसके अतिरिक्त, अंतिम प्रयोक्ता और पीटीएफई एवं एफकेएम के आवेदन पत्र पूरी तरह से भिन्न हैं। पीटीएफई के मामले में अंतिम अपेक्षाएं इतनी कठोर नहीं हैं जितनी एफकेएम (जो आधारभूत रूप से कठोर ऑटो अनुप्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है) के मामले में हैं। पीटीएफई के मामले में अंतिम प्रयोक्ता कभी प्रयोग किए जाने वाले ग्रेड और विनिर्माता का उल्लेख नहीं करता है, परंतु एफकेएम के मामले में ऑटो कंपनियां उनके द्वारा जारी आरेख के भाग में ग्रेड और विनिर्माता का स्पष्ट रूप से उल्लेख करती हैं जिससे रबड़ उद्योग के पास कोई लचीलापन नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में, भारतीय रबड़ उद्योग महंगी कीमत पर आयातित उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा जिससे वे अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धियों की अपेक्षा कम प्रतिस्पर्द्धी बन जाएंगे। सुजुकी, टोयोटा, होंडा आदि जैसी कंपनियों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता हैं जो भारतीय रबड़ उद्योग की वृद्धि पर भारी खतरा पैदा कर रहे हैं।
  - ग. यद्यपि घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि पीटीएफई बाजार भारत में 6800 मी. टन तक बढ़ गया है, तथापि, उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया है कि उसी अवधि में चीन का पीटीएफई बाजार कई गुना अधिक 90,000 मी. टन से अधिक बढ़ गया है। यह दर्शाता है कि जीएफएल ने भारतीय पीटीएफई उपभोक्ताओं पर अधिक कीमतें लगाने के लिए पाटनरोधी संरक्षण का लाभ लेने का कैसे प्रयास किया है जिससे वे गैर-प्रतिस्पर्द्धी हो गए हैं और उनकी वृद्धि रुक रही है। हम पुनः दोहराते हैं कि वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान में एमएसएमई क्षेत्र होगा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धियों में नुकसान उठाएंगे।
- xx. दिनांक 28 फरवरी, 2018 की व्यापार सूचना सं. 5/2018 व्यापार नोटिस जारी करने के बाद शुरू की गई जांचों पर लागू है। चूंकि, वर्तमान जांच 02 जनवरी, 2018 को शुरू की गई थी, अतः वह व्यापार नोटिस प्रतिभागी निर्यातकों/ आयातकों पर लागू नहीं है। तथापि, यदि प्राधिकारी चाहें तो हम पूरी सूचना देने के इच्छुक हैं।
- xxi. भारतीय घरेलू उद्योग को पहले ही सीमा शुल्क के रूप में 7.5 प्रतिशत का संरक्षण है। यदि व्यापार उपचार महानिदेशालय संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का निर्णय लेता है तो फिर याचिकाकर्ता को यह संरक्षण अनावश्यक होगा क्योंकि संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में एफकेएम के निचले बाजार की वृद्धि ही रुकेगी।

### **एकाधिकार का मुद्दा**

- xxii. शुल्क लगाने से एकाधिकार की स्थिति बनेगी और जीएफएल अधिक कीमत लगाकर स्थिति का लाभ उठाएगा।
- xxiii. घरेलू उद्योग व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा दिए गए संरक्षणों का दुरुपयोग कर रहा है। घरेलू उद्योग का समग्र निष्पादन भारी लाभ दर्शा रहा है जबकि वे दावा कर रहे हैं कि उन्हें क्षति हुई है जो कि सही नहीं है। इसके अधिकतर उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के लाभ हो रहे हैं जिससे जीएफएल का एकाधिकार बन रहा है जिससे भारतीय उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।

### **अन्य उत्पादकों/उद्योग से संबंधित चिंता**

- xxiv. घरेलू उद्योग के संयंत्र में किसी बल उपाय से भारी कमी होगी; कार्बन ब्लैक में वर्तमान स्थिति एक उदाहरण है। निर्धारित संयंत्र रख-रखाव, खराबी के रख-रखाव, बल उपाय आदि के कारण उनके उत्पादन में किसी व्यवधान से रबड़ विनिर्माता उच्चतर लागत पर सामग्री खरीदने के लिए मजबूर होंगे।
- xxv. एफकेएम पर किसी अतिरिक्त शुल्क से रबड़ संघटकों का निर्यात अब व्यवहार्य हो जाएगा क्योंकि रबड़ प्रसंस्करणकर्ता कार्बन ब्लैक की कमी के कारण लागत में भारी वृद्धि का सामना कर रहे हैं जिससे एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा जिस पर सरकार जोर दे रही है।
- xxvi. कोई अतिरिक्त शुल्क लगाने से संरक्षणवादी नीति बनेगी जिससे हजारों लघु और मध्यम रबड़ प्रसंस्करणकर्ताओं की अर्थक्षमता की लागत और वृद्धि पर एक कंपनी को लाभ होगा। यह सरकार के एमएसएमई क्षेत्र को भारी बढ़ावा देने तथा "मेक इन इंडिया" नीति के दावे के विरुद्ध जाएगा।
- xxvii. ऑटोमोबाइल क्षेत्र एफकेएम आधारित उत्पादों का एक प्रमुख उपभोक्ता है; इससे उनकी उत्पाद लागत में भी वृद्धि होगी जो अंतिम रूप से लाखों भारतीय उपभोक्ताओं की तरफ जाएगी।

### **सार्वजनिक हित**

- xxviii. पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। भारतीय रबड़ उद्योग ने अधिकतर रबड़ प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता एमएसएमई क्षेत्र से हैं और आला ग्राहकों के लिए कम मात्रा में उनके विशेष आदेशों को पूरा करने के लिए प्रचालन करता है। वे व्यापक रूप से बेहतर गुणवत्ता के कारण आयात सामग्री पर निर्भर करते हैं। जीएफएल को अभी विश्व श्रेणी के मानक तक पहुँचना है और ग्राहक की विशिष्टि को पूरा करना है। पाटनरोधी शुल्क व्यापक ऑटोमोबाइल कंपनियों को उनकी विनिर्माण आधार बनने में हतोत्साहित करेगा क्योंकि उनकी उत्पादन लागत विकल्पों के प्रतिबंध से बढ़ जाएगी। डीजीएडी को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए जो उतनी अनुकूल स्थिति नहीं है जो कि बढ़ सके, यदि पाटनरोधी शुल्क एफकेएम पर लगाया जाता है और वे तदनुसार निर्णय लें।

### **एनआईपी मुद्दे**

- xxix. आवेदक ने कुल अचल परिसंपत्तियों पर 26 प्रतिशत की आय का दावा किया है। यह दावा बढ़ा हुआ है और कानून के अनुसार नहीं है।
- xxx. निर्दिष्ट प्राधिकारी एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर करते हैं। यह निर्धारण अत्यधिक बढ़ाया गया है और नियमावली के अनुबंध-III के पैरा 4 के अनुसार वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं है।
- xxxi. निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वे उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर आय अपनाएं जब उपयुक्त लाभ मार्जिन के रूप में पाटन का कोई आरोप नहीं था न कि नियोजित आय पर 22 प्रतिशत को अपनाएं। 22 प्रतिशत प्रदान करना गलत है क्योंकि (i) नियोजित पूंजी का ऋण भाग जिस पर लगभग 10-12 प्रतिशत ब्याज दर दी जाती है, पर 22 प्रतिशत दिया जाता है, (ii) इससे नियोजित पूंजी पर निवल मूल्य भाग पर 22 प्रतिशत आय से अधिक प्रदान करने का परिणाम आता है, (iii) वैश्विक मंदी के युग के दौरान घरेलू उद्योग को इतनी अधिक आय की अनुमति देना पूर्णतः गलत है और कभी सुना भी नहीं गया है।
- xxxii. डीजीएडी क्षति रहित कीमत निकालने के लिए 22 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर आय अपनाते रहे हैं और वह गलत है। दिए गए नमूना परिकलन के अनुसार 22 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर आय घरेलू उद्योग को इक्विटी पर 41 प्रतिशत लाभ मार्जिन का अनुचित लाभ और संरक्षण देता है।
- xxxiii. क्षति रहित कीमत निकालने के लिए 22 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर आय अपनाना उपयुक्त नहीं है। इस परिपाटी को अपनाना उपयुक्तता के लिए आधार नहीं हो सकता। औषधियां (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 (डीपीसीओ, 1987) में भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया 22 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर आय का आधार 30 वर्ष बाद उपयुक्त नहीं माना जा सकता जब ब्याज दर और निगम कर जैसे मानदंड भिन्न थे। वास्तविक आधार पर निगम कर और ब्याज दर की वर्तमान दरें लागू करने से तालिका में दिए गए अनुसार इक्विटी अनुपात के अलग-अलग सेट के लिए निम्नलिखित रूप में नियोजित पूंजी पर आय निकलेगी जो यह दर्शाता है कि 22 प्रतिशत आय घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण देती है।
- xxxiv. ब्रिज स्टोन टायर बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में निर्णय के अनुसार नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय ने क्षति मार्जिन को रंग चढ़ाया है और कम कीमत पर बिक्री तथा क्षति मार्जिन बढ़ाया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को उस

अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ अपनाना चाहिए जब उपयुक्त आय के परिकलन के लिए आधार के रूप में पाटन का आरोप नहीं था। यूरोपीय संघ भी इसी परिपाटी को अपनाता है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

22. विविध मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विभिन्न अनुरोधों की जांच की गई और निम्नलिखित रूप में उन्हें हल किया गया ।

23. जहां तक आवेदन पत्र में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई अपर्याप्त सूचना का तर्क है, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदन पत्र में जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए अनिवार्य प्रथम दृष्टया सूचना थी। प्राधिकारी ने उस पर विचार करने के बाद ही वर्तमान जांच शुरू की। इसके अतिरिक्त, जांच की शुरुआत के बाद आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई है और वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए उसे अपनाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि साक्ष्य की विश्वसनीयता में जांच की प्रगति होने पर सुधार आता है।

24. क्षति मार्जिन परिकलनों के तर्कों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि क्षति मार्जिन पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार परिकलित घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के दौरान विद्यमान सीमा शुल्क अपनाया गया है।

25. जहां तक मांग-आपूर्ति अंतराल का तर्क है, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान स्थिति चीन से आयातों के संबंध में ही है। भारत में 822 मी. टन आयातों के विरुद्ध 415 मी. टन अर्थात् 43.54 प्रतिशत की मांग गैर-संबद्ध देशों से थी और बिना किसी पाटनरोधी शुल्क के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगी। यह भी नोट किया जाता है कि गैर-चीनी स्रोतों से आयातों की पहुँच कीमत क्षति रहित कीमत से अधिक कीमत पर है। यह मानते हुए कि नियमावली में कमतर शुल्क नियम लागू करने का प्रावधान है, इसका अर्थ है कि किसी भी दशा में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश पर विचार कर रहे प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश किए जाने पर भी चीन जन.गण से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की एनआईपी से अधिक नहीं होगी।

26. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आंकड़ों के दो अलग-अलग सेट दिए गए हैं। प्राधिकारी ने सत्यापित आंकड़ों संबंधी अपने विश्लेषण को आधार बनाया है।

27. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद की क्षमता, गुणवत्ता और विशिष्टियों तथा भारत में आयातित उत्पादों के संबंध में तर्क दिया है। तथापि, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु है और दोनों का प्रयोग प्रयोक्ताओं/आयातकों द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए सामान उस प्रयोजन के लिए सामानों की गुणवत्ता संबंधी मुद्दे उठाए जाते समय प्रयोग नहीं किए जा सकते जिसके लिए सामानों का आयात किया गया था।

28. इस तथ्य के संबंध में कि याचिकाकर्ता कंपनी एक बहु उत्पाद एवं बहु प्रभाग कंपनी है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए अलग रखा गया है तथा पाटनरोधी मामले के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन का मूल्यांकन विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किया गया है।

29. याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्टों जैसे सार्वजनिक विवरणों पर घरेलू उद्योग को क्षति सिद्ध करने के लिए उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

30. चूंकि, याचिकाकर्ता कंपनी एक बहु उत्पाद कंपनी है, अतः प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सूचना तथा याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा रखे गए और विधिवत सत्यापित रिकार्डों पर विश्वास किया है। याचिकाकर्ता कंपनी के प्रकाशित वित्तीय परिणाम इस संबंध में सीमित संदर्भ के हैं क्योंकि यह सूचना अकेले पूर्णतः विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं है तथा इस कंपनी के समग्र निष्पादन से संबंधित है।

31. जहां तक इन अनुरोधों का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क से एकाधिकार की स्थिति बनेगी, प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटी द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना ही है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के संघटन और संरचना को ध्यान में न रखते हुए पाटन और क्षति के बीच कारणात्मकता की जांच की है। वर्तमान मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि यह वास्तविक शिथिलता का मामला है, प्राधिकारी ने बाद के पैरा में यथा उल्लिखित 18 महीने की अवधि के लिए ही उपाय पर विचार किया है।

## ड. विभिन्न प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा किए गए अनुरोध

### 32. मैसर्स हाई-टेक अराई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुरोध

- (i) हाई-टेक अराई प्राइवेट लिमिटेड ऑयल सील्स, ओ-रिंग, मॉल्डेड रबड़ पाटर्स, रीड वाल्व, असेंबली आदि जैसे ऑटोमोबाइल सहायक हिस्स-पुर्जों के विनिर्माण के लिए मैसर्स अराकई सीसाकुशो कं. लि., जापान के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।
- (ii) ये उत्पाद भारत में मूल उपस्कर विनिर्माण (ओईएम) को आपूर्ति किए जाते हैं यथा – मारुति सुजुकी इंडिया लि., टोयोटा किलॉस्कर ऑटो पाटर्स प्रा. लि., होंडा कार इंडिया लि., निसान मोटर इंडिया लि., हीरो मोटर कॉर्प लि., बजाज ऑटो लि., इंडिया यामाहा मोटर प्रा. लि., होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्रा. लि. और टीवीएस मोटर कंपनी लि. आदि हम अपने उत्पाद अराई सीसाकुशो कं. लि., जापान क्रिसलर ग्रुप एलएलसी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पियागियो एंड सीएसपीए, इटली को भी निर्यात कर रहे हैं।
- (iii) हमारे उपर्युक्त सभी उत्पादों में हम निम्नलिखित कंपनियों द्वारा विनिर्मित फ्लोरोलस्टोमर्स (एफकेएम) के विभिन्न ग्रेडों का प्रयोग कर रहे हैं:
  - क. चेमर्स कंपनी एफसी, एलएलसी, संयुक्त राज्य अमेरिका (पूर्व में डुपोंट)
  - ख. 3एम, संयुक्त राज्य अमेरिका (पूर्व में डाइनोन)
  - ग. डैकिन इंडस्ट्रीज लि., जापान
  - घ. डैकिन फ्लोरोकेमिकल्स कं. लि., चीन
  - ङ. झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि., चीन
  - च. चेमर्स फ्लोरोलस्टोमर्स, चीन
  - छ. सॉल्वे, इटली/चीन
- (iv) हम भारत में फ्लोरोलस्टोमर्स (एफकेएम) के प्रमुख उपभोक्ता हैं और हमारी एफकेएम की वार्षिक आयात मात्रा लगभग 250 मी. टन है जिसमें से हम चीनी विनिर्माताओं से लगभग 40 मी. टन का आयात करते हैं।
- (v) इनमें से डैकिन, चेमर्स और सॉल्वे चीन में भी एफकेएम की विनिर्माण यूनिटें हैं। कारण यह है कि फ्लोरस्फर जैसी एक आधारभूत कच्ची सामग्री, जो फ्लोरीन युक्त मिनरल है, चीन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
- (vi) अब घरेलू विनिर्माता जीएफएल भारत में एफकेएम का विनिर्माण करने के प्रारंभिक विकास चरण में है और आवश्यक रूप से मोनोमर्स का आयात कर रहे हैं।
- (vii) एफकेएम ग्रेडों के भारी क्षेत्र की उपलब्धता बनाने वाले एफकेएम की कई प्रकार की किस्में और ग्रेड हैं जिनसे रबड़ कंपाउंडर्स महीन बन पाते हैं और ओईएम के विशेष अनुप्रयोगों के लिए कंपाउंडों का विकास हो पाता है। किसी एक विनिर्माता के लिए अंतिम प्रयोक्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी ग्रेड रखने की उम्मीद करना लगभग असंभव है। यह भी मुख्य कारण है कि हम अपने विभिन्न ग्रेडों को पूरे विश्व में भिन्न-भिन्न विनिर्माताओं से ले रहे हैं।
- (viii) हमारे रबड़ रसायनविदों द्वारा उपयुक्त ब्लैंड्स तैयार और विकसित किए जाते हैं तथा कई प्रयोगात्मक कार्य अंतिम कंपाउंड रिसाइप अंतिम रूप से निकालने के लिए किए जाते हैं जो ओईएम की पूरी निर्धारित विशिष्टियों को पूरा करे।
- (ix) यही कारण है कि किसी संतोषपूर्ण उत्पाद में परिणाम लाने के लिए काफी समयावधि लग जाती है।
- (x) चीन में एफकेएम के विनिर्माताओं को "फ्लोरस्फर" लेने का सबसे बड़ा लाभ है और इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड एफकेएम के विनिर्माण के लिए आरंभिक बिन्दु है।
- (xi) झोंघाओ चेंगुआंग, सॉल्वे, चेमर्स जैसे अधिकतर स्थापित विनिर्माताओं में एफकेएम की तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थिर गुणवत्ता विकसित करने में अनुसंधान एवं विकास के कई वर्ष लगाए हैं।
- (xii) आज की तारीख में बिक्री के पुर्जों की लागत संरचना पर ओईएम के साथ स्थिर स्पष्ट वाणिज्यिक संतुलन है।
- (xiii) यदि यह स्थिति है और एफकेएम की कीमत काफी ऊपर जाती है तो ओईएम भारत से बाहर विभिन्न अनुमोदित स्रोतों से सीलों का आयात करने पर विचार करना शुरू करेंगे।

- (xiv) इससे भारत की विनिर्माण यूनिटों में कम रोजगार/बेरोजगारी होगी।
- (xv) एफकेएम सीलिंग पाटर्स और ओईएम के विनिर्माता के बीच आज एक संतोषजनक स्थापित समीकरण है जो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और जिससे बहुत गंभीर असंतुलन होगा।
- (xvi) यह माना जाना चाहिए कि यह पाटनरोधी शुल्क जीएफएल को कोई सहायता प्रदान नहीं करने जा रहा है, जिसकी मूल समस्या गुणवत्ता में असंगति और ओईएम की विशिष्टियों को पूरा करने के लिए विभिन्न तकनीकी विशिष्टियों वाले ग्रेडों की विविधता का अभाव है।
- (xvii) यह स्पष्ट है कि भारत में जीएफएल को एफकेएम का एक विश्वसनीय स्रोत बनने के लिए उन्हें गुणवत्ता और विश्वसनीयता से संबंधित अपनी प्रौद्योगिकी में पर्याप्त सुधार करने चाहिए।

### 33. मैसर्स सुपर सील्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुरोध

- (i) भारत में इस उत्पाद का एक सबसे पुराना ग्राहक होने के नाते हम प्रति वर्ष लगभग 15 मीटर एफकेएम की खपत करते हैं और पिछले तीन दशकों से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए रबड़ से मेटल बॉलडेड ऑयल सील्स, गास्केट आदि का विनिर्माण करते हैं। हमारी सीलें और ऑटोमोबाइल इंजन में फिट करने के बाद गास्केट निरंतर हीट ऑयल में रखी जाती हैं। हमारे प्रमुख ग्राहकों में मैसर्स सिम्पसन एंड कं., आईटीएल, एमजीटीएल, एसीई लि., मैक्सिफोर्स, मिडको, एलएनटी, राणे, एसएमएल, एमएंडएम, अशोल लीलैंड, ताफे शामिल हैं।
- (ii) इस महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के कारण हम अपने स्तर पर कठोर गुणवत्ता प्रक्रिया अपनाते हैं। हमारी कच्ची सामग्री का चयन हमारे अनुसंधान एवं विकास दल द्वारा विश्लेषण के बाद ध्यानपूर्वक किया जाता है। हम हमारी प्रयोगशाला में ऑटोमोबाइल इंजन के भीतर पाई गई स्थितियों का अनुकूल करने का प्रयास करते हैं। फिर हमारे उत्पादों का वास्तविक प्रयोग के दौरान शून्य विफलता सुनिश्चित करने के लिए इस अनुकूलित स्थिति में बार-बार परीक्षण किया जाता है क्योंकि ऐसी विफलता के घातक परिणाम हो सकते हैं।
- (iii) यह अनुरोध है कि हमने गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लि. से नमूनों का बार-बार परीक्षण किया है और कठोर स्थितियों में उसका निष्पादन कमजोर पाया है। वह उत्पाद उस समय विफल रहा जब उसे निरंतर ताप में रखा गया। उनका उत्पाद निष्पादन अपेक्षित विशिष्टि से कहीं कम था। इस प्रकार, हमारे अनुसंधान एवं विकास दल द्वारा उनके नमूनों को बार-बार रद्द किया गया है। इसके अतिरिक्त, उनके पास सीमित विकसित ग्रेड ही हैं जो ऑटोमोबाइल उद्योग की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती।
- (iv) हम कई वर्षों से अपना एफकेएम गम स्टॉक झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. से और चेमर्स से खरीद रहे हैं और अपनी यांत्रिक विशिष्टि तथा अपने ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। कोई शिकायत नहीं रही है और हमारे ग्राहकों के स्तर पर शून्य विफलता है।
- (v) यह भी अनुरोध है कि सरकार समझेगी कि एफकेएम काफी परीक्षण और विश्लेषण के बाद सभी प्रतिष्ठित ऑटो संघटक विनिर्माताओं द्वारा सामान्य रूप में चुना जाता है। यदि सरकार हमारे वर्तमान आपूर्तिकर्ताओं पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाती है तो हम उनसे उच्चतर कीमत पर एफकेएम खरीदने के लिए मजबूर होंगे। हमें पहले ही उच्च कीमतों और कार्बन ब्लैक की कमी के कारण भारी हानि हो रही है। इस दिशा में कोई भी अगला कदम भारत में हमारी तरह कई रबड़ उद्योगों के लिए अंतिम रूप से मरणशील होगा। इससे भारत में रबड़ उद्योग की वृद्धि ही नहीं रुकेगी बल्कि भारी बेरोजगारी भी होगी।

### 34. मैसर्स एलएफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स द्वारा अनुरोध

- (i) सामान्यतः हमारे ग्राहक अपने अनुप्रयोग में प्रयुक्त किए जाने के लिए कच्ची सामग्री के ग्रेड के लिए हमारा उल्लेख करते हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि एफकेएम उच्च लागत वाला विशेषता का रबड़ है, अतः हम विभिन्न गुणवत्ता मानदंडों के तहत हमें आपूर्ति की गई सामग्री की प्रत्येक खेप की जांच करते हैं।
- (ii) हमने अपनी फैक्ट्री में कई बार जीएफएल की सामग्री का प्रयोग करने का प्रयास किया, परंतु हमारे उत्पादन विभाग द्वारा उनकी गुणवत्ता को रद्द किया गया।
- (iii) जीएफएल भारत में एफकेएम का एक मात्र विनिर्माता है, अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से एकाधिकारिक बाजार की स्थिति बनेगी और जीएफएल फैक्ट्री में किसी खराबी अथवा बल उपाय की स्थिति में हमें उच्चतर लागत पर खरीददारी करने की आवश्यकता होगी जिससे हम पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हमें भय है कि जीएफएल भी इस स्थिति का अनुचित लाभ लेगा और हमें प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर स्थिर एवं समय पर आपूर्ति प्राप्त करने में उनकी दया पर रहना पड़ेगा।

- (iv) हम डीजीएडी से अनुरोध करते हैं कि वे चीन से एफकेएम पर कोई शुल्क न लगाएं क्योंकि हम पहले ही भारत में कार्बन ब्लैक की आपूर्ति में उसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, यद्यपि, उसके चार विनिर्माता हैं परंतु पाटनरोधी शुल्क की सहायता के कारण वे हम पर अत्यधिक ऊंची कीमतें लगा रहे हैं और यहां तक कि हमारे उत्पादन के लिए पर्याप्त सामग्री भी नहीं दे रहे हैं।

### 35. मैसर्स अपोलो सील्स कं. द्वारा अनुरोध

- (i) यह अनुरोध है कि हम औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए रबड़ पार्ट बनाने वाले छोटे पैमाने की रबड़ फैक्ट्री हैं। फ्लोरोलस्टोमर हमारे लिए रबड़ की एक बहुत ही विशेष किस्म है और अन्य सामान्य रबड़ (एसबीआर, पीबीआर, एमबीआर) की तरह नहीं है जो हम कीमत के आधार पर खरीदते हैं।
- (ii) यह अनुरोध है कि प्रमुख रूप से ओई उद्योगों को आपूर्ति किए जाने वाले रबड़ पार्ट्स की विभिन्न किस्में बनाते समय हम ओई विनिर्माताओं से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना आसानी से ग्रेड में परिवर्तन करते हैं। समान रूप से हमारे अंतिम प्रयोक्ता समुचित क्षेत्रीय परीक्षण करने के बाद किसी विनिर्माता के किसी ग्रेड का अनुमोदन करने में कई वर्ष लगा देते हैं।
- (iii) इसके अतिरिक्त, हम कई वर्षों से झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. एफकेएम - गम स्टॉक ग्रेड का प्रयोग करते आ रहे हैं और हमारे ग्राहकों ने सतत एवं स्थिर गुणवत्ता के कारण उसे अनुमोदित किया है।
- (iv) गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ने अभी-अभी एफकेएम का उत्पादन हाल ही में शुरू किया। हमने जीएफएल सामग्री का प्रयोग करने का प्रयास किया था, परंतु उनकी गुणवत्ता स्थिर और अनुकूल नहीं पाई गई। साथ ही हमने यह भी पाया कि उनके पास विश्व में एफकेएम के अन्य प्रतिष्ठित विनिर्माताओं की तरह व्यापक किस्म के ग्रेड नहीं हैं।
- (v) हम पहले ही भारत में हमारे द्वारा प्रयुक्त अधिकतर कच्ची सामग्री में पाटनरोधी शुल्क और उच्च आयात शुल्क के कारण अपनी पूरी कच्ची सामग्री की उच्च लागत के कारण निर्यात बाजार में सख्त प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहे हैं। हमारी अतिरिक्त कच्ची सामग्री पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूरी तरह से गैर-प्रतिस्पर्द्धा हो जाएंगे।
- (vi) भारत में एफकेएम का केवल एक विनिर्माता है और शुल्क लगाए जाने से एकाधिकारिक बाजार स्थिति बनेगी तथा घरेलू उत्पादक द्वारा कीमत में तोड़-मरोड़ होगा। पाटनरोधी शुल्क से भारत में हमारे जैसे हजारों एमएसई और एसएमएसई प्रभावित होंगे जिसके परिणामस्वरूप रोजगार छिन जाएंगे।

### 36. मैसर्स गोवेल रबड़ इंडस्ट्रीज द्वारा अनुरोध

- (i) यह अनुरोध है कि भारत का एक सबसे बड़ा रबड़ ऑटो संघटक ओईएम विनिर्माता होने के नाते हमारे लिए यह विषय वस्तु गंभीर चिंता की है। हमारे ग्राहकों में बजाज, हीरो, मारुति सुजुकी, टाटा आदि जैसे दोपहिया वाहनों एवं चार पहियों वाले वाहनों, दोनों के विनिर्माता शामिल हैं।
- (ii) फ्लोरोलस्टोमर्स हमारे द्वारा प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है जिसमें हमारी वार्षिक खपत लगभग 25 एमटीएस है। हम उससे ऑटोमोटिव सील्स, गास्केट और ओ-रिंग्स का विनिर्माण कर रहे हैं। हमारे कुछ विनिर्मित उत्पादों में वाहनों का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा संघटक शामिल है। ऐसी स्थिति में हमारे स्तर पर सभी अपेक्षित विशिष्टि को पूरा करने, ध्यानपूर्वक प्रसंस्करण करने वाले विशेष विनिर्माताओं से कच्ची सामग्री के सही ग्रेड को चुनने के लिए हमारे स्तर पर पूरी मेहनत सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। साथ ही, ऑटोमोबाइल विनिर्माता को सुपुर्दगी से पूर्व अंतिम पार्ट की गुणवत्ता की समुचित जांच करने की भी आवश्यकता होती है।
- (iii) विनिर्मित किए जा रहे रबड़ संघटक की महत्ता के कारण अधिकतर मामलों में प्रयुक्त किए जाने वाले एफकेएम ग्रेड का चयन का उनकी वैश्विक गुणवत्ता अनुमोदन के आधार पर खुद ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा निर्णय लिया जाता है। यहां तक कि जब हम ग्रेड बताते हैं तो हम अपने स्तर पर कठोर गुणवत्ता निरीक्षण अपनाते हैं और चयन के लिए ग्रेड को अंतिम रूप देने से पूर्व कई महीनों का निरीक्षण करते हैं। परीक्षण के परिणाम ऑटोमोबाइल विनिर्माता को उनकी सहमति और अनुमोदन के लिए बताए जाते हैं।
- (iv) हमारे उपर्युक्त सभी कदम कठोरता से अपनाए जाते हैं क्योंकि हमारे एफकेएम आधारित रबड़ संघटक ऑटोमोबाइल में महत्वपूर्ण सुरक्षा पार्ट हैं।
- (v) हम झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. से एफकेएम ए36 और एफकेएम ए412 का प्रयोग करते आ रहे हैं। ये ग्रेड हमारे सभी आंतरिक परीक्षणों को पास करते हैं और दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह है



कि हमें ग्राहक स्तर पर उत्पाद विफलता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि उसका अर्थ ग्राहक की सुरक्षा को समाप्त करना होगा।

- (vi) हमने भारतीय विनिर्माता – गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लि. (जीएफएल) के नमूनों का भी कई बार मूल्यांकन किया है। उनके ग्रेड असंगत परिणामों से गुणवत्ता में बहुत घटिया पाए गए। उनके पास इस समय ऐसा कोई ग्रेड नहीं है जो हमारे ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा कर सके। सख्त गुणवत्ता नीति के अनुरूप हम कभी भी अपने महत्वपूर्ण सुरक्षा उत्पादों के लिए इन ग्रेडों का प्रयोग करने का जोखिम नहीं ले सकते।
- (vii) हम यह भी समझते हैं कि जीएफएल इस उत्पाद के लिए एक मात्र विनिर्माता है। अतः हम आशा करते हैं कि सरकार इस बड़े उद्यम को अनुचित एवं अनावश्यक संरक्षण प्रदान करने की कोई एकपक्षीय कार्रवाई नहीं करेगी जिससे हमारी जैसी हजारों लघु एवं मध्यम पैमाने की कंपनियां समाप्त हो जाएंगी जो कि उच्चतम गुणवत्ता देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और भारतीय ग्राहकों को सर्वोत्तम सुरक्षा उत्पाद प्रदान करते हैं।
- (viii) पाटनरोधी शुल्क किसी भी सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माता और अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माता के बीच समान व्यापारिक क्षेत्र लेने के लिए लगाया जाता है। जहां दोनों विनिर्माताओं की गुणवत्ता समान होती है परंतु जीएफएल के मामले में उनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय एफकेएम विनिर्माता मानदंड से काफी घटिया है। इस प्रकार, कोई भी अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से लाखों भारतीय ग्राहकों को भारी हानि होगी।

### 37. मैसर्स आईएसजी एकास्टोमर्स द्वारा अनुरोध

- (i) यह अनुरोध है कि आईएसजी एकास्टोमर्स एक रबड़ प्रसंस्करण यूनिट है। हम लंबे समय से झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. से एफकेएम गम स्टॉक ग्रेड – सीजीए372, सीजीए36 और सीजीए412 का प्रयोग करते आ रहे हैं और उनकी गुणवत्ता की सहायता से हम अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता के रबड़ उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम रहे हैं। उनकी गुणवत्ता का प्रयोग करके हमारे ग्राहकों से कोई शिकायत नहीं हुई है। हमारी एफकेएम की वार्षिक खपत लगभग 5-7 एमटीएस है।
- (ii) हमने अपनी फैक्ट्री में कई बार जीएफएल फ्लोरोलस्टोमर्स का प्रयोग करके परीक्षण भी किया था, परंतु हमारी रद्द करने की प्रतिशतता बढ़ गई और हमें बाजार से शिकायतें भी प्राप्त होनी शुरू हो गईं। जीएफएल सामग्री में अलग-अलग लॉट में अंतर है तथा उत्पाद गुणवत्ता बहुत असंगत है।
- (iii) एफकेएम हम जिन अन्य रबड़ों की खरीद करते हैं, उनकी तुलना में बहुत अधिक कीमत वाला रबड़ है। इस प्रकार, हम किसी भी नए ग्रेड का चयन करते समय गुणवत्ता को काफी महत्व देते हैं। यदि कोई गुणवत्ता संबंधी मुद्दे हैं, जिनसे हमको एफकेएम की लागत के रूप में भारी हानि उठानी पड़ेगी तो वह अन्य रबड़ों की तुलना में बहुत अधिक है और हमारी बाजार प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी।
- (iv) हम डीजीएडी विभाग से अनुरोध करते हैं कि वे एफकेएम पर कोई अतिरिक्त शुल्क न लगाएं क्योंकि इससे हम पर लागत का अतिरिक्त भार पड़ेगा और इससे हम भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्णतः गैर-प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।

### 38. मैसर्स रावत इंजीनियरिंग टेक. (प्रा.) लि. द्वारा अनुरोध

- (i) यह अनुरोध है कि एक लघु पैमाने का उद्योग होने के नाते हमारी एफकेएम की वार्षिक खपत लगभग 9 टन प्रति वर्ष है जो वाटर प्यूरीफायरों और फिल्टरों के लिए सील बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है जिसकी आपूर्ति यूरेका फोर्ब्स और कैंट जैसी कंपनियों को की जाती है। हमारी सीलों का प्रयोग वाटर प्यूरीफायरों और फिल्टरों में बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग में किया जाता है जो पानी की लीकेज को रोकते हैं। हमारी सीलों में किसी विफलता से शुद्ध पानी का प्रदूषण होगा जिससे लाखों लोगों को स्वास्थ्य संबंधी हानियां होंगी। इस प्रकार, हम एफकेएम के किसी भी नए ग्रेड को चुनने से पूर्व कई आंतरिक परीक्षण करते हैं।
- (ii) परंतु हर समय उनके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की अलग-अलग खेप में अंतर था। जीएफएल सामग्री से बनी हमारी सीलों में मेटल युक्त प्रमुख बांडिंग विफलता थी और कम्प्रेसर सेट बहुत अधिक था। इस प्रकार, हमने प्रमुख रूप से जीएफएल सामग्री का प्रयोग न करने का निर्णय लिया जिनकी गुणवत्ता हमारे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के लिए अस्थिर और प्रयोग न करने योग्य है जिसके अनुप्रयोग से हमारे व्यापार को भी हानि हो सकती है। हमारा जेडईडी प्रमाणीकरण है। हम आपके संदर्भ के लिए जीएफएल मुख्य सामग्री की अपनी कुछ आंतरिक परीक्षण रिपोर्टें तथा जेडईडी प्रमाण पत्र भी संलग्न कर रहे हैं।
- (iii) हमने उनकी सामग्री का प्रयोग करके हमारे सामने आई विभिन्न समस्याओं के संबंध में उनके तकनीकी प्रमुख की अध्यक्षता वाली जीएफएल टीम को सूचित किया था, परंतु अभी तक वे कोई समाधान करने में असमर्थ हैं।

- (iv) हम 2013 से झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. और चेमर्स से एफकेएम का प्रयोग करते आ रहे हैं और हम उनके द्वारा आपूर्ति की गई गुणवत्ता से बहुत संतुष्ट हैं।
- (v) हम उस कंपनी को संरक्षण देने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क न लगाए जाने का अनुरोध करते हैं जिसकी गुणवत्ता कमजोर तथा अस्थिर है क्योंकि जीएफएल गुणवत्ता को अभी अंतर्राष्ट्रीय मानक तक पहुँचना है। इसके अतिरिक्त, इससे भारत में एकाधिकारिक स्थिति बनेगी क्योंकि जीएफएल इस उत्पाद का एक मात्र विनिर्माता होने के नाते इस स्थिति का लाभ लेने का प्रयास करेगा।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग ने उपलब्धता अनुकूल गुणवत्ता और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के प्रयोग से संबंधित तकनीकी कठिनाईयों का समाधान न होने से संबंधित चिंताएं उठाई हैं। प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- (i) घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री बढ़ी है और यहां तक कि उन्होंने निर्यात किए हैं।
- (ii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग को तकनीकी स्थिरीकरण के कारण नए उत्पाद की गुणवत्ता की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तथापि, घरेलू उद्योग को कुछ ग्राहकों द्वारा बार-बार ऑर्डर दिए गए हैं जो घरेलू उद्योग के सामानों की बढ़ती हुई स्वीकार्यता दर्शाता है।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उठाए गए मुद्दे इस तथ्य से संबंधित नहीं हैं कि विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान समान वस्तु नहीं हैं बल्कि गुणवत्ता संबंधी प्रतिकूलताएं हैं। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी उपाय अनुचित कीमत के पहलू का ही हल करते हैं। एफएफकेएम और एफकेएम कंपाउंड विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग में इनका उत्पादन करने की क्षमता नहीं है।

### **च. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**

#### **41. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

- (i) व्यापार उपचार महानिदेशक से अनुरोध है कि वे कच्चे गोंद और प्री-कंपाउंड की वास्तविक निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर पर विचार करें क्योंकि घरेलू उद्योग ने जान-बूझकर कच्चे गोंद को कोपोलाइमर प्री-कंपाउंड में वर्गीकृत किया है। कच्चे गोंद को प्री-कंपाउंड में शामिल करने के कारण प्री-कंपाउंड की औसत कीमत कम हो गई है और इसके परिणामस्वरूप कच्चे गोंद और प्री-कंपाउंड के संबंध में बहुत अधिक पाटन मार्जिन है।
- (ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी को चीन की बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर चीन को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करना चाहिए। सामान्य मूल्य का परिकलन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार करना चाहिए और समान देश के आंकड़े लागू करने के बजाए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस उत्तर में कंपनी द्वारा दिए गए आंकड़ों और कीमतों को लागू करना चाहिए।
- (iii) झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि., चीन जन. गण., यदि व्यापार उपचार महानिदेशालय यह निष्कर्ष निकालते हैं कि झोंघाओ चेंगुआंग पाटन कर रहा है उस स्थिति में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 15 के अनुसार कीमत वचनबद्धता देने के इच्छुक हैं अथवा प्राधिकारी संदर्भ कीमत निर्धारित करें।
- (iv) सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और किसी भी साक्ष्य से समर्थित नहीं है। वह पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद-1 के पैरा 7 का भी उल्लंघन करता है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के अंतिम विकल्प के आधार पर अर्थात् भारत में उत्पादन लागत के आधार पर विधिवत समायोजित करके पहले दो विकल्पों को लिए बिना सामान्य मूल्य का परिकलन करने के तरीके को स्वीकार किया है। शेनयांग मत्सुसिता एस. बैट्री कं. लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लि. और अन्य [(2005) 3एससीसी 39] देखें।
- (v) प्रत्येक समायोजन के संबंध में याचिका में प्रस्तुत आंकड़े मात्र कथन हैं और साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं हैं जिस पर मामले की शुरुआत करने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप जीएफएल द्वारा निकाली गई विकृत निर्यात कीमत पाटन "दर्शने" के लिए झूठी है और उसे रद्द किया जाना चाहिए।
- (vi) संबद्ध देश से कोई पाटन नहीं है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

- (vii) उत्तरदाताओं की अपूर्ण मूल्यश्रृंखला के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा सीएफएसई पर लागू नहीं है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान हमने अपनी कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पाद की ही बिक्री की है और विचाराधीन उत्पाद के किसी व्यापार में नहीं लगे रहे। प्राधिकारी दायर की गई सूचना का सत्यापन कर सकते हैं।
- (viii) उत्तरदाता ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में प्रोत्साहनों अथवा सब्सिडी, जो भी लागू है, के संबंध में सभी संगत सूचना दी है। वर्तमान जांच पाटनरोधी जांच है न कि एक प्रतिकारी जांच। अतः याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा असंगत है। इंडोनेशिया और वियतनाम से प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड (एमडीएफ) के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच में जांच परिणाम का संदर्भ दिया जाता है (फा. सं. 14/23/2014-डीजीएडी दिनांक 05 मई, 2016)
- (ix) पाटनरोधी नियमावली की धारा 9क(1)(ग) के प्रावधानों के अनुसार अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए सीएफएसई द्वारा दायर वास्तविक आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाएगा कि पाटन मार्जिन नकारात्मक है।
- (x) 11 दिसंबर, 2016 के बाद पाटनरोधी करार और जीएटीटी 1994 के प्रावधान, जो साधारण रूप से बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण पर लागू होते हैं, बिना किसी निर्धारण के चीन जन. गण. से आयातों पर लागू होंगे। उपर्युक्त अनुरोधों के मद्देनजर, प्राधिकारी निर्यातकों की निर्धारित वास्तविक घरेलू कीमतों के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं जैसा कि पाटनरोधी नियमावली की धारा 9क(1)(ग) के प्रावधानों के अनुसार अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए किया गया है।
- (xi) सीएफएसई ने इस अवधारणा का खंडन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर की प्रश्नावली दायर की है कि वह गैर-बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के तहत प्रचालन कर रही है और यह दर्शाने के लिए कि उसकी लागत और कीमत संरचनाएं पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार उसके व्यापार के उचित मूल्य को दर्शाती हैं।
- (xii) उत्तरदाता पक्षकारों की अपूर्ण मूल्यश्रृंखला के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा 16वें ग्रुप पर लागू नहीं है क्योंकि यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। एसएसपीसी भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात सीधे ही करता है। ये संबद्ध सामान एसएसआईपीएल द्वारा आयात किए जाते हैं जो उसके बाद उन्हें भारत में अन्य ग्राहकों को बेचता है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि, चीन में घरेलू बिक्री अपरिणामी है क्योंकि एसएसपीसी ने बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा नहीं किया है। एसएससीएल ने भी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं क्योंकि एसएसपीसी द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान घरेलू बाजार में बेचे जाते हैं और एसएससीएल द्वारा अन्य देशों को निर्यात किए जाते हैं।
- (xiii) चीनी उत्पादकों द्वारा प्राप्त लाभों को प्रकट न करने के संबंध में 16वें ग्रुप का अनुरोध है कि प्राधिकारी दिए गए आंकड़ों का सत्यापन करें। साथ ही, वह सूचना अपरिणामी है क्योंकि उसका किसी पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार, जो कोई सूचना सही नहीं है और अपर्याप्त है। निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय गलत है और वह अनदेखा किए जाने के योग्य है। यदि इस प्रकार का कोई सब्सिडी कार्यक्रम उत्तरदाता द्वारा गलती से सूचित नहीं किया गया है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उसे ठीक किए जाने की अनुमति दे सकते हैं।
- (xiv) घरेलू उद्योग ने गलत दावा किया है कि किसी भी चीनी उत्पादक ने पाटन की मौजूदगी पर विवाद नहीं किया है। उत्तरदाताओं ने इस कारण चीन से संबद्ध सामानों के पाटन के दावे पर विवाद करते हुए पहले ही अनुरोध किए हैं कि वह घरेलू उद्योग की कीमतों के आधार पर सिद्ध कर दिया गया है जो कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है।
- (xv) घरेलू उद्योग ने याचिका में निर्मित सामान्य मूल्य का दावा किया था जबकि लिखित अनुरोधों में उन्होंने दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों से भारत सहित अन्य देशों को कीमत का सहारा चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए लिया जाए। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से अन्य देशों को कीमतों के आधार पर कार्यवाही करने का निर्णय लेते हैं तो वह अग्रिम तौर पर सही समय में उत्तरदाताओं सहित हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया जाए ताकि उसकी उपयुक्तता की जांच की जा सके और अपेक्षित होने पर इस संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य दिए जा सकें।
- (xvi) वर्तमान जांच एक पाटनरोधी जांच है न कि प्रतिकारीशुल्करोधी जांच यदि सरकार द्वारा कोई सब्सिडी अथवा अन्य लाभ के रूप में लाभ दिए जाते हैं तो वर्तमान जांच में वह संगत नहीं है।

- (xvii) घरेलू उद्योग ने चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों के संबंध में दावा किया जिनमें उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ दिए जा रहे हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने उपर्युक्त दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। झोंघाओ चेंगुआंग को चीन सरकार से कोई लाभ नहीं दिए गए हैं।
- (xviii) वर्तमान जांच एक पाटनरोधी जांच है न कि सब्सिडीरोधी जांच। वर्तमान जांच एक पाटनरोधी जांच है न कि सब्सिडीरोधी जांच। यदि सरकार द्वारा कोई सब्सिडी अथवा अन्य लाभ के रूप में लाभ दिए जाते हैं तो वर्तमान जांच में वह संगत नहीं है।
- (xix) चीनी उत्पादक पाटन के विरुद्ध हैं। वे भारतीय उद्योग की मांग और आवश्यकताओं के अनुसार संबद्ध सामानों की बिक्री कर रहे हैं। वस्तुतः चूंकि एफकेएम ऑटो कंपनियों द्वारा किए गए कई माह/वर्षों के परीक्षणों के बाद अनुमोदित विनिर्माता के विशिष्ट व्यौरों वाला अत्यधिक विशेषीकृत उत्पाद है, अतः चीनी उत्पादकों द्वारा पाटन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (xx) यूनी एलाइंस लिमिटेड डेकिन द्वारा विनिर्मित संबद्ध सामानों का निर्यात करता है और कहीं भी 10 मई, 2018 की व्यापार सूचना 9/2018 में दी गई परिभाषा के अनुसार डेकिन से संबद्ध नहीं है।
- (xxi) डेकिन ने यूनी एलाइंस लिमिटेड (कुल निर्यात का 79 प्रतिशत) और मित्सुबिशी कारपोरेशन प्लास्टिक्स लि. (कुल निर्यात का 21 प्रतिशत) के माध्यम से संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। यूनी एलाइंस लिमिटेड ने प्राधिकारी के पास पूरे उत्तर दायर किए हैं जबकि डेकिन ने अपना पूरा प्रयास किया कि मित्सुबिशी कारपोरेशन प्लास्टिक्स लि. प्राधिकारी के पास प्रश्नावली के उत्तर दायर किए। मित्सुबिशी कारपोरेशन प्लास्टिक्स लि. डेकिन से संबद्ध नहीं है, अतः डेकिन निर्यातक को वर्तमान जांच का भाग बनने के लिए विवश नहीं कर सका। चूंकि, डेकिन के अधिकतम निर्यात (कुल निर्यात का 79 प्रतिशत) यूनी एलाइंस लिमिटेड के माध्यम से किया गया था और यूनी एलाइंस लिमिटेड ने प्राधिकारी को पूरा उत्तर दायर कर दिया है। अतः व्यापार उपचार महानिदेशक से अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें।
- (xxii) घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन. गण. सरकार द्वारा उत्पादकों/ निर्यातकों को विभिन्न लाभ दिए जाते हैं और चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में उल्लेख किया जिनमें उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। तथापि, उपर्युक्त दावे को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। डेकिन और यूनी एलाइंस लिमिटेड का अनुरोध है कि उन्हें चीन सरकार से ऐसे कोई लाभ नहीं दिए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे असंगत हैं और सिद्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान जांच एक पाटनरोधी जांच है न कि प्रतिकारीशुल्करोधी जांच। यदि सरकार द्वारा कोई सब्सिडी अथवा अन्य लाभ के रूप में लाभ दिए जाते हैं तो वर्तमान जांच में वह संगत नहीं है।

#### 42. एमईटी स्तर संबंधी दावे के संबंध में सीएफएसी द्वारा किए गए अनुरोध

- i. चीन जनवादी गणराज्य के अभिगम संबंधी नयाचार की धारा 15(घ) के अनुसार "किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे।" तदनुसार, सदस्यों के लिए यह अपेक्षित है कि वे 11 दिसंबर, 2016 के बाद नयाचार की धारा 15(क)(ii) के तहत उल्लिखित सिद्धांतों का प्रयोग समाप्त करें और उसके बाद इन सिद्धांतों का निरंतर प्रयोग पाटनरोधी करार तथा जीएटीटी 1994 के तहत सदस्य के दायित्वों के उल्लंघन में होगा। अतः 11 दिसंबर, 2016 के बाद पाटनरोधी करार और जीएटीटी 1994 के प्रावधान, जो साधारणतः बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण पर लागू होते हैं, बिना किसी निर्धारण के चीन जन. गण. में आधारित कंपनियों पर लागू होंगे। इसका अर्थ है कि चीन जन. गण. में आधारित कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए उनकी वास्तविक घरेलू कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए।"
- ii. मैसर्स सीएफएसई चीन जन. गण. से एक मात्र सहयोगी निर्यातक है जिसने बाजार अर्थव्यवस्था स्तर (एमईटी) का दावा किया है क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि उनकी लागत और कीमत संरचना भारतीय पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार उनके व्यापार का उचित मूल्य दर्शाती है।
  - क. हमारी कंपनी का कोई प्रमुख शेयरधारक सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में नहीं है।
  - ख. सीएफएसई पर सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है और इसीलिए सीएफएसई में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
  - ग. सीएफएसई में निजी शेयरधारिता 85 प्रतिशत से अधिक है और अप्रत्यक्ष सरकारी शेयरधारिता 15 प्रतिशत से कम है।

घ. बुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इन्वेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) में निजी शेयरधारिता 70 प्रतिशत से कम है और सरकार की शेयरधारिता 40 प्रतिशत से कम है।

- iii. प्राधिकारी का ध्यान चीन जन. गण. की 2016 में वित्त मंत्रालय की डिक्री सं. 32 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 4 (सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के लेन-देन के पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए उपाय) की ओर भी आकर्षित किया जाता है। अनुच्छेद 4 की विषय वस्तु प्राधिकारी के सुलभ संदर्भ की आसानी के लिए नीचे दी गई है:

*"अध्याय 1 का अनुच्छेद 4 इन उपायों में उल्लिखित किए गए अनुसार सरकार के स्वामित्व और सरकार द्वारा धारित उद्यम तथा सरकार के वास्तविक नियंत्रणाधीन उद्यमों में निम्नलिखित शामिल हैं:*

*(1) सरकार विभाग द्वारा स्थापित पूर्णतः सरकार स्वामित्व वाले उद्यम (कंपनियां) संगठन और संस्थाएं तथा पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम जिनका उपर्युक्त यूनिटों और उद्यमों की कुल 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शेयरधारिता वाले उद्यम;*

*(2) जिन उद्यमों में इस अनुच्छेद के पैरा (1) में सूचीबद्ध यूनिटें/उद्यम पृथक अथवा संयुक्त पूंजीगत योगदान करते हैं, वे संपत्ति (शेयर) अधिकार के कुल स्वामित्व का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक हैं तथा उनमें से एक सबसे बड़ा शेयरधारक है।*

*(3) उप उद्यम जिनमें इस अनुच्छेद के पैरा (1) व (2) में सूचीबद्ध उद्यम जिनका उनके पूंजीगत योगदान में 50 प्रतिशत से अधिक की इक्विटी है।*

*(4) वे उद्यम जो सबसे बड़े शेयरधारकों द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित किए जा सकते हैं, जो सरकारी विभाग, संगठन, संस्थाएं, शेयरधारक करारों, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रिजॉल्यूशन अथवा अन्य करारों के माध्यम से एकल सरकारी स्वामित्व अथवा सरकारी नियंत्रण वाले उद्यम, यद्यपि सरकार विभागों, संगठन, संस्थाओं, एकल सरकारी स्वामित्व अथवा सरकारी नियंत्रण वाले उद्यमों द्वारा धारित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शेयर 50 प्रतिशत से कम है।*

- iv. भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के संगत उद्धरण भी प्राधिकारी के अवलोकन के लिए नीचे दिए जा रहे हैं:

(45) "सरकारी कंपनी" का अर्थ उस किसी कंपनी से है जिसमें केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों अथवा केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से तथा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से धारित प्रदत्त शेयर पूंजी के 51 प्रतिशत से कम न हो और जिसमें वह कंपनी शामिल हो जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो।

- v. उपर्युक्त से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि किसी कंपनी को निम्नलिखित दो स्थितियों में ही सरकारी स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रण वाली कहा जा सकता है:

क. सरकारी विभाग, संगठन, संस्थाओं, एकल, सरकारी स्वामित्व अथवा सरकारी नियंत्रण वाले उद्यमों द्वारा धारित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शेयर 50 प्रतिशत से अधिक हो।

अथवा,

ख. शेयरधारक करार, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रिजॉल्यूशन अथवा अन्य करार सरकार को नियंत्रण करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

- vi. सीएफएसई में सरकारी अप्रत्यक्ष शेयरधारिता केवल \*\*\* प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, सीएफएसई के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष को कंपनी के दिन प्रति दिन के प्रचालनों पर नियंत्रण रखने के लिए प्राधिकृत करते हैं क्योंकि अध्यक्ष कंपनी का कानूनी प्रतिनिधि होता है। कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (अनुच्छेद 27 से अनुच्छेद 30) पूरक प्रश्नावली के उत्तर के साथ संलग्न कर दिया गया है। अतः सीएफएसई सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है।

- vii. जहां तक हमारा एक मात्र गैर-वैयक्तिक प्रमुख शेयरधारक अर्थात् बुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इन्वेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) का संबंध है, यह बात दोहराई जाती है कि सरकार की धारिता केवल \*\*\* प्रतिशत है। यह भी नोट किया जाए कि भागीदारी करार में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि बुक्सी गुओलियान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कं. लि., बुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इन्वेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) का एक मात्र सामान्य भागीदार है और उसके दैनिक प्रचालनों पर पूरा नियंत्रण है। यह अनुरोध है कि बुक्सी गुओलियान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कं. लि. के सभी शेयरधारक निजी व्यक्ति हैं। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि बुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इन्वेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है।

- viii. आवेदक ने बिना किसी आधार के आरोप लगाया है कि सीएफएससी अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण में है और सीएफएसई में सरकार का पर्याप्त हस्तक्षेप है। अपने दावे को सिद्ध करने के लिए प्राधिकारी का ध्यान भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियंत्रण की परिभाषा की ओर आकर्षित किया जाता है।

**"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27)**

(27) "नियंत्रण" में शेयरधारिता अथवा प्रबंधन अधिकारों अथवा शेयरधारक करारों अथवा वोटिंग करारों अथवा किसी अन्य तरीके की दृष्टि सहित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग अथवा मिलकर कार्य करते हुए निष्पादनीय नीति निर्णयों अथवा प्रबंधन के निर्णय के लिए अधिकतर निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार अथवा प्रबंधन का नियंत्रण करने का अधिकार शामिल होगा।

- ix. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि नियंत्रण करने के लिए शेयरधारक को अधिकतर निदेशकों की नियुक्ति करने अथवा प्रबंधन पर नियंत्रण करने अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग अथवा मिलकर निष्पादनीय नीति निर्णय करने का अधिकार होगा। यह बात दोहराई जाती है कि सीएफएसई में सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से कुल शेयरों के केवल \*\*\* प्रतिशत पर नियंत्रण है, अतः यह स्पष्ट है कि न तो सरकार का सीएफएसई पर नियंत्रण है और न ही सीएफएसई के प्रबंधन में सरकार का कोई हस्तक्षेप है।
- x. इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि दैनिक प्रचालनों से संबंधित निर्णय सीएफएसई के निदेशक बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। यह कंपनी का कार्यपालक अंग है। अध्यक्ष कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव 2/3 निदेशकों द्वारा किया जाता है।
- xi. सीएफएसई के तीन निदेशक हैं। दो निदेशक सीएफएसई के निजी शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और तीसरा निदेशक कंपनी अर्थात् वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) के गैर-व्यक्ति शेयर द्वारा नामित किया जाता है।
- xii. सीएफएसई अर्थात् वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) का प्रमुख गैर-व्यक्ति शेयरधारक ही सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है। यह एक सीमित भागीदारी वाली कंपनी है। अनुरोध है कि सीमित भागीदारी निम्नलिखित दो कारणों से सामान्य भागीदारी से भिन्न है
- क. सीमित भागीदारी का प्रबंधन "सामान्य भागीदार" में होता है।
- ख. सीमित भागीदार "मौन भागीदार" होते हैं क्योंकि वे कंपनी में निवेश कर सकते हैं, परंतु उसके दैनिक प्रचालनों में नियंत्रण अथवा मतदान का अधिकार नहीं होता है।
- xiii. आवेदक ने दावा किया है कि वुक्सी गुओलियान इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कं. लि. (वुक्सी गुओलियान वेंचर इंवेस्टमेंट कं. लि. के रूप में उल्लिखित जो कि एक टंकण की गलती प्रतीत होती है) का हमारे प्रमुख शेयरधारक अर्थात् वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) में 20 प्रतिशत हिस्सा है। इस संदर्भ में यह अनुरोध है कि वुक्सी गुओलियान इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कं. लि., वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) का एक सीमित भागीदार है और उसकी दैनिक प्रचालनों में कोई भूमिका नहीं है। वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) के भागीदार करार की एक प्रति प्रस्तुतिकरणों के साथ संलग्न है। इस भागीदार करार में पूंजी में भागीदारों के योगदान से संबंधित व्यौरे भी हैं।
- xiv. प्राधिकारी का ध्यान भागीदारी करार के निम्नलिखित पैरा की ओर आकर्षित किया जाता है जो निःसन्देह सिद्ध करेगा कि वुक्सी जुनयान कैपिटल मैनेजमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी), वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) का केवल सामान्य भागीदार है और उसके दैनिक प्रचालनों पर उसका पूर्ण नियंत्रण है।

*"1.13 वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) में सामान्य भागीदार और कार्यपालक भागीदार देखें"*

*"2.7.1 भागीदारी का केवल सामान्य भागीदार वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) है।"*

*"5.1.1 सीमित भागीदारी सामान्य भागीदारों द्वारा भागीदारी कार्यों में की जाएगी। भागीदारी के प्रबंधन नियंत्रण, प्रचालन और निर्णय करने की शक्तियां, उसके निवेश व्यापार और अन्य क्रियाकलाप पूरी तरह से सामान्य भागीदार में निहित हैं और वे सीधे ही अथवा सामान्य भागीदार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं।"*

*"5.1.2 सभी भागीदार सामान्य भागीदार वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) को भागीदारी कार्यों के निष्पादन में भागीदारी के भागीदार के रूप में सहमत हुए।"*

वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) में सरकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कोई शेयरधारिता नहीं है। इस कंपनी के सभी शेयरधारक निजी शेयरधारक हैं। अतः वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) के दैनिक प्रचालनों में सरकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है जो कि सीएफएसई का एक भागीदार है। ऐसी स्थिति में यह भी स्पष्ट है कि सीएफएसई के दैनिक प्रचालनों में सरकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है।

- xv. न तो हमारा कोई शेयरधारक और न ही हमारी कंपनी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी है। तदनुसार, कच्ची सामग्री प्रौद्योगिकी और श्रमिक की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश सहित कीमतों, लागतों और इनपुट के संबंध में सीएफएसई के निर्णय आपूर्ति एवं मांग दर्शाने वाले बाजार संकेतकों के अनुसार तथा बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के लिए जाते हैं।
- xvi. प्राधिकारी को सीएफएसई को एमईटी स्तर प्रदान करने पर विचार करना चाहिए और हमारी वास्तविक घरेलू कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जैसा कि अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के निर्यातकों के लिए किया जाता है।

#### 43. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- i. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं. लि. को छोड़कर किसी भी पक्षकार ने एमईटी प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।
- ii. दूसरे, बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उत्तरदाता निम्नलिखित प्रत्येक शर्त को पूरा नहीं करता:
  - क. बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर उस स्थिति में नहीं दिया जा सकता जहां एक प्रमुख शेयरधारक सरकारी स्वामित्व/नियंत्रण वाली कंपनी हो। वर्तमान मामले में 4 निर्यातक तथा उत्पादक अर्थात् चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं. लि., झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि., शंघाई 3एफ एवं इनर मंगोलिया 3एफ अपेक्षाकृत रूप से काफी सरकारी हस्तक्षेप के साथ चीन सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित हैं। संगत साक्ष्य पहले ही रिकार्ड में रख दिए गए हैं।
  - ख. बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उत्तरदाता चीनी निर्यातक यह सिद्ध न कर दें कि प्रमुख इनपुट की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती हैं।
  - ग. ऐसी स्थिति में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार रद्द किया जाना चाहिए जहां चीनी निर्यातक यह सिद्ध करने में असमर्थ हों कि उनकी बहियां अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएस) के अनुरूप हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुपालन पर जोर देने की आवश्यकता वार्षिक रिपोर्ट में व्यक्त किए गए राजस्व और खर्चों, परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिशुद्धता तथा पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए है।
  - घ. बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उत्तरदाता चीनी निर्यातक नियमों के तहत निर्धारित प्रत्येक मापदंड के संबंध में परीक्षण उत्तीर्ण न कर लें। यद्यपि, क्षति की मौजूदगी सिद्ध करने के लिए एक मापदंड पर्याप्त है, तथापि, एक मापदंड को पास करने की विफलता बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को रद्द करने के लिए पर्याप्त है।
  - ङ. उत्तरदाता चीनी निर्यातकों को यह सिद्ध करना है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत प्रचालन कर रहे हैं।
  - च. बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उत्तरदाता कंपनी और समग्र रूप से उसका समूह दावा न करे। यदि एक या अधिक कंपनियां समूह के भाग हैं और उन्होंने उत्तर दायर नहीं किया है तो बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर रद्द किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के शपथ पत्र के अनुसार डेकिन फ्लोरो केमिकल्स (चीन) कं. लि., ("डीसीसी") और उससे संबद्ध कंपनी मित्सुबिशी ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। परंतु चूंकि, सभी निर्यातकों तथा उत्पादकों ने शेयरधारिता की सूचना गोपनीय रखी है, तथापि, अन्य संबंधित कंपनी के विचाराधीन उत्पाद में शामिल होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।
  - छ. ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान शेयरधारक ने खुद अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं, परंतु किसी अन्य पक्षकार से वह प्राप्त की है, बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक रूपांतरण की प्रक्रिया दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से पूरी तरह सिद्ध न कर दी जाए।

- iii. चेंगआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं. लि., जिसने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली दायर की है, सहित कोई भी निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था स्तर प्रदान किए जाने के लिए योग्य होने हेतु क्षेत्राधिकार से तैयार प्रत्येक शर्त को पूरा नहीं करता। इस प्रकार, चीनी उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता।
- iv. दिनांक 20 दिसंबर, 2017 की व्यापार रक्षा जांचों के प्रयोजन के लिए चीन जनवादी गणराज्य की अर्थव्यवस्था में काफी गिरावटों के संबंध में यूरोपीय आयोग के स्टाफ वर्किंग दस्तावेज के अनुसार चीन की सरकारी संचालित अर्थव्यवस्था में सरकार में उत्पादन के बहु विध भूमिका नियंत्रणकारी कारकों के निर्वाह के रूप में अपने उद्योग नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन कारकों का पूरी तरह से प्रबंधन करने की क्षमता है। इस प्रकार, सरकार नई उत्पादन क्षमताओं की विदेश में अधिप्राप्ति के समर्थन के माध्यम से अथवा कुछ कंपनियों की उत्पादन लागतों को छूट देने के माध्यम से कुछ रसायनों का उत्पादन करने अथवा क्रियाकलाप को दूसरे उप बाजारों में ले जाने के लिए सीमाओं अथवा प्रोत्साहनों के माध्यम से अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति, मांग और कीमतों को प्रभावित करती है। ये सभी उपाय बाजार की मुक्त कार्यप्रणाली तथा कंपनी के निर्णयों को काफी प्रभावित करते हैं अथवा बाधा डालते हैं जो कि अब उपयुक्त रूप से बाजार संचालित नहीं हैं।
- v. संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग ("विभाग") ने अपने दिनांक 26 अक्तूबर, 2017 के ज्ञापन में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चीन के स्तर के संबंध में निष्कर्ष निकाला कि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है क्योंकि वह विभाग के पाटनरोधी विश्लेषण के प्रयोजन के लिए चीनी कीमतों और लागतों के प्रयोग की अनुमति देने हेतु बाजार सिद्धांतों पर पर्याप्त रूप से प्रचालन नहीं करता। विभाग के निष्कर्ष का आधार यह है कि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका और बाजारों तथा निजी क्षेत्र के साथ उसके संबंधों से चीन की अर्थव्यवस्था में मौलिक गिरावट आती है।
- vi. ऐसी स्थिति में चीन के लिए सामान्य मूल्य उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार ही निर्धारित किया जा सकता है।
- vii. यद्यपि, चीनी अभिगम नयाचार का अनुच्छेद 15(क)(ii) 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया, तथापि, प्राधिकारी को इस कारण वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एमएमई) के रूप में मानना चाहिए कि जांच की अवधि का प्रमुख भाग दिसंबर, 2016 तक था क्योंकि जांच की अवधि के दौरान विद्यमान स्थिति संगत महत्व की बन जाती है।
- viii. इन नियमों के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है:
  - क. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत
  - ख. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य
  - ग. ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत
- ix. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किए हैं कि उसके पास उपलब्ध सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य का दावा किया गया है। प्राधिकारी सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सिद्धांत को उपयुक्त रूप से अपनाएं।
- x. विचाराधीन उत्पाद का चीन में सामान्य मूल्य इस कारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार याचिकाकर्ता ने अंतिम विकल्प का सहारा लिया। हितवद्ध पक्षकारों के पास भी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश बताने और उसके लिए उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए जांच की शुरुआत से पर्याप्त समय और अवसर था।
- xi. इसके अतिरिक्त, उत्तरदाताओं ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि यह समझना कि "चीन को पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए किसी अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्य के रूप में उसी तरह माना जाना चाहिए", संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा नहीं बताया गया है जब उन्होंने अपने लिखित अनुरोधों के प्रश्न 18 में उल्लेख किया – "जब तक हाल में यह समझ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों द्वारा भी नहीं बताई जाती"। याचिकाकर्ता ने यहां "बताई जाती" शब्द के प्रयोग पर जोर दिया है जो स्पष्ट रूप से वर्तमान स्थिति नहीं दर्शाता।
- xii. उत्तरदाता का संयुक्त राज्य अमेरिका के 1999 के संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन द्विपक्षीय करार संबंधी व्हाइट हाउस के विवरण और काउंसिल डिसीजन एसेसन प्रोटोकॉल से संलग्न यूरोपीय संघ के 2001 के एक्सप्लानेटरी मैमोरेण्डम का संदर्भ देना असंगत और भ्रामक है क्योंकि वे एसेसन प्रोटोकॉल की पूर्व तारीखें हैं और धारा 15घ के निर्वचन



पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ की हाल की स्थितियों को नहीं दर्शाते जो कि काफी परिवर्तित हो गई हैं और अब आगे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।

- xiii. सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदाता का ईसी-फास्टमर मामले में संदर्भ भ्रामक है क्योंकि अपीलीय निकाय ने खुद स्पष्ट किया है कि "[.....] चीन का पैनेल के समक्ष दावा अलग-अलग और देशव्यापी पाटन मार्जिन और शुल्कों के निर्धारण से संबंधित है, और चीन को शामिल करके पाटनरोधी जांचों में सामान्य मूल्य के परिकलन में वैकल्पिक सिद्धांतों का सहारा लेने की संभावना नहीं है।" और इसके अतिरिक्त, उद्धृत पैसेज "प्रतिनिधि देश" की परिपाटी के प्रयोग को बाधित करने के उत्तरदाता के तर्क का समर्थन नहीं करता अथवा चीन को "बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" माने जाने के लिए अनिवार्य बनाता है। धारा 15 के निर्वचन तथा चीन के स्तर का मामला डब्ल्यूटीओ में न्यायाधीन है।
- xiv. घरेलू उद्योग ने अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं में निर्यात कीमत प्रदान की है, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार और निर्धारित तरीके तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की परिपाटी के अनुरूप समायोजन किए हैं। घरेलू उद्योग वास्तविक साक्ष्य में मर्मभेदी नहीं है और इसीलिए उसे प्रदान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। किसी भी स्थिति में चीन से निर्यातक को अपनी निजी प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर पाटन मार्जिन की मांग करने के लिए पूरी और विश्वसनीय सूचना के साथ उत्तर देना चाहिए। प्राधिकारी सत्यापन के बाद वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत कीमतों को अपनाएं, यदि प्रश्नावली का उत्तर प्रत्येक दृष्टि से पूरा है।
- xv. उपर्युक्त कारणों से किसी भी चीनी उत्पादक/निर्यातक को चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं. लि. सहित बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही, एमईटी प्रश्नावली के उत्तर में लगभग प्रत्येक सूचना गोपनीय होने का दावा किया गया था जो याचिकाकर्ता के प्रभावी टिप्पणियां करने के अधिकार में बाधा डालता है।
- xvi. यह तथ्य कि निर्यातकों ने पाटन का सहारा लिया है, उनके अपने मौन स्वीकरण से पाटन की मौजूदगी अस्वीकार न करने में सिद्ध हो जाती है।
- xvii. घरेलू उद्योग ने अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार आयात आंकड़ों की पहचान की है। घरेलू उद्योग को अब जो दिखता है, वह यह है कि निर्यातक कम मूल्य वाले उत्पाद के रूप में अपने उच्चतर मूल्य के उत्पाद दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने स्तर पर इन कुकृत्यों को दबाने के लिए कहानियां बना रहे हैं। याचिकाकर्ता का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया प्रश्नावली के उत्तर पर विचार करें और भारतीय आयात आंकड़ों से उसे मिलाएं। जब तक प्रश्नावली का उत्तर भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों से नहीं मिलाए जाते, प्रश्नावली का उत्तर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- xviii. पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- xix. प्राधिकारी पूर्व मामलों में विगत में निर्यातकों द्वारा दी गई कीमत वचनबद्धता के लिए अनुरोध को रद्द करते रहे हैं क्योंकि प्राधिकारी ने महसूस किया कि इन कीमत संबंधी वचनबद्धताओं की मॉनीटरिंग करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि विचाराधीन उत्पाद विभिन्न रूपों में उत्पादित/आपूर्ति किया जाता है, इससे वचनबद्धता के कार्यान्वयन में और व्यावहारिक कठिनाइयां आएंगी।
- xx. उत्तरदाताओं का उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि वे अपने संबद्ध पक्षकारों के नाम, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाले अपने संबद्ध पक्षकार के ब्यौरे, उनके द्वारा प्राप्त लाभों और प्रोत्साहनों से संबंधित तथ्यों को छिपाने जैसी महत्वपूर्ण सूचना प्रकट करने में विफल रहे हैं।
- xxi. घरेलू उद्योग का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इन संबद्ध/समूह कंपनियों के लिए भारित औसत तथा पाटन एवं क्षति मार्जिन पर विचार करें। संबद्ध कंपनियों के अलावा, चीनी उत्पादकों का एक विशेष सेट भी है जिन्होंने वर्तमान जांच में उत्तर दिया है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

44 किसी अनुच्छेद के संबंध में सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के तहत "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है :

*व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्भूत वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्भूत वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

45. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के तहत सामान्य मूल्य के परिकलन से संबंधित निम्नलिखित संगत प्रावधानों को भी नोट करते हैं।

46. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और पैरा 8 के तहत निम्नलिखित प्रावधान है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ कि देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों का लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं। जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या - (क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास अन्य बड़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं। तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

(4) तथापि, उप पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मान सकते हैं जिसे संगत मानदंडों, जिनमें उप पैरा 3 में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी देश द्वारा, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है अथवा माने जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

47. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सस्मिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, 15(क)(i) प्रावधान भी चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए उनका दावा सिद्ध करने का दायित्व देता है। पाटनरोधी नियमावली के पैरा 7 तथा पैरा 8 में सामान्य मूल्य से संबंधित सिद्धांत तथा बाजार अर्थव्यवस्था के दावे सिद्ध करने की शर्तें भी निर्धारित हैं।

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने प्रश्नावली के उत्तर दिए और दायर किए हैं:

क. सॉल्वे (शंघाई) कं. लि., चीन जन. गण.

ख. मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं., चीन जन. गण.

ग. उनी-एलाइंस लिमिटेड, चीन जन. गण.

घ. डेकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कं. लि., चीन जन. गण.

ङ. झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि., चीन जन. गण.

च. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं. लि., चीन जन. गण.

छ. शंघाई 3एफ, चीन जन. गण.

ज. इनर मंगोलिया 3एफ, चीन जन. गण.

50. केवल मैसर्स चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं. लि., चीन जन. गण. ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया है। अन्य उत्पादकों/निर्यातकों, जिन्होंने निर्धारित प्रश्नावली दायर करके बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, परंतु चीन को बाजार अर्थव्यवस्था माने जाने के संबंध में अनुरोध किए हैं और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयुक्त सिद्धांत का भी अनुरोध किया है।

### **सीएफएसई के एमईटी स्तर का मूल्यांकन और उसके सामान्य मूल्य का परिकलन**

51. प्राधिकारी बाजार अर्थव्यवस्था स्तर के दावे के संबंध में मैसर्स चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं. लि. (सीएफएसई) द्वारा किए गए अनुरोधों, घरेलू बिक्री के संबंध में दायर प्रश्नावली, बाजार अर्थव्यवस्था स्तर के दावे के संबंध में पूरक प्रश्नावली के साथ निर्यात बिक्री और उत्पादन लागत तथा बाजार अर्थव्यवस्था स्तर के दावे के संबंध में अतिरिक्त अनुरोधों को नोट किया है।

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. सी एफ एस ई एक किस्म का विचाराधीन उत्पाद ही उत्पादित करते हैं अर्थात् प्री-कंपाउंड (कोपोलाइमर और टरपोलाइमर) न कि कच्चे गोंद का जो कि एफकेएम का प्री-कंपाउंड तैयार करने के लिए नींव है। कच्चे गोंद का हिस्सा कुल बिक्री लागत के लगभग 70-75 प्रतिशत है और कुल कच्ची सामग्री लागत का 75 प्रतिशत से अधिक है। यह लागत अनुपात भी घरेलू उद्योग के उत्पादन संघटन की लागत से मेल खाता है जिसमें कच्ची सामग्री की लागत मुख्य रूप से कच्चे गोंद की बिक्री लागत का 95 प्रतिशत से अधिक है। मै. सी एफ एस ई द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था स्तर के दावे से संबंधित अनुरोध विचाराधीन उत्पाद की केवल एक किस्म के मूल्यवर्धन भाग संबंधी उनके सीमित प्रचालन के संदर्भ में ही है और उसके उन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कच्चे गोंद (जो विचाराधीन उत्पाद भी है) के उत्पादन संबंधी विस्तृत सूचना तथा साक्ष्यों के साथ नहीं है जिन्हें भी यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत प्रचालन कर रहे हैं। सीएफएसई की प्रश्नावली में कच्ची गोंद के उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं के प्रश्नावली के उत्तर शामिल नहीं हैं। सीमित और अपूर्ण सूचना से संबद्ध मामलों के लिए मै. सी एफ एस ई को बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर के दावे की जांच नहीं हो सकती और उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता।

53. प्राधिकारी ने फिर भी केवल वहां के कंपाउंडों के लिए उत्पादक/निर्यातक द्वारा दी गई उत्पादन लागत की जांच की है जहां भी विसंगतियां नोट की गई थीं जिनमें परिसंपत्तियों के स्वामी के नाम त्रुटिपूर्ण, कच्ची सामग्री की भिन्न खरीद कीमतें अनौचित्यपूर्ण और सिद्ध न की गई तथा उत्पादक द्वारा दायर की गई बिजली के बिलों में विसंगतियां शामिल हैं। जहां तक सरकारी अनुमान का संबंध है, उत्पादक/निर्यातक ने अपना शेयरधारिता पैटर्न दिया है जिसमें इसके एक शेयरधारक अर्थात् मैसर्स बुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इन्वेस्टमेंटर सेंटर (सीमित भागीदारी) जिसका उत्पादक/निर्यातक के शेयर का \*\*\* प्रतिशत हिस्सा है, की वस्तुतः \*\*\* प्रतिशत की सीमा तक सरकारी शेयरधारिता है। इस \*\*\* प्रतिशत शेयरधारिता में मैसर्स बुक्सी गुओलियान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कं. लि. (\*\*\* प्रतिशत), मैसर्स बुक्सी न्यूजपेपर डेवलेपर कं. लि. (\*\*\* प्रतिशत) और मैसर्स बुक्सी न्यू डिस्ट्रिक्ट साइन्स एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंसियल वेंचर कैपिटल ग्रुप कं. लि. (\*\*\* प्रतिशत) है जिनका सरकारी शेयरधारिता में 100 प्रतिशत हिस्सा है। उत्पादकों/निर्यातकों का निवेश स्वरूप प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से सरकारी उद्यमों द्वारा काफी निवेश दर्शाता है। प्राधिकारी सीएफएसई द्वारा किए गए अनुरोधों को भी नोट करते हैं कि मैसर्स बुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इन्वेस्टमेंटर सेंटर (\*\*\* प्रतिशत) का मैसर्स बुक्सी जुनयान कैपिटल मैनेजमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) (\*\*\* प्रतिशत निजी) एक सामान्य भागीदार के रूप में है जो अन्य सीमित भागीदारों के असमान दैनिक प्रबंधन निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत है और निर्णय करने में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। "प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में यह उल्लेख है कि:

- क. ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है;
- ख. ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;
- ग. ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है:-
- घ. विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं। तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7

*तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के बजाए पैरा 1 से 6 में पाटनरोधी नियमावली, 1996 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।"*

54. इस मामले में मैसर्स बुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इन्वेस्टमेंट्स सेंटर, जो सीएफएसई में प्रमुख शेयरधारक है, के भागीदार करार के 6.4 के तहत प्रावधानों में निवेश संबंधी निर्णय करने में सभी शेयरधारकों की भूमिका निर्धारित है जो उपयुक्त रूप से सीएफएसई में निवेश संबंधी निर्णय करने में सरकारी हस्तक्षेप को स्पष्ट करता है। अतः सरकारी कंपनियों के हस्तक्षेप वाले उत्पादक/निर्यातक द्वारा निवेश के लिए निर्णय करने से एमईटी स्तर का दावा करने के लिए पैरा 8(3)(क) के तहत शर्त पूरी नहीं होती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जहां तक विदेशी मुद्रा लेन-देन का संबंध है, उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उनके वित्तीय लेखाओं में दर्शाई गई विनिमय दर चीन के पीपल्स बैंक द्वारा प्रकाशित दर पर आधारित है। तथापि, इस पहलू के संबंध में कोई अनुरोध नहीं है कि क्या विनिमय दर पर सरकार का नियंत्रण है। प्राधिकारी दिनांक 08.04.2017 के पूर्व के जांच परिणाम संख्या 14/14/2014-डीजीएडी को ध्यान में रखते हैं जिनमें सरकार द्वारा विनिमय दर के सतत नियंत्रण संबंधी पैरा 108 को उल्लिखित किया गया था, उत्पादन लागत, शेयरधारिता पैटर्न और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे संबंधी मुद्दे केवल विचाराधीन उत्पाद के मूल्यवर्धित संघटक तक सीमित होने के नाते और कच्ची सामग्री की कोई भागीदारी न होने पर उत्पादक/आपूर्तिकर्ता उत्पादक/निर्यातक अर्थात् मैसर्स सीएफएसई को बाजार अर्थव्यवस्था स्तर प्रदान करने का औचित्य नहीं बनाते और उसके योग्य नहीं है।

55. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की प्राधिकारी द्वारा बाद के पैराओं में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से जांच की गई है। अतः प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों की अवशिष्ट श्रेणी सहित अन्य 4 सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए वही सिद्धांत अपनाया जो सीएफएसई के लिए सामान्य मूल्य हेतु अपनाया गया है।

#### **एमईटी स्तर का दावा न करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए "सामान्य मूल्य" का परिकलन**

56. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित किए गए अनुसार "सामान्य मूल्य" निर्धारित करने के लिए अनुक्रम को नोट करते हैं; और सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयुक्त सिद्धांत पर विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निम्नलिखित अनुरोधों को भी नोट करते हैं।

57. घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स टीपीएम ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(i) गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निम्नलिखित तीन विकल्प उपलब्ध हैं:

क. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य

ख. ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत

ग. उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में दी गई अथवा देय कीमत

(ii) घरेलू उद्योग द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के संबंध में सूचना एकत्र करने के प्रयास किए गए थे, परंतु वे इस संबंध में संगत सूचना प्राप्त नहीं कर पाए। इस प्रकार, सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तीन देशों से भारत में कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है क्योंकि वह अनुबंध-1 पैरा 7 के परीक्षण पास करता है:

- संयुक्त राज्य अमेरिका (भारत में आयातों का हिस्सा 28.15 प्रतिशत है)।
- जापान (भारत में आयातों का हिस्सा 15.70 प्रतिशत है) – तथापि, विचाराधीन उत्पाद के सभी स्वरूप भारत में आयात नहीं किए गए हैं।
- इटली (भारत में आयातों का हिस्सा 2.13 प्रतिशत है) – तथापि, विचाराधीन उत्पाद के सभी स्वरूप भारत में आयात नहीं किए गए हैं और आयातों की मात्रा न्यूनतम है।

(iii) इन देशों से भारत में कीमत के संबंध में पूरी सूचना याचिका में दी गई है। चूंकि, ये कीमतें सीआईएफ कीमतें हैं और निर्यात कीमत, कारखानागत निर्यात कीमत है, अतः कीमत को भाड़ा, बीमा, बैंक प्रभार और अंतर्देशीय भाड़ा आदि जैसे खर्चों के लिए समायोजित किया गया है। इसे विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य के रूप में माना जाना चाहिए।

58. मैसर्स झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स वर्ल्ड ट्रेड कंसल्टेंट्स तथा अधिवक्ताओं ने निम्नलिखित उल्लेख किए हैं:

- (i) निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर इस समझ से दायर किए गए हैं कि 11 दिसंबर, 2016 के बाद व्यापार उपचार महानिदेशक डब्ल्यूटीओ में चीनी अभिगम संबंधी नयाचार का पालन करेंगे।
- (ii) विश्व व्यापार संगठन ने चीन जन. गण. के अभिगम संबंधी नयाचार की धारा 15(क)(ii) के अनुसार 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई। भारत का गैर-बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग करके चीनी उत्पादों की पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य परिकलित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के करारों के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार की अपेक्षाओं और अन्य शामिल करारों के असंगत होगा। हम विश्वास करते हैं कि यह जांचकर्ता प्राधिकारी के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का यह दायित्व है कि वे, वह सूचना मांगें जिसकी डब्ल्यूटीओ नियमावली के अनुसार पाटन मार्जिन का परिकलन करने के लिए उन्हें आवश्यकता है।
- (iii) यदि व्यापार उपचार महानिदेशक हमारे अनुरोधों से सहमत नहीं हैं और फिर भी चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानते हैं तो यह अपेक्षित है कि डीजीटीआर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पालन करें।

**"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य कीमत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों में कीमत अथवा बाजार अर्थव्यवस्था के तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।"**

- (iv) पाटनरोधी नियमावली के तहत सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा उस तीसरे देश से अन्य देशों में कीमत के आधार पर किया जाएगा। उपर्युक्त के मद्देनजर यह सुझाव दिया जाता है कि निम्नलिखित मानदंडों को अपनाकर सामान्य मूल्य निर्मित किया जाए।
  - (क) संबंधित प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए लागत निर्मित करने के लिए कच्ची सामग्री खपत मानदंड अपनाए जाएंगे।
  - (ख) कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार किया जाए।
  - (ग) यूटिलिटियों की लागत चीन जन. गण. में विद्यमान कीमतों के आधार पर निकाली जाए।
  - (घ) चीन जन. गण. सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान ब्याज दर पर विचार किया जाए।

59. मैसर्स इनर मंगोलिया 3एफ वानहो फ्लोरोकेमिकल्स कं. लि. ("इनर मंगोलिया 3 एफ") और मैसर्स शंघाई हुआई 3एफ न्यू मैटेरियल्स सेल्स कं. लि. ("शंघाई 3एफ") का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स दुआ एसोसिएट्स ने निम्नलिखित उल्लेख किया है:

- (i) अनुबंध-1 के पैरा में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देशों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नलिखित रूप में क्रम दिया गया है:
  - क. **प्रथम सिद्धांत:** इस आधार पर कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों में कीमत।
  - ख. **द्वितीय सिद्धांत:** जहां सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रथम सिद्धांत के अनुसार संभव है, वहां सामान्य मूल्य उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो समान उत्पाद को विधिवत समायोजित करके भारत में वास्तव में दी गई अथवा देय कीमत के आधार पर परिकलित किया जाना।
- (ii) उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इटली अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध सामानों की कीमत अपनाएं। उपर्युक्त सूचना लेने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वे संबंधित देशों में भारत में दूतावासों के माध्यम से इटली अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका से सूचना मांगें। हम यह भी उल्लेख करना चाहते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पीसीएन में बंटा हुआ है। अतः प्राधिकारी को उत्पाद श्रेणी के अनुसार सूचना मांगनी चाहिए।
- (iii) चूंकि, उपर्युक्त सिद्धांत विशेष रूप से कठिन है, अतः उपर्युक्त के विकल्प के रूप में प्राधिकारी इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य का परिकलन भारत में संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य के आधार पर भी कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकारी इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में संबद्ध सामानों का आयात मूल्य ले सकते हैं और भारत सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क और करों में छूट, अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा और निर्यातक द्वारा दिया गया बीमा, घरेलू अंतर्देशीय भाड़ा तथा अन्य प्रभार और प्रतिनिधि देश में दिए गए कर जैसे आवश्यक समायोजन कर सकते हैं।

(iv) उपर्युक्त सिद्धांत निम्नलिखित कारणों से सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए सबसे उपयुक्त हैं:

- क. प्राधिकारी के पास प्रतिनिधि देश से आयातित सामानों के लेन-देन वार आयात आंकड़े हैं। उपर्युक्त आयात आंकड़ों को संबद्ध देश से आयात को अलग करने के लिए अपनाए गए उसी सिद्धांत के अनुसार पीसीएन आधार पर अलग किया जा सकता है।
- ख. उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर निकाली गई लागत/विक्री कीमत कारखानागत स्तर पर होगी और इसलिए कारखानागत निर्यात कीमत के साथ तुलना के लिए वह सबसे उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 6 अधिदेशित करता है कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना उसी स्तर पर की जानी चाहिए और प्राधिकारी उसकी तुलना कारखानागत स्तर पर करना बेहतर मानते हैं।
- ग. घरेलू उद्योग में उदीयमान उत्पादक हैं जिन्होंने जून, 2015 (जैसा कि आवेदन पत्र में स्वीकार किया गया है) से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। अतः भारतीय उत्पादक और भारतीय बाजार किसी स्थापित उद्योग के लिए कीमत का प्रतिनिधिकारक नहीं है। इस संबंध में पैरा 7 में यह भी अधिदेशित है कि प्राधिकारी को प्रतिनिधि देश का चयन करते समय संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्रुगत उत्पाद को मद्देनजर रखना चाहिए।
- घ. उपर्युक्त सिद्धांत सबसे अधिक उपयुक्त सिद्धांत होगा क्योंकि परिकलित सामान्य मूल्य विश्वसनीय सूचना पर आधारित होगा।
- ङ. उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन करने से अनावश्यक विलंब नहीं होगा।
- च. घरेलू उद्योग ने कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए चीन जन. गण. के लिए फैक्ट्री के बाद के खर्च दिए हैं। अतः, प्राधिकारी प्रतिनिधि देश में संबद्ध सामानों की लागत/कीमत निकालने के लिए उन आंकड़ों (फैक्ट्री के बाद के खर्चों से संबंधित) को समायोजित कर सकते हैं।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

60. प्राधिकारी चीन अभिगम नयाचार प्रावधानों के संबंध में मै. डब्ल्यूटीसी द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं और यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे के लिए अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के प्रावधानों को पूरा करना अपेक्षित है। दिनांक 11.12.2016 को यद्यपि, 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी गई सूचना/आंकड़ों के माध्यम से भारत की पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित है। केवल एक उत्पादक/निर्यातक अर्थात् मै. चेंगुआंग फ्लूरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं. लि. ने अपेक्षित सूचना दी है जिसकी पूर्व के पैरा में जांच की गई है। अतः जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदन किए जाने का दावा नहीं किया है, उनके लिए सामान्य मूल्य का परिकलन पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी इस पैरा के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त सिद्धांत अपनाने पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश और विभिन्न अनुरोधों के मामले में सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए विकल्पों का क्रम नोट करते हैं।

61. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में नोट किया था कि सामान्य मूल्य के लिए प्रतिनिधि तीसरे बाजार की अर्थव्यवस्था वाले देश में घरेलू कीमतों पर विचार करने के लिए पहला परंतुक व्यवहार्य नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के कई पीसीएन हैं जिनके लिए तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में घरेलू विक्री की सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कोई सूचना दायर नहीं की है। प्राधिकारी ने नोट किया कि पैरा 7 के दूसरे परंतुक में यह निर्धारित है कि ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में विचाराधीन उत्पाद की कीमत पर विचार किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमरीका से विचाराधीन उत्पाद के काफी आयात के मद्देनजर विचाराधीन उत्पाद, अत्याधुनिक ऑटो सेक्टर में अनुप्रयोगों वाले विशिष्ट रबड़, स्थान और जल शुद्धिकरण प्रणालियों की बाजार अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रवृत्ति के मद्देनजर प्राधिकारी ने पैरा 7 के दूसरे परंतुक के अनुसार भारत में उसकी निर्यात कीमतों का संदर्भ देने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका को एक प्रतिनिधि बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में प्रस्तावित किया था।

62. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका से आयात कीमत का संदर्भ देते हुए चीन में संबद्ध सामानों के लिए प्रकटन में उनके द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पर उपर्युक्त दृष्टिकोण का विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने विरोध किया है। प्राधिकारी इस संदर्भ में यह बताते हैं कि भारत में एक प्रतिनिधि देश के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका से आयात कीमतों पर विचार करने के मुद्दे के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

सार्वजनिक फाइल के माध्यम से विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों को बताए गए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि इस दृष्टिकोण को घरेलू उद्योग और एक उत्पादक/निर्यातक ने औचित्यपूर्ण बताया है, तथापि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि यह दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है क्योंकि भारत में संयुक्त राज्य अमरीका से कच्चे गोंद की निर्यात कीमतें प्री कंपाउंड कीमतों से अधिक हैं जो विसंगत और संगत है और औचित्यपूर्ण नहीं है। प्राधिकारी ने "सामान्य" मूल्य के परिकलन के संबंध में विभिन्न अनुरोधों के मद्देनजर इस जांच परिणाम में सर्वोत्तम परिपाटियों/मानदंडों के अनुसार लागत के विभिन्न घटकों को उपयुक्त रूप से मानक बनाकर और संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत पर उपयुक्त आय की अनुमति देकर घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित "सामान्य मूल्य" अपनाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दृष्टिकोण विगत मामलों में भी उनके द्वारा निरंतर अपनाया गया है और इस प्रकटन विवरण में दिए गए दृष्टिकोण पर उठाई गई विभिन्न चिंताओं का ध्यान रखा गया है।

63. प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय चीन में कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और बिजली की लागत को अपनाया जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनकी सतत परिपाटी के अनुसार वे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का संदर्भ देते हैं। वर्तमान मामले में दो मुख्य कच्ची सामग्री वीएफ-2 और जी एक्स 902 का घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि में आयात किया गया है जिन्हें "सीएनवी" के लिए लागत घटक के रूप में बताया गया है। दूसरी प्रमुख कच्ची सामग्री "पीएफसी" है जो कैप्टिव रूप से विनिर्मित की जाती है और व्यापार योग्य नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में सर्वोत्तम परिपाटियों/मानदंडों के साथ घरेलू उद्योग की मानक लागत को चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए माना गया है। इसके अतिरिक्त, दो कच्ची सामग्रियां अर्थात् वीएफ-2 और जीएक्स 901, डब्ल्यू टी ए आंकड़ा आधार के अनुसार, चीन में क्रमशः बहुत ही कम मात्रा में अथवा शून्य मात्रा में आयातित की जाती हैं और इसीलिए, भारत में इन दो कच्ची सामग्री की आयात कीमत पर एशिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रतिनिधि के रूप में विचार किया जा सकता है और "सीएनवी" प्रयोजन के लिए अपनाया जाना औचित्यपूर्ण है।

64. अतः प्राधिकारी ने उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर "सामान्य मूल्य" निर्मित किया है।

ग्रेड	सीएनवी (\$/किग्रा)
को पालीमर कच्ची गोंद	***
को पालीमर प्री कंपाउंड	***
टपोटलाइमर – बिसफेनोल क्योरड कच्चा गोंद	***
टर्पोलाइमर – पेरोक्साइड क्योरड कच्चा गोंद	***
टर्पोलइमर बिसफेनोल प्री कंपाउंड	***

#### छ. निर्यात कीमत का निर्धारण

65. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

- क. सॉल्वे (शंघाई) कं. लि., चीन जन. गण.
- ख. मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं., चीन जन. गण.
- ग. उनी-एलाइंस लिमिटेड, चीन जन. गण.
- घ. डेकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कं. लि., चीन जन. गण.
- ड. झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि., चीन जन. गण.
- च. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं. लि., चीन जन. गण.
- छ. शंघाई 3एफ, चीन जन. गण.
- ज. इनर मंगोलिया 3एफ, चीन जन. गण.



**सॉल्वे (शंघाई) कं. लि. और मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं. की निर्यात कीमत का निर्धारण**

66. उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान अपनी संबद्ध कंपनी अर्थात् मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसएसआईपीएल) को भारत में सीआईएफ आधार पर संबद्ध सामानों अर्थात् एफकेएम (कोपॉलीमर प्री-कंपाउंड) का 136.51 मी. टन बेचा है। संबद्ध आयातक ने यह सामान अंतिम उपभोक्ताओं को कार्यगत आधार पर बेचे हैं, परंतु उन्हें जांच की अवधि के दौरान \*\*\* रूपए की हानि हुई है। प्राधिकारी ने कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए इन हानियों को उपयुक्त रूप से समायोजित किया है।

67. प्राधिकारी ने \*\*\* डॉलर/मी. टन तक संभारिकी खर्चों (समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और पत्तन सार-संभाल), \*\*\* डॉलर/मी. टन तक बैंक प्रभार और \*\*\* डॉलर/मी. टन तक ऋण लागत संबंधी समायोजनों को इन घटकों संबंधी खर्चों की वास्तविक स्थिति के आधार पर उपयुक्त रूप से माना है। इसके अतिरिक्त, संबंधित आयातक द्वारा की गई बिक्री पर हानियों संबंधी समायोजन पर भी \*\*\* डॉलर/मी. टन तक विचार किया गया है। कारखानागत निर्यात कीमत \*\*\* डॉलर/मी. टन प्रस्तावित है। संगत शुल्कों और प्रभारों को जोड़ने के बाद पहुँच मूल्य \*\*\* डॉलर/मी. टन आता है।

**झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. की निर्यात कीमत**

68. उत्पादक/निर्यातक ने कुल \*\*\* अमेरिकी डॉलर मूल्य पर जांच की अवधि में 131 मी. टन तक (केवल को-पॉलीमर कच्चा गोंद) संबद्ध सामानों का निर्यात किया है (कार्यगत और सीआईएफ दोनों के संबंध में)। पत्तन प्रभार तथा सार-संभाल, अंतर्देशीय परिवहन, विदेशी परिवहन, बीमा, बैंक प्रभार के निमित्त विभिन्न खर्चों के आधार पर जांच की अवधि के दौरान सभी लेन-देनों के लिए समतुल्य सीआईएफ मूल्य \*\*\* अमेरिकी डॉलर परिकलित किया गया है। प्रति यूनिट सीआईएफ कीमत \*\*\* डॉलर/मी. टन आती है। पत्तन प्रभार और सार-संभाल, अंतर्देशीय परिवहन, विदेशी परिवहन, बीमा और बैंक प्रभार तथा वैट पर क्रमशः \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* डॉलर/मी. टन तक समायोजन करने के बाद कारखानागत निर्यात कीमत \*\*\* डॉलर/मी. टन आती है।

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उनके मैसर्स झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. अर्थात् चेमर्स चेंगुआंग फ्लोरो मैटेरियल्स (शंघाई) कं. लि. ने जांच की अवधि के दौरान सीधे ही संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। प्राधिकारी ने उसे महानिदेशक प्रणाली के लेन-देन वार आंकड़ों से भी वैध किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिभागी उत्पादक/निर्यातक द्वारा सीधे निर्यात के लिए ही पाटन मार्जिन का परिकलन किया जा रहा है।

70. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि \*\*\* मी. टन आयातों के लिए उत्तर मैसर्स ईस्टकॉर्प इंटरनेशनल द्वारा एक आयातक के रूप में दायर किया गया है जिनका सीआईएफ भी उत्पादक के उत्तर से व्यापक रूप से सहसंबंध रखता है।

**उनी-एलाइंस लिमिटेड, और डेकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कं. लि. की निर्यात कीमत**

71. मैसर्स डेकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कं. लि. ने संबद्ध सामानों अर्थात् फ्लोरोलस्टोमर्स का जांच की अवधि के दौरान भारत को 2 चैनलों अर्थात् मैसर्स मित्सुबिशी (23.80 मी. टन) और उनी एलाइंस (28.52 मी. टन) के माध्यम से 112.32 मी. टन फ्लोरोलस्टोमर्स का निर्यात किया है। मैसर्स मित्सुबिशी ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। मैसर्स उनी एलाइंस द्वारा निर्यात में 4.2 मी. टन फ्लोरोलस्टोमर्स (कंपाउंड) शामिल है जो विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है और उसे अलग किए जाने का प्रस्ताव है। अतः तीन ग्रेडों अर्थात् टरपोलाइमर, विसफेनल प्री-कंपाउंड, को-पॉलीमर प्री-कंपाउंड, टरपोलाइमर पैरोक्साइड क्यूरेबल रॉ गम का 84.50 मी. टन तक विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मैसर्स उनी एलाइंस द्वारा \*\*\* मी. टन, \*\*\* मी. टन, \*\*\* मी. टन क्रमशः \*\*\* अमेरिकी डॉलर, \*\*\* अमेरिकी डॉलर और \*\*\* अमेरिकी डॉलर के कुल बीजक मूल्य पर किया गया है।

72. टरपोलाइमर, विसफेनल प्री-कंपाउंड के मामले में अंतर्देशीय भाड़ा, सार-संभाल प्रभार, समुद्री बीमा, विदेशी भाड़ा, बैंक प्रभार, ऋण लागत और वैट पर क्रमशः \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन तक समायोजन करने के बाद कारखानागत निर्यात कीमत \*\*\* डॉलर/मी. टन आती है। सभी लागू शुल्क लगाने के बाद पहुँच मूल्य \*\*\* डॉलर/मी. टन आता है।

73. को-पॉलीमर प्री-कंपाउंड के मामले में अंतर्देशीय भाड़ा, सार-संभाल प्रभार, समुद्री बीमा, विदेशी भाड़ा, बैंक प्रभार, ऋण लागत और वैट पर क्रमशः \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन तक समायोजन करने के बाद कारखानागत निर्यात कीमत \*\*\* डॉलर/मी. टन आती है। सभी लागू शुल्क लगाने के बाद पहुँच मूल्य \*\*\* डॉलर/मी. टन आता है।





क्र. सं.	उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन - अम.डॉ./किग्रा.	पाटन मार्जिन - %	पाटन मार्जिन रेंज- %
2	डेकन फ्लोरोकेमिकल्स (चाइना) कं. लि., चीन जन. गण.	उनी-एलियांस लिमिटेड, चीन जन. गण.	***	***	20-30
3	झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि., चीन जन. गण.	झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि., चीन जन. गण.	***	***	30-40
4	चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टमर्स कं. लि., चीन जन. गण.	चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टमर्स कं. लि., चीन जन. गण.	***	***	30-40
5	इनर मंगोलिया 3एफ, चीन जन. गण.	शंघाई 3एफ, चीन जन. गण.	***	***	100-110
6	शेष अन्य		***	***	100-110

#### ज. क्षति का निर्धारण और कारणात्मक संपर्क

##### 81. निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- घरेलू उद्योग तीन वर्षों से पहले से ही अस्तित्व में है। उसने जुलाई, 2015 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। तदनुसार, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इस पाटन से घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी हुई है। घरेलू उद्योग वास्तविक मंदी का दावा नहीं कर सकता क्योंकि वह पहले से ही स्थापित है।
- क्षति के तीनों रूप एक साथ नहीं रह सकते (कोरिया – संयुक्त राज्य अमेरिका से पोलियासेटल रेजिन्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क देखें)।
- डब्ल्यूटीओ में वास्तविक मंदी संबंधी प्रस्ताव का कोई कानूनी आधार नहीं है।
- घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति का खतरा अथवा वास्तविक मंदी नहीं हुई क्योंकि संगत आर्थिक मानदंड काफी सुधार दर्शाते हैं।
- याचिकाकर्ता ने संबद्ध सामानों के बड़े हुए आयातों को बहुत अधिक दिखाया है और जानबूझकर वास्तविक मंदी बनाई है।
- याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए स्थिति प्रदान करने हेतु पाटन और/अथवा क्षति का कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है जबकि जांचकर्ता प्राधिकारी ने तथ्यों की उपयुक्त जांच नहीं की है।
- आवेदन पत्र पाटन, क्षति और तथाकथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के संबंध में साक्ष्यपरकता और कानूनी मानकों को पूरा नहीं करता।
- जांच की शुरुआत में वास्तविक और कानूनी आधार की कमी है, आधारहीन है और इस प्रकार उसे रद्द किया जाना चाहिए।
- याचिकाकर्ता के दावे तोड़े-मरोड़े गए और क्षति दर्शाने के लिए बनावटी प्रतीत होते हैं।
- संबद्ध देश से आयात मांग में वृद्धि के साथ बढ़े हैं और उन्होंने अन्य देशों से आयातों में गिरावट की क्षतिपूर्ति की है। जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों के कारण कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं है।

- xi. याचिकाकर्ता ने संबद्ध सामग्री का अन्य देशों को निर्यात उन कीमतों से काफी कम कीमत पर किया है जिन कीमतों पर चीन जन. गण. से भारत में सामान आयात किए गए हैं और वह भी मुख्य रूप से उसकी सहायक कंपनियों से यथा जीएफएल अमेरिका, जीएफएल जीएमबीएच। यह घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति का एक मुख्य कारण है।
- xii. कीमत कटौती, जो कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है, पूरी क्षति अवधि के दो रान नकारात्मक है।
- xiii. कुछ अन्य कारक हो सकते हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। यह याचिका जानबूझकर उन कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में जानबूझकर विफल है जिनका संबद्ध आयातों से स्वतंत्र रूप से घरेलू उद्योग पर प्रभाव था।
- xiv. क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग जांच की अवधि के दौरान उच्चतम स्तर पर रहे हैं और इन मापदंडों में कोई कमी नहीं है।
- xv. याचिकाकर्ता उन सबकी बिक्री कर रहा है जिसका वे उत्पादन कर रहे हैं। उनका जोर अपनी इच्छा से निर्यात करना रहा है, न कि अवसर से तथा भारतीय बाजार की वजह से।
- xvi. घरेलू उद्योग को उस समय भी क्षति की अवधि के दौरान हानि हो रही है जब आयातों से क्षति नहीं हो रही थी। उसकी क्षति के लिए कोई अन्य कारण हो सकते हैं न कि संबद्ध आयात।
- xvii. घरेलू उद्योग की उत्पादकता बढ़ी है।
- xviii. कोई कीमत प्रभाव नहीं है क्योंकि कीमत न्यूनीकरण जीएफएल की अपनी कीमत संबंधी नीतियों के कारण है।
- xix. लाभप्रदता के संबंध में नकारात्मक निष्पादन घरेलू कंपनी द्वारा उत्पादित समान वस्तुओं की अलाभप्रद कीमत के कारण है।
- xx. घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ का परिकलन करने में घरेलू बिक्री लाभ/हानि से निर्यात लाभ/हानि को अलग नहीं किया है। अतः ह्रास की मात्रा गलत है क्योंकि निर्यातों के कारण क्षति का कोई पृथक्करण नहीं है।
- xxi. उत्पादन की शुरुआत मांग में गिरावट के साथ हुआ, अतः परियोजना रिपोर्टों में अनुमानित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका जो उस समय निर्धारित थे जब मांग बढ़ रही थी, तथापि, घरेलू उद्योग ने बहुत कम समय में उपयुक्त बाजार लिया।
- xxii. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में कोई क्षति नहीं है और घरेलू उद्योग की बिक्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।
- xxiii. मालसूची का विश्लेषण करने के लिए सही तरीका अंत मालसूची की तुलना घरेलू उद्योग द्वारा की गई घरेलू बिक्री से करना है, जैसा कि माननीय सेसटेट द्वारा ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2011 (270) ईएलटी 696 (ट्राई. - डेल.) के मामले में निर्धारित किया गया है।
- xxiv. याचिकाकर्ता का यह कथन कि उसने देश में उत्पाद के पाटन के कारण ही विचाराधीन उत्पाद की काफी मात्रा का निर्यात किया है, भ्रामक है। याचिकाकर्ता की घरेलू और निर्यात बिक्री दोनों 2015-16 (याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन की शुरुआत का वर्ष) की तुलना में, जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ी हैं। उत्तरदाता ने किसी पाटन का सहारा नहीं लिया है।
- xxv. प्रचालन के छोटे से दो वर्षों में याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री पांच गुना तक बढ़ी है, बाजार हिस्सा चार गुना तक बढ़ा है, क्षमता उपयोग दोगुना तक बढ़ा है आदि। ऐसी स्थिति में यह कहना आधारहीन और गलत है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग की वृद्धि में बाधक बन रहे हैं। याचिकाकर्ता को यदि कोई क्षति हुई है तो वह उसकी अदक्षताओं और उत्पाद की कम गुणवत्ता के कारण हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि यह इन अन्य कारणों से है कि याचिकाकर्ता को घरेलू बाजार में ही हानियां नहीं हुई हैं, बल्कि निर्यात बाजार में भी हुई हैं।
- xxvi. अनुरोध है कि 2014-15 के आंकड़ों को न देखा जाए। इसके अतिरिक्त, 2015-16 को क्षति विश्लेषण के लिए आधार वर्ष माना जाना चाहिए। साथ ही जांच को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह जांच याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़ों और सूचना के गलत विश्लेषण के आधार पर शुरू की गई है।
- xxvii. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि चीनी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा कम कीमत पर पाटन से घरेलू उद्योग बांछित बाजार हिस्सा नहीं ले पा रहा है और उससे उनकी वृद्धि रुक रही है, गलत है और इस कारण धोखापूर्ण है कि घरेलू उद्योग उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की बिक्री उन कीमतों पर करता रहा है जो चीन से आयातों के पहुँच

मूल्य से कम थीं। सस्ते पाटित आयातों के कारण बाजार हिस्सा लेने में असमर्थता की स्थिति उसी समय उत्पन्न हो सकती है जब घरेलू उद्योग अपने सामानों की कीमतें उन तथाकथित पाटित आयातों की कीमतों से अधिक रखें। एकमात्र कारण जिसके लिए संबद्ध सामानों के प्रयोक्ता घरेलू उद्योग से उसे नहीं लेंगे, वह गुणवत्ता संबंधी मुद्दे का कारण होगा, जैसा कि सिद्ध है कि जिन कीमतों पर घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों की पेशकश कर रहा है, वे आयातों की कीमतों से काफी कम होने पर अधिक आकर्षक होने से कहीं दूर हैं।

- xxviii. जुलाई, 2015 से पूर्व के आंकड़े भारत के घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की विद्यमान प्रवृत्तियों के विश्लेषण की सीमा तक संगत हैं। चूंकि, जुलाई, 2015 से पूर्व संबद्ध सामानों का कोई उत्पादन नहीं था, अतः संबद्ध सामानों की मांग तथा खपत, कीमतों की प्रवृत्तियां यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि क्या घरेलू उद्योग का कीमतों को कम करने, घरेलू बाजार में खपत और मांग के पैटर्न में परिवर्तनों आदि जैसे दावे सही हैं।
- xxix. जुलाई, 2015 से पूर्व के आंकड़े लेकर ऐसी प्रवृत्ति की तुलना वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि यह देखा जा सकता है कि घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की मांग में 2015 में पूर्व वर्ष की तुलना में तेजी से गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, चीन से आयातों का पहुँच मूल्य 2015 में लगभग 9 प्रतिशत तक बढ़ा। यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग के भ्रामक दावे का विरोधाभासी है कि चीन में उस समय भारत ने अपनी कीमतें कम कीं जब घरेलू उद्योग ने 2015 में उत्पादन आरंभ किया, जब वस्तुतः चीनी आयात और अधिक महंगे हो गए थे।
- xxx. क्षति के दो रूपों के एक साथ रहने के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा पूरी तरह से गलत किया गया है क्योंकि धारा 9ख(1)(ख)(ii) में निर्धारित क्षति के रूपों को "अथवा" शब्द से अलग-अलग किया गया है जिसका प्रयोग उसके असंयुक्त भाव में किया गया है जो यह दर्शाता है कि वे पारस्परिक रूप से विशिष्ट हैं। यह कानून की निर्धारित स्थिति है जिसमें यह दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है कि "अथवा" शब्द का प्रयोग उसके साधारण भाव में किया जाना होता है जब तक कि उसे असंयुक्त रूप में पढ़ा न जाए, वह समझ में न आने वाला अथवा गलत अर्थ में परिणाम देगा। दिल्ली नगर निगम बनाम टेक चंद भाटिया (1980) 1 एससीसी 158 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अथवा को जब तक संदर्भ न दर्शाए तब तक उसके साधारण असंयुक्त भाव में पढ़ा जाना है।
- xxxi. पाटनरोधी नियमावली, 1995 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह दर्शाए कि यदि क्षति का एक रूप नहीं पाया जाता है तो दूसरे रूप की जांच की जाए। न ही धारा 9ख(1)(ख)(ii) और न ही नियम 11 अथवा अनुबंध-II या तो स्पष्ट रूप से अथवा आवश्यक प्रभाव के माध्यम से प्रावधान करते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षति के दूसरे रूप की जांच करनी चाहिए, यदि घरेलू उद्योग द्वारा आरंभिक दावे की प्रकृति में क्षति नहीं दर्शाई गई है।
- xxxii. यद्यपि, कोरिया – संयुक्त राज्य अमेरिका से पॉलीसेटल रेसिन्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (एडीपी)/92 तथा (कोर.-I) निर्णय वर्तमान पाटनरोधी करार के अस्तित्व में आने से पूर्व जारी किया गया था, तथापि, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी पूर्व के करार के तहत "क्षति" शब्द के संबंध में संगत प्रावधान ("टोकियो राउंड एंटी डंपिंग कोड") पाटनरोधी करार में परि मेटेरिया हैं। पाटनरोधी करार की पादटिप्पणी 9 तथा टोकियो राउंड एंटी डंपिंग कोड की पादटिप्पणी 3 के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि "वास्तविक क्षति", "वास्तविक क्षति का खतरा" और "वास्तविक मंदी" शब्द की समझ में, जैसा कि वे टोकियो राउंड एंटी डंपिंग कोड में दिए गए थे, वर्तमान पाटनरोधी करार के तहत कोई परिवर्तन नहीं आया है।
- xxxiii. सीमा शुल्क आयुक्त, बेंगलूर बनाम जी.एम. एक्सपोटर्स एवं अन्य [(2016) 1एससीसी 91] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह बात भी अब नहीं रह गई है कि म्युनिसिपल कानून में प्रावधान का निर्वचन करते समय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधि में हस्ताक्षरकर्ता होने के परिणामस्वरूप भारत द्वारा किए गए दायित्वों के परिणामस्वरूप विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया है, ऐसी संविधि का निर्वचन घरेलू पूर्वोदाहरणों के बजाए सामान्य स्वीकार्यता के व्यापक सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए क्योंकि उनका आशय संधि के दायित्वों को पूरा करना है न कि उनके प्रतिकूल होना।
- xxxiv. क्षति के सिद्ध होने के संबंध में भारतीय प्रावधान पाटनरोधी करार में निहित प्रावधानों पर आधारित हैं, अतः कोरिया – संयुक्त राज्य अमेरिका से पॉलीसेटल रेसिन्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (उपर्युक्त) में जीएटीटी पैनल रिपोर्ट के मद्देनजर, यह सिद्ध किया जाता है कि "क्षति" के तीनों रूप उसी घरेलू उद्योग के लिए साथ-साथ नहीं हो सकते।
- xxxv. घरेलू उद्योग ने 23 जनवरी, 1990 के ईयू कमीशन रेगुलेशन (ईईसी) संख्या 135/90 पर विश्वास किया है जिसमें यूरोपीय आयोग ने अपने दावे को सिद्ध करने के लिए वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी, दोनों पाई। तथापि,

यह पॉलीसेटल रेसिन्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (उपर्युक्त) के मद्देनजर, यह अब अच्छा कानून नहीं है जिसने पूरी तरह उसके विपरीत नियम दिया है।

- xxxvi. घरेलू उद्योग का एसबीआर 1500-1700 श्रृंखला के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के 12 जुलाई, 2017 के अंतिम जांच परिणाम और उस पर सेसटेट अपील पर विश्वास भी गलत किया गया है क्योंकि उपर्युक्त मामले में घरेलू उद्योग में दो घरेलू उत्पादक थे – एक वह जिसको इस तथ्य पर वास्तविक क्षति हुई कि वह स्थापित घरेलू उत्पादक था, दूसरे की इस कारण वास्तविक मंदी के लिए जांच की गई थी कि उसे स्थापित उद्योग के रूप में नहीं माना गया था क्योंकि वह शुरू नहीं हुआ था। अतः उस मामले के तथ्य और परिस्थितियां वर्तमान मामले पर लागू होने योग्य नहीं हैं क्योंकि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग केवल एक घरेलू उत्पादक है।
- xxxvii. निर्दिष्ट प्राधिकारी और माननीय सेसटेट को कोरिया – संयुक्त राज्य अमेरिका से पॉलीसेटल रेसिन्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क में जीएटीटी पैनल की रिपोर्ट का लाभ नहीं मिला जिसे एसबीआर के मामले में निर्णय देते समय जी. एम. एक्सपोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार इस मुद्दे पर प्राधिकृत घोषणा के रूप में माना जाना है और इस प्रकार उपर्युक्त निर्णय निर्धारित कानूनी सिद्धांत की उपेक्षा में पारित किए गए थे कि क्षति के तीनों रूप साथ-साथ नहीं हो सकते।
- xxxviii. चीन जन. गण. और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएचपीजी दाने साल्ट के संबंध में पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्धारण पक्षकारों के तर्कों को ध्यान में रखे बिना और समान घरेलू उद्योग के लिए क्षति के दोनों रूप कैसे साथ-साथ हो सकते हैं, के संबंध में कोई कारण दिए बिना किया गया था। क्षति के उपर्युक्त मुद्दे के संबंध में ऐसे कारणहीन जांच परिणाम को मौन माना जाना होता है और इसीलिए वर्तमान मामले में निर्णय लेते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर. बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लि. एंड एएनआर. [(1991) 4 एससीसी 139] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया जाता है।
- xxxix. घरेलू उद्योग ने वास्तविक मंदी कैसे सुनिश्चित की जाए, विशेष रूप से अनुच्छेद 3.9 को जोड़कर पाटनरोधी करार में प्रस्तावित संशोधन पर, यह सिद्ध करने के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के विचार-विमर्श और प्रस्तावों पर विश्वास करने की पुनः मांग की है। यहां तक कि यद्यपि संधि के महत्वपूर्ण प्रावधानों में इस प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया है, तथापि, उस पर विश्वास किया जा सकता है, यदि संधि के निर्वचन अथवा वीसीएलटी के अनुच्छेद 31(3)(क) के अनुसार उसके प्रावधानों के निर्वचन के संबंध में पक्षकारों के बीच बाद में कोई करार हो। दुर्भाग्यवश घरेलू उद्योग ऐसे किसी करार की मौजूदगी के संबंध में कोई वास्तविक तथ्य देने के संबंध में समर्थ नहीं रहा है।
- xl. घरेलू उद्योग ने उत्कृष्ट निर्यात निष्पादन और वृद्धि दर्शाते हुए अपनी पूरी सुनवाई पूर्व के अनुरोध (17 मई, 2018 का पत्र) द्वारा जांचकर्ता प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने लाभ के अनुसार अपनी बात रखने के लिए सूचीबद्ध आंकड़ों का प्रयोग किसी उद्देश्य से किया। जैसे ही चीनी उत्पादकों और एआईआरआईए ने मौखिक सुनवाई के दौरान उल्लेख किया कि उनकी सामग्री बहुत कम कीमतों पर पेश किए जाने के बावजूद दुर्बल गुणवत्ता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विफल रही।
- xli. हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे इसका संज्ञान लें कि यह अचानक ही अपने निर्यात निष्पादन को हटाने के लिए "मेक फॉर इंडिया" संयंत्र बन गया। संभवतः सम्मानित प्राधिकारी आश्चर्य करेंगे कि तथाकथित वैश्विक कंपनी ने घरेलू बाजार की ही पूर्ति के इरादे से संयंत्र स्थापित किया है जबकि वे विश्वास करते हैं कि उनकी उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय मानक से तुलनीय है, निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उसकी बारीकी से जांच करें।
- xlii. झोंगाओ चेंगुआंग ने विस्तृत अनुसंधान एवं विकास कार्य किए हैं और कई ग्रेडों को पेटेंट किया है जो पूर्णतः उनके द्वारा ही उत्पादित किए जा रहे हैं। इस प्रकार, उन उत्पादों को कम कीमतों पर बेचने अथवा घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने के लिए बेचने की आवश्यकता नहीं है। जिन कीमतों पर झोंगाओ चेंगुआंग बिक्री कर रहा है, वे पूर्णतः बाजार संचालित हैं।
- xliii. अनुरोध है कि 28 फरवरी, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 5/2018 व्यापार सूचना जारी किए जाने के बाद शुरू की गई जांचों पर लागू है। चूंकि, वर्तमान जांच 02 जनवरी, 2018 को शुरू की गई थी, अतः वह व्यापार सूचना प्रतिभागी निर्यातकों/आयातकों पर लागू नहीं है। तथापि, यदि प्राधिकारी चाहें तो हम पूरी सूचना देना चाह रहे हैं।

## 82. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- i. संबद्ध देश से आयात क्षति की अवधि में पूरी तरह से बढ़े हैं और जांच की अवधि में मांग में 13 प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध आधार वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत तक बढ़े हैं।
- ii. भारत में आने वाले कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा पूरी क्षति अवधि में बढ़ा है और जांच की अवधि में 49.50 प्रतिशत है जबकि अन्य देशों का वह हिस्सा तदनुसारी पूरी अवधि के दौरान घटा है।
- iii. घरेलू मांग/खपत में संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा भी क्षति की अवधि में बढ़ा है और जांच की अवधि के दौरान 42.67 प्रतिशत है।
- iv. क्षति की अवधि में आयात कीमत में 28 रुपए/कि.ग्रा. तक गिरावट है और वह औसत सीआईएफ कीमत से तथा अन्य देशों की सीआईएफ आयात कीमत से काफी कम है।
- v. संबद्ध देश से आयात कीमत में 2015-16 के बाद उस वर्ष में भारी गिरावट आई जिसमें घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। वह 2015-16 जब घरेलू उद्योग अस्तित्व में आया, की तुलना में जांच की अवधि में 113 कि.ग्रा. अर्थात् 11 प्रतिशत तक कम हुआ।
- vi. चीन से कीमत कटौती नकारात्मक है क्योंकि घरेलू उद्योग संबद्ध देश से सस्ती आयात कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कम कीमतें रखने के लिए विवश है।
- vii. संबद्ध देश के आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण हो रहा है।
- viii. भारतीय मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में बढ़ा है, परंतु देश में उत्पाद की मांग बढ़ने के बावजूद निरंतर आंशिक रूप से कम है।
- ix. घरेलू उद्योग पाटित आयातों की मौजूदगी से देश में काफी मांग और क्षमताओं के अस्तित्व में होने के बावजूद अपना उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा बढ़ाने से रुका है।
- x. घरेलू उद्योग में मालसूची कम उत्पादन के बावजूद निरंतर बढ़ रही है।
- xi. याचिकाकर्ता को काफी वित्तीय हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हो रही है।
- xii. घरेलू उद्योग की वृद्धि कई कीमत संबंधी मानदंडों के संबंध में नकारात्मक है।
- xiii. क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी है।
- xiv. विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग अपने को पूरी तरह स्थापित नहीं कर पा रहा है। घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2015 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था और वर्तमान जांच में जांच की अवधि जुलाई, 2016 से जून, 2017 है। निर्दिष्ट प्राधिकारी (क) पाटन का प्रभाव सिद्ध करने के लिए वास्तविक उत्पादन, (ख) क्षति का खतरा सिद्ध करने के लिए संभावित स्थिति और (ग) क्या विचाराधीन उत्पाद के पाटन से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी हो रही है, पर विचार करें।
- xv. याचिकाकर्ता यह समझने में विफल रहा कि कोई उद्योग अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर मंदी का दावा कैसे नहीं कर सकता।
- xvi. नियमावली में यह उल्लेख नहीं है कि मंदी का दावा तभी किया जाना चाहिए जब कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू न किया है। यदि किसी नए उद्योग को क्षति हो रही है तो इसका अर्थ है कि उसे वास्तविक मंदी हो रही है। एसबीआर के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय का संदर्भ दिया जाता है और विश्वास किया जाता है जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की है। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी उद्योग को वास्तविक मंदी हो रही है, परंतु वास्तविक क्षति नहीं हो रही है। विशेष रूप से यदि घरेलू उद्योग ने कुछ समय से निष्पादन किया है, वस्तुतः निष्पादन की सीमा तक वास्तविक क्षति का अभाव मंदी के मामले में पूर्व अपेक्षा होनी चाहिए।
- xvii. याचिकाकर्ता "व्यापार के उदीयमान चरण" में है। नियमों में यह उल्लेख नहीं है कि प्राधिकारी इस तरह की क्षति को तभी रिकार्ड करें यदि घरेलू उद्योग का 1 वर्ष से कम का निष्पादन हो। वस्तुतः जांच की अवधि के संबंध में डब्ल्यूटीओ के दिशा-निर्देश यह बताते हैं कि यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन तीन वर्ष से कम है तो वह उदीयमान चरण की श्रेणी में आएगा। कानून में केवल तीन रूपों – स्थापना को मंदी, वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति के खतरे को माना है। इस प्रकार, विकास अथवा विकसित की प्रक्रिया में घरेलू उद्योग के दो से अधिक चरण न हो सकते।



- xviii. वर्तमान मामले में, आयातों से वास्तविक मंदी हो रही है। याचिकाकर्ता को अब तक 30 करोड़ के निवेश में 12.74 करोड़ की हानि हो चुकी है। घरेलू उद्योग का अब तक का निष्पादन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रचालन की इस छोटी-सी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन कम हुआ है।
- xix. क्षति के तीन रूप अर्थात् वास्तविक क्षति, वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति का खतरा एक साथ नहीं हो सकते। नियमावली बताती है कि यदि क्षति का एक रूप नहीं पाया जाता है तो क्षति के दूसरे रूप की जांच की जानी चाहिए। "अथवा" को "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, यदि क्षति का एक से अधिक स्वरूप मौजूद हो।
- xx. घरेलू उद्योग ने उस सीमा तक घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी के आधार पर अनिवार्य रूप से क्षति का दावा किया है जहां तक याचिकाकर्ता को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से रोका गया है और उसे इष्टतम से काफी कम उपयोग तथा काफी कम वित्तीय हानियां हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने विद्यमान स्थिति के अनुसार याचिकाकर्ता के निष्पादन पर वास्तविक क्षति का दावा किया है और वह काफी वित्तीय और नकद हानियां दर्शाता है।
- xxi. प्राधिकारी ने वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी साथ-साथ होना बार-बार पाया है, जैसा कि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी फ्लैक्स फिल्मस, रूस, उक्रेन और कोरिया से इंडक्शन हार्डर्ड फोर्ड स्टील रॉड, चीन जन. गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी किस्मों के 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोथीन अथवा आर-134ए और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड से संबंधित जांचों में किया गया है।
- xxii. चीन जन. गण. और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी(-) पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसीन मिथाइल पौटेथियम दाने साल्ट और चीन जन. गण. और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी(-) पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसीन बेस से संबंधित पाटनरोधी जांचों में प्राधिकारी ने क्षति के तीनों रूपों अर्थात् वास्तविक मंदी, वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति का खतरा पाया। ईयू जापानीज डायनमिक रेंडम एक्सेस मैमोरी (डीआरएएम) केस (रेगुलेशन (ईईसी) 165/90, ओजेएल 20, 25.01.90) पर भी विश्वास किया जाता है।
- xxiii. उत्तरदाता का कोरिया – संयुक्त राज्य अमेरिका से पॉलीसेटल रेसिन्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का संदर्भ दो प्रमुख कारणों से संगत है। पहला, उपर्युक्त निर्णय पाटनरोधी करार के अस्तित्व में आने से पहले का था और दूसरा, स्टाइरीन बुटाडीन रबड़ के मद्देनजर जिसमें प्राधिकारी ने अपने 12 जुलाई, 2017 के जांच परिणाम में वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति, दोनों की साथ-साथ जांच की है। प्राधिकारी ने माना कि:

*"x. पाटनरोधी नियमावली इन दोनों रूपों की साथ-साथ जांच करने से नहीं रोकती। यह नहीं माना जा सकता कि क्षति के तीनों रूप पारस्परिक रूप से विशिष्ट हैं।"*

प्राधिकारी के जांच परिणाम को इस आधार पर एसबीआर में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच परिणाम का विरोध करते हुए सेसटेट में चुनौती दी गई थी कि दोनों प्रकार की क्षति की जांच साथ-साथ नहीं की जा सकती। सेसटेट ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के जांच परिणाम को रोक दिया।

- xxiv. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित वीनीर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग के मामले में भी दिनांक 13 फरवरी, 2018 को वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति का साथ-साथ होना माना। विभिन्न मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त विश्लेषण को देखते हुए बार-बार यह माना गया कि क्षति के सभी स्वरूप "पारस्परिक रूप से विशिष्ट नहीं हैं" और घरेलू उद्योग को हो रही विभिन्न प्रकार की क्षति के निर्धारण के लिए साथ-साथ रह सकती हैं।
- xxv. प्राधिकारी कृपया वर्तमान मामले पर ऐसे मामले के रूप में विचार करें जहां घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंदी हो रही थी और वह एक ओर मौजूदा निष्पादन पर विचार करते हुए सिद्ध है तथा प्रस्तावित/लक्षित निष्पादन से मौजूदा निष्पादन की तुलना है। तथापि, यदि हितबद्ध पक्षकार इस बात पर जोर दें कि घरेलू उद्योग पहले से ही स्थापित है और वास्तविक मंदी एवं वास्तविक क्षति एक साथ नहीं हो सकते तो उस स्थिति में प्राधिकारी कृपया वास्तविक क्षति के निर्धारण के प्रयोजन के लिए वर्तमान मामले में विचार करें, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जुलाई, 2015 में पहले ही अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। ऐसी स्थिति में, प्राधिकारी कृपया क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए अनुबंध-III लागू करें और इस पर विचार करें कि जांच की अवधि में क्षमता उपयोग उसके इष्टतम स्तर पर था और उस स्थिति में एनआईपी का निर्धारण जांच की अवधि के दौरान प्राप्त क्षमता उपयोग पर विचार करके किया जाना अपेक्षित है। यदि निर्दिष्ट

प्राधिकारी वास्तविक क्षति के मामले के रूप में वर्तमान मामले की जांच करें क्योंकि जांच की अवधि में क्षमता उपयोग इष्टतम था तो एनआईपी के निश्चरण के लिए कोई मानक न बनाया जाए।

- xxvi. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का वास्तविक मूल्यांकन और घरेलू उद्योग की स्थिति में बाधक बनने वाले तत्व शामिल होने चाहिए। कानून यह नहीं कहता कि आर्थिक मानदंड आवश्यक रूप से गिरावट दर्शाएं। "मूल्यांकन" शब्द का अर्थ "प्रदर्शन" और "अस्तित्व" नहीं है। ऐसा मूल्यांकन निश्चित रूप से संबंधित उद्योग की स्थिति के अनुसार प्रत्येक मामले के लिए बाधक होगा। इसी - बेड लिनेन (अनुच्छेद 21.5 - भारत) में निर्णय पर विश्वास किया जाता है।
- xxvii. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा बाजार में पाटित आयातों की उपलब्धता के कारण क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ पाई। घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान 36.10 प्रतिशत तक तथा 2017-18 में 54.76 प्रतिशत तक ही अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाया। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में 238 मी. टन उत्पादन करने पर घरेलू उद्योग अपने उत्पादन की सीमा तक बिक्री करने में सक्षम नहीं था और भारत से बाहर उत्पाद का निर्यात करने के लिए मजबूर था।
- xxviii. यह तथ्य कि कुछ मानदंड क्षति नहीं दर्शाते स्वीकारात्मक जांच परिणाम पर अविश्वास नहीं करेंगे।
- xxix. संबद्ध आयात क्षति की अवधि में 50 प्रतिशत तक बढ़े हैं। संबद्ध आयातों से वास्तविक क्षति हो रही है और वे घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंदी कर रहे हैं।
- xxx. विरोधी पक्षकार यह उल्लेख करने में विफल रहा कि नियम 5 की यह पूर्व शर्त कैसे पूरी नहीं की गई।
- xxxi. घरेलू उद्योग द्वारा दायर सूचना का प्राधिकारी द्वारा पहले ही सत्यापन कर दिया गया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटन के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर शुरू की है। आवेदक ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के अपना दावे के समर्थन में सभी संगत सूचना दी है और प्राधिकारी ने जांच शुरू करना उपयुक्त पाया है।
- xxxii. संबद्ध सामानों का निर्यात करना घरेलू उद्योग का विकल्प नहीं था बल्कि उनकी मजबूरी थी। जीएफएल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में कम कीमतों पर चीनी उत्पादों की बिक्री के कारण ही कम कीमत पर अमेरिकी बाजार में बिक्री करने के मजबूर था।
- xxxiii. जहां तक संबद्ध पक्षकार को कम कीमत पर निर्यात का संबंध है, यद्यपि, यह मुद्दा वर्तमान जांच के लिए असंगत है, तथापि, यदि प्राधिकारी फिर भी इसे संगत मानते हैं तो घरेलू उद्योग यह दर्शाने के लिए निर्यातित उत्पाद की पुनः बिक्री संबंधी सूचना दे सकता है कि याचिकाकर्ता की निर्यात कीमत में और अमेरिकी से संबद्ध कंपनी (उनके खर्चों के लिए समायोजन करने के बाद) के निर्यात की बिक्री कीमत में कोई वास्तविक अंतर नहीं है।
- xxxiv. जहां तक चीन जन. गण. से आयातों के कारण कोई मात्रात्मक प्रभाव न होने का संबंध है, संबद्ध आयात आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 50 प्रतिशत तक बढ़े हैं, मांग 13 प्रतिशत तक 112 मी. टन तक बढ़ी है।
- xxxv. गैर-संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है, परंतु उनकी आयात कीमत में वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध देश की आयात कीमत कम हुई है।
- xxxvi. घरेलू उद्योग की 2014-15 में कोई बिक्री नहीं थी क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई, 2015 में शुरू किया। वह 2015-16 में 26 मी. टन से बढ़कर जांच की अवधि में 132 मी. टन हो गई। घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं है और उसकी क्षमता उपयोग दर बहुत कम चल रही है। बाजार में बढ़ी हुई मांग के बाद भी संबद्ध आयात जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री से 68 प्रतिशत अधिक हैं। संबद्ध आयातों ने हमेशा दबाव बनाया है, जैसा कि घरेलू उद्योग के बिक्री आंकड़ों से देखा जा सकता है। मांग में वृद्धि के बाद भी घरेलू उद्योग उसे नहीं बेच पाया जिसका उसने उत्पादन किया। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों के कारण कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं है।
- xxxvii. कीमत कटौती कानून के तहत सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। नियम कीमत कटौती तथा कीमत न्यूनीकरण/ह्रास का संदर्भ देते हैं और उन्हें "अथवा" में रखते हैं जिसका अर्थ विकल्प है। इस प्रकार, दावे के विपरीत कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास बराबर स्तर पर हैं।
- xxxviii. वर्तमान मामले में कीमत कटौती बहुत ही वैध कारण से नकारात्मक है। याचिकाकर्ता ने एक नया व्यापारी होने के नाते ग्राहकों को आयातित उत्पाद से बदलने के लिए अनुकूल कीमतें दी हैं, परंतु निर्यातकों ने अपनी कीमतें और कम कम दीं।

- xxxix. इष्टतम लागत और क्षति रहित कीमत पर विचार करने पर याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई आरंभिक कीमतें स्वयं में क्षतिकारक थीं (याचिकाकर्ता वास्तविक लागत, कीमत, लाभ के आधार पर क्षति का दावा नहीं कर रहा है)। दूसरे मंदी का मामला होने के नाते, चार वर्ष की लंबी अवधि के लिए कोई आंकड़े नहीं हैं और इसलिए न्यूनीकरण एवं ह्रास का निर्धारण काफी कम अवधि के आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। संगत निर्धारण इष्टतम लागत और क्षतिरहित कीमत है।
- xi. क्षति पहुँचाने वाले अन्य कारकों की मौजूदगी के तर्क के संबंध में उत्तरदाता अपने दावे का औचित्य बनाने अथवा किसी अन्य कारक की मौजूदगी दर्शाने में विफल रहे हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकता है। उत्तरदाता ने "नाजुक मुद्दों" का उल्लेख नहीं किया है जिनका संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग पर स्वतंत्र रूप से प्रभाव था।
- xli. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को आयातों के कारण क्षति न होने पर भी जांच की अवधि के दौरान हानियां हो रही हैं, वास्तविक रूप से स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को उसके वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के समय से ही क्षति हो रही है और यह लगातार पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण है।
- xlii. घरेलू उद्योग का संयंत्र जांच की अवधि के दौरान मात्र 36.10 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर संचालित हो रहा था जिसे किसी उत्पादन तरीके ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए मापदंड नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है। पूरी क्षति अवधि में उत्पादन बढ़ा है। तथापि, बिक्री में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से कहीं कम थी।
- xliii. घरेलू उद्योग स्वीकार करता है कि पूरी क्षति अवधि में प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता बढ़ी है। इस प्रकार, उत्पादकता में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता।
- xliv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि न्यूनीकरण जीएफएल की अपनी कीमत संबंधी नीति के कारण है, वह गलत है क्योंकि संबद्ध देश से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम है।
- xlv. चूंकि, घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2015 से बाजार में विचाराधीन उत्पाद पेश करना शुरू किया, अतः, घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतें आयात कीमतों के लिए निर्धारण थीं।
- xlvi. घरेलू उद्योग की कम कीमतों के लिए उत्तरदायी एकमात्र कारक संबद्ध देश से उत्पाद की आयात कीमतें और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत हैं।
- xlvii. अलाभप्रद कीमत के तर्क के संबंध में यह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने से गहन पाटन है जिससे याचिकाकर्ता कीमतें कम करने के लिए मजबूर हुए हैं।
- xlviii. लागत में कमी इनपुट लागत में गिरावट के कारण नहीं थी बल्कि उत्पादन में वृद्धि और प्रति यूनिट निर्धारित लागतों में कमी के कारण थी।
- xlix. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि ह्रास की मात्रा गलत है, क्योंकि निर्यातों के कारण क्षति अलग से नहीं है; घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए क्षति संबंधी अनुरोध घरेलू बिक्री के आधार पर हैं, न कि निर्यातों के आधार पर।
- i. घरेलू उद्योग को उसकी मौजूदगी के अनुसार देखे जाने की आवश्यकता है न कि आदर्श स्थिति में, जैसा कि निप्पोन जियोन कं. लि., जापान तथा अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [1997 (96) ईएलटी 126 (टी)] में अधिकरण द्वारा माना गया है।
- ii. अगले वर्षों की तुलना में आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की स्थिति घरेलू उद्योग की विद्यमान स्थिति का सही-सही संकेतक नहीं है क्योंकि जीएफएल ने संबद्ध सामानों का अपना उत्पादन हाल ही में शुरू किया है और बाजार में एक नया व्यापारी है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

83. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए विभिन्न संगत अनुरोधों को नोट करते हैं जिन पर इस भाग में बाद में कार्रवाई की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी, दोनों के आधार पर आवेदन पत्र दायर किया था जैसा कि जांच की शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित किया गया है।

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी के कारण क्षति सिद्ध करना समय-समय पर डब्ल्यू टी ओ वार्ता समूह नियमों के तहत विचार-विमर्श का पहलू रहा है। तथापि, वास्तविक मंदी सिद्ध करने के लिए उपयुक्त मानदंडों के कूटीकरण में सहमति नहीं हो पाई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित दस्तावेजों में कुछ सुझाव डब्ल्यू टी ओ में बैठकों में दिए गए थे।

(i) 30 नवंबर, 2007 का दस्तावेज सं. टीएन/टीएल/डब्ल्यू/213-पाटनरोधी और एससीएम करारों का समेकित अध्यक्षीय पाठ का प्रारूप, निम्नलिखित रूप में अनुच्छेद 3.9 को जोड़कर करार में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था:

3.9क घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी का निर्धारण तथ्य के आधार पर होगा और न कि केवल आरोप अटकलबाजी अथवा सुदूर संभावना पर होगा। किसी उद्योग को स्थापना में तभी माना जाएगा जब किसी समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन करने के लिए संसाधनों की पर्याप्त एवं उपयुक्त प्रतिबद्धता की गई हो, इसमें आयातक सदस्य के क्षेत्र में पहले से उत्पादित उत्पाद शामिल नहीं होगा, परंतु वह उत्पाद शामिल होगा जिसका उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है और वाणिज्यिक मात्रा<sup>1</sup> में अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। यह निर्धारण करने में कि क्या एक उद्योग स्थापना में है और उस उद्योग की स्थापना पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच करने में प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ संस्थापित क्षमता, किए गए निवेशों और प्राप्त किए गए वित्त तथा व्यावहार्यता अध्ययनों, निवेश योजनाओं और बाजार अध्ययनों<sup>2</sup> से संबंधित साक्ष्य को ध्यान में रख सकते हैं।

(ii) 13 मई, 2005 के दस्तावेज संख्या टीएन/आरएन/जीईएन/40, 31 मार्च, 2015 मिश्र के सं. टीएन/आरएन/ई/105 तथा सं. टीएन/आरएन/डब्ल्यू/175 में एक डब्ल्यूटीओ सदस्य देश ने यह प्रस्ताव किया है कि :

"परिभाषा ..... यह स्पष्ट करने के लिए अनुच्छेद 3 की पाद टिप्पणी 9 के वर्तमान पाठ को स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि "वास्तविक मंदी" की संकल्पना उन उद्योगों तक सीमित नहीं है, जो शून्य से स्थापित हैं बल्कि उन सभी घरेलू उद्योगों पर लागू होनी चाहिए जो विकास के सीमित स्तर और/अथवा नई संगठन के रूप में उल्लिखित किए जाते हैं"

..... उन उद्योगों पर "वास्तविक मंदी" परीक्षण सीमित न करना महत्वपूर्ण है जो नए नए स्थापित हैं; अतः विशेष ध्यान एम्ब्रायनिक, पुनर्गठन और नए-नए निजी उद्योगों पर दिया जाना चाहिए जिन्हें स्थापना की प्रक्रिया में उद्योगों के रूप में माना जाना चाहिए। यह मामला विकासशील देश सदस्यों से विशेष रूप से संबंधित है क्योंकि उनके घरेलू उद्योग मुश्किल से ही विकसित हैं।

परीक्षण ..... अनुच्छेद की पाद टिप्पणी 9 में निर्धारित है कि क्षति जिसका अर्थ वास्तविक मंदी भी होगा, का निर्वचन करार के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अतः मिश्र समझता है कि जांचकर्ता प्राधिकारियों को वास्तविक मंदी के मामले में अनुच्छेद 3.4 में सूचीबद्ध कारकों पर भी विचार करना चाहिए और उनका मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका समर्थन मैकिस्को-एचएफसीएस में पैनल के जांच परिणाम द्वारा भी किया गया है। उस मामले में पैनल ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3.7 उन अतिरिक्त कारकों को निर्धारित करता है जिन पर क्षति के खतरे के मामले में विचार किया जाना चाहिए परंतु अनुच्छेद 3.4 की अपेक्षाओं के अनुसार घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने के दायित्व को समाप्त नहीं करता। दूसरे शब्दों में पैनल के अनुसार जांचकर्ता प्राधिकारियों को क्षति के खतरे के मामले में अनुच्छेद 3.7 में सूचीबद्ध कारकों तथा अनुच्छेद 3.4 में सूचीबद्ध कारकों, दोनों पर विचार करना चाहिए। पैनल ने स्पष्ट किया कि यह निष्कर्ष अनुच्छेद के पाठ द्वारा अधिदेशित है जो समग्र रूप से क्षति के निर्धारण से संबंधित है जो किसी घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक क्षति, वास्तविक क्षति के खतरे, अथवा वास्तविक मंदी के रूप में परिभाषित है ..... "

(iii) दस्तावेज सं. जी/एडीपी/एचजी/डब्ल्यू/168 - सचिवालय, कोरिया द्वारा नोट, एक डब्ल्यूटीओ सदस्य देश ने विचार विमर्श किया है कि:

"1.2.2 (कोरिया) पाद टिप्पणी 9 के तहत "वास्तविक" क्षति और "वास्तविक" मंदी दोनों में "वास्तविक" निर्धारित करने में मानदंड"

प्राधिकारी अनुच्छेद 3.2 के तहत क्रमशः पाटित आयातों में वृद्धि, पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती और पाटित आयातों द्वारा न्यूनीकरण प्रभाव की मात्रा पर विचार करेंगे।

अनुच्छेद 3.4 पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच करने में प्राधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए संगत आर्थिक कारकों और तत्वों के चार समूहों का उदाहरण देता है। एक वस्तुपरक सिद्धांत कार्यसूची मद

<sup>1</sup> तथापि, प्राधिकारी इस पर विचार कर सकते हैं कि कोई उद्योग घरेलू समान उत्पाद के स्थापित उत्पादकों की मौजूदगी पर भी स्थापना में है, यदि वे स्थापित उत्पादक पर्याप्त मात्रा में प्रश्नगत उत्पाद के लिए घरेलू मांग पूरी करने में समर्थ नहीं हैं; वरन् कि किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई उद्योग स्थापना में होने के लिए माना जाएगा। यदि स्थापित उत्पादकों की सामूहिक उत्पादन क्षमता प्रश्नगत उत्पाद के लिए घरेलू मांग के 10 प्रतिशत से अधिक है।

<sup>2</sup> सदस्य मानते हैं कि संभावित वास्तविक मंदी की जांच स्थापित होने के लिए उद्योग के प्रयासों पर पाटित आयातों के प्रभाव से संबंधित है और यह कि इस प्रकार का प्रभाव निष्पादन में वास्तविक अथवा संभावित गिरावटों में नहीं दर्शाया जा सकता। फिर भी प्राधिकारी आंकड़ों की मौजूदगी की सीमा तक प्रश्नगत घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी की जांच के लिए संगत सभी आर्थिक कारकों और तत्वों के संबंध में उपलब्ध सूचना की सीमा तक मूल्यांकन करेंगे।

सं. 3 के रूप में उसी कारण से सिद्ध किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या प्रत्येक समूह का प्रत्येक घटक सामूहिक रूप से अलग-अलग रहा है अथवा क्या समूह का भारित औसत एक सामान्य सूचकांक के रूप में कार्य कर सकता है”।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल्यांकन के विभिन्न बताए गए मानदंडों में से घरेलू उद्योग के विकास के स्तर के लिए वास्तविक मंदी की मौजूदगी तथा मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए अनुच्छेद 3.4 के तहत सूचीबद्ध मानदंडों के विरुद्ध उपयुक्त विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

85. प्राधिकारी ने कुछ मामलों में घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी के कारण क्षति का विश्लेषण विगत में किया है। इस प्रकार की क्षति का विश्लेषण समग्र क्षति का अभिन्न भाग रहा है। इन मामलों में 13 फरवरी, 2018 के चीन जन.गण., मलेशिया, इंडोनेशिया और यूरोपीय यूनियन से विनीरड इंजीनियर्ड वूडन फ्लोरिंग, 19 दिसंबर, 2017 का चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड 12 जुलाई, 2017 का यूरोपीय संघ, कोरिया जन.गण. और थाइलैंड से 1500 सीरीज और 1700 सीरीज के स्टाइरीन बूटाडिन रबड़ (एसबीआर), 10 मई, 2013 के चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “इंशुलेशन बोर्ड, लेमिनेटेड फाइबर बोर्ड तथा उन बोर्डों को छोड़कर जो रेजिन” अथवा अन्य आर्गेनिक तत्वों से बाउंडेड नहीं है, 6 एमएम से कम की मोटाई वाले लिगनियस फाइबर बोर्डों अथवा रेजिन अथवा अन्य आर्गेनिक संस्टेंट बाउंडेड वूड, 29 जुलाई, 2011 के चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी फ्लैक्स फिल्म, 2 जुलाई, 2003 का रूस, यूक्रेन और कोरिया जन.गण. से इंडक्शन हार्डन फोर्ड स्टील रॉल, चीन जन गण और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी (-) पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल गिलीसीन मिथाइल पोटेथियम दाने साल्ट और चीन जन.गण. तथा सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी (-) पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल गिलीसीन बेस शामिल हैं।

86. विश्लेषण के मानदंड व्यापक रूप से क्षमता उपयोग, बिक्री और लाभप्रदता रहे हैं जो वास्तविक क्षति के लिए भी मानदंड माने गए हैं। तथापि, वास्तविक मंदी सिद्ध करने के बाद प्राधिकारी ने इन मानदंडों की जांच उद्योग के विकास की वृद्धि और स्तर तक की है। प्राधिकारी ने कुछ मामलों में 5 वर्ष की भी सामान्य अवधि से कम उपायों की सिफारिश भी की है। क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में प्रकटन पश्चात अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम में कार्रवाई की गई है।

87. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित विभिन्न मात्रात्मक और कीमत संबंधी मानदंडों का मूल्यांकन और विश्लेषण किया है (वास्तविक क्षति तथा वास्तविक मंदी) जो नीचे तालिका में दी गई है।

(क) **मांग और बाजार हिस्सा**

88. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग अथवा खपत निम्नलिखित तालिका-1 में दर्शाए गए अनुसार सभी स्रोतों से आयातों तथा भारतीय उत्पादक की घरेलू बिक्री की मात्रा के रूप में निर्धारित की गई है।

**तालिका 1 : मांग और बाजार हिस्सा**

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
<b>मांग (मी.ट.)</b>					
घरेलू उद्योग की बिक्री	वास्तविक	-	26	108	131
घरेलू उद्योग की बिक्री	सूचीबद्ध	-	100	310	376
चीन से आयात	मी.ट.	271	300	352	407
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	570	402	421	415
<b>कुल मांग</b>	<b>सूचीबद्ध</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>105</b>	<b>113</b>
<b>मांग में बाजार हिस्सा %</b>					
घरेलू उद्योग की बिक्री	सूचीबद्ध	-	100	341	383
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	-	-	-	-
संबद्ध देश- चीन	सूचीबद्ध	100	128	124	132
अन्य देशों का हिस्सा	सूचीबद्ध	100	81	70	64

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है, जो आधार वर्ष 2014-15 में (\*\*\* एम टी) से जांच की अवधि में \*\*\* एम टी हुई है जो 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है अर्थात् प्रतिवर्ष लगभग 3 प्रतिवर्ष है। वर्ष 2015-16 में मांग में थोड़ी सी गिरावट आई है जो चीन को छोड़कर अन्य देशों से कम हुए आयातों में भी दर्शायी गई है।

90. घरेलू मांग/खपत में संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा क्षति की अवधि में 2014-15 में \*\*\*% से बढ़कर जांच की अवधि में \*\*\*% हो गया। चूंकि विगत में भारत में संबद्ध सामानों का कोई उत्पादन नहीं था अतः पूरी मांग आयातों से पूरी की जा रही थी। याचिकाकर्ता ने संबद्ध सामानों का वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई, 2015 में शुरू किया और उनका बाजार हिस्सा 2015-16 में \*\*\*% से बढ़कर जांच की अवधि में \*\*\*% हो गया।

#### (ख) संबद्ध देशों की आयात मात्रा और हिस्सा

91. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। भारत में आने वाले कुल आयातों में आयातों की मात्रा और बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका-2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2: आयात विवरण

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
<b>आयात मात्रा</b>					
संबद्ध देश- चीन	मी.ट.	271	300	352	407
अन्य देश	मी.ट.	570	402	421	415
कुल आयात मात्रा	मी.ट.	<b>841</b>	<b>702</b>	<b>773</b>	<b>822</b>
आयातों में बाजार हिस्सा					
चीन	%	32.25	42.75	45.56	49.50
अन्य देश	%	67.75	57.25	54.44	50.50
<b>कुल आयात मात्रा में कुल हिस्सा</b>	<b>%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
के अनुपात में चीनी आयात					
याचिकाकर्ता उत्पादन	सूचीबद्ध	-	100	50	50
खपत	सूचीबद्ध	100	128	124	132
कुल आयात	%	32.25	42.75	45.56	49.50
याचिकाकर्ता बिक्री	सूचीबद्ध	-	100	28	27

- घरेलू उद्योग का हिस्सा गैर- पाटित स्रोतों से आयातों के विस्थापन के अनुरूप बढ़ा।
- संबद्ध देश से आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से और क्षति की अवधि में कुल आयातों तथा खपत के संबंध में भी बढ़ा।
- अन्य देशों से आयात पूर्ण दृष्टि से और संबंधित दृष्टि से क्षति की अवधि में कम हुए हैं।

#### (ग) आयात कीमत की प्रवृत्ति

92. निम्नलिखित तालिका 3 (क), 3(ख) और 3 (ग) क्षति की अवधि में क्रमशः समग्र रूप में, पीसीएन आधार और तिमाही आधार पर आयात कीमत की प्रवृत्ति दर्शाती हैं।

तालिका 3(क): आयात कीमतों में प्रवृत्ति

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई*
संबद्ध देश- चीन	रु./ किग्रा.	951	1,037	922	923
अन्य देश	रु./ किग्रा.	1,595	1,647	1,740	1,757

तीसरे देशों की कीमत % की तरह चीनी कीमत	%	60%	63%	53%	53%
--	---	-----	-----	-----	-----

तालिका 3(ख): क्षति अवधि के दौरान पीसीएनवार आयात

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई*
<b>कोपोलीमर प्री-कंपाउंड</b>	रु./ किग्रा.	1,138	1,117	1,097	1,114
चीन – संबद्ध देश	रु./ किग्रा.	959	974	908	934
अन्य देश (हिस्सा => 3%)	रु./ किग्रा.	1,295	1,298	1,504	1,647
अन्य देश(हिस्सा < 3%)	रु./ किग्रा.	967	1,476	954	1,151
<b>को पॉलीमर कच्ची गोंद</b>	रु./ किग्रा.	1,307	1,661	1,782	1,359
चीन – संबद्ध देश	रु./ किग्रा.	621	-	-	666
अन्य देश (हिस्सा => 3%)	रु./ किग्रा.	1,510	1,661	1,782	1,732
अन्य देश(हिस्सा < 3%)	रु./ किग्रा.	-	-	-	-
<b>टरपोलीमर बिसफेनोल कच्ची गोंद</b>	रु./ किग्रा.	1,689	1,741	1,724	1,663
चीन – संबद्ध देश	रु./ किग्रा.	-	-	-	-
अन्य देश (हिस्सा => 3%)	रु./ किग्रा.	1,741	1,847	1,775	1,704
अन्य देश(हिस्सा < 3%)	रु./ किग्रा.	1,225	1,074	1,187	1,183
<b>ट्रीपोलीमर पेरोक्साइड अपरिष्कृत कच्ची गोंद</b>	रु./ किग्रा.	1,990	2,450	2,051	1,940
चीन – संबद्ध देश	रु./ किग्रा.	-	-	-	-
अन्य देश (हिस्सा => 3%)	रु./ किग्रा.	1,995	2,449	2,048	1,952
अन्य देश(हिस्सा < 3%)	रु./ किग्रा.	1,650	3,651	2,099	1,796
<b>टरपोलीमर बिसफेनोल अपरिष्कृत प्री-कंपाउंड</b>	रु./ किग्रा.	1,754	2,066	1,699	1,747
चीन – संबद्ध देश	रु./ किग्रा.	-	2,066	-	-
अन्य देश (हिस्सा => 3%)	रु./ किग्रा.	1,754	2,064	1,699	1,747
अन्य देश(हिस्सा < 3%)	रु./ किग्रा.	-	-	-	-
<b>अज्ञात ग्रेड्स / प्रकार</b>	रु./ किग्रा.	1,245	1,461	1,424	1,411
चीन – संबद्ध देश	रु./ किग्रा.	948	1,103	963	897
अन्य देश (हिस्सा => 3%)	रु./ किग्रा.	1,686	1,800	1,855	1,828
अन्य देश(हिस्सा < 3%)	रु./ किग्रा.	842	1,028	1,316	1,558
<b>सकल योग</b>	रु./ किग्रा.	1,388	1,386	1,367	1,344
चीन – संबद्ध देश	रु./ किग्रा.	951	1,037	922	923
अन्य देश (हिस्सा => 3%)	रु./ किग्रा.	1,615	1,669	1,754	1,772
अन्य देश(हिस्सा < 3%)	रु./ किग्रा.	1,146	1,082	1,384	1,428

**तालिका 3(ग): घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत के बाद आयात कीमतों की तिमाही प्रवृत्ति**

विवरण	सीआईएफ कीमत संबद्ध देश— चीन	सीआईएफ कीमत अन्य देश	तीसरे देशों की कीमत के % रूप में चीनी कीमत
इकाई	रू./ किग्रा.	रू./ किग्रा.	%
2015-16 ति.2	882	1,649	53%
2015-16 ति.3	1,030	1,784	58%
2015-16 ति.4	1,025	1,694	61%
2016-17 ति.1	931	1,591	59%
2016-17 ति.2	900	1,835	49%
2016-17 ति.3	938	1,899	49%
2016-17 ति.4	909	1,691	54%
2017-18 ति.1	930	1,646	57%

उपर्युक्त तालिकाएं यह दर्शाती हैं कि:

- चीन के लिए आयात कीमत अन्य देशों से आयात कीमत के 50-60 प्रतिशत की दर पर रही हैं। इसके अतिरिक्त 2016-17 में चीन से आयात कीमत घरेलू उद्योग द्वारा जुलाई, 2015 में उत्पादन शुरू किए जाने के बाद 11 प्रतिशत तक कम हो गई। यह कीमत व्यवहार अन्य देशों से कीमत व्यवहार के विपरीत है।
- 3 प्रतिशत से कम हिस्से वाले देशों से आयात कीमतें भी चीन से आयात कीमतों की अपेक्षा काफी अधिक हैं।

**झ. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंडों की जांच**

93. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण यहां निम्नलिखित रूप में किया जाता है:-

**(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री**

94. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित तालिका 5 (क) और 5(ख) में दिए गए अनुसार है :-

**तालिका 5(क): उत्पादन और बिक्री मापदंड**

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
क्षमता	वास्तविक(मी.ट.)	-	495	660	660
क्षमता	सूचीबद्ध	-	100	100	100
उत्पादन	वास्तविक(मी.ट.)	-	86	200	235
उत्पादन	सूचीबद्ध	-	100	175	205
क्षमता उपयोग	वास्तविक (%)	-	17.31	30.36	35.53
क्षमता उपयोग	सूचीबद्ध	-	100	175	205
घरेलू बिक्री	वास्तविक(मी.ट.)	-	26	108	131
घरेलू बिक्री	सूचीबद्ध	-	100	310	376



तालिका 5(ख): तिमाहीवार उत्पादन और बिक्री मापदंड

उत्पादन	क्षमता (मी.ट.)	उत्पादन (मी.ट.)	क्षमता उपयोग (%)	बिक्री (मी.ट.)	
				घरेलू	निर्यात
अवधि	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध
2015-16 ति2	100	100	100	100	100
2015-16 ति3	100	50	50	263	244
2015-16 ति4	100	84	84	349	906
2016-17 ति1	100	73	73	595	250
2016-17 ति2	100	141	141	763	355
2016-17 ति3	100	181	181	555	2791
2016-17 ति4	100	153	153	1031	5561
2017-18 ति1	100	166	166	1228	3013

(i) उत्पादन और क्षमता प्रवृत्तियां (वार्षिक/तिमाही) यह दर्शाती हैं कि उत्पादन और क्षमता दोनों सामान्यतः बढ़ती हुई हैं परंतु \*\*\*% पर सर्वोत्तम तिमाही क्षमता उपयोग के साथ कम हैं, यद्यपि, घरेलू उद्योग को लगभग दुगुने पर प्रचालित करने के लिए देश द्वारा दिए गए अवसर में अंतराल क्षमता उपयोग दर्शाता है।

(ii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री ग्राहकों के लिए दोहराई गई प्रकृति की थी और उन्होंने फिर भी काफी निर्यात किए हैं। अतः कम बिक्री के लिए बाधक कारक के रूप में गुणवत्ता का मुद्दा नहीं दिखाई देता।

ग्राहक वार

#### (ख) मांग में बाजार हिस्सा

95. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरेलू मांग/खपत में संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा क्षति की अवधि में बढ़ा है जो \*\*\*% से बढ़कर \*\*\*% हो गया। चूंकि विगत में भारत में संबद्ध सामानों का कोई उत्पादन नहीं था, अतः पूरी मांग आयातों द्वारा पूरी की जा रही थी। याचिकाकर्ता ने संबद्ध सामानों का वाणिज्यिक उत्पाद, जुलाई, 2015 में शुरू किया और उनका बाजार हिस्सा 2015-16 में \*\*\*% से बढ़कर जांच की अवधि में \*\*\*% हो गया।

#### (ग) मालसूची

96. मालसूची के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित तालिका 6(क) और 6(ख) में दर्शाया गया है :

तालिका 6(क): मालसूची प्रवृत्ति

विवरण (इकाई मी.ट. में)	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
प्रारंभिक	सूचीबद्ध	-	-	100	107
अंतिम	सूचीबद्ध	-	100	203	210
औसत	सूचीबद्ध	-	100	303	317

तालिका 6(ख): मालसूची में तिमाही प्रवृत्ति

विवरण	प्रारंभिक स्टॉक (मी.ट.)	अंतिम स्टॉक (मी.ट.)
	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध
2015-16 ति2	-	100
2015-16 ति3	100	123

2015-16 ति4	123	166
2016-17 ति1	166	178
2016-17 ति2	178	246
2016-17 ति3	246	352
2016-17 ति4	352	337
2017-18 ति1	337	349

वार्षिक और तिमाही दोनों का अंतिम स्टॉक बिक्री के लगभग 5 माह होने के नाते औसत मालसूची में एकत्रित स्टॉक की प्रगति दर्शाता है।

#### ट. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

97. कीमतों पर पाटित आयातों पर प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन पाटित आयातों का कीमतों का न्यूनीकरण करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने पर प्रभाव है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच लागत से की गई है। कीमत न्यूनीकरण प्रभाव का विश्लेषण कीमत मंदी के रूप में उसके प्रदर्शन के संबंध में किया गया है जिससे घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद के ईष्टतम स्तर तक लाने के लिए उत्पादन रुका है।

#### (क) पाटित आयातों का कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभाव

98. यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों पर न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव डाल रहे हैं जो कीमत वृद्धि के रोकते हैं फिर जो अन्यथा उचित रूप से और पर्याप्त रूप से हुई होती, प्राधिकारी निम्नलिखित तालिका 4 (क) से 4 (घ) में दर्शाए गए अनुसार क्षति की अवधि में आयातों की लागत कीमत और पहुंच मूल्य में परिवर्तनों को नोट करते हैं।

तालिका 4(क): लागत/कीमत प्रवृत्ति

विवरण (इकाई रु./किग्रा) में	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई*
बिक्री की लागत(वास्तविक)	सूचीबद्ध	-	100	83	81
बिक्री की लागत (ईष्टतम)	सूचीबद्ध	-	100	86	85
बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	-	100	88	87
पहुंच मूल्य	रु./किग्रा.	1,035	1,128	1,003	1,004
बिक्री लागत के % के अनुसार बिक्री कीमत (वास्तविक)	सूचीबद्ध	-	100	105	106
बिक्री लागत के % के अनुसार बिक्री कीमत (ईष्टतम)	सूचीबद्ध	-	100	101	101
पहुंच मूल्य के % की तरह पहुंच मूल्य	सूचीबद्ध	-	100	99	98

\*निर्यातक आंकड़ों के आधार पर \*\*\*% के सर्वोत्तम क्षमता उपयोग का प्रयोग करते हुए।

तालिका 4(ख): क्षति की अवधि में कीमत कटौती

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई*
आयात मात्रा	मी.ट.	271	300	352	407
आयातों की पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	1,035	1,128	1,003	1,004

निवल बिक्री प्राप्ति (रू./किग्रा.)	सूचीबद्ध	-	100	88	87
कीमत कटौती (रू./किग्रा.)	सूचीबद्ध	-	100	97	110
कीमत कटौती (%)	रेंज	-	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक

तालिका 4(ग): कीमत कटौती की तिमाही प्रवृत्ति

अवधि	बिक्री कीमत (रू./किग्रा.)	पहुंच मूल्य	कीमत कटौती	
यूओएम	सूचीबद्ध	रू./किग्रा.	सूचीबद्ध	रेंज
2015-16 ति2	100	960	100	10-20
2015-16 ति3	90	1,121	-44	नकारात्मक
2015-16 ति4	83	1,116	-89	नकारात्मक
2016-17 ति1	83	1,013	-29	नकारात्मक
2016-17 ति2	75	979	-65	नकारात्मक
2016-17 ति3	76	1,020	-81	नकारात्मक
2016-17 ति4	77	989	-57	नकारात्मक
2017-18 ति1	77	1,012	-70	नकारात्मक

तालिका 4(घ): जांच की अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री

विवरण	रू./किग्रा.	अम.डॉ./किग्रा.
		67.40
क्षतिरहित कीमत (एनआईपी)	***	***
पहुंच मूल्य	1,004.22	14.90
कम कीमत पर बिक्री	***	***
कम कीमत पर बिक्री (% रेंज)	10-20	10-20

- (i) यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की लागत, बिक्री कीमत तथा चीन से आयातों का पहुंच मूल्य भी क्षति की अवधि में कम हुआ है।
- (ii) क्षति की अवधि की पहली तिमाही में जब घरेलू उद्योग ने उत्पादन शुरू किया था, घरेलू उद्योग की आरंभिक बिक्री कीमत चीन से आयातों से पहुंच मूल्य से अधिक नोट की गई है। पहली तिमाही में कीमत कटौती बाद में चीन से पहुंच मूल्य की अपेक्षा क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की सभी बाद की तिमाही बिक्री कम होने के नाते कीमत न्यूनीकरण में प्रदर्शित हुई पाई गई है। घरेलू उद्योग ने क्रमिक रूप से घरेलू बाजार में आपूर्ति के संदर्भ में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अपना उत्पादन बढ़ाया। तथापि, यह तदनुसारी कीमत ह्रास की प्रवृत्ति के साथ होना नोट किया गया है।
- (iii) क्षति की अवधि की पहली तिमाही को छोड़कर कीमत कटौती बाद में पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक रही जो काफी कीमत मंदी का उदाहरण है। कीमत न्यूनीकरण चीन से आयातों के पहुंच मूल्य के \*\*\* - \*\*\*% होने के नाते और मानक लागत के केवल \*\*\*% शामिल करके घरेलू उद्योग की कीमत बिक्री की वसूली द्वारा भी दर्शायी गई है।

**(घ) लाभ, पीबीआईटी, निवेश पर आय और नकद प्रवाह**

99. लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका 7(क) से 7(घ) में वार्षिक और तिमाही के आधार पर क्षति की अवधि के लिए किया गया है।

**तालिका 7(क): लाभप्रदता मापदंड(वार्षिक)**

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
बिक्री की लागत(वास्तविक) रु./किग्रा.	सूचीबद्ध	-	100	83	81
बिक्री कीमत- रु./किग्रा.	सूचीबद्ध	-	100	88	87
लाभ/(हानि) प्रति इकाई- रु./किग्रा.	सूचीबद्ध	-	(100)	(74)	(70)
लाभ/(हानि) - लाख रुपए	सूचीबद्ध	-	(100)	(230)	(263)
नकद लाभ- लाख रुपए	सूचीबद्ध	-	(100)	(162)	(270)
पीबीआईटी - लाख रुपए	सूचीबद्ध	-	(100)	(233)	(266)
आरओसीई- घरेलू - %	सूचीबद्ध	-	(100)	(200)	(235)

**तालिका 7(ख): लाभप्रदता मापदंड (तिमाही)**

अवधि	बिक्री की लागत (वास्तविक) (रु.किग्रा.)	बिक्री कीमत (रु.किग्रा.)	लाभ/हानि (रु.किग्रा.)	लाभ/ (हानि) (रु.किग्रा.)	आरओआई (%)
यूओएम	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध
2015-16 ति2	100	100	-100	-100	-100
2015-16 ति3	100	90	-127	-335	-347
2015-16 ति4	100	83	-149	-519	-540
2016-17 ति1	83	83	-82	-490	-440
2016-17 ति2	83	75	-106	-812	-731
2016-17 ति3	83	75	-104	-578	-520
2016-17 ति4	83	77	-101	-1,040	-937
2017-18 ति1	81	77	-92	-1,130	-1,045

\* पूरे वर्ष के लिए मूल्यांकित की गई बिक्री लागत भी उसी वर्ष के अंतर्गत तिमाही अवधियों के लिए दी गई है।

**तालिका 7(ग): नियोजित पूंजी पर आय (वार्षिक)**

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
बिक्री की लागत (ईष्टतम) - रु./कि.ग्रा.	सूचीबद्ध	-	100	87	85
बिक्री कीमत- रु./कि.ग्रा.	सूचीबद्ध	-	100	88	87
लाभ/(हानि) प्रति इकाई- रु./किग्रा.	सूचीबद्ध	-	(100)	-82	-80
लाभ/(हानि) - रु./कि.ग्रा.	सूचीबद्ध	-	(100)	(255)	(301)
नकद लाभ- लाख रुपए	सूचीबद्ध	-	(100)	(140)	(318)
पीबीआईटी - रु./कि.ग्रा.	सूचीबद्ध	-	(100)	(260)	(307)
आरओसीई - घरेलू - %	सूचीबद्ध	-	(100)	(298)	(360)

तालिका 7(घ): नियोजित पूंजी पर आय (तिमाही)

अवधि	बिक्री की लागत रु./कि.ग्रा.	बिक्री कीमत रु./कि.ग्रा.	लाभ/हानि (रु./किग्रा)	लाभ/(हानि) (लाख रुपए)	आरओई (%)
यूओएम	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध
2015-16 ति2	100	100	-100	-100	-100
2015-16 ति3	100	90	-156	-412	-448
2015-16 ति4	100	83	-201	-702	-771
2016-17 ति1	87	83	-105	-624	-592
2016-17 ति2	87	75	-155	-1,184	-1,127
2016-17 ति3	87	75	-151	-836	-794
2016-17 ति4	87	77	-144	-1,481	-1,412
2017-18 ति1	85	77	-133	-1,631	-1,597

दो प्रमुख लाभप्रदता तत्व अर्थात् प्रति युनिट हानि और नियोजित पूंजी पर आय जिनका मूल्यांकन वास्तविक बिक्री लागत तथा बिक्री की मानक लागत के आधार पर किया गया है, क्रमशः हानियाँ और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्शाते हैं। हानियों/ नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय की मात्रा वास्तविक बिक्री लागत पर विचार करने पर काफी अधिक है। यदि आरंभिक समस्याओं को \*\*\*% क्षमता उपयोग पर विचार करके उपयुक्त रूप से कम किया जाए तो फिर भी ये दो मानदंड पर्याप्त रूप से प्रतिकूल रहते हैं। कीमत न्यूनीकरण उपयुक्त क्षमता उपयोग बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग के लिए नकारात्मक रहते हुए कीमत कटौती के साथ नोट किया गया है जो कीमत मंदी दर्शाते हुए लाभप्रदता को नष्ट करना दर्शाता है।

#### (ड.) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

100. निम्नलिखित तालिका 8 से यह देखा जा सकता है कि प्रतिदिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता क्षति की अवधि में बढ़ती रही है।

तालिका 8: उत्पादकता मानदंड

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या – सं.	सूचीबद्ध	-	100	200	222
मजदूरी – लाख रुपए	सूचीबद्ध	-	100	155	171
प्रति दिवस उत्पादकता (मी.ट./दि.)	सूचीबद्ध	-	100	156	182
प्रति कर्मचारी उत्पादकता (मी.ट./दि.)	सूचीबद्ध	-	100	117	123

#### (च) वृद्धि

101. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि उत्पादन, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा और क्षमता उपयोग के संदर्भ में सकारात्मक रही है। तथापि, घरेलू उद्योग को हमेशा वित्तीय हानियाँ होती रही हैं और लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में उसकी वृद्धि नकारात्मक रही है।

विवरण % में	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
निवल उत्पादन	सूचीबद्ध	-	-	100	25
घरेलू बिक्री मात्रा	सूचीबद्ध	-	-	100	23

विवरण % में	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
घरेलू बिक्री की लागत	सूचीबद्ध	-	-	(100)	(15)
घरेलू बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	-	-	(100)	(12)
औसत स्टॉक	सूचीबद्ध	-	-	100	7

### (छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

102. प्राधिकारी मानते हैं कि नकारात्मक लाभप्रदता नकद प्रवाह, आय, बढ़ी हुई हानियों से पूंजी निवेश जुटाने में घरेलू उद्योग की क्षमता प्रभावित होने की संभावना है।

### (ज) पाटन का स्तर और पाटन मार्जिन (डीएम)

103. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश के आयात पाटित कीमतों पर देश में आ रहे हैं और संबद्ध देश से पाटन मार्जिन काफी अधिक है।

### (झ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

104. संबद्ध देश से आयात कीमतों की जांच, पाटित आयातों को छोड़कर वे कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं आदि यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम है। घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2015 से बाजार में विचाराधीन उत्पाद पेश करना शुरू किया है और घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतें आयात कीमतों के लिए निर्धारण थीं। उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के सामने आई कीमत ह्रास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं हो सकता। कोई परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग एकमात्र उत्पादक है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की कम कीमतों के लिए एकमात्र उत्तरदायी कारक संबद्ध देश से उत्पाद की आयात कीमतें हैं।

### (ट) क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

105. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य से की जाती है और इस प्रकार निकाला गया क्षति मार्जिन निम्नलिखित है :

क्र. सं.	उत्पादक	निर्यातक	क्षति मार्जिन अम.डॉ./किग्रा.	क्षति मार्जिन - %	क्षति मार्जिन रेंज- %
1	मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं., चीन जन. गण.	सॉल्वे (शंघाई) कं. लि., चीन जन. गण.	***	***	30-40
2	डेकन फ्लोरोकेमिकल्स (चाइना) कं. लि., चीन जन. गण.	उनी-एलियांस लिमिटेड, चीन जन. गण.	***	***	0-10
3	झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि., चीन जन. गण.	झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि., चीन जन. गण.	***	***	30-40
4	चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टमर्स कं. लि., चीन जन. गण.	चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टमर्स कं. लि., चीन जन. गण.	***	***	20-30
5	इनर मंगोलिया 3एफ, चीन जन. गण.	शंघाई 3एफ, चीन जन. गण.	***	***	20-30
6	रेजीड्यूअल/ अन्य असहयोगी निर्यातक/उत्पादक		***	***	50-60

शेष श्रेणी के लिए इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त पीसीएन की एन आई पी और न्यूनतम पहुंच मूल्य पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के बीच निर्धारित उच्चतम क्षति मार्जिन पर विचार किया है।

**(क) जांच की अवधि के पश्चात- आर्थिक मापदंड**

विवरण	इकाई	पोस्ट पीओआई(जुलाई'17- दिसं'17)	वार्षिकीकृत (प्रोस्ट पीओआई )
आयात मात्रा	मी.ट.	<b>417</b>	<b>834</b>
संबद्ध देश – चीन	मी.ट.	238	476
अन्य देश	मी.ट.	179	359
सीआईएफ आयात कीमत			
संबद्ध देश – चीन	रु./किग्रा.	950	950
अन्य देश	रु./किग्रा.	1640	1640
तीसरे देशों के प्रतिशत के अनुसार चीनी कीमतें	%	58%	58%
आयात मात्रा में बाजार हिस्सा			
संबद्ध देश – भारत	%	57.02%	57.02%
अन्य देश	%	42.98%	42.98%
भारत में मांग/खपत (मी ट.)	सूचीबद्ध	<b>120</b>	<b>120</b>
घरेलू उद्योग की बिक्री (मी ट.)	सूचीबद्ध	681	681
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री (मी.ट.)	सूचीबद्ध	-	-
चीन से आयात	मी.ट.	238	476
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	179	359
मांग में बाजार हिस्सा %			
घरेलू उद्योग का हिस्सा	सूचीबद्ध	490%	490%
अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा	%	-	-
संबद्ध देश का हिस्सा – चीन	सूचीबद्ध	146%	146%
अन्य देशों का हिस्सा	सूचीबद्ध	52%	52%
पहुंच आयात कीमत			
संबद्ध देश – चीन	रु./किग्रा.	1033	1033
अन्य देश	रु./किग्रा.	1784	1784

घरेलू उद्योग के 2015-16 से मानदंड सूचकांक और आधार वर्ष 2014-15 से अन्य मानदंड

विवरण	इकाई	पीओआई पश्चात (जुलाई –दिसं.'17)	वार्षिकीकृत (पीओआई पश्चात )
क्षमता	वास्तविक(मी.ट.)	330	660
क्षमता	सूचीबद्ध	100	100
उत्पादन	वास्तविक(मी.ट.)	164	329
उत्पादन	सूचीबद्ध	384	384

क्षमता उपयोग	वास्तविक (%)	49.79	49.79
क्षमता उपयोग	सूचीबद्ध	288	288
घरेलू बिक्री	वास्तविक(मी.ट.)	89	178
घरेलू बिक्री	सूचीबद्ध	681	681
अंतिम स्टॉक (मी.ट.)	सूचीबद्ध	307	307
बिक्री कीमत घरेलू (रू./मी.ट.)	सूचीबद्ध	92	92

घरेलू उद्योग के 2015-16 से मानदंड सूचकांक

यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग ने निरंतर कीमत न्यूनीकरण के साथ \*\*\*% का क्षमता उपयोग प्राप्त किया है।

106. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति संबंधी किए गए दावों के संबंध में विभिन्न अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत संबंधी सूचना वास्तविक क्षति तथा वास्तविक मंदी से संबंधित है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वर्तमान मामला घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी का मामला नहीं है और यह कि दोनों तरह की क्षति एक साथ नहीं हो सकती। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों का अपना उत्पादन जुलाई, 2015 में ही शुरू किया और घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम है। विदेशी उत्पादकों द्वारा दायर सूचना \*\*\*% की रेंज में क्षमता उपयोग दर्शाता है जबकि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच की अवधि में केवल \*\*\*% था। याचिकाकर्ता उतनी उत्पादन क्षमता प्राप्त नहीं कर पाया जितनी संयंत्र की स्थापना के समय याचिकाकर्ता ने परिकल्पना की थी। प्राधिकारी पूर्व में की गई समान जांचों के मामले में जांच की ओर इसका ध्यान आकर्षित करने पर विचार करते हैं।

107. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि के कारण हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात उस समय बढ़े जब घरेलू उद्योग ने उत्पादन आरंभ किया था और उसकी क्षमताएं घरेलू मांग से अधिक थीं तथा उत्पाद का उत्पादन और बिक्री की।

108. जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि जांच की अवधि के दौरान पूर्व की अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में सुधार हुआ है, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति मात्रा एवं कीमत संबंधी मानदंडों के वांछित निष्पादन स्तरों से कम रहने के कारण है। यदि दावा की गई वास्तविक मंदी जांच की अवधि के बाद भी सिद्ध है तो प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद के क्षमता उपयोग और कीमत संबंधी मंदी की भी जांच की है।

109. प्राधिकारी मानते हैं कि इस मामले में संगत कारक कीमत न्यूनीकरण/ह्रास तथा कम क्षमता उपयोग हैं जो तिमाही समयावधि पर जांच किए जाने पर मूलभूत स्तर पर सिद्ध होते हैं।

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी के मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने हेतु सिद्धांत संबंधी कोई विशेष नियम नहीं है। इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को नोट करते हुए प्राधिकारी ने अपने विगत निर्धारणों, विभिन्न न्यायिक निर्णयों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों की परिपाटियों से संबंधित उपलब्ध सूचना पर विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग का लंबी अवधि में निष्पादन नहीं है, वहां क्षति विश्लेषण पर विचार करके घरेलू उद्योग को क्षति का विश्लेषण करना संभव नहीं है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा वास्तविक क्षति के मामले में किया जाता है। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि पाटनरोधी परिपाटियों संबंधी डब्ल्यू टी ओ समिति ने निर्धारित किया है कि क्षति के प्रयोजनों के लिए आंकड़ों के विश्लेषण की अवधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए जब तक कि संबंधित घरेलू उद्योग का तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्तित्व न हो। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि प्राधिकारी उन स्थितियों में भी घरेलू उद्योग को क्षति की जांच कर सकते हैं जहां घरेलू उद्योग के पास तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए आंकड़े न हों। इसके अतिरिक्त, तीन या उससे अधिक वर्षों को मानने का प्रयोजन जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार करना और यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व की अवधियों से उसकी तुलना करना है कि क्या जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन पूर्व के वर्षों में निष्पादन को ध्यान में रखते हुए क्षतिकारक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लंबी अवधि में आंकड़ों का विश्लेषण करने में सामान्य रूप से लागू किए जाने वाले सिद्धांत पर विचार करते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान मामले जैसे मामले में जहां घरेलू उद्योग का निष्पादन तीन वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां घरेलू उद्योग के निष्पादन को जांच की अवधि के अंतर्गत विभाजित करना उपयुक्त होगा। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग का अपना प्रचालन जुलाई, 2015 से है। प्राधिकारी ने विभिन्न क्षति मानदंडों का तिमाही विश्लेषण करके इस अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण किया है।

111. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति एक साथ नहीं हो सकते, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के एक रूप से अधिक की जांच के लिए कानून के तहत कोई अड़चन नहीं है। प्राधिकारी उन मामलों में घरेलू



उद्योग की स्थापना को वास्तविक क्षति और वास्तविक मदी, दोनों की जांच करते रहे हैं जिनमें घरेलू उद्योग का लंबी अवधि में निष्पादन नहीं है और घरेलू उद्योग ने हाल की अवधि में उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। प्राधिकारी प्रत्याशित निष्पादन के साथ घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना करते रहे हैं और उसकी मौजूदगी की सीमा तक घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच करते रहे हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तरीके से प्राधिकारी द्वारा किए गए विगत निर्णयों को सेस्टेट द्वारा रोका गया है। इस प्रकार, इस मामले के तथ्य पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति की जांच सभी संभव मूल्यांकन-घरेलू उद्योग की मौजूदगी/प्रचालनों की सीमा तक वास्तविक निष्पादन, जांच की अवधि तक वास्तविक निष्पादन पर विचार करके संभावित निष्पादन, जांच की अवधि के बाद स्थूल आर्थिक मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन तथा संयंत्र की स्थापना का निर्णय लेते समय याचिकाकर्ता द्वारा बनाई गई योजना और माने गए निष्पादन के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलना करके की गई है। प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए भी जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार किया है कि क्या घरेलू उद्योग का निष्पादन जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी प्रतिकूल था।

112. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड ह्रास दिखाएं। कुछ मानदंड ह्रास दर्शा सकते हैं जबकि कुछ सुधार दर्शा सकते हैं। अतः प्राधिकारी ने यह मूल्यांकन करने के लिए सभी संगत क्षति मानदंडों पर विचार किया है कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक मंदी हुई है अथवा नहीं।

#### **ठ. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संपर्क**

113. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को पाटन और वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की जांच के लिए पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध उन अन्य कारकों की जांच की है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

##### **क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत**

114. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से संबद्ध सामानों के आयात आंकड़ों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि फिर भी तीसरे देशों से आयात काफी हैं। गैर-संबद्ध से संबद्ध सामानों की आयात कीमत चीन से आयात कीमत की अपेक्षा वास्तविक रूप से अधिक है और इसीलिए ये आयात घरेलू उद्योग को निर्धारित क्षति का कारण नहीं हैं, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है:

सीआईएफ आयात कीमत	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि*
संबद्ध देश – चीन	रु./कि.ग्रा.	951	1,036	921	923
अन्य देश	रु./कि.ग्रा.	1,595	1,647	1,740	1,757

##### **ख) मांग में संकुचन**

115. जांच की अवधि में संबंधित उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है और इसीलिए मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

##### **ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

116. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तनों को घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण नहीं माना जा सकता।

##### **घ) प्रौद्योगिकी में विकास**

117. उत्पाद के उत्पादन के लिए किसी भिन्न प्रौद्योगिकी का दावा नहीं किया गया है अथवा कोई परिवर्तन होने संबंधी विरोध नहीं किया गया है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता।

##### **ङ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां**

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामान भारत में किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों में नहीं हैं। याचिकाकर्ता देश में विचाराधीन उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है और इसीलिए घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती।

##### **च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का निष्पादन और उस पर क्षति की जांच यथासंभव सीमा तक घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालन के निष्पादन के संबंध में की गई है। घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित ह्रास घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

### **छ) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन**

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से प्राधिकारी द्वारा किए गए घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।

121. इस प्रकार, यह देखा जाता है कि क्षति का कोई भी सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है।

### **कारणात्मक संपर्क स्थापित करने वाले कारक**

122. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण निम्नलिखित हैं:

- क) पाटित आयात पूरी क्षति अवधि में भारतीय बाजार में आए हैं और मात्रा पूर्ण दृष्टि से बढ़ी है जिसके परिणामस्वरूप कीमत ह्रास हुआ है।
- ख) चूंकि, घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2015 से विचाराधीन उत्पाद की बिक्री शुरू की, अतः घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतें आयात कीमतों के लिए निर्धारण होने की आवश्यकता थी।
- ग) पाटित आयातों की मौजूदगी से घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है और अपना उत्पादन तथा बिक्री अधिकतम नहीं कर पा रहा है। घरेलू उद्योग को देश में काफी मांग आपूर्ति अंतराल की मौजूदगी के बावजूद उसके उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा बढ़ाने से रोका गया है।
- घ) घरेलू उद्योग को हो रहा कीमत न्यूनीकरण देश में पाटन के कारण है।
- ङ) घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानियां हुई हैं जिससे नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में ह्रास हुआ है।
- च) घरेलू उद्योग की वृद्धि नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ जैसे कई कीमत मानदंडों के संबंध में नकारात्मक है।
- छ) संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप बाजार में क्षतिरहित कीमत की तुलना करने पर कम कीमत पर बिक्री भी हो रही है।

विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग अपने को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पा रहा है और यह देश में संबद्ध वस्तु के लिए क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तर तक अपना उत्पादन और बिक्री बढ़ाने में असमर्थ है।

### **ब. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां**

123. प्रकटन विवरण के अनुसरण में घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

### **क. घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स टीपीएम द्वारा अनुरोध**

- (i) प्रत्युत्तर अनुरोध, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ पत्राचार, पाटन मार्जिन, निर्यातकों/ उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट प्रकट की जानी चाहिए।
- (ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत अनुचित रूप से कम है क्योंकि प्राधिकारी ने सर्वोत्तम प्राप्त क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की लागत को मानक बनाया है। यहां तक कि जब यह माना जाए कि याचिकाकर्ता ने इष्टतम स्तरों तक उत्पादन नहीं किया है, जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद में लगाए गए खर्चों पर विचार करना और उसे राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर मानक बनाना उपयुक्त नहीं होगा। यह इस साधारण कारण से है कि ये कई खर्चे उत्पादन/ बिक्री/कारोबार से संबद्ध विभाजन सिद्धांत अपनाकर उत्पाद में लगाए गए हैं।
- (iii) अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित दृष्टिकोण पर विचार किया जाए – (क) उत्पादन के इष्टतम स्तर पर विचार करके प्रपत्र सी-11 पुनः तैयार किया जाए, (ख) संशोधित कारोबार के अनुपात में विचाराधीन उत्पाद और अन्य उत्पाद के बीच निर्धारित खर्चों को बांटा जाए।
- (iv) पाटन की मौजूदगी पर चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विवाद नहीं किया गया है।
- (v) प्रयोक्ता उद्योग द्वारा किए गए काफी अनुरोध प्रकटन विवरण के माध्यम से पहले बार याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की जानकारी में आए हैं। याचिकाकर्ता को अब तक प्रयोक्ता उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों का खंडन करने का मौका नहीं मिला है। याचिकाकर्ता उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध करता है।

- (vi) शेनयांग मत्सुशिता एस. बैट्री कं. लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्री लि. और अन्य [(2005) 3 एससीसी 39] में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और सेंच्युरी प्लाईवोर्ड्स लि. बनाम भारत संघ में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्यात कीमत निर्मित सामान्य मूल्य की तुलना में सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए ली जानी है।
- (vii) पाटनरोधी शुल्क अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा. में व्यक्त पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा (शुल्क की निर्धारित स्वरूप) के रूप में लगाई जाए।

#### **ख . विभिन्न निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा अनुरोध**

- (i) याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान टरपोलाइमर प्री-कंपाउंड का विनिर्माण नहीं किया है और इस प्रकार उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग रखा जाना चाहिए। साथ ही, याचिकाकर्ता ने टरपोलाइमर रॉ गम को ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है न कि प्री-कंपाउंड को। टरपोलाइमर प्री-कंपाउंड के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई पीसीएन नहीं बताया गया है (प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड, जिप्सम सीलिंग बोर्ड विद एल्युमीनियम एजेज सील्स इन व्हाइट फिल्म एंड सेचुरेटिड फैट्री एल्कोहल में निर्णय देखें)।
- (ii) निर्यातक की निर्यात बिक्री संबंधी सूचना जो सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है, प्रकट की गई है जबकि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानदंडों की गोपनीयता के दावे स्वीकार किए गए हैं। उत्तरदाता मात्रात्मक मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के साथ स्थित हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को वह लाभ समानता के आधार पर उत्तरदाताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को देना चाहिए।
- (iii) इस याचिका में दायर आंकड़े सुनवाई पूर्व लिखित अनुरोधों में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते। इसी प्रकार, सुनवाई पूर्व लिखित अनुरोधों में दिए गए आंकड़ों और सत्यापित आंकड़ों में भारी अंतर है।
- (iv) अलग पाटन अथवा क्षति मार्जिन तथा एमईटी स्वीकार करने अथवा रद्द करने के लिए पाटनरोधी जांच में मूल्यवर्धन कोई मानदंड नहीं है। सीएफएसई असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा गोंद खरीदता है।
- (v) उच्च गुणवत्ता के ग्रेड के कच्चे गोंद की खरीद द चेमर्स चेंगुआंग फ्लोरो मैटेरियल्स (शंघाई) कं. लि. से की जाती है और इसीलिए कीमत अधिक है।
- (vi) अनुरोध है कि पाटनरोधी करार के अनुबंध-II के पैरा 3 के अनुरूप सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कच्चे गोंद से प्री-कंपाउंड का उत्पादन करने के लिए याचिकाकर्ता के सर्वोत्तम विद्युत खपत (किलोवाट/केजी) तथा उत्तरदाता द्वारा दिए गए विद्युत बीजकों के अनुसार प्रति किलोवाट औसत लागत, विद्युत लागत को छोड़कर उत्तरदाता द्वारा दिए गए लागत के सभी घटकों पर विचार करें।
- (vii) कीमतों, लागत और इनपुट, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में सीएफएसई के निर्णय बाजार संकेतकों के अनुरूप किए जाते हैं और किसी महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं।
- (i) बुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इन्वेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है और इसीलिए सीएफएसई में निवेश संबंधी निर्णय करने में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है।

कानून के अनुसार किसी कंपनी को निम्नलिखित दो स्थितियों में ही सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली माना जा सकता है:

- (क) सरकारी विभाग, संगठन, संस्था, एकल सरकारी स्वामित्व अथवा सरकारी नियंत्रण वाले उद्यमों द्वारा धारित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शेयर 50 प्रतिशत से अधिक हो, अथवा;
- (ख) शेयरधारक करार, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रिजॉल्यूशन अथवा अन्य करार सरकार को नियंत्रण करने के लिए प्राधिकृत करें।

बुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इन्वेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) (बुक्सी इन्वेस्टमेंट) में सरकार का हिस्सा केवल 34 प्रतिशत है। यह भी नोट किया जाए कि भागीदारी करार में स्पष्ट उल्लेख है कि बुक्सी जुनयान कैपिटल मैनेजमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) (बुक्सी कैपिटल), बुक्सी इन्वेस्टमेंट का केवल एक सामान्य भागीदार है और उसका उसके दैनिक प्रचालनों पर पूरा नियंत्रण है। बुक्सी कैपिटल के सभी शेयरधारक निजी व्यक्ति हैं। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि बुक्सी इन्वेस्टमेंट एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है।

- (ii) बुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इन्वेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) सरकारी नियंत्रण में नहीं है और इसलिए सीएफएसई में निवेश संबंधी निर्णय करने में सरकारी हस्तक्षेप नहीं है।

बुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इन्वेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) के शेयरधारक सरकारी शेयरधारिता में सीमित भागीदार है और दैनिक प्रचालनों में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

भागीदारी करार यह पूर्ण तरह से स्पष्ट करता है कि वुक्सी कैपिटल, वुक्सी इन्वेस्टमेंट का केवल एक सामान्य भागीदार है और उसका उसके दैनिक प्रचालनों पर पूरा नियंत्रण है। निवेश समिति के निर्णय व्यावसायिक नीतियों के अनुसार तथा कंपनी कानून के अनुरूप तथा प्रतिभूति निवेश निधि कानून तथा अन्य कानूनों और प्रशासनिक विनियमों के अनुसार लिए जाते हैं।

- (viii) चीन में विनिमय दर बाजार बलों के आधार पर निर्धारित की जाती है और सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। साथ ही, यह एक स्थूल आर्थिक मुद्दा है और कंपनी का बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर टाइल्स केस के अनुसार अकेले इस मुद्दे के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।
- (ix) सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीन में कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत तथा बिजली की लागत पर विचार किया जाए।
- (x) व्यापारी के लिए कीमत हमेशा अंतिम उपभोक्ता के लिए कीमत से कम होगी (6 प्रतिशत तक अलग-अलग)। इस प्रकार, निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य, पाटन और क्षति मार्जिन प्रत्येक ग्राहक के लिए परिकलित किया जाना चाहिए।
- (xi) उत्तरदाता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे 4 प्रतिशत के वैट समायोजन का परिकलन करने के लिए सीएफएसई की एफओबी निर्यात कीमत में 0.4/1.04 का सूत्र यह मानते हुए लागू करें कि निर्यात कीमत में अलग-अलग पीसीएन की कारखानागत निर्यात कीमत के परिकलन के लिए 4 प्रतिशत वैट शामिल है।
- (xii) जांच की अवधि के बाद के आंकड़े क्षति अथवा वास्तविक मंदी की जांच के मामले में संगत नहीं हैं।
- (xiii) निर्यात निष्पादन याचिकाकर्ता को क्षति, यदि कोई है, का कारण है।
- (xiv) याचिकाकर्ता को यदि कोई क्षति है तो वह उसके उत्पादों की घटिया गुणवत्ता, आंतरिक अदक्षताओं, कुप्रबंधन, कीमत और पूर्व की कीमत नीति आदि जैसे अन्य कारणों से है।
- (xv) प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना है। तथापि, इसके बावजूद प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की मानी गई उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है। यह सिद्धांत केवल इसलिए अपनाया गया है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से समग्र आयात कंपनियों का 10 प्रतिशत वर्तमान जांच के अनुसार ग्रेड/पीसीएन निर्दिष्ट नहीं करता। यहां तक कि यद्यपि, प्राधिकारी ने यह माना है कि भारतीय कानून में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के मामले में सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय एक श्रृंखला को अपनाए जाने का प्रावधान है, तथापि, प्राधिकारी ने दूसरा सिद्धांत अपनाने में (अर्थात् किसी अन्य उपयुक्त आधार पर) और भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात आंकड़ों के 90 प्रतिशत की उपेक्षा करने में गलती की है। यह उल्लेख करना भी संगत है कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध सामानों के आयात आंकड़ों के समान भारत में चीन से आयात लेन-देनों की भारी संख्या भी ग्रेडों को विनिर्दिष्ट नहीं करती। तथापि, प्राधिकारी ने भारत में चीन से संबद्ध सामानों के आयात आंकड़ों को स्वीकार किया है जबकि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के आयात आंकड़ों को निरस्त किया है। अनुरोध है कि प्राधिकारी को अन्य किसी आधार को अपनाने के बजाए भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यात कीमत के आधार पर "सामान्य मूल्य" के अपने निर्धारण को आधार बनाना चाहिए।
- (xvi) प्राधिकारी ने शंघाई 3एफ द्वारा निर्यातित सामानों की कारखानागत कीमत का निर्धारण करने में गलती की है।
- (xvii) प्राधिकारी को जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के आधार पर अपने निर्धारण को आधार नहीं बनाना चाहिए। साथ ही, औसत मालसूची का मूल्यांकन गलत किया गया है।
- (xviii) प्राधिकारी को मोरक्को – टर्की से कतिपय हॉट रोलड स्टील पर पाटनरोधी उपाय में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक मंदी अथवा वास्तविक क्षति का मूल्यांकन करने के लिए पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 में सूचीबद्ध सभी 15 आर्थिक मानदंडों की अनिवार्य रूप से जांच करनी चाहिए।
- (xix) घरेलू उद्योग को क्षति तथा संबद्ध आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क नहीं है।
- (xx) घरेलू उद्योग को कीमत न्यूनीकरण स्वप्रभावित है।
- (xxi) संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित देश है जबकि चीन विकासशील देश है। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध सामानों की कीमत चीन के लिए सामान्य मूल्य के रूप में नहीं ली जा सकती।

- (xxii) संयुक्त राज्य अमेरिका ने जांच की अवधि के दौरान भारत को को-पॉलीमर रॉ गम (लगभग 3 मी. टन) की बहुत कम मात्रा का निर्यात किया है जो कि एक नगण्य मात्रा है और वह विशेषता के ग्रेड वाली है। आयातों की इतनी छोटी मात्रा को चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निकालने हेतु प्रतिनिधि मात्रा नहीं कहा जा सकता।
- (xxiii) अनुरोध है कि सामान्य मूल्य चीन में कीमतों के अनुसार तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान ब्याज दर के अनुसार कच्ची सामग्री की खपत के मानदंड, कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, यूटिलिटी लागत अपनाकर निर्मित किया जाए।
- (xxiv) संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्यात कीमत पर वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह दोनों देशों के विकास के स्तर में अंतर के कारण चीन जन. गण. के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश नहीं है।
- (xxv) निर्यातक की निर्यात बिक्री के संबंध में सूचना, जो कि सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है, प्रकट की गई है जबकि उसके मात्रात्मक मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावे स्वीकार किए गए हैं। उत्तरदाता मात्रात्मक मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के समान ही बराबर स्तर पर हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को समानता के आधार पर उत्तरदाताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समान लाभ प्रदान करना चाहिए था।
- (xxvi) क्षति के तीनों रूप साथ-साथ नहीं हो सकते। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस संबंध में उत्तरदाताओं के अनुरोधों को दरकिनार कर दिया है और उनका समाधान नहीं किया है।
- (xxvii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहीं किया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोरिया पैनल रिपोर्ट क्यों लागू नहीं है।
- (xxviii) एसबीआर में अंतिम जांच परिणाम तथा सेसटेट आदेश लागू नहीं हैं क्योंकि उसने वर्तमान जांच की तुलना में भिन्न तथ्य हैं।
- (xxix) जीएफएल समान वस्तु का एक स्थापित घरेलू उद्योग है। चूंकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास यह निर्धारित करने के लिए कोई मानक परीक्षण नहीं है कि कोई उद्योग पहले से ही स्थापित है अथवा स्थापित किया जा रहा है। अतः अन्य क्षेत्राधिकारों में पाटनरोधी प्राधिकारियों द्वारा लागू किया गया परीक्षण अपनाया जाए।
- (xxx) यूआईएसटीसी ने (i) घरेलू प्रचालनों की लंबाई; (ii) घरेलू उत्पादन की विशेषताओं; (iii) घरेलू प्रचालनों का आकार; (iv) क्या घरेलू उद्योग किसी उपयुक्त वित्तीय "ब्रेकविन" स्तर पर पहुँच गया है; और (v) क्या पहले से ही स्थापित व्यापार द्वारा नई उत्पादन लाइन शुरू करने की प्रकृति में स्टार्ट अप अधिक है, की जांच करते हैं – जीएफएल पहले से ही एक सुस्थापित व्यापार है जो कि वैश्विक रूप से पीटीएफई का चौथा सबसे बड़ा विनिर्माता है जिसका फ्लोरो एलास्टोमर्स निचले स्तर का एक मात्र उत्पाद है। जीएफएल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, फ्लोरोलस्टोमर्स के विनिर्माण के लिए क्षमताएं बढ़ाने हेतु न्यूनतम पूंजी व्यय की आवश्यकता होती है और यह पहले से ही स्थापित परिसंपत्तियों का दोहन करेगा।
- (xxxi) डब्ल्यूटीओ के प्रस्ताव पर वास्तविक मंदी का मापन करने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता। संधियों के कानून संबंधी वियना कन्वेंशन के अनुसार विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रस्ताव निर्माण में किसी भी वैध सहायता की परिधि के अंतर्गत नहीं आते।
- (xxxii) निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस तथ्य पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि घरेलू उत्पादन की तुलना में आयात वास्तविक रूप में कम हुए हैं। चीन जन. गण. से आयातों में वृद्धि गैर-संबद्ध देशों से आयात कम होने की लागत पर ही हुए हैं। अतः चीन जन. गण. से आयातों का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं रहा।
- (xxxiii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से आयातों की तुलना गैर-संबद्ध देशों के आयातों से की है और इससे यह पाया है कि चीन जन. गण. से आयात कीमतें अन्य देशों से आयात कीमतों का 50-60 प्रतिशत पर रही हैं। इस प्रकार का विश्लेषण पहले नहीं हुआ है और जहां तक अनुबंध-II के पैरा 2 के तहत विश्लेषण का संबंध है, यह संगत नहीं है।
- (xxxiv) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि "कीमत न्यूनीकरण प्रभाव का विश्लेषण कीमत मंदी के रूप में उसके प्रतिनिधि के संबंध में किया गया है जिससे घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद इष्टतम स्तर को लेने के लिए उत्पादन रुका है।" किसी विश्लेषण के लिए यह निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II में किसी भी प्रावधान के तहत नहीं पाया जाता है। "कीमत मंदी" शब्द का पाटनरोधी शुल्क

लगाए जाने के लिए शासित होने वाले किसी प्रावधान अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी के किसी विगत निर्धारण में कोई मूल आधार नहीं है। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे "कीमत मंदी" की जांच करते समय शामिल विश्लेषण की प्रकृति स्पष्ट करें अथवा वह क्या बनता ताकि हितबद्ध पक्षकार सार्थक टिप्पणियां दे सकें।

- (xxxv) कीमत कटौती की तिमाही प्रवृत्तियों से संबंधित आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि 2016-17 की पहली तिमाही से 2017-18 की पहली तिमाही तक पांच तिमाहियों के बीच कीमतें व्यापक रूप से न्यूनतम अंतरों में समान रही हैं। जुलाई से दिसंबर, 2018 की दो तिमाहियों के जांच की अवधि के बाद के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि आयात कीमतें और बढ़ी हैं।
- (xxxvi) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की कीमतों की पहली तिमाही में चीन जन. गण. से आयातों के कारण कटौती हो रही थी। तथापि, बाद में कीमत कटौती नकारात्मक हो गई जिसके परिणामस्वरूप कीमत ह्रास हुआ। पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (ii) के तहत यह अपेक्षा है कि क्या आयातों से भारत में समान उत्पाद की कीमतों की काफी कटौती हुई है। अतः कीमत न्यूनीकरण के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित कारण इस निर्धारित स्थिति के विपरीत है कि कीमत कटौती की मौजूदगी को ही कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास के लिए जिम्मेदार माना जाता है न कि उसके अभाव को।
- (xxxvii) चीन जन. गण. से कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से अधिक थीं जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उनकी कीमतें आयातों से दबाव में नहीं थीं। नकारात्मक कीमत कटौती का मार्जिन वास्तव में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ा। उसकी बिक्री कीमत कम से कम चीन से आयातों के स्तर के बराबर समान स्तर पर और बढ़ाने की पर्याप्त छूट होने के बावजूद घरेलू उद्योग ने अपनी कीमत कम करने का विकल्प चुना।
- (xxxviii) चीन में पैनल रिपोर्ट – यूरोपीय संघ से एकसरे सुरक्षा निरीक्षण उपस्करों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क का संदर्भ लेने पर कीमत कटौती नकारात्मक थी क्योंकि घरेलू उद्योग आयातों के पहुँच मूल्य से कम पर बिक्री कर रहा था, कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास अकाट्य कारणों के अभाव में आयातों के कारण नहीं हो सकता, यह स्पष्ट करते हुए कि घरेलू उद्योग कम से कम आयातों के स्तर तक अपनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ा पाया।
- (xxxix) मात्रात्मक मानदंडों ने भारी सुधार दर्शाया है और फिर भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि उपर्युक्त मानदंड कम हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी की उपर्युक्त टिप्पणी गलत रखी गई है क्योंकि एफकेएम अत्यधिक विशेषीकृत अनुप्रयोग वाला उत्पाद है और इसीलिए घरेलू उद्योग से रातों-रात पूरा बाजार लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निरंतर सुधारों को यह बताकर नहीं नकारा जा सकता कि बेहतर निष्पादन प्राप्त किया जा सकता था।
- (xl) जब घरेलू उद्योग की बिक्री की प्रतिशतता देखें तो मालसूची आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वास्तविक रूप से कम हुई है (ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [(2011) 270 ईएलटी 696] में सेसटेट के निर्णय के अनुसार)।
- (xli) घरेलू उद्योग को रोजगार, उत्पादकता अथवा मजदूरी के संबंध में क्षति नहीं हुई है।
- (xlii) चीन जन. गण. से आयातों का घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए सामानों की कीमतों पर बिक्री कीमत काफी अधिक होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- (xliii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह मानने का प्रस्ताव किया है कि हानियों से घरेलू उद्योग की क्षमता पूंजी निवेश जुटाने में प्रभावित होगी। निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इस तथ्य को ध्यान में रखें कि घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 में स्वयं ही स्वीकार किया है कि "यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसके पास किसी भी समय और अधिक पूंजी आसानी से जुटाने की क्षमता है।"
- (xliv) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कीमत कटौती नकारात्मक होने के परिणामस्वरूप कीमत न्यूनीकरण के लिए घरेलू उद्योग की गिरती हुई लाभप्रदता को कारण माना है। तथापि, उपर्युक्त टिप्पणी अंतर्निहित विरोधाभास से युक्त है क्योंकि सकारात्मक कीमत कटौती ही कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास के लिए उत्तरदायी है जबकि नकारात्मक कीमत कटौती का अर्थ है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत किसी दबाव में नहीं है। इसके बजाए, आयातों की कीमतें अधिक होने के नाते घरेलू उद्योग अपनी कीमतें आयातों की कीमतों की तुलना के स्तर पर बढ़ा भी सकता है।

- (xlv) जांच की अवधि के बाद के आंकड़े केवल जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 के बीच दो तिमाहियों (6 माह) के लिए दिए गए हैं और इसीलिए आंकड़ों का वार्षिकीकरण विभिन्न आर्थिक मानदंडों के मापन के लिए अपनाया गया है। केवल दिसंबर, 2017 तक के आंकड़े इस तथ्य के बावजूद दिए गए थे कि घरेलू उद्योग द्वारा सूचना 7 नवंबर, 2018 को दायर की गई थी। जीएफएल की वेबसाइट पर केवल वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट ही उपलब्ध नहीं है बल्कि 30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए उसके वित्तीय परिणाम भी उपलब्ध हैं।

#### कारणात्मक संपर्क

- (xlvii) अलग से आयातों की मात्रा में पूर्ण वृद्धि का पुनर्समाधान कीमत न्यूनीकरण से नहीं किया जा सकता। कीमत न्यूनीकरण का मूल्यांकन करने के लिए संगत मानदंड यह जांच करना है कि क्या आयातों की कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है। केवल स्थिति वह है जब आयातों की मात्रा में वृद्धि से कीमत न्यूनीकरण हो, यदि वह कीमत कटौती के साथ हो जो कि वर्तमान जांच में मामला नहीं है।
- (xlviii) घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक मानदंडों में प्रशंसनीय सुधार किया है और घरेलू उद्योग से रातों रात पूरे घरेलू बाजार को लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती। फ्लोरो एलास्टोमर्स का प्रयोग अत्यधिक विशेषीकृत अनुप्रयोगों में किया जाता है। प्रयोक्ताओं को अनुरूपता तथा निष्पादन का मापन करने के लिए उत्पाद परीक्षणों के माध्यम से विभिन्न विनिर्माताओं से लिए गए सामानों का मूल्यांकन करना होता है जिसमें समय लग जाता है।
- (xlix) ऐसी स्थिति में जब कीमत कटौती नकारात्मक हो तो पाटन कीमत न्यूनीकरण का कारण नहीं हो सकता। आयातों की कीमतों की घरेलू उद्योग की कीमतों के साथ यह जांच करने के लिए तुलना किए जाने की आवश्यकता होती है कि क्या आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों पर हावी हैं और उससे न्यूनीकरण हो रहा है।
- (xli) घरेलू उद्योग को हुई वित्तीय हानियां उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को अलाभप्रद कीमतों पर बेचने के कारण हैं जो कि आयात की उन कीमतों से तुलनीय नहीं हैं जो कि पूरी क्षति विश्लेषण अवधि में निरंतर अधिक रही हैं।
- खुद पाटन घरेलू उद्योग को उसकी बिक्री, उत्पादन अथवा क्षमता उपयोग बढ़ाने से नहीं रोकता। इसे कीमत कटौती जैसे अन्य कारकों के साथ मिलाया जाना चाहिए जो इसे प्रयोक्ताओं को कम कीमत के आयातों में ले जाने के लिए अधिक आकर्षक बनाता है। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पाटन से घरेलू उद्योग इष्टतम क्षमता उपयोग प्राप्त करने से कैसे रह गया, जबकि घरेलू उद्योग ने उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की कीमतें निरंतर घरेलू उद्योग की कीमतों से कम रखी हैं। अतः यह कारक संबद्ध सामानों के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क सिद्ध नहीं करता।
  - पूर्व के जांच परिणामों (कास्टिक सोडा, एन बुटानोल, पीवीआर और बेल्टिंग फैब्रिक) का संदर्भ दिया जाता है जिनमें जांचों को रद्द किया गया है क्योंकि पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है, उन मामलों में जहां अधिकतर आर्थिक कारकों ने लाभप्रदता में कमी के बावजूद सुधार दर्शाया है।

#### ग. प्रयोक्ता उद्योग (मैसर्स हाइटेक अराई प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स देवाशीष पॉलीमर्स प्रा. लि.) द्वारा अनुरोध

- को-पॉलीमर गम की कीमत 24.60 अमेरिकी डॉलर और को-पॉलीमर प्री-कंपाउंड की कीमत 22.25 अमेरिकी डॉलर होने के परिकलन का संदर्भ देते हुए यह अनुरोध है कि यह मूल्य अपने आप में तथ्यात्मक रूप से और सैद्धांतिक रूप से पूर्णतः गलत है। को-पॉलीमर गम की कीमत, प्री-कंपाउंड बनाने के लिए खर्चीले क्रिएटिक्स के साथ मिश्रित को-पॉलीमर गम की कीमत से कम से कम 20-25 प्रतिशत कम होनी चाहिए। प्रक्रिया अपने आप में विशिष्ट है और इसमें सावधानी बरतनी होती है। अतः अत्यधिक महंगे क्रिएटिक्स जोड़ने के बाद भी तथा सख्त विनिर्माण प्रक्रिया अपनाने के बाद भी प्री-कंपाउंड की कीमत गम की कीमत से सस्ती होगी। इसके अतिरिक्त, कच्चे गोंद की कीमत के परिकलन में आश्चर्यजनक रूप से कमी है, को-पॉलीमर कच्चे गोंद की कीमत टर-पॉलीमर कच्चे गोंद से अधिक महंगी होने का परिकलन किया गया है। टर-पॉलीमर में तीन मोनोमर्स होते हैं जबकि को-पॉलीमर में दो मोनोमर होते हैं। तीसरे मोनोमर को जोड़ने का काम नियंत्रित पर्यावरण में किया जाता है जो टर-पॉलीमर रॉ गम को को-पॉलीमर रॉ गम से महंगा बना देता है तथा उसका प्रयोग बहुत ही अधिक मांग वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है। अतः डीजीटीआर का को-पॉलीमर प्री-कंपाउंड से अधिक को-पॉलीमर रॉ गम की उच्च कीमत जैसे परिकलन के लिए दृष्टिकोण तथ्यात्मक रूप से और सैद्धांतिक रूप से गलत है।

- II. डीजीटीआर द्वारा मानी गई क्षति रहित कीमत (एनआईपी) उससे लगभग 30 प्रतिशत अधिक है जो घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में दावा की गई है। यह एक किस्म का मामला है जिसमें डीजीटीआर घरेलू उद्योग को उससे अधिक बिक्री कीमत (संरक्षण के उच्चतर स्तर के संदर्भ में) की अनुमति देना चाहते हैं जिसकी घरेलू उद्योग ने एक उचित कीमत के रूप में मांग की थी। इस प्रकार, मध्यम एवं लघु उद्योगों के हितों की अनदेखी की गई है। डीजीटीआर ने आश्चर्यजनक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान कीमतों के आधार पर उचित कीमतों का परिकलन किया है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व की सबसे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था है, की कीमतों का प्रयोग करने और चीन तथा भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में विद्यमान उचित कीमतों का परिकलन करने के पीछे तर्क नहीं समझ पाते। संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम विद्यमान श्रम लागत, ऊपरी खर्च तथा अन्य संबंधित खर्च हैं।
- III. अतिरिक्त शुल्कों के माध्यम से लागत में वृद्धि से पूरे ऑटोमोबाइल पाटर्स विनिर्माण यूनिट प्रभावित होंगे जो विश्व बाजार में प्रगति कर रहे हैं।
- IV. यह अनुरोध है कि डीजीटीआर घरेलू उद्योग के उत्पाद से जुड़े गुणवत्ता के मुद्दों को हल करने में विफल रहे हैं। उत्पाद में भारी सुसंगतता के मुद्दे थे। घरेलू उद्योग को कई बार यह सूचित किया गया था, परंतु वे अपने स्तर से इसे हल करने में विफल रहे। एफकेएम जैसे उच्च निष्पादन वाले उत्पाद में यह पूर्णतः अस्वीकार्य है।
- V. अनुरोध है कि सामग्री की श्रेणी के रूप में फ्लोरोलस्टोमर्स को कई किस्मों में विभाजित किया जाता है और वे कई ग्रेडों में उपलब्ध हैं; वर्तमान में क्षति का दावा करने वाले आवेदक इस प्रकार की सामग्री का उत्पादन नहीं करते और इस समय ऐसा करने का इरादा भी नहीं रखते। चीन से आयात किए जा रहे उत्पादों की उसी श्रेणी से संबंधित कई उत्पाद हैं जो समान अथवा बेहतर परिणाम नहीं देते जिसे कि क्रेता अपनी प्रकायात्मक आवश्यकता के लिए सामग्री खरीदने के लिए चुन सके। क्षति का दावा करने वाले आवेदक इस संबंध में स्पष्ट हैं कि यदि कंपनी का इरादा राँ गम अथवा प्री-कंपाउंड के रूप में सामग्री की पेशकश करने का है और यदि एक हित है तो पाटनरोधी शुल्क स्पष्ट रूप से जोड़ा जाना चाहिए न कि हर तरीके से उसके हितों की सुरक्षा के लिए दोनों को।
- VI. अनुरोध है कि विभाग को उचित पैटर्न पर विचार करना चाहिए जिसमें सामग्री की चुनिंदा श्रेणी रखी जाए ताकि उद्योग को आयात जारी रखने, अपने अंतिम उत्पादों का विनिर्माण और बिक्री करने में आसानी हो। रबड़ उद्योग को भारत और अन्य राष्ट्रों के बीच कई व्यापारिक करारों से भारी चोट पहुँची है जिनमें परिष्कृत रबड़ पाटर्स बेस राँ मैटेरियल का मूल सीमा शुल्क से भी काफी कम शुल्कों पर आयात किए जा रहे हैं जिससे ओईएम खुद भारत को छोड़कर अन्य देशों से लाभ ले सकें। उस कच्ची सामग्री की लागतों पर अनौचित्यपूर्ण वृद्धि, जो भारत में उत्पादित भी नहीं की जाती है, से भारत में रबड़ संघटकों के विनिर्माताओं पर आसन्न प्रभाव पड़ेगा और उन्हें व्यापार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और दूसरों के विरुद्ध खो जाएंगे।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितवद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों की गुणवत्ता विशेषकर उत्पाद की निरंतरता के संबंध में भी चिंताएं उठाई हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में लगभग 50 प्रतिशत का क्षमता उपयोग प्राप्त किया है जो यह दर्शाता है कि गुणवत्ता संबंधी चिंताएं घरेलू उद्योग द्वारा दूर की जा रही हैं। पाटनरोधी उपाय के माध्यम से अनुचित आयातों का “कीमत संशोधन” केवल उचित व्यापारित क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए है। आयात संशोधित उचित कीमत पर आ सकते हैं। मै. सोल्वे स्पेशियलिटी पालीमर्स (चांगशु) कंपनी लिमिटेड, मै. सोल्वे (शंघाई) कं. लि. और मै. सोल्वे सिपेशियलिटीज इंडिया प्रा. लि. का प्रतिनिधित्व करने वाली मै. सीतारमन एंड एसोसिएट्स ने उल्लेख किया है कि यद्यपि, सहयोगी निर्यातकों की कुल निर्यात बिक्री प्रकट की गई है परंतु घरेलू उद्योग के लिए उसे गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी ने इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए इन अनुरोधों पर विचार करने के बाद इस जांच परिणाम में घरेलू उद्योग की कुल घरेलू बिक्री भी प्रकट की है।

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. इनर मंगोलिया 3 एफ वानहो फ्लूरोकैमिकल कं. लि. (“आईएम 3एफ”), मै. इनर मंगोलिया ऑल टॉप फ्लोरीन कैमैस्ट्री न्यू मैटेरियल्स डेवलपमेंट कंपनी लि. (“ऑल टॉप”) और मै. शंघाई हुआई 3 एफ न्यू मैटेरियल्स सेल्स कंपनी लिमिटेड (“एस एच 3 एफ”) का प्रतिनिधित्व करने वाली मै. दुआ एसोसिएट्स ने उल्लेख किया है कि कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में निर्यातक की सीआईएफ कीमत से चीन में उत्पादक की कीमत निकाल कर किया जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में चूंकि निर्यातक ने लाभ पर निर्यात किए हैं, अतः चीन में उत्पादक अर्थात् आईएम 3 एफ और संबद्ध निर्यातक अर्थात् एस एच 3एफ के बीच संगत मूल्य श्रृंखला संबंध पर उत्पादक स्तर पर कारखानागत निर्यात कीमत का मूल्यांकन करने के लिए विचार किया गया है। चूंकि निर्यातक द्वारा लिया गया लाभ कारखानागत निर्यात कीमत का भाग नहीं हो सकता, अतः निर्यातक द्वारा बताया गया दृष्टिकोण घिसा-पिटा है।



यथानिर्धारित और प्रकटन में निर्यातकों को गोपनीय आधार पर प्रकट की गई कारखानागत निर्यात कीमत पुष्ट है। इसके अतिरिक्त, निर्यात कीमत वैट का निवल है।

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क विश्लेषण, मुख्य रूप से जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों और वह भी केवल 6 माह के आंकड़ों का प्रयोग न करके, अनुच्छेद 3.4 के सभी मानदंडों का मूल्यांकन करते हुए, करने से संबंधित अनुरोध किए गए हैं, घरेलू उद्योग को कीमत न्यूनीकरण, कारणात्मक संपर्क न होने से स्व-प्रभावित है, क्षति के तीनों रूप एक साथ नहीं हो सकते, और डब्ल्यू टी ओ के प्रस्ताव पर वास्तविक मंदी के मापन के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता।

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि टर्पोलाइमर प्रीकंपाउंड को कंपाउंड और एफएफकेएम के साथ अलग किया जाए क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान टर्पोलाइमर प्रीकंपाउंड का उत्पादन नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में टर्पोलाइमर प्रीकंपाउंड का उत्पादन किया है। तथापि, कंपाउंडों और एफ एफ के एम के लिए यद्यपि, घरेलू उद्योग के पास क्षमता नहीं है, तथापि, टर्पोलाइमर प्रीकंपाउंड, प्रीकंपाउंड का एक ग्रेड है जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत है। प्राधिकारी ने कच्चे गोंद और प्रीकंपाउंड (कोपोलाइमर और टर्पोलाइमर) को दो मुख्य किस्मों के विचाराधीन उत्पाद के रूप में माना है जिसके आगे भिन्न परिवर्तक हैं। सभी प्रवर्तकों पर विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में विचार किया गया है। चूंकि क्षति का दावा वास्तविक बंदी का है, अतः ये किस्में जांच की अवधि में उत्पादित नहीं की गई परंतु घरेलू उद्योग के पास क्षमता को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

128. अतः प्राधिकारी अनुरोधों तथा जांच की अवधि के दौरान विनिर्मित न किए गए उत्पाद को अलग करने से संबंधित पूर्व के पाटनरोधी मामलों के उल्लेख को नोट करते हुए यह मानते हैं कि चूंकि घरेलू उद्योग को क्षति वास्तविक मंदी तथा वास्तविक क्षति के संबंध में मूल्यांकित की गई है, अतः केवल वे उत्पाद किस्में अर्थात् कंपाउंडस और एफएफकेएम, जिनके लिए घरेलू उद्योग के पास उत्पादन हेतु कोई क्षमता नहीं है, को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है।

129. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि टर्पोलाइमर प्रीकंपाउंड के लिए क्षतिरहित कीमत मूल्यांकन क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मूल्यवर्धन सहित किया गया है जिसमें प्रीकंपाउंड में कच्चा गोंद शामिल है। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की तुलना एक-एक करके ही की गई है।

130. प्राधिकारी इस अनुरोध को नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के दौरान आंकड़ों के अलग अलग सैट दायर किए थे और सूचना बुरी है। प्राधिकारी मानते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर आंकड़ों का सत्यापन या तो स्थल पर किया जाता है या डेस्क अध्ययन पर। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए सत्यापित आंकड़ों पर विचार करते हैं। यदि आंकड़ों में विसंगतियां सही की गई हैं और सभी हितबद्ध पक्षकारों को बताई गई हैं तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होता और प्राकृतिक न्याय के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता।

131. प्राधिकारी चीन के अभिगम नयाचार के अनुसार घरेलू कीमतों के निर्धारण के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में मै. सीएफएसई के अनुरोधों को नोट करते हैं। उत्पादकों/निर्यातकों ने उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों की मौजूदगी बताने के लिए प्रश्नावली दायर की थी।

मै. सीएफएसई के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पृष्ठ 11 धारा 15(क)(i) की ओर आकर्षित करता है। “यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से दर्शा सकें कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विनिर्माण, उत्पादन और उस उत्पाद की बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनात्मकता निर्धारित करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का प्रयोग करेगा”।

132. प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर सूचना का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया है। प्राधिकारी उत्पादक/निर्यातक के अनुरोधों को नोट करते हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन अथवा बाजार अर्थव्यवस्था विभाग प्रदान करने के लिए मूल्यवर्धन कोई मानदंड नहीं है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि वर्तमान मामले में उत्पादक/निर्यातक कच्ची सामग्री बाहर से ले रहा है जोकि अपने आप में विचाराधीन उत्पाद की किस्म है और उत्पादक/निर्यातक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद किस्म की प्रमुख लागत है तथा इस संदर्भ में कच्चे गोंद के विनिर्माण के लिए “बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार” मूल्यवर्धित स्तर, मूल्यवर्धित उत्पाद किस्म अर्थात् प्रीकंपाउंड के लिए एमईटी प्रदान करने पर विचार करने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस कच्ची सामग्री को बाहर से लेना, चाहे संबद्ध अथवा असंबद्ध से हो, एक घिसी-पिटी बात है क्योंकि जो मुद्दा तय किया जाना है, वह यह है कि क्या कच्चे गोंद का विनिर्माण बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की अपेक्षाओं को पूरा करता है। उत्पाद के इस महत्वपूर्ण भाग के लिए उत्तर दायर न करना उत्पादक/निर्यातक द्वारा निर्यात किए गए सामानों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने में अक्षम बनाता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने गुणवत्ता बेहतर होने के कारण उच्च कीमत पर कुछ आपूर्तिकर्ताओं से कच्ची सामग्री लेना स्पष्ट किया है। पूरे आपूर्तिकर्ताओं में मुख्य कच्ची सामग्री में कीमत के अंतर भी यह दर्शाते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद के

आपूर्तिकर्ताओं के लागत में अंतर हैं और क्या वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं, इसके लिए बारीकी से जांच की आवश्यकता है जिसके लिए संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को प्रश्नावली के उत्तर दायर करने चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान नहीं किया है।

133. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने यह उल्लेख किया है कि खरीद दस्तावेज और बिजली के बिलों में विसंगतियां हैं जो टंकण/लिपिकीय प्रकृति की हैं।

134. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 53 और 54 में माना था कि :

"जहां तक सरकारी अनुमान का संबंध है, उत्पादक/निर्यातक ने अपना शेयरधारिता पैटर्न दिया है जिसमें इसके एक शेयरधारक अर्थात् मैसर्स वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंटर्स सेंटर (सीमित भागीदारी) जिसका उत्पादक/निर्यातक के शेयर का \*\*\* प्रतिशत हिस्सा है, की वस्तुतः \*\*\* प्रतिशत की सीमा तक सरकारी शेयरधारिता है। इस \*\*\* प्रतिशत शेयरधारिता में मैसर्स वुक्सी गुओलियान इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कं. लि. (\*\*\* प्रतिशत), मैसर्स वुक्सी न्यूजपेपर डेवलेपर कं. लि. (\*\*\* प्रतिशत) और मैसर्स वुक्सी न्यू डिस्ट्रिक्ट साइन्स एंड टैक्नोलॉजी फाइनेंसियल वेंचर कैपिटल ग्रुप कं. लि. (\*\*\* प्रतिशत) हैं जिनका सरकारी शेयरधारिता में 100 प्रतिशत हिस्सा है। उत्पादकों/निर्यातकों का निवेश स्वरूप प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से सरकारी उद्यमों द्वारा काफी निवेश दर्शाता है। प्राधिकारी सीएफएसई द्वारा किए गए अनुरोधों को भी नोट करते हैं कि मैसर्स वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंटर्स सेंटर (\*\*\* प्रतिशत) का मैसर्स वुक्सी जुनयान कैपिटल मैनेजमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) (\*\*\* प्रतिशत निजी) एक सामान्य भागीदार के रूप में है जो अन्य सीमित भागीदारों के असमान दैनिक प्रबंधन निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत है और निर्णय करने में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। "प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में यह उल्लेख है कि:

क. ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, विक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं;

ख. ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती हैं। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास अन्य बड़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;

ग. ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती हैं जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है:-

घ. विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं। तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के बजाए पैरा 1 से 6 में पाटनरोधी नियमावली, 1996 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।"

इस मामले में मैसर्स वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंटर्स सेंटर, जो सीएफएसई में प्रमुख शेयरधारक है, के भागीदार करार के 6.4 के तहत प्रावधानों में निवेश संबंधी निर्णय करने में सभी शेयरधारकों की भूमिका निर्धारित है जो उपयुक्त रूप से सीएफएसई में निवेश संबंधी निर्णय करने में सरकारी हस्तक्षेप को स्पष्ट करता है। अतः सरकारी कंपनियों के हस्तक्षेप वाले उत्पादक/निर्यातक द्वारा निवेश के लिए निर्णय करने से एमईटी स्तर का दावा करने के लिए पैरा 8(3)(क) के तहत शर्त पूरी नहीं होती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जहां तक विदेशी मुद्रा लेन-देन का संबंध है, उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उनके वित्तीय लेखाओं में दर्शाई गई विनियम दर चीन के पीपल्स बैंक द्वारा प्रकाशित दर पर आधारित है। तथापि, इस पहलू के संबंध में कोई अनुरोध नहीं है कि क्या विनियम दर पर सरकार का नियंत्रण है। प्राधिकारी दिनांक 08.04.2017 के पूर्व के जांच परिणाम संख्या 14/14/2014-डीजीएडी को ध्यान में रखते हैं जिनमें सरकार द्वारा विनियम दर के सतत नियंत्रण संबंधी पैरा 108 को उल्लिखित किया गया था, उत्पादन लागत, शेयरधारिता पैटर्न और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे संबंधी मुद्दे केवल विचाराधीन उत्पाद के मूल्यवर्धित संघटक तक सीमित होने के नाते और कच्ची सामग्री की कोई भागीदारी न होने पर उत्पादक/आपूर्तिकर्ता उत्पादक/निर्यातक अर्थात् मैसर्स सीएफएसई को बाजार अर्थव्यवस्था स्तर प्रदान करने का औचित्य नहीं बनाते और उसके योग्य नहीं है।"

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. सीएफएसई ने यह औचित्य बनाने के लिए पूर्व के अनुरोधों को दोहराया है कि निवेश संबंधी निर्णय करने में अथवा दिन प्रति दिन के नियंत्रण में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। प्राधिकारी प्रकटन विवरण में अपनी टिप्पणियों तथा ऊपर दी गई टिप्पणियों को भी लेते हैं तथा मानते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए उत्पादकों/निर्यातकों का दावा निवेश की निर्णय करने की प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप सिद्ध न होने के कारण

कम पड़ता है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद अर्थात् कच्चा गोंद का काफी अनुपात लेते हुए, जिसके लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कोई प्रश्नावली दायर न किए जाते हुए और ऊपर बताए गए अनुसार उत्पाद लागत के रिकॉर्डों में तकनीकी बेमेल की विसंगतियां होने से प्राधिकारी विचाराधीन संबद्ध सामानों के लिए मै. सीएफएसई को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का स्तर प्रदान नहीं करते।

136. जहां तक क्षति मानदंड संबंधी अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से और खपत/मांग के संबंध में भी बढ़ी है। तथापि, उत्पादन के संदर्भ में आयातों में गिरावट आई है।

137. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि यद्यपि चीन से संबद्ध सामानों की कीमत का तथ्य, गैर-संबद्ध देशों से कीमतों के लगभग 60 प्रतिशत होने पर, घिसा-पिटा प्रतीत होता है परंतु इस पहलू को दर्शाना चीन से आयातों में वृद्धि में पाया जाता है जिसे प्राधिकारी ने विश्लेषण में उल्लिखित किया है।

138. घरेलू उद्योग उन गैर-संबद्ध देशों के बाजार हिस्से का विस्थापन कर 2015 से जांच की अवधि तक अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में सक्षम रहा है, जिनकी कीमतें चीन से लगभग 70 प्रतिशत अधिक हैं। एक ओर चीन से आयातों के कम कीमत स्तर से चीन से संबद्ध सामानों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई और साथ ही दूसरी ओर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर कीमत न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा। यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि की पहली तिमाही में ही चीन से आयातों द्वारा कीमत कटौती सकारात्मक थी, जिससे बाद में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर मंदी का प्रभाव पड़ा, जो क्षति की अवधि में जारी रहा। घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानदंड अर्थात् उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, क्षमता उपयोग में यद्यपि, क्षति की अवधि में वृद्धि हुई, तथापि, मात्रात्मक वृद्धि कीमत न्यूनीकरण के प्रभाव पर है।

139. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के इन अनुरोधों को नोट करते हैं कि सकारात्मक कीमत कटौती ही कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास के लिए उत्तरदायी है जबकि नकारात्मक कीमत कटौती का अभिप्राय है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत किसी दबाव में नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि यद्यपि, कीमत कटौती नकारात्मक है, क्योंकि घरेलू उद्योग को चीन जन गण से आयात कीमतों के दबाव में अभिभूत होना था।

140. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद अत्यधिक विशेषीकृत उत्पाद है और घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में समय लगाएगा तथा मात्रात्मक मानदंडों के संबंध में उसका वर्तमान निष्पादन पूर्णतः सतोषजनक है। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने निस्संदेह अपना बाजार हिस्सा बढ़ाया है परंतु उसे अपना स्थान गैर-संबद्ध देशों से आयात विस्थापित करके बनाया है और यह कि चीन से पाटित आयातों की वृद्धि अक्षुण्ण रही। पूर्व में बताया गया कीमत मंदी का प्रभाव नहीं लिया जा सकता यदि संबद्ध देश से अनुचित आयातों का हल नहीं निकाला जाता। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति दोनों की बात इस मामले में मौजूद है। जैसा कि एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध किया गया है कि मोरक्को - टर्की से कुछ हॉट रोलड स्टील पर पाटनरोधी उपाय शीर्षक के मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल की हाल की रिपोर्ट में यह माना गया है कि अनुच्छेद 3.4 के सभी मानदंडों की जांच किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम में अनुच्छेद 3.4 के तहत सभी मानदंडों की जांच की है।

प्राधिकारी मानते हैं कि यह नोट करना भी व्यवहारिक है कि यह अनिवार्य नहीं है कि सभी कारक नकारात्मक प्रवृत्ति अथवा गिरावट दर्शाए जैसा कि डब्ल्यू टी ओ द्वारा पैनल रिपोर्ट **ईसी-बैड लिनन मामला** में माना गया है। इसके बजाए, विश्लेषण और निष्कर्षों में प्रत्येक कारक में विचार किया जाना चाहिए; घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में कारण सहित निष्कर्ष निकालने के लिए मुद्दे पर उद्योग विशेष के संदर्भ में प्रत्येक कारक की संगतता निर्धारित की जानी चाहिए।

जहां तक एसबीआर मामले का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की संकल्पना नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार समग्र रूप में घरेलू उत्पादकों के रूप में देखी जानी है। यद्यपि यह हो सकता है कि किसी मामले में घरेलू उद्योग की दो युनिटें हों परंतु वे साथ-साथ घरेलू उद्योग हैं। एसबीआर मामले में प्राधिकारी ने सिफारिश की है कि घरेलू उद्योग की एक युनिट को वास्तविक क्षति हुई है और दूसरी युनिट को वास्तविक मंदी हुई है। सारभूत रूप से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी दोनों हुई हैं। यह सेस्टेट और सर्वोच्च न्यायलय द्वारा माना गया है। इस प्रकार, यह स्थिति नहीं हो सकती कि एसबीआर का मामला यहां संगत नहीं है।

141. अनुच्छेद 3.4 के तहत सभी मापदंडों की जांच करने के बाद प्राधिकारी के लिए यह सिद्ध करने के लिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों को देखने के लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि क्या क्षति की अवधि में नोट किए गए घरेलू उद्योग के निष्पादन में मंदी अब भी जारी है अथवा उसमें कोई परिवर्तन हुआ है। इस संबंध में प्राधिकारी एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध को नोट करते हैं कि जांच की अवधि के बाद की अवधि संगत नहीं है और यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने केवल जांच की अवधि के बाद 6 माह पर ही विचार किया है जब ज्यादा अवधि के आंकड़े उपलब्ध थे। प्राधिकारी मानते हैं कि जांच की अवधि के बाद 6 माह सामान्यतः भिन्न किस्म की पाटनरोधी जांच अर्थात् निर्णायक समीक्षा, क्षति के खतरे अथवा

वास्तविक मंदी की जांच के लिए माने जाते हैं। इस मामले में भी प्राधिकारी इस परिपाटी से अलग नहीं हुए हैं और जांच की अवधि के बाद के 6 माह के आंकड़ों को केवल संकेतात्मक नोट किया है।

142. प्राधिकारी वास्तविक मंदी के मामले के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के 2-3 वर्ष की मौजूदगी वाले उद्योग को पात्र न मानने के संबंध में अनुरोधों को नोट करते हैं। तथापि, जिन परिस्थितियों में इस पर विचार किया जाता है, वह विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न हो सकता है। किसी स्थापित उद्योग का मानदंड भी एक देश से दूसरे देश में अलग-अलग होगा। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने दिसंबर, 2017 में एक याचिका दायर की थी जिसमें जुलाई, 2016 से जून, 2017 तक मानी गई जांच की अवधि में पाटन का आरोप लगाया था। अतः घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2015 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के एक वर्ष बाद क्षति विशेष रूप से वास्तविक मंदी का दावा किया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान मामले की परिस्थितियों में वास्तविक मंदी के लिए घरेलू उद्योग का दावा औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है और और इस जांच परिणाम में उसका उपयुक्त रूप से विश्लेषण किया गया है।

143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक हितबद्ध पक्षकार ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया है कि उसके पास आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय आसानी से अधिक पूंजी जुटाने की क्षमता है और इस प्रकार पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता लड़खड़ाई नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जी एफएल एक बहु उत्पाद कंपनी है और बहु उत्पाद कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सभी उत्पादों और खंडों तथा कंपनी के समग्र प्रचालनों के संबंध में निष्पादन दर्शाती है और एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए ही संगत है।

## **ढ. निष्कर्ष**

144. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों तथा इस जांच परिणाम में दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के पास उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- i. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।
- ii. घरेलू उद्योग के संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी हुई है।
- iii. उपर्युक्त क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।

## **ण. सिफारिश**

145. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के लिए उत्पादक/निर्यातक जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का पाटन करते हुए पाए गए हैं और यह कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत पर पाटन के मंदीकरण प्रभाव के कारण कीमत संबंधी क्षति हुई है। वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी के संदर्भ में कीमत संबंधी मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नियंत्रित रहा है।

146. इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना कीमत के मामले में पिछड़ गया है परन्तु यह अपनी क्षमता के उपयोग और घरेलू बिक्री को बढ़ाने में सक्षम हुआ है। इस मामले में क्षति का विश्लेषण क्षति की अवधि का केवल 24 महीने तक सीमित रहा है। जाँच की अवधि के बाद के आगे की 6 महीने की अवधि की भी जाँच की गई है जिसका उद्देश्य इस बात को समझना है कि घरेलू उद्योग शिथिलता के प्रभाव को दूर करने में सक्षम रहा है। कीमत पर ह्रास जाँच की अवधि के बाद की अवधि में जारी है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि 2 वर्षों की क्षति की अवधि के आधार पर, यह न्यायोचित नहीं होगा कि 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटन रोधी उपाय लगाए जाने की सिफारिश की जाए। इस कारण से प्राधिकारी अधिसूचना की तिथि से 18 महीने की अवधि के लिए ही पाटन रोधी उपाय की सिफारिश करने के लिए इसे उपयुक्त मानते हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि उस समय तक लगभग 5 वर्षों के लिए घरेलू उद्योग का प्रदर्शन आँकड़े उपलब्ध होंगे जो घरेलू उद्योग को याचिका दायर करने यदि ऐसा वे चाहें, के लिए सक्षम बना सकता है। उस समय प्राधिकारी इस स्थिति में होंगे कि वे घरेलू उद्योग को क्षति का मूल्यांकन करने के लिए क्षति की पूर्ण अवधि से संबंधित आँकड़े की जाँच कर सकेंगे।

147. प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन की मार्जिन और क्षति की मार्जिन में से कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। इस कारण से प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं कि वे नीचे दिए गए निर्धारित रूप में और तरीके से 18 महीने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करें।

**शुल्क तालिका**

सं.	शीर्ष /उप शीर्ष**	वस्तुओं विवरण *	क उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	39046990, 39049000 एवं 39046910	फ्लूरो इलेस्टोमर्स (एफकेएम)	चीन	चीन	इतर मंगोलिया 3एफ वानहाओ फ्लूरोकेमिकल कं. लि.('आईएम3एफ')	शंघाई हुआयी 3एफ न्यू मैटीरियल्स सेल्स कं. लि. ("एसएच 3एफ")	3.85	किग्रा.	अम.डॉ.
2.	39046990, 39049000 एवं 39046910	फ्लूरो इलेस्टोमर्स (एफकेएम)	चीन	चीन	मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं. लि.	मैसर्स सॉल्वे (शंघाई) कं. लि.	4.24	किग्रा.	अम.डॉ.
3.	39046990, 39049000 एवं 39046910	फ्लूरो इलेस्टोमर्स (एफकेएम)	चीन	चीन	चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टमर्स कं. लि.(सीएफएसई)	चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टमर्स कं. लि.(सीएफएसई)	3.6	किग्रा.	अम.डॉ.
4.	39046990, 39049000 एवं 39046910	फ्लूरो इलेस्टोमर्स (एफकेएम)	चीन	चीन	डेकन फ्लोरोकेमिकल्स (चाइना) कं. लि.	यूनआई एलाइंस लिमिटेड	0.078	किग्रा.	अम.डॉ.
5.	39046990, 39049000 एवं 39046910	फ्लूरो इलेस्टोमर्स (एफकेएम)	चीन	चीन	झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	3.56	किग्रा.	अम.डॉ.
6.	39046990, 39049000 एवं 39046910	फ्लूरो इलेस्टोमर्स (एफकेएम)	चीन	चीन	उपर्युक्त कं. सं. 1 से 5 से इतर अन्य कोई संयोजन		7.31	किग्रा.	अम.डॉ.
7.	39046990, 39049000 एवं 39046910	फ्लूरो इलेस्टोमर्स (एफकेएम)	चीन	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	7.31	किग्रा.	अम.डॉ.
8.	39046990, 39049000 एवं 39046910	फ्लूरो इलेस्टोमर्स (एफकेएम)	चीन	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	7.31	किग्रा.	अम.डॉ.

\* एफकेएम कंपाउंड और परफ्लूरोइलास्टोमर (एफएफकेएम) को संबद्ध सामानों के क्षेत्र से अलग किया जाता है।

\*\* आयात ITC हेड 39045090 के अन्तर्गत भी हुआ।

**त. आगे की प्रक्रिया**

148. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th December, 2018

**FINAL FINDINGS**

**Subject: Anti-dumping duty investigation on the imports of Fluoroelastomers, (FKM), originating in or exported from People's Republic of China**

1. **F. No. 6/25/2017/DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof.
2. And whereas, M/s Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter also referred to as “Petitioner” or “Applicant” or “domestic industry”) filed an application in the present case before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority), Directorate General of Trade Remedies in accordance with the Act and the Rules for initiation of anti-dumping investigation and imposition of appropriate duty thereof on dumped imports of “Fluoroelastomers”, also known as FKM, (hereinafter referred to as subject goods or product under consideration) originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter also referred to as subject country).
3. And whereas, the Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant justifying initiation of anti-dumping investigation, issued a public notice vide Notification No. 6/25/2017-DGAD dated 2<sup>nd</sup> January, 2018 in accordance with the Rule 5 of the Rules to examine and determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry

**(a) PROCEDURE**

4. Procedure described herein below has been followed with regard to this investigation, after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority:
  - i. The Authority notified the Embassy/Representatives of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
  - ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
  - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country and Importers/users in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
  - iv. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to the Embassy along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
  - v. The Authority sent Exporter's Questionnaire and Market Economy Treatment Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
    - a. M/s. Zhengxin Fluorocarbons, China PR
    - b. M/s. Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd, China PR

- c. M/s. Changzhou Xiangtong Chemical Co. Ltd, China PR
  - d. M/s. Taizhou Meilan Resin Process, China PR
  - e. M/s. ShanDong DongYue Polymer, China PR
  - f. M/s. DuPont (Changshu) Fluoro Technolozy Co. Ltd., China PR
  - g. M/s. Sichuan Chenguang Institute of Chemical Industry, China PR
  - h. M/s. Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd., China PR
  - i. M/s. Shanghai 3F New Materials Co., Ltd.,
  - j. M/s. Fuxin Hengtong Fluorine, China PR
  - k. Chenguang Research Institute of Chemical Industry, China PR
  - l. The Chemours Chemical (Shanghai) Co., Ltd., China PR
  - m. Daikin Flurochemicals (China) Co.Ltd., China PR
  - n. FluroChemicals Shanghai FluronTM Chemicals, China PR
  - o. Chengdu Dowhon Industrial, China PR
  - p. Solvay, China PR
  - q. Guangzhou Polain Chemical Technology Co.Ltd, China PR
  - r. Shandong Huaxia Shenzhou, China PR
  - s. Jiangsu Meilan Chemical Co. Ltd, China PR
  - t. Shanghai HeChang Flurocarbon Co Ltd, China PR
  - u. Wuxi Fuda Fluroplastics Co Ltd, China PR
  - v. Beijing Ruicheng Co Ltd., China PR
  - w. Kam Pin Paint Works Ltd, China PR
  - x. Hubei Danchang China Co.Ltd, China PR
  - y. Wuxi Ta Tang Compound Material Co Ltd, China PR
  - z. Shanghai Kinering Co Ltd, China PR
  - aa. Chenguang Fluoro & Silicone Polymer Co Ltd, China PR
- vi. In response to the above notification, the following exporters/ producers responded and submitted questionnaire responses.
- a. Solvay (Shanghai) Co., Ltd, China PR
  - b. M/s. Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co, China PR
  - c. Uni-Alliance Limited, China PR
  - d. Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd, China PR
  - e. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd, China PR
  - f. Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR
  - g. Shanghai 3F, China PR
  - h. Inner Mongolia 3F, China PR
- vii. Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR has filed the Market Economy Treatment Questionnaire response also.
- viii. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- a) Meen Been Elastomers
  - b) JMF Synthetic
  - c) Polmann India Ltd
  - d) BP Chemicals
  - e) Nishiganda Polymers
  - f) Hind Elastomers
  - g) Jayashree Polymers
  - h) Vikas Elastochem Agencies Pvt.ltd.,
  - i) Divekar W&S Precision Seals P.Ltd.
  - j) Devashish Polymers Pvt. Ltd.,
  - k) Nu-Cork Products (P) Ltd.
  - l) S.J.Rubber Industries Ltd.
  - m) M.K. Marketing
  - n) Zenith Industrial Rubber
  - o) Rawat Engg Tech. Pvt. Ltd.
  - p) Kokoku Intech India
  - q) BDS Polychem
- ix. In response to the above notification, the following importers/users responded and submitted questionnaire responses.
- a) Solvay Specialities India Private Limited
  - b) Eastcorp International
  - c) Nishigandha Polymers Pvt. Ltd
- x. Further, All India Rubber Industries Association, Jayem Auto Industries Pvt. Ltd, and Roop Polymers Ltd filed certain submissions opposing the petition and initiation thereof within the time limit prescribed by the Authority via the initiation notification.
- xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- xiii. The Non-Injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xiv. The Authority held an oral hearing on 29<sup>th</sup> May, 2018 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 6 (6), which was attended by the representatives of domestic industry and other interested parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and submit their rejoinders thereafter.



- xv. The verification of the information provided by the domestic industry was carried out to the extent considered necessary on 30<sup>th</sup>-31<sup>st</sup> May, 2018. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.
- xvi. Data verification through desk study of questionnaires filed by various producers/exporters was undertaken.
- xvii. Spot verification was carried out at the premises of M/s. Solvay Specialities India Private Limited to correlate to the extent possible their data with response filed by Solvay (Shanghai) Co., Ltd, China PR and M/s. Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co, China PR.
- xviii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is July, 2016 – June, 2017 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.
- xix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this Finding.
- xx. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- xxii. The Authority issued a disclosure statement under Rule 16 on 28<sup>th</sup> November, 2018 and provided an opportunity to give comments to the disclosure statement till 7<sup>th</sup> December, 2018.
- xxiii. “\*\*\*” in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules. ( ) bracket in this final finding indicates negative number/range.
- xxiv. Further post disclosure comments filed by the Domestic industry and various interested parties have also been appropriately considered in this finding.
- xxv. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.67.40 = 1 US\$.

#### **A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

##### **Submissions by Domestic industry**

5. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:

##### **About the product:**

- i. The product under consideration in the present investigation is “Fluoroelastomers (FKM)”. FKM is a class of synthetic rubber designed for very high temperature operation. With excellent over-all properties, it is called as the “Rubber King”. It contains not-fully-fluorinated molecular structure, and its main and side chains contain strong electronegativity of fluorine atoms. The C-F bond is stable because of its big energy (C-F bond energy 485 KJ/111 mol). Moreover, Fluorine atom covalent radius is 0.072 nm, nearly twice the size of a single hydrogen atom, equivalent to half of the C-C bond length of 0.131 nm, the fluorine atom is able to well shield the main chain of the carbon chain to ensure the stability of the C-C bond, so that the FKM has a prominent superior performance over the other rubbers.
- ii. There are various applications of Fluoroelastomers (FKM) such as industrial use in hydraulic O-ring seals, check valve balls, military flare binders, diaphragms, electrical connectors, flue duct exp.

joints, valve liners, roll covers, sheet stock / cut gaskets; automotive use in shaft seals, valve stem seals, fuel injector O-rings, fuel hoses, in tank and quick connect fuel system seals, gaskets (valve & manifold), bales for check valves, lathe cut gaskets; and aerospace use in O-ring seals in fuels, lubricants & hydraulic system, manifold gaskets and fuel tank bladders, firewall seals, engine lube siphon hose, clips for jet engines, tire valve stem seals.

- iii. Fluoroelastomers, a family of fluoropolymer rubbers, can be classified by their fluorine content, and can be 66%, 68%, & 70% respectively (with permissible tolerances). Fluoroelastomers having higher fluorine content have increasing fluids resistance derived from increasing fluorine levels. Peroxide cured fluoroelastomers have inherently better water, steam, and acid resistance. FKM's are broadly categorized in two sets- Copolymer and Terpolymer. Copolymers (F 66%) are pre-compounds and Terpolymers (F 67-70%) are Raw Gum. All forms of FKM are within the scope of the product under consideration. While the petitioner has given specific values for these product categories, it is clarified that these products are normally produced within a permissible tolerance. This gets clearly established by various technical literatures relating to the product under consideration. Thus, the Designated Authority may consider these specific values as "typical values" only.
- iv. The main fluoro elastomers compositions are shown below:
  - a. Copolymer fluoro elastomers:  $-(CF_2-CF)-(CH_2-CF_2)-CF_3$
  - b. Terpolymer fluoroelastomer:  $-(CF_2-CF)-(CH_2-CF_2)-(CF_2-CF_2)-CF_3$  – TFE level can be varied for different fluorine contents
  - c. Improved Low Temperature Fluoroelastomer Terpolymer  $-(CF_2-CF)-(CH_2-CF_2)-(CF_2-CF_2)-CF_3$  HFP replaced with fluoro-ether O-CF<sub>3</sub>
  - d. Non-VF<sub>2</sub> Fluoro elastomer Terpolymer:  $-(CF_2-CF)-(CH_2-CH_2)-(CF_2-CF_2)-CF_3$  VF<sub>2</sub> replaced with ethylene, imparts base /amine resistance O-CF<sub>3</sub>
- v. Based on the above combinations FKM can be majorly categorized into two types-
  - a. Copolymer FKM's are prepared out of vinylidene fluoride (VDF) and hexafluoropropylene (HEP). It has a significant temperature resistance, oxidation resistance, oil resistance and chemical resistance and good mechanical properties. With fluoride content of 66%, FKM is one of the best temperature resistance rubbers, and it can be used at 250°C for a longtime and at 300°C for short term.
  - b. Terpolymer FKM's are prepared out of vinylidene fluoride (VDF), tetra-fluoroethane (TFE) and Hexa fluoropropylene (HEP). Terpolymers can further be categorized in cured and curable Terpolymers. It can be cured with Amine/Bisphenol and Peroxide cure system. It has high chemical resistance and long-term heat resistance properties and with peroxide cure system FKM's also exhibit low temperature resistance properties. With fluorine content of 67-70%, FKM Terpolymers has higher acid, ketone and ester resistance than copolymers.
- vi. Petitioner has considered a PCN system for ensuring fair comparison of normal value, export price, domestic industry selling price and non-injurious price. Further, while the petitioner has categorized the product under consideration into four types, should the Designated Authority consider it necessary to further sub-divide these categories into specific product types, the petitioner shall provide relevant information to the Designated Authority.
- vii. The product does not have dedicated classification. The product under consideration is classified under Chapter 39 under customs subheading no 3904, 390469 and 39046990 of the Customs Tariff Act, 1975. It is however submitted that the customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

**Submissions regarding exclusion claims raised by other interested parties:**

- viii. The present petition is for consideration of whether dumping of the product under consideration is materially retarding establishment of the domestic industry. Since the domestic industry is not even fully established, it follows that the domestic industry may not have offered all the product types of

the product under consideration. Thus, absence of a particular product type by the petitioner does not imply a need for exclusion.

- ix. Notwithstanding, the petitioner has already offered like article to all the product forms being imported from China. Relevant details have already been provided.
- x. The argument with respect to negligible quantity of one type of product under consideration cannot be accepted because volume of imports must be seen for product under consideration as a whole and not one or few product types. Further, the interested parties themselves conceded at the time of hearing that the actual volume of imports is far higher. The Designated Authority may kindly consider questionnaire response on record from the exporters.

**Submission regarding quality concerns raised by other interested parties:**

- xi. At the outset, responding to the concerns about the quality of the domestic industry product, petitioner has submitted as follows
  - a. There is no express legal provision under the law dealing with the issue of product under consideration, its scope and how the same should be defined/determined. However, there is enough guidance and jurisprudence in the decisions taken by the WTO Panels / Appellate Body as well as by the Hon'ble Designated Authority on the subject which the Domestic Industry would like to rely upon in the event interested party pursue their argument with substantive claims supported by due evidence.
  - b. All products which qualify as a like product remains as a part of the product under consideration. It is for the party claiming exclusion to prove with requisite evidence that the domestic industry has not offered like article to any particular product type imported into India.
  - c. The domestic industry has also provided details of various customers to whom domestic industry has sold the material. These consumers collectively command majority of the consumption of product under consideration in India as far as supplies by China and Indian producers are concerned. If some consumer has preferred not to buy petitioner's product due to other factors, such as price of Chinese product. Merely because one of the consumers is not able to use the goods produced and supplied by the petitioners when other consumers in the same segment have used and produced the eventual end product, does not justify exclusion of a product type.
  - d. The import data shows shifting of significant volume of imports from third countries to China. This shift was not driven out of technical considerations but driven out of commercial considerations and low price at which Chinese producers are willing to sell the product.
  - e. While contending that the quality of the petitioner's product is bad, the interested parties have not even specified the meaning of quality. The Designated Authority considers technical and commercial parameters. The interested party should have identified the technical parameters that are so different in petitioner's product which renders it un-substitutable to the imported product.
  - f. Quality is not a relevant parameter in anti-dumping investigations in consideration to like product determination, particularly when the claim of poor quality is neither substantiated nor quantified.
  - g. The Hon'ble Authority in a number of past investigations (such as USB Flash Drives, Bus and Truck Radial Tyres, Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels, Phenol and EPDM) has consistently held that quality is not a relevant consideration to like product determination. The same has been upheld by the Hon'ble CESTAT in the matter of *DSM Idemitsu Limited Versus Designated Authority*.
  - h. In past about 44% of FKM market was supplied by non-Chinese suppliers. The share of Chinese suppliers rose from 32% in 2014-15 to 43% in POI, while on the other hand, the share of non-Chinese supplies declined from 68% in 2014-15 to 44% in POI. These shifts from non-Chinese sources to Chinese sources is clearly driven out of significant price difference between Chinese and non-Chinese suppliers.
  - i. The quality issue is just a ploy used by the importers and users to pressurize the domestic industry to reduce their prices. Therefore, the argument relating to quality issues must be rejected by the

Authority on its merit, legal premise and the consistent practice of the Authority, as reflected in a plethora of decisions.

- j. In this context, AIRIA has merely made hollow claims regarding rejection of their finished goods due to the use of inferior quality domestic supplies. The same is factually incorrect and misleading. In any case, even the returns received by the Domestic Industry on account of quality issues are very less as compared to the volume sold.
- k. As regards the argument with respect to sales realization, while the inferior quality claims of the domestic industry's goods have been addressed, the technology as also the production process for producing subject goods have not undergone any significant development and the technology employed by the company is at par with the world class technology. As GFL has the world class manufacturing facility with advanced process and quality control. It has a separate pilot plant for FKM new grade developments supported by R&D laboratory. Moreover, their FKM Quality control laboratory is fully equipped with globally renowned testing equipment's able to deliver high degree of accuracy, precision and reliability in test results. Therefore, the only factor actually responsible for the negative sales realization is aggressive dumping by the Chinese producers.
- xii. The prices of Chinese suppliers on an average have been lower than non-Chinese suppliers, by Rs. 908 per kg in POI only. This in itself evidences the dumping behavior of the Chinese suppliers. But, in fact, the petitioner does not even intend to charge the price that is being charged by the non-Chinese suppliers. The petitioner has in fact targeted the price which is at the middle of the price at which the Chinese and non-Chinese suppliers have supplied the material in the Indian market.
- xiii. The fact that Chinese producers actually resorted to dumping in this range of products further gets established by significant dumping that has been found by the US authorities. While US authorities determined dumping margin of 18.49% in respect of Indian suppliers i.e. for Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL), US authorities have found a dumping margin of 84.75 % in respect of Chinese suppliers i.e. for Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd. As far as GFL is concerned, it is conceded that Indian producers were forced to sell in US market at low price only because the Chinese producers exported their products at very low price to US market.
- xiv. Besides, if there may be any other factor, existence of other factors causing injury does not vitiate or breaks the causal link between dumping from China and injury to the domestic industry so as to conclude no injury on account of dumped imports from China. The petitioner refers and relies on WTO Panel Report in the matter of Thailand – Anti-Dumping Duties on Angles, Shapes and Sections of Iron or Non-Alloy Steel and H-Beams from Poland.

**Submissions regarding other product issues:**

- xv. The Government of India has not mandated any prescriptions for the product under consideration. The Designated Authority should consider only such prescriptions as have been laid down by a competent authority in the Country and not which are not in the prescription standards. Under the rules, the domestic industry is required to offer like article. Merely because the product supplied by the exporter is patented does not imply that the domestic industry does not supply like article.
- xvi. The petitioner has provided all the relevant information with regard to the raw materials used and its cost. While the purchased raw material is valued at delivered cost, the captively produced raw material is transferred at cost of production. The only two raw materials i.e. Hexa fluoro propylene (HFP) and TFE are used captively for the production of FKM, which the company transfers it, at cost to the product under consideration.
- xvii. It is indeed correct that FKM is a special product used in highly specialized applications and for its quality assurance GFL has the world class manufacturing facility with advanced process and quality control. GFL has separate pilot plant for FKM new grade developments supported by R&D laboratory. Besides, FKM Quality control laboratory is fully equipped with globally renowned testing equipment's able to deliver high degree of accuracy, precision and reliability in test results. Moreover, since the end usage of PTFE and FKM are totally different, the end users are also different. Hence it is not correct to allude that PTFE customer base can be used for FKM.

**Like article:**

- xviii. None of the Chinese exporters have declared the product type exported by them in their exporter questionnaire response. The petitioner requests the authority to kindly disclose the product types that have been exported to India during the relevant period by each of the responding exporters so as to enable it to identify the like article that is being offered by the petitioner in competition to the imported product. The petitioner shall identify a like article to such imported product. There can be nothing confidential as far as the product type that has been exported to India.
- xix. There is no known difference in the product under consideration exported from China PR and that produced by the Indian industry. In the present case, both the imported and the domestic product have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable.

**Submissions by exporters, importers and other interested parties**

- 6. The following are the submissions made by exporters/importers/other interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article:

**Exclusion claimed by other interested parties:**

- i. As, per the import data submitted by the Domestic Industry, only 2 categories i.e. Copolymer Pre-Compound and Copolymer Raw gum are imported. Terpolymer category is not imported into India and the end product requirements for such type of product are also different.
- ii. It is requested that the Authority issues a clarification at the earliest that FKM Compounds and Perfluoroelastomer (Commonly known as “FFKM”) are not covered within the scope of the present investigation. In petition, it was stated that FKM imported to India consists of only two types (Raw Gum and Pre-compound). Petitioner is not manufacturing FKM Compounds and FFKM. They do not fall within the scope of product under consideration. Secondly, Raw Gum and Pre-compound are Intermediate products and FKM Compounds and FFKM are final products so they’re not ‘like products.’
- iii. The import statement at Page No. 47 of the non-confidential version of the petition depicts that only 6 MT copolymer raw gum is imported from China PR. How such negligible quantities of 6 MT can cause injury to the Domestic Industry.

**Quality & Grades**

- iv. The producers produce select grades of FKM as per requirement. One to one grade comparison between any two producers is not possible. Each manufacturer has its own specialty grades which are not easily replaceable by other manufacturers. Substitution of a grade is difficult and is only possible if a superior grade is developed.
- v. Price is not a major factor while choosing a new grade or for grade substitution. Choice of grade is made on the basis of quality, process acceptability, requirement of the end user and not price.
- vi. Imported goods are of better quality than that produced by domestic industry which is inconsistent as well. Domestic industry being a new entrant has not developed all grades yet, required by the Indian industry including automobile companies. As such rubber processors in India cannot rely on GFL to meet their demand. The quality is important as the products manufactured using FKM are used as important safety products in the vehicle.
  - a. Many members of AIRIA have tried the products of domestic industry and found the same to be of inferior quality and some grades were rejected by the production department.
  - b. Final customers of FKM based products are big automobile companies which will not accept any quality deviation in their product, forcing the rubber processors to buy expensive imported products.

- vii. Major end users are large multinational companies which generally specify the grade of FKM to be used from a particular manufacturer for each of their product in order to maintain the quality standards.
- viii. The decline in sales realization of the domestic industry could be attributed to the inferior quality of the product due to the inferior technology employed by the domestic industry.
- ix. The claim made by the petitioner that quality is not a relevant parameter in anti-dumping investigations in consideration to like product determination, particularly when the claim of poor quality is not quantified is misplaced. All the cases that the petitioner has referred to are of injury and not of material retardation. In the case of material retardation, quality is a major concern since in such case domestic industry might be suffering on account of the inferior quality of its products.
- x. The petitioner is a new industry and its product is of inferior quality. The subject goods is used in Aero-Space, Oil Refineries and other industries. The product manufactured using FKM are used as important safety products, and therefore, any compromise with the quality of subject goods will adversely impact the business of the user industry.
- xi. If the quality of subject goods was indeed at par with that of imports from China, it ought to have been able to capture its expected and desired market share. The Domestic Industry has also referred to the declining imports from other countries to contend that the domestic market is price sensitive and therefore, since the prices from China reduced, the users shifted to sourcing the subject goods from China. However, this submission is misplaced inasmuch as had the aforesaid assertion of the Domestic Industry been true, it would have dominated the domestic market of the subject goods in India as it has consistently been selling its product at a price which is much lower than that of China.
- xii. Most of major auto OEM have rejected the material produced by the domestic industry due to quality issues. Hitech Arai which accounts for almost 30% of India's FKM demand appeared for the oral hearing to put forward its complaint.
- xiii. The petitioner has failed to inform why in spite of manufacturing FKM since last 3 years they do not have a single auto OEM (from companies such as Suzuki, Hero, Toyota etc.) approval for their product. GFL grades have failed to meet the stringent requirement of auto-companies. Further, the rubber companies have to use the specified grades, without any deviation of grade/manufacturer allowed at their end. As such any additional duty will only be counter-productive as the Indian rubber companies shall be forced to buy the specific imported grade at a higher price.
- xiv. The manufacturer of the subject product knows that the rubber industry has no choice but to use their grade for a particular auto-component (as the name of manufacturer along with grade is mentioned in the component drawing released by the auto company), as such the manufacturer have no reason to dump the material at a lower cost.
- xv. In case of a product like FKM, quality is the most important aspect to be taken care of. The use of FKM products are very crucial and used in the manufacturing of safety products, one should take extreme care while choosing the grades without taking any risks. Use of any inferior quality of product may risk the life of people using the final product. The final customers of FKM based products are big automobile companies.

#### **Other Issues**

- xvi. The entire existence of Zhonghao Chenguang is based on development of new technology and strong R&D towards fluoroelastomer technology. This has helped Zhonghao Chenguang hold more than 20 patents worldwide primarily in USA, Japan, Europe and South Korea. Many of these patented grades and technologies are exclusive to Zhonghao Chenguang and are not available with GFL
- xvii. Petitioner has not given any indication of the raw materials used in the production of Fluoroelastomers. In multi-product companies like Gujarat Fluorochemicals Ltd., raw material is captively produced or purchased for the production of different products. The petitioner has not provided any information about the distribution of cost of raw material. The Domestic Industry

- may please be advised to submit the details of transfer pricing at which the raw material was transferred for the captive consumption to produce Fluoroelastomers.
- xviii. FKM is used for highly specialized applications and has to undergo rigorous testing and approval procedures by the user industry before being accepted. And GFL could acquire the market share despite the rigorous requirements because of its established market hold in the production line of PTFE, which enabled them to leverage its existing customer base.
- xix. As per domestic industry, FKM is categorized in two types co-polymer & ter-polymer. The monomer used in making co-polymer is HFP & VDF whereas for ter-polymer it is HFP, VDF & TFE. VDF, PVME and Cure Site monomer (4<sup>th</sup> monomer) are a very important monomers used in manufacturing Terpolymer FKM, Co-Polymer FKM, Low Temperature Resistant FKM & Peroxide Curable FKM but the domestic industry GFL is not manufacturing the same and is dependent on imports which gives a major disadvantage not only in price but also in quality consistency. Further very importantly they do not have the technology to make high end peroxide curable FKM which is major hinderance to meet the latest BSVI norms and exceed the automobile safety requirements.
- xx. Fluorspar is another major raw material for the production of FKM. China is one of the few countries in the world which has huge availability of very high purity Fluorspar, due to which most global manufacturers such as Zhonghao Chenguang, Solvay, Daikin have set up their plants in China. This helps these company to get Fluorspar not only at a competitive price but also ensure utmost quality of FKM.
- xxi. Curatives which again is an important raw material for making FKM Pre-compounds is not manufactured in India. Chemicals which are used in making curatives is not being produced in India. Therefore, the domestic industry is again dependent on the imports for buying curatives whereas there are many manufacturers of curative chemicals in China. This gives another added advantage to manufacture FKM pre-compounds in China.
- xxii. It is submitted that while indicating the average landed price of other countries and China in table given in Para 43, Domestic Industry has purposely not classified the type of FKM exported by these countries. China is exporting only co-polymer pre-compound and co-polymer gum but from other countries, majorly high-end specialty grades basically ter-polymers are exported to India. More than 70% of material exported from other countries are ter-polymers and specialty grades. There is a huge difference in prices of co-polymer grades and specialty terpolymer grades, which the domestic industry has purposely ignored. In fact, some of the grades exported are very special grades such as extreme low temperature grades, extreme high temperature resistance grades which are multiples time more expensive. This has led to increase in average export price from other countries, as such there cannot be any comparison between the price of other countries and export price of China. For any comparison to be made, the price of only co-polymer pre-compound exported from China should be compared with copolymer pre-compound price from other countries. The Designated Authority is requested to consider the above facts.

#### **Examination by the Authority**

7. The Authority notes that the product under consideration has been comprehensively defined in the Initiation Notification dated January 02, 2018 as under;

*“The product under consideration (PUC) in the present investigation is Fluoroelastomers (FKM). Fluoroelastomers (FKM) is a class of synthetic rubber designed for very high temperature operation. With excellent over-all properties, Fluoroelastomers (FKM) is called as the "Rubber King. It contains not-fully fluorinated molecular structure, and its main and side chains contain strong electronegativity of fluorine atoms. "Fluoroelastomers" are a family of fluoropolymer rubbers, not a single entity. It can be classified by their fluorine content, 66%, 68%, & 70% respectively. FKMs are broadly categorized in two sets - Copolymer and Terpolymer.*

*There are various applications of Fluoroelastomers (FKM) such as industrial use in hydraulic O-ring seals, check valve balls, electrical connectors, automotive use in shaft seals, fuel injector O-rings, and aerospace use in O-ring seals in fuels, lubricants & hydraulic system, manifold gaskets and fuel tank bladders.”*

8. The two main fluoro elastomers categories based on monomers, fluoroine content and curatives, are as follow

**a) Copolymer fluoroelastomers (F 66%):**

These are prepared out of vinylidene fluoride (VDF) and hexafluoropropylene (HFP). Co-polymer FKM can be in two forms i.e. Raw Gum and Pre-Compound. It has a significant temperature, oxidation, oil and chemical resistance and good mechanical properties. With fluorine content of 66%, FKM is one of the best temperature resistance rubbers, and it can be used at 250°C for a long time and at 300°C for short time.

**b) Terpolymer fluoroelastomers (F 67-70%):**

- These are prepared using vinylidene fluoride (VDF), tetra-fluoroethane (TFE) and Hexa fluoropropylene i.e HFP or propylene or Perfluoromethylvinylether (PMVE). Terpolymer FKM can be in two forms i.e. Raw Gum and Pre-Compound. It can be cured with curatives i.e Amine, Bisphenol and Peroxide. It has high chemical and long-term heat resistance properties. With fluorine content of 67-70%, Terpolymers FKM has higher acid, ketone and ester resistance than copolymers.

9. The Authority notes various submissions and aspects regarding the scope of the product.

- 1) The domestic industry based on the scope of the product range manufactured by them in the period of investigation have provided the following PCNs, post initiation:

SN	Name of Product Type	PCN	Description of PCN
1	Copolymer Raw gum	FCP#RG0001	Fluoroelastomers (FKM) Co-Polymer Raw Gum
2	Copolymer Pre-Compound	FCP#PC0004	Fluoroelastomers (FKM) Copolymer Pre-Compound
3	Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum	FTPBRG0002	Fluoroelastomers (FKM) Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum
4	Terpolymer Peroxide Curable Raw Gum	FTPPRG0003	Fluoroelastomers (FKM) Terpolymer Peroxide Curable Raw Gum

- 2) The response filed by the producers/exporters include exports of 'Terpolymer Pre compound also.
- 3) Some interested parties have requested for excluding FKM compounds from the scope of PUC.
10. The Authority in view of the aforesaid, holds that the PUC i.e. Fluoroelastomers includes copolymer and terpolymer both in raw gum and pre-compound form and of different types. Compounds and FFKM are excluded from the scope of PUC. The types (PCN) stated by the DI in their submission have been considered for evaluating Dumping Margin and injury Margin separately for different types (PCN's) of PUC. The Authority notes that DI has capability to produce terpolymer pre-compound also besides terpolymer raw gum. Though the terpolymer pre-compound has not been produced by domestic industry during POI and has been produced in post POI, the DI has provided information regarding value addition for raw gum to pre compound for terpolymer category. The Authority has evaluated dumping and injury margin for the terpolymer pre-compound also by factoring the aforesaid value addition.

## **B. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

### **Submissions by the Domestic Industry**

11. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:
- i. The petition has been filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter also referred to as "GFL"). The domestic industry is the sole producer of the product concerned. Thus, production of the producer commands 100% of the total Indian production.



- ii. The petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and is not related to any exporter or producer of the subject goods in China PR or any importer or user of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).
- iii. The petitioner has sufficient standing and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

**Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties**

12. None of the interested parties has raised any issues with respect to the standing of the applicant in the present investigation.

**Examination by the Authority**

13. Rule 2 (b) of the AD rules defines the domestic industry as under: “  
*(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”*
14. The application has been filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. as the domestic industry. As per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes “a major proportion” of the domestic production; in fact, 100% share of domestic production.
15. It is further noted that they have neither imported the product under consideration, nor they are related to any importer or exporter of the product under consideration.
16. Considering the information provided and submissions made by various interested parties and legal provision, the authority determines that the application has been filed by the domestic industry and the application satisfies the requirements of ‘standing’ under Rule 5 of the AD Rules. The Petitioner constitutes ‘Domestic Industry’ in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

**C. CONFIDENTIALITY**

**Submissions by Domestic industry**

17. The Domestic Industry made the following submissions:
  - i. The responding exporters have claimed excessive confidentiality without any proper justification. In the absence of even indexed information, the Domestic Industry is totally handicapped in defending its interests and offering its comments on these highly deficient responses.
  - ii. The exporters chose to keep the information pertaining to shareholders and related parties completely confidential. It is stressed here that this information is in public domain and does not merit any confidentiality.
  - iii. The petitioner has claimed only such information confidential which is not in public domain and for which there is no mandatory requirement for disclosure in the Country.
  - iv. Disclosure of actual information with regard to petitioners’ domestic industry can also jeopardize the future business in the product. The information can be gold mine information for a prospective Indian Producer trying to set up a plant in India, having no definitive information about the actual current performance of current producers.
  - v. The information provided in Section VI relates to costing and pricing of the subject goods produced and sold by the domestic industry and none of this information is available in public domain.
  - vi. The Petitioner has provided all the information as per the prescribed format including the Annual Report to the Authority on confidential basis.

- vii. The petitioner has defined, for the purpose of the present petition, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales and imports from all sources. The information related to domestic sales of the domestic industry is highly confidential, disclosure of which would cause serious prejudice to the domestic industry. Such claim of the domestic industry is consistent with law and past practice of DGAD.
- viii. As regards the non-disclosure of information relating to price effect, there is no requirement under the law for such information. The requirement is for profits, cash profits and ROI for which information has already been provided.

**Submissions by exporter, importer and other interested parties**

18. The exporter, importer and other interested parties made the following submissions:
- i. The petitioner has claimed excessive confidentiality and thus, the right of defense cannot be fully exercised. The petition fails to meet the standards laid down in Rule-7 of the Rules and Trade Notice No. 01/2013 dated December 09, 2013 and is in violation of principles of natural justice.
  - ii. In response to Section VI of the application, the petitioner has not furnished any information at all.
  - iii. Various question of Part 6 is answered as - “as per annual report” and GFL being a multi-product company, this answer is misleading.
  - iv. Information related to demand, price effect has been confidential without any reason.
  - v. The respondent has claimed only such information as confidential, which is business sensitive and not available in the public domain. On the contrary, the petitioner has itself claimed confidentiality on number of parameters like production, domestic sales, and demand and market share of petitioner in Indian demand. Reference is made the Findings in anti-dumping investigation against imports of Sheet Glass from China PR (F.No.14/22/2013-DGAD dated 19<sup>th</sup> December, 2014)
  - vi. The claims of the Domestic Industry regarding excessive confidentiality being claimed by the Respondents is not only vague as they have not stated exactly what would constitute a proper statement of reasons other than what has already been provided by the Respondents but is also entirely contradictory inasmuch as a bare perusal of the Domestic Industry’s own petition will reveal that the reason assigned by it while claiming confidentiality has been succinctly stated as “business proprietary information not amenable to summarization” without any further statement of reasons in respect thereof.
  - vii. By virtue of the doctrine of election, the Domestic industry cannot approbate and reprobate at the same time and is estopped from contending that the Exporters and Producers in China have to provide indexed figures of their data or any further statement of reasons for claiming confidentiality beyond what is already provided. Reference is made to the judgment by House of Lords in *Lissenden v. Bosch Ltd.*, 1940 AC 412 in this regard.
  - viii. DI has claimed about numbers of programs being run by the Govt. of China wherein benefits are being provided to the producers/exporters. AIRIA therefore submits that the Domestic Industry has not furnished any evidence to substantiate the above claim. The petitioner is trying to mislead the Authority. The claims made by Domestic Industry are irrelevant and not substantial.
  - ix. Zhonghao Chenguang has provided all the information as per the rules and also enclosed the justification table clarifying the reasons for claiming the confidentiality.
  - x. Daikin and Uni-Alliance Ltd. have provided all the information as per above mentioned rule and also enclosed the justification table clarifying the reasons for claiming the confidentiality. The claims of the Domestic Industry that excessive confidentiality is claimed is irrelevant. However, Daikin and Uni-Alliance Ltd. are ready to provide any further information as may be required by the Designated Authority for concluding the present investigation.

**EXAMINATION BY AUTHORITY**

19. Submissions made by interested parties with regard to confidentiality as considered relevant have been examined and addressed accordingly in the light of legal provisions and the consistent practices adopted by the Authority. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has not been disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority notes that any information which is available in the public domain has not been treated as confidential. The Authority notes that the disclosure of the total export sales of all cooperating Producers/Exporters has been reacted to by certain Producers/Exporters. Since there are many PCN's the Authority has disclosed total sales of all cooperating producers/exporters and also production, Capacity and domestic sales of DI for all PCN's cumulatively in this finding. The Authority also notes that product description in the DGCIS transaction wise data more or less reveals the production source of PUC

**D. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS****Domestic industry**

20. The Domestic Industry made the following submissions:
- i. False and misleading statements have been made by the exporters in the questionnaire response regarding absence of any subsidies by the Chinese government since there are non-exhaustive list provided by the petitioner stating the programs that are being run by the Government of China wherein benefits are being provided to the exporters.
  - ii. The injury submissions made by the petitioner are on the basis of domestic sales and not exports. The Authority may verify.
  - iii. Besides, the respondent has alleged that the information provided by the petitioner is "manipulated and is incorrect" and this allegation is based, as stated, "As per data available with [them]", relating to GFL's export slump. The respondent cannot base their arguments on mere surmises and conjectures as the said data is nowhere presented. If something has been given to the Designated Authority on confidential basis, the same must be disclosed to the petitioner.
  - iv. As regards the allegation that the annual report curated in a certain manner to show material retardation, a reputed company like GFL is very prudent in their business activities and they do not resort to such unethical practices.
  - v. Anti-dumping duty on other products doesn't have relevance here. The applicant is a multi-product company and if the Government have imposed antidumping duty on some of their products after due investigation, they cannot be faltered for approaching the authority for levy of anti-dumping duty on the subject goods as per law. The information related to product under consideration in the present investigation is only relevant.
  - vi. The public statements in the Annual Report do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the domestic industry.
  - vii. Designated Authority is concerned about domestic operations of the subject goods, whereas the Annual Reports are concerned about company's overall operations.
  - viii. Projections made were reasonable. The Designated Authority may examine. The petitioner has large network of dealers/ distributors. It is not a case wherein the petitioning company is a new company. GFL is a well-known, well established and reputed name in the Country and is known for its products and quality. Had the petitioning company been inefficient or unable to manage its business, it would not have been successful in its other businesses.

- ix. The respondents are making baseless claims regarding non-delivery without any material to substantiate the same in order to mislead the Designated Authority.
- x. It is by now a well settled principle of law that demand-supply gap is not a ground for non-imposition of anti-dumping duty. Imposition of anti-dumping duty is against the unfair trade practice being practiced by the exporters and aims at providing a level playing field to the domestic industry. It does not bar imports.
- xi. The argument relating to inappropriate protection measures cannot be accepted as such submissions are full of conjectures & surmises, not backed with any study and contrary to the experience gained in case of petitioner itself where the petitioner has not only grown in PTFE, but also the consumers have grown and the petitioner has become more competitive. Had the arguments of the interested parties were to be true, there would not have been an option with the industry in developing and nascent stage to approach the Authority in case of being injured due to injurious effects of dumping, there would not have been any concept called material retardation recognized by WTO and worldwide.
- xii. There has been no change in the data and no different sets of data have been provided. The only difference is that quarterly data with regard to capacity, gross production, net production and capacity utilization have been provided in the pre-hearing submissions whereas in the petition, only yearly data has been provided. The Authority may verify.
- xiii. It is expressly clarified that the error is in the analysis conducted in the petition and there is no error in the data/information filed with the petition. The authority may kindly consider the data contained in the petition and the analysis in the pre-hearing written submissions and submissions made thereafter. It is pointed out in this regard that it is the data / information contained in the petition which has formed the basis for initiation.
- xiv. The petitioner has not provided details of capacity utilization considering net production. The Authority may verify.
- xv. The arguments regarding existence of basic customs duty of 7.5% is irrelevant if the subject goods are being dumped in India and the domestic industry is still suffering injury despite this customs duty. Both are different not only in concept and substance, but also in purpose and operation.
- xvi. FKM is produced globally in India, China, Europe, USA, Japan & Russia. The capacity of major global producers of FKM is 49,560 MT, out of which China's capacity is 22,500 MT.

**Issues regarding monopoly**

- xvii. The apprehension of the respondents that the imposition of duty would lead to monopolistic situation is baseless. The anti-dumping law does not bar the sole producer from being considered as domestic industry.
- xviii. There have been a number of anti-dumping investigations wherein the domestic industry was the sole producer of the product concerned in India and the Authority has recommended imposition of antidumping duty.
- xix. The anti-dumping duties are not detrimental to the importing country. Rather it tries to curb a foreign unfair trade practice.
- xx. The purpose of anti-dumping is not to create monopolistic situations. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The purpose of the anti-dumping law is to create a level playing field for production and consumption of the goods in the Indian market by protecting domestic production of the goods against unfair trade practices of producers from other countries. Existence and sustainability of a domestic production base is important for general economic development which has to be protected against injurious dumping.

**Submissions regarding impact on other products/industries and public interest**

- xxi. As regards the argument of force majeure creating a shortage, it is without any basis and irrelevant in an anti-dumping investigation. Accidents that could not be foreseen cannot be a ground for justifying an act which is in human control i.e. adopting the dumping practice.
- xxii. These issues of carbon black are not in relevance to the case in hand. Shortage of any other product does not have relevance in an anti-dumping investigation. The information related to product under consideration is only relevant.
- xxiii. The respondent has not furnished any evidence to show the impact on growth of the MSME sector. Nonetheless, the domestic industry is seeking relief under the law for the injury suffered by it due to dumped imports.
- xxiv. Anti-dumping measures are not protectionist in nature. Anti-dumping regime is designed to provide relief for aggrieved industries from this unfair trade practice. Anti-dumping duty laws are not designed to exclude or limit imports which compete with domestic products. Rather, they are designed to deter foreign producers from using discriminatory pricing practices to injure domestic industries.
- xxv. As regards the contention with respect to increase in product costs, the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India for a short term. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures.
- xxvi. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from subject country in any manner and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain multiple sources of supply.
- xxvii. Non-imposition of the anti-dumping duty would bear more devastating effects on the country than the imposition of the duty. The non-imposition of duty would lead to decimation of production of this critical product in India. The effect of such dumped imports is already seen on the domestic industry. The effect on the downstream industry will be miniscule.
- xxviii. Anti-dumping measures are to ensure fair trade and provide a level-playing field to the domestic industry. They are not a measure to restrict import or cause an unjustified increase in cost of products. The purpose of the present petition is not to take any kind of undue advantage. The petitioner simply wishes the unfair dumping to be checked so that the petitioner can fully establish itself in the market and cater to the requirements of the consumers at fair price, while earning reasonable return on the investments made. It is more justified as it is the sole producer in the country.
- xxix. The argument relating to the pleading of MSME sector is actually fallacious and misleading. In fact, as stated, about 90% of FKM demand in the past was being met by non-Chinese suppliers, while 48% demand in 2016-17 and 44% demand in POI was being catered by non-Chinese suppliers in the relevant period at a price which were almost double that of the price at which Chinese suppliers were selling in the market. If these MSME consumers could merrily buy the material from non-Chinese sources at such a high price and could not only survive but also grow, there is no basis for the argument that these Chinese suppliers will suffer as a result of imposition of anti-dumping duty.
- xxx. Besides, the petitioner has faced the same experience in PTFE where production is again in MSME sector. Despite ADD on PTFE for quite some time, the PTFE market has grown from 1729 MT in 2005-06 to 6800 MT in 2016-17. PTFE market has grown despite the anti-dumping duty. The facts here clearly evince that the MSME sector in the product under consideration shall not suffer as a result of proposed anti-dumping duty. In any event, the petitioner submits that the consumers have not furnished any evidence or verifiable information to establish their claim.

- xxxi. It is also relevant to point out that the arguments are being advanced in the name of MSME sector, whereas the fact is that a number of consumers of the product under consideration are in fact companies having significant turnover.

**Submissions regarding NIP claims:**

- xxxii. The Authority may provide ROCE as per its consistent practice, even though the domestic industry has sought higher ROCE.
- xxxiii. The DA has a practice to allow 22% return in all situations and, therefore, principles of equity demand that the same is applied to all situations. The DA should not accept pick and choose policy and approach of interested parties.
- xxxiv. The submission of the interested parties in this regard has no merit as the Authority has been allowing the return on capital employed at 22% almost in every case for the last so many years without considering the actual rate of return earned by the domestic industry during the period when there was no dumping.
- xxxv. The present case is a case where dumping is materially retarding establishment of the domestic industry in the Country. Further, such being an issue with respect to policy and practice of DGAD, the Authority may decide appropriately as it deems fit.

**Submissions by exporter, importer and other interested parties**

21. The exporters, importers and other interested parties made the following submissions:

**Miscellaneous Issues**

- i. Letter filed by the Domestic Industry claims that exports by Domestic Industry have increased substantially. Data available with respondents shows huge slump in export of subject goods.
- ii. Annual report drafted by GFL should not be relied upon as they might have intentionally curated the same in a way to show material retardation.
- iii. GFL is a habitual petitioner for imposition of anti-dumping duties on various imported products.
- iv. Financial statement of GFL discloses healthy profit earned by the company during POI disputing their own claim of suffering loss.
- v. While comparing domestic industry's actual performance to projections it is essential to examine the reasonableness of the assumptions made by domestic industry in its project report since petitioner is new in this industry.
- vi. There is demand and supply gap in country. The domestic industry is focusing on exports. Many times, it fails to deliver on time due to non-availability of subject goods.
- vii. Inappropriate protection measures not only protect the domestic industry but may damage its long term and fundamental interest. It may cause domestic industry reluctant to improve the production technology and efficiency.
- viii. Two petitions have been filed and petitioner claims that no error in data or information filed with original petition. But in fact, different sets of data have been provided in petition and pre-hearing submission for Capacity, Gross Production, Net Production and Capacity Utilization.
- ix. The petitioner may have provided details of capacity utilization considering net production with objective of undermining actual capacity utilization to demonstrate a non-existent injury.
- x. Respondent requests the Authority to compare both the import and the petitioner's data considering 2015-16 as the base year, since domestic industry started production from July 2015 and the period of injury of current investigation is 2014-15, 2015-16, 2016-17 and POI.
- xi. There is already basic customs duty of 7.5% and any additional duty will only block exports from China PR.

- xii. The request made by the petitioner to the Authority to direct the producers / exporters to file the information in terms of Trade Notice No. 5/2018 dated 28th February, 2018 is wrong as the Trade Notice No. 5/2018 is applicable for investigation initiated after 28th February, 2018. The respondent has filed the response in the correct applicable Proforma.
- xiii. The petitioner is a habitual user of trade remedial measures and is suffering on account of the inferior quality of its product, inefficiencies and market entry strategy. The same gets substantiated by the fact that the petitioner has also suffered huge losses in the export market.
- xiv. The reference made by the petitioner to the US determination is irrelevant here. The complete details have been filed with the Authority. Further, as per the findings of the US Authorities, petitioner has also dumped subject goods in the US Market.
- xv. The petitioner has provided different sets of data for the year 2016-17 in the petition, pre-hearing written submissions and written submissions. This raises serious doubts about the veracity of the data filed by the petitioner to allege a non-existent injury.
- xvi. The petitioner has claimed that it has already supplied the PUC to a large number of consumers. It is in operations since almost last 3 years. Thus, the petitioner is well established industry. Therefore, the respondent request the Authority to terminate the investigation outright as material retardation measure is only for that industry, which has not been established yet.
- xvii. The Domestic Industry's previous experience with anti-dumping duties were referred by the Respondents to caution the DA of the fact that project reports and market feasibility tests would not be safe to be relied upon in the instant case as the Domestic Industry, being well versed with the nuances involved in an anti-dumping investigation, would be in a position to manipulate its projections in order to benchmark its actual performance to show that it has not been able to meet its expected performance which may not be realistic otherwise and thereby, show material retardation to its establishment. The Domestic Industry has intentionally priced its goods at a price much lower than that of imports from China in order to incur losses in its books for the purpose of showing injury to it.
- xviii. The reliance placed upon the determination by USDOC in the anti-dumping investigation to showcase that the dumping margin determined against Chinese suppliers was to the extent of 84.75% is irrelevant as the same pertains to PTFE and not FKM.
- xix. Domestic Industry has compared the market performance of PTFE with FKM. This argument itself proves misconstruction of facts by the domestic industry, reason being:
  - a. There are 2 manufacturers of PTFE in India including GFL, which ensures Indian end users don't have to rely on a single domestic supplier. Also, as there are only 2 manufacturers, no single manufacturer can over charge the end users.
  - b. Further, the end users and application of PTFE and FKM are totally different. In case of PTFE, the end requirements are not as stringent as FKM (which is basically used in stringent auto application). In case of PTFE, final end user never specifies the grade/manufacturer to be used. But in case of FKM, the auto-companies clearly mention the grade and the manufacturer in part drawing released by them, leaving the rubber industry with no flexibility. In such a situation, the Indian rubber industry will be forced to buy imported products at an expensive price, making them less competitive than their international competitors. Companies such as Suzuki, Toyota, Honda etc. have global suppliers, posing a major threat to growth of Indian rubber industry.
  - c. While the domestic industry has mentioned that the PTFE market has grown to 6800MT in India, they have not mentioned that in the same period the Chinese PTFE market has grown multifold times to more than 90,000 MT. This shows that how GFL has tried to take advantage of the anti-dumping protection to charge higher prices to Indian PTFE consumers, thereby making them un-competitive and curtailing their growth. We again reiterate that in the present situation, the biggest losers shall be the MSME sector, who shall loose out to international competitors.

xx. Trade Notice No. 5/2018 dated 28<sup>th</sup> February 2018 is applicable to the investigations initiated after the issuance of trade notice. Since the present investigation was initiated on 2<sup>nd</sup> January 2018, the same trade notice is not applicable to the participating exporters/importers. However, if the Authority so desires, we are willing to provide all information.

xxi. Indian domestic industry is already having protection of 7.5% in the form of Customs duty. If the Directorate General of Trade Remedies decides to levy Anti-dumping duty of subject goods, then this protection to petitioner will be unwarranted as levy of anti-dumping duty on subject goods will only block the growth of FKM downstream market in India.

#### **Monopoly Issues**

xxii. Imposition of duty would lead to monopolistic situation and GFL would exploit the situation by charging a higher price.

xxiii. The Domestic Industry is misusing the protections granted by the Directorate General of Trade Remedies. The overall performance of the domestic industry is showing bumper profits whereas they are claiming that they have faced injury which is not correct. Most of its products are enjoying the benefits of anti-dumping which is leading to monopoly of GFL which may affect the Indian industry adversely.

#### **Concern regarding other products/industry**

xxiv. Any force majeure in the domestic industry's plant would create a huge shortage; the current situation in carbon black is an example. Any disturbance in their production on account of scheduled plant maintenance, breakdown maintenance, force majeure, etc would force the rubber manufacturers to buy the material at higher cost.

xxv. Any additional duty on FKM will make export of rubber components unfeasible as rubber processors are facing huge rise in cost due to shortage of carbon black which in turn will impact growth of MSME sector on which the government is focusing.

xxvi. Any additional duty will lead to a protectionist policy benefiting one company at the cost of viability and growth of thousands of small and medium rubber processors/manufacturers. This will go against Government's claim of giving big push to MSME sector and 'Make in India' policy.

xxvii. Automobile sector is one of major consumers of FKM base products; it would also lead to increase in their product cost which would finally be passed to the millions of Indian consumers.

#### **Public interest**

xxviii. Levy of anti-dumping duty will not be in public interest. Most of the rubber processors/manufacturers in Indian rubbery industry are from MSME sectors and operates at low volume for niche customers to meet their specific orders. They largely depend on import material due to better quality. GFL is yet to reach world class standard and meet customer specification. ADD would discourage the large automobile companies to make India as their manufacturing base, since their production cost will increase with restriction of choices. DGAD should give due consideration on the not so favourable situation that may arise if ADD is levied on FKM and make decision accordingly.

#### **NIP Issues**

xxix. The applicant has claimed a return of 26% on gross fixed assets. Such claim is inflated and not in accordance with law.

xxx. The DA determines NIP on the basis of cost of production of domestic industry, such determination is highly inflated and is not based on real situation as per para-4 of the Annexure III of the Rules.

xxxi. DA should adopt ROCE earned by the industry when there was no allegation of dumping as reasonable profit margin and not 22% ROCE. Providing 22% is incorrect because (i) debt portion of capital employed which attracts about 10-12% interest rate is provided 22%, (ii) this in turn result in providing more than 22% return on net worth portion of capital employed, (iii) during an era of global recession allowing such a high return to domestic industry is totally incorrect and is unheard of.



- xxxii. DGAD has been adopting 22% ROCE to arrive at non-injurious price and the same is incorrect. As per the sample calculation provided, 22% ROCE gives undue advantage and protection of 41% profit margin on equity to the domestic industry.
- xxxiii. Adoption of 22% ROCE to arrive at NIP is not reasonable. Adoption of a practice cannot be a ground for reasonability. Basis of 22% ROCE designed by GOI in Drugs (Prices Control) Order, 1987 (DPCO, 1987) cannot be termed reasonable after 30 years when parameters like interest rate and corporate tax were different. By applying the current rates of corporate tax and interest rate on actual basis, ROCE will work out as under for different set of equity ratios as tabulated which shows 22% gives undue protection to domestic industry:
- xxxiv. As per the decision in Bridge Stone Tyre vs DA, 22% ROCE has colored the injury determination and has inflated the price underselling and injury margin. DA should adopt the actual profit earned by the domestic industry during the period when there was no allegation of dumping as a basis for calculating reasonable return. European Union also follows the same practice.

#### **Examination by the Authority**

22. Various submissions have been made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed below.
23. As regards the argument of insufficient information provided by the domestic industry in the application, the Authority holds that the application contained essential prima facie information for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after considering the same initiated the present investigation. Further, subsequent to initiation, information has been sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary and the same has been adopted for the purpose of the present findings. The Authority notes that credibility of evidence improves as an investigation progresses.
24. Regarding the arguments of injury margin calculations, it is noted that injury margin is based on Non-injurious price of the domestic industry calculated as per the methodology prescribed in Annexure-III of the AD Rules. Further, the customs duty as prevailing during period of investigation is adopted.
25. As far as the argument of demand supply gap, the Authority holds that the present petition is only in respect of imports from China. As against 822 MT imports into India, 415 MT representing 43.54% of demand were from non-subject countries and would continue to be available to the consumers without any ADD.-It is also noted that the landed price of imports from non-China sources are at a price above NIP. Considering that the Rules provide for application of lesser duty rule, it follows that in any case, the landed price of imports from China shall not exceed the NIP of the domestic industry even in the event of Authority considering recommending ADD.
26. The interested parties have also argued that two different sets of data have been provided by the petitioner. The Authority has based its analysis on the verified data.
27. The interested parties have argued about the capability, quality and specifications of the product manufactured by the domestic industry and those imported into India. The Authority however holds that the product manufactured by the domestic industry is a like article to the product being imported into India and the two are being used interchangeably by the users/importers. The interested parties have not established that the goods supplied by the domestic industry cannot be used for the purpose for which the goods were imported, while raising issues on quality of goods.
28. Regarding the fact that the Petitioner Company is multi product and multi division company, the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has been segregated for the purpose of injury analysis and the assessment of the domestic industry's performance for the AD case has been carried out with regard to the product under consideration.
29. Public statements like annual reports of petitioner are considered appropriately to establish injury to DI.
30. Since the petitioning company is a multi-product company, the Authority has relied on the information with regard to product under consideration and on the basis of records maintained by the petitioning company and duly verified. The published financial results of the petitioning company are of limited

relevance in this regard, as this information does not pertain exclusively to the product under consideration alone and relates to overall performance of this company.

31. As regards the submissions that anti-dumping duty would result in monopolistic situation, the Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is only to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practice of dumping. The Authority has to establish the causality between dumping and injury irrespective of the composition and structure of domestic industry. In the instant case keeping in view the fact that this is a case of Material retardation, the Authority has considered measure only for a period of 18 months as stated in the later paras.

**E. Submissions by various User Industries:**

**32. Submissions by Ms/ Hi-Tech Arai Private Limited:**

- (i) Hi-Tech Arai Pvt Ltd., is a joint Venture Company with M/s Arai Seisakusho Co Ltd., Japan for manufacturing of Automobile Ancillaries viz., Oilseals, O-rings, Moulded Rubber parts, Reed Valve Assembly etc.
- (ii) These products are supplied to the Original Equipment Manufacturing (OEMs) in India Viz., Maruti Suzuki India Ltd, Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt Ltd, Honda Cars India Ltd, Nissan Motor India Pvt Ltd, Hero Motor Corp Ltd, Bajaj Auto Ltd, India Yamaha Motor Pvt Ltd, Honda Motorcycle & Scooter India Pvt Ltds, and TVS Motor Company Ltd etc., We are also exporting our products to Arai Seisakusho Co Ltd., Japan, Chrysler Group LLC, USA and Piaggio & C.S.P.A, Italy.
- (iii) In all our above products, we are using different grades of Fluoroelastomers (FKM) manufactured by the following Companies:
  - a) Chemours Company FC, LLC, USA (formerly Dupont)
  - b) 3M, USA (formerly Dyneon)
  - c) Daikin Industries Ltd., Japan
  - d) Daikin Fluorochemicals Co Ltd, China
  - e) Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd., China
  - f) Chemours Fluoromaterials, China
  - g) Solvay, Italy / China
- (iv) We are the major consumer of Fluoroelastomer (FKM) in India and our annual import quantity of FKM is around 250MT, out of which, we import around 40 MT from Chinese Manufacturers.
- (v) Out of these, Daikin, Chemours and Solvay have manufacturing units of FKM in China also. The reason is, one of the basic raw materials viz., Fluorspar, which is a mineral containing Fluorine is available abundantly in China.
- (vi) Now the domestic manufacturer, GFL, are in the very early development stage of manufacturing FKM in India, importing the monomers as necessary.
- (vii) There are many varieties and grades of FKM- making the availability of a huge spectrum of grades which enables the Rubber Compounders to fine tune and develop compounds, for specific applications of OEMs. It is almost impossible to expect for a single manufacturer to have all the grades suiting the end users' requirement. This is again the main reason we are sourcing our various grades from different manufacturers all over the world.
- (viii) Suitable BLENDS are designed and developed by our Rubber Chemists and many experimental evaluations are done to finally arrive at the final Compound Recipe meeting all laid out specifications of the OEMs.
- (ix) This is why it takes a considerable period of time to result in a satisfactory product.

- (x) FKM manufacturers in China have the biggest advantage of having access to “Fluorspar” and therefore, the Hydrogen Fluoride which is the starting point for the manufacture of FKM.
- (xi) Most of the established manufacturers such as Zhonghao Chenguang, Solvay, Chemours have put years of R&D in developing technically stable quality of FKM.
- (xii) There is a clear commercial equilibrium established with OEMs on the cost structure of selling parts as of today.
- (xiii) If this is upset and price of FKM goes up considerably, the OEMs will start to consider importing the Seals from various approved sources outside India.
- (xiv) This will lead to under-employment / unemployment in the India Manufacturing Units.
- (xv) There is a satisfactory equation established today between the Manufacturer of FKM sealing parts and the OEMs, which will be upset totally leading to a very serious imbalance.
- (xvi) It must be appreciated that this antidumping duty is not going to provide any support to GFL. Whose basic problem is Inconsistency in Quality and lack of variety of grades with different Technical Specifications to meet OEM’s specifications.
- (xvii) It is clear that for GFL to become a Reliable source of FKM in India, they should make considerable improvements in their Technology relating to Quality and Reliability.

**33. Submissions by M/s Super Seals India Limited:**

- (i) Being one of the oldest consumers of this product in India, we consume approximately 15mts of FKM per annum and are manufacturing rubber to metal bonded oil seals, gaskets etc for critical applications in automobile sector since last 3 decades. Our seals and gaskets are exposed to continuous heat oil, after fitment inside the automobile engine. Our products play an important part in smooth running of the engine. Our major customers include: M/s Simpson & Co., ITL, MGTL, ACE Ltd., Maxiforce, Midco, L&T, Rane, SML, M&M, Ashok Leyland, Tafe.
- (ii) Due to such critical application, we follow stringent quality procedures at our end. Our raw materials are carefully chosen, after analysis by our R&D team. We try to simulate the conditions observed inside the automobile engine, in our lab. Our products are then tested repeatedly in this simulated condition to ensure zero failure during actual use. As, such failure could have fatal consequences.
- (iii) It is submitted that we have repeatedly tested samples from Gujarat Fluorochemicals Ltd and found its performance poor in stringent conditions. The product failed when exposed to continuous heat. Their product performance was far below the required specification. Thus their samples have been repeatedly rejected by our R&D team. Further they have only limited grades developed which can never be sufficient to meet the wide variety of requirements of automobile industry.
- (iv) We are buying our FKM Gumstock from Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd & from Chemours since many years and is meeting our internal specification and our customer’s requirement. There has been no complaint and zero failure at our customers end.
- (v) It is further submitted that, the Govt. will understand FKM is generally chosen by all reputed auto component manufacturers after lot of testing and analysis. In case the Govt levies any additional duty on our current suppliers, we shall be forced to buy FKM from them at a higher price. We are already suffering heavy loss due to high prices and shortage of carbon black. Any further move in this direction would be final nail in the coffin for many rubber industries like us in India. This will not only stop the growth of rubber industry in India but also lead to large scale unemployment.

**34. Submissions by M/s ALF Industrial Products:**

- (i) Usually our customers specify us the grade of raw material to be used in their application. Further as FKM is a high cost speciality rubber we check each lot of material supplied to us under various quality parameters.

- (ii) We tried using GFL materials several times in our factory but their quality rejected by our production department.
- (iii) GFL being the only manufacturer of FKM in India as such any levy of anti-dumping duty will create a monopolistic market situation and in case of any breakdown or force majeure in GFL factory we would need to buy at higher cost which will put extra burden on us. We are afraid even GFL will take undue advantage of the situation and we have to remain under their mercy in getting stable and timely supply at competitive prices.
- (iv) We request DGAD not to levy any duty on FKM from China as already we are facing similar situation in Carbon Black supply in India although there are 4 manufacturers of the same but due to anti-dumping duty support they are charging us with extremely high prices and even not providing sufficient materials for our production.

**35. Submissions by M/s Apollo Seals Co.**

- (i) It is submitted that being a small scale Rubber factory making Rubber parts for industrial application, Fluoroelastomer is very special kind of Rubber to us and not like any other general Rubber (SBR, PBR, NBR,) which we purchase on the basis of price.
- (ii) It is submitted that making different kinds of Rubber parts which is supplied to majorly O.E Industries were we change the grade easily without taking prior approvals from the OE manufacturers. Equally our end users takes several years to approve any grade of any manufacturer after taking proper field trials
- (iii) Further, we have been using Zhonghao Chenguang Chemicals Research Institute of Chemical Industry Co Ltd FKM- Gum Stocks Grade – since many years and it has been approved by our customers because of consistent & stable quality.
- (iv) Gujarat Fluorochemicals Ltd has just recently started the production of FKM. We had tried using GFL materials but their quality was found not to be stable and consistent. Also we found they do not have wide variety of grades as like other reputed manufacturers of FKM in the world.
- (v) Already we are facing in India stiff competition in export market because of high cost of all our raw materials due to high import duty and Anti-Dumping Duty in majority of the raw materials used by us. Any levy of additional duty on our additional raw materials will make us totally non-competitive in International market.
- (vi) There is only 1 manufacturer of FKM in India and any levy of duty will create monopolistic market situation and price manipulation by the domestic producer. ADD will affect hundreds of MSE & SMSE like us in India thus resulting in job losses.

**36. Submissions by M/s Gowell Rubber Industries:**

- (i) It is submitted that being one of India's largest rubber auto-component OEM manufacturers, the subject matter is of grave concern to us. Our customers include both two wheelers and four wheeler manufacturers such as Bajaj, Hero, Maruti Suzuki, TATA etc.
- (ii) Fluoroelastomers are one of the most important raw material used by us with our annual consumption being around 25MTS. We are manufacturing automotive seals, gaskets, and o-rings out of it. Some of our products manufactured constitute an important safety component in the vehicles. In such a case we need to ensure utmost diligence at our end to choose the right grade of raw material from a particular manufacturers meeting all the required specification, careful processing at our end. And proper quality check of the end part before delivery to the auto-mobile manufacturer.
- (iii) Due to the importance of the rubber component being manufactured, in most cases the choice of grade of FKM to be used is decided by automobile manufacturers themselves, on the basis of their global quality approval. Even when we suggest the grade, we follow a strict quality inspection at our end and several months of trial before finalizing the grade for selection. The trial results are shared with automobile manufacturer for their consent and approval.

- (iv) All the above steps are strictly followed as our FKM based rubber components are important safety parts in automobile.
- (v) We have been using FKM A36 and FKM A412 Gumstocks from Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd. These grades pass all our internal tests and another important factor is we have never received any complaint for product failure at the consumer end, as that would mean jeopardizing on customer safety.
- (vi) We have also evaluated the samples from the Indian manufacturer – Gujarat Fluorochemicals Ltd (GFL) several times. These grades were found much inferior in quality with in-consistent results. They do not have any grade currently which can pass our customers requirement. In line with strict quality policy, we can never take the risk of using these grades for our important safety products.
- (vii) We also understand the GFL is the only Indian manufacturer for this product. As such we hope that Govt will not take any unilateral action to grant undue and unwarranted protection to this large enterprise which will destroy hundreds of small and medium scale companies like us who are working day and night to give the highest quality and provide best safety product to Indian consumers.
- (viii) Anti-Dumping duty is levied by any government to have level playing field between domestic manufacturer and international manufacturer where the quality of both the manufacturers are same but in case of GFL their quality is far inferior to international FKM manufacturers standard. As such by levying any additional duty the greatest loss would be to millions of Indian consumers.

### 37. Submissions by M/s ISG ELASTOMERS:

- (i) It is submitted that ISG ELASTOMER are a Rubber Processing Unit. We have been using FKM Gum Stock Grade – CGA372, CGA36 & CGA412 from Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd. since long time and with the help of their quality we have been able to supply high quality rubber products to our customers. There has been no complain from our customers by using their quality. Our Annual consumption of FKM is about 5-7 Mts.
- (ii) We had also tried using GFL Fluroelastomer several times in our factory but our rejection percentage increased and we also started getting complains from the market. There is lot to lot variation in GFL materials and the product quality is very inconsistent.
- (iii) FKM is a very high priced rubber compared to other rubbers we purchase as such we give lot of importance on quality at the time of choosing any new grade. If there are any quality issues we will suffer huge loss as cost of FKM is high compared to other rubbers and also our market reputation will be in stake.
- (iv) We request DGAD department not to impose any extra duty on FKM as it will give us extra burden of cost and will totally make us non-competitive in India as well as in international market.

### 38. Submissions by M/s Rawat Engg. Tech (PVT.) LTD.

- (i) It is submitted that being a small scale industry and our annual consumption of FKM is around 9 ton per annum used for making seals for water purifiers and filters which is supplied to companies like Eureka Forbes & Kent. Our seals are used in very critical application in water purifiers/filters which prevents leakage of water. Any failure in our seals will result in contamination of purified water, leading to health hazards to millions of people. As such we conduct lot of internal test before choosing any new grade of FKM.
- (ii) But every time the material supplied by them had lot to lot variation. Our seals made up of GFL materials had major bonding failure with metal and the compression set was very high as such we principally decided not to use GFL materials whose quality is unstable and unusable for our critical application which application which may even result in loss of business. Being a ZED

certification. We are also enclosing some of our internal test reports of GFL material as well as ZED certificate for your reference.

- (iii) We had informed GFL team headed by their technical head about various problems faced by us using their materials but till now they are unable to provide any solutions.
- (iv) We have been using FKM from Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical industry Co Ltd. and Chemours since 2013 and we are very satisfied with the quality supplied by them.
- (v) We request not to put any additional duty to protect a company whose quality is poor and unstable as GFL quality is yet to reach International standard. Further it would create a monopolistic situation in India as GFL being the only manufacturer of this product would try to take advantage of this situation.

#### **Examination by Authority**

39. The Authority notes that user industry has raised concerns on availability, consistent quality and non resolution of technical difficulties related to the usage of the product supplied by the domestic industry. The Authority notes the following:

- (i) The domestic sales of domestic industry have increased and also they have undertaken exports.
- (ii) The Authority notes that user industry may face challenge of quality of a new product due to technical stabilization. However repeated orders have been placed by certain customers on the DI it indicate increasing acceptance of Domestic industry's goods.

40. The Authority notes that issues raised do not relate to the fact that PUC and goods produced by DI are not like article but there are quality inconsistencies. Under these circumstances the Authority holds that AD measure endeavours to address the unfair price aspect only. FFKM and FKM compounds are not a part of the PUC as domestic industry does not have capability to produce these.

#### **F. Market Economy Treatment (MET), Normal Value, Export Price and Dumping Margin**

##### **41. Submissions by exporters, importers and other interested parties**

- i. The Director General Trade Remedies is requested to consider the questionnaire response of exporters to determine the real export price and landed value of Raw Gum and Pre-Compound, since the domestic Industry has deliberately classified raw gum into copolymer pre-compound. Reason being inclusion of raw gum into pre-compound has lowered the average price of pre-compound and resulted into very high dumping margin in respect of Raw Gum and Pre-Compound.
- ii. The Designated Authority should grant MET to China based on the development of market economy of China, conduct any normal value calculation in accordance with Article 2 of ADA and apply the data and prices provided by the Company in this response for the determination of the normal value rather than applying analogue country data.
- iii. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd., China PR is willing to give price undertaking as per Rule 15 of anti-dumping rules in case the Director General Trade Remedies concludes that Zhonghao Chenguang is dumping, or the Authority may fix reference price.
- iv. The determination of the normal value violates the provisions of paragraph 7 of Annexure I and is not supported by any evidence. The same also violates paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules as the Designated Authority has accepted the Petitioner's way to compute the normal value based on the last option, i.e. on the basis of cost of production in India, duly adjusted, without exhausting the first two options. Referred to Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. and others [(2005) 3 SCC 39].
- v. Data presented in the petition with regard to every adjustment are bare assertions and unsubstantiated by evidence, which could not have been relied on for initiating the case. As a result, deflated export price arrived at by GFL to "show" dumping is frivolous and must be rejected.

- vi. There is no dumping from the subject country and has not caused any injury to the domestic industry.
- vii. The petitioner's claim regarding incomplete value chain of the respondents is not applicable to CFSE as during the POI we have only sold products manufactured by our company and not engaged in any trading of the PUC. The Authority may verify the filed information.
- viii. The respondent has provided all relevant information regarding incentives or subsidies, as applicable, in its questionnaire response. The present investigation is an anti-dumping investigation and not a countervailing investigation. Therefore, the issue raised by the petitioner is irrelevant. Reference is made to the findings in the anti-dumping investigation against imports of Plain Medium Density Fibre Board (MDF) from Indonesia and Vietnam (F. NO. 14/23/2014-DGAD dated 5th May 2016).
- ix. The actual data filed by CFSE should be considered for the determination of its individual dumping margin in terms of the provisions of section 9A (1) (c) of the AD Rules, which will clearly show that the dumping margin is negative.
- x. Post 11th December 2016, the provisions of the ADA and the GATT 1994 that ordinarily apply to the determination of normal value for companies from market economy companies will apply to imports from China PR without any discrimination. In view of the above submissions, the Authority may determine the normal value for China PR based on the actual domestic prices of the exporters as done for other market economy countries in terms of the provisions of section 9A(1)(c) of the AD Rules.
- xi. CFSE has filed the market economy status questionnaire to rebut the presumption that it is operating under non-market economy principles and to demonstrate that its cost or pricing structures reflect the fair value of its merchandise in accordance with the criteria specified in paragraph 8 (3) of Annexure I of the AD Rules.
- xii. The claim of domestic industry regarding incomplete value chain of responding parties is not applicable to Solvay Group as it has been already clarified that SSPC directly exports the subject goods to India. These subject goods are imported by SSIPL, who in turn sells it to other customers in India. Furthermore, though domestic sales in China are inconsequential as SSPC has not claimed Market Economy status. SSCL has also filed EQR as the subject goods produced by SSPC are sold in the domestic market and exported to other countries by SSCL.
- xiii. With regard to the non-disclosure of benefits received by Chinese producers, Solvay Group submits that the Authority may verify the furnished data. Also, such information is inconsequential as the same have no relevance for the purposes of an anti-dumping investigation. Thus, any information which is not accurate or inadequate is inadvertent while submitting the EQR and is liable to be ignored. If any such subsidy program has not been reported inadvertently by the Respondents, the DA may allow the same to be rectified.
- xiv. The Domestic Industry has wrongly claimed that none of the Chinese producers disputed the existence of dumping. The Respondents have already made submissions disputing the claim of dumping of the subject goods from China for the reason that the same has been established on the basis of the Domestic Industry's prices which are not appropriate in the facts and circumstances of the present case.
- xv. The domestic industry had claimed constructed normal value in the petition, while in the written submissions it has claimed that the price from a market economy third country to other countries, including India may be resorted to for the purpose of determining the normal value in China. In case the Designated Authority decides to proceed on the basis of prices from a market economy third country to other countries, the same may be disclosed to the interested parties including the respondents well in advance so that the appropriateness of the same may be examined and additional evidence to this effect may be provided if required.
- xvi. The present investigation is an anti-dumping investigation, not an anti-countervailing investigation. The benefits in form of subsidies or other, if at all provided by the Government, are not relevant to the present investigation.

- xvii. DI has claimed about numbers of programs being run by the Govt. of China wherein benefits are being provided to the producers/exporters. However the Domestic Industry has not furnished any evidence to substantiate the above claim. Zhonghao Chenguang have not been granted any benefits from Government of China.
- xviii. The present investigation is an anti-dumping investigation, not an anti-susidy investigation. The benefits in form of subsidies or other, if at all provided by the Government, are not relevant to the present investigation.
- xix. Chinese producers are against dumping. They are selling the subject goods as per demand and requirements of the Indian industry. In fact, since FKM is a highly specialized product with specific grades of the manufacturer, approved after several months/years of trial done by auto-companies, there is no need for dumping by Chinese producers.
- xx. Uni-Alliance Limited exports the subject goods manufactured by Daikin and is nowhere related to Daikin as per definition provided in trade notice 9/2018 dated 10<sup>th</sup> May 2018.
- xxi. Daikin has exported the subject goods through Uni-Alliance Ltd. (79% of the total exports) and Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (21% of the total exports). Uni-Alliance Ltd. has filed the complete response with the Authority whereas Daikin tried its best that Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. files the questionnaire response with the Authority. Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. is not related to Daikin, so Daikin could not compel the exporter to be a part of the present investigation. Since majority of exports (79% to total exports) of Daikin was done through Uni-Alliance Ltd. and Uni-Alliance Ltd. has filed the complete response with the Authority, Director General Trade Remedies is requested to consider the same.
- xxii. The Domestic Industry has claimed that the various benefits are given to producers/exporters by Government of China PR and stated about various programs being run by the Govt. of China wherein benefits are being provided to the producers/exporters. However has not furnished any evidence to substantiate the above claim. Daikin and Uni-Alliance Ltd. submit that they have not been granted any such benefits from Government of China. The claims made by domestic industry are irrelevant and insubstantial. In addition, it is also submitted that the present investigation is an anti-dumping investigation, not an anti-countervailing investigation. The benefits in form of subsidies or other, if at all provided by the Government, are not relevant to the present investigation.

42. **Submissions made by CFSE regarding claim on MET status**

- i. In terms of Section 15(d) of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China, "in any event, the provisions of subparagraph (a) (ii) shall expire 15 years after the date of accession". Accordingly, Members are required to terminate the use of methodologies mentioned under section 15(a)(ii) of the Protocol after 11 December, 2016 and the continued use of these methodologies thereafter will be in violation of a member's obligations under the ADA and the GATT 1994. Therefore, post 11 December, 2016, the provisions of the AD Agreement and the GATT 1994 that ordinarily apply to the determination of normal value for companies from market economy countries will apply to the companies based in China PR without any discrimination. It means that for the calculation of the normal value for the companies based in China PR their actual domestic prices should be considered.
- ii. M/s CFSE is the sole cooperating exporter from China PR, which has claimed market economy status (MET) since we believe that our cost or pricing structures reflect the fair value of our merchandise in accordance with the criteria specified in paragraph 8(3) of Annexure I of the Indian Anti-dumping Rules, 1995.
  - a) None of the major shareholders of our company are state owned or controlled;
  - b) CFSE is not indirectly controlled by the Government, and therefore, there is no interference of Government in CFSE.
  - c) The private shareholding in CFSE is more than 85% & indirect government shareholding in less than 15%.



- d) The private shareholding in Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre (Limited Partnership) is less than 70% & government shareholding is less than 40%.
- iii. Attention of the Authority is also invited to the Article 4 of Chapter 1 of the Ministry of Finance Decree No.32 in 2016 of China PR (Measures for Supervision and Management of State Owned Assets transaction.) The content of Article 4 is reproduced below for the ease of ready reference of the Authority.
- “Article 4 of Chapter 1. State owned and state holding enterprises and state actual controlled enterprises as mentioned in these measures include:*
- (1) Wholly state-owned enterprises (companies) established by government department, organizations and institutions, and wholly state-owned*
- Enterprises with 100% direct or indirect total shareholdings of the above-mentioned units and enterprises;*
- (2) enterprises in which the units and enterprises listed in paragraph (1) of this Article make separate or joint capital contributions, the proportion of the total ownership of property (shares) rights exceeds 50% and one of them is the largest shareholder;*
- (3) Sub-enterprises in which the enterprises listed in paragraphs (1) and (2) of this Article, which have more than 50% equity in their capital contributions;*
- (4) enterprises that can be effectively controlled by the largest shareholders who shall be government departments, organizations, institutions, single state-owned or state-controlled enterprises through shareholders agreements, articles of association, board resolutions or other agreements, although direct or indirect shares held by government departments, organization, institutions, single state-owned or state-controlled enterprises is less than 50%.”*
- iv. The relevant excerpts of section 2(45) of the Indian Companies Act, 2013 are also reproduced below for the perusal of the Authority.
- (45) “Government company” means any company in which not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the Central government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments, and includes a company which is a subsidiary company of such a Government company;
- v. It is amply clear from the above that a company can be termed as state owned & controlled only in the following two situations:
- a) Direct or indirect shares held by government department, organization, institutions, single state-owned or state-controlled enterprises is more than 50%, or;
- b) Shareholder agreements, articles of association, board resolutions or other agreements authorizes the government to exercise control.
- vi. The indirect government shareholding in CFSE is only \*\*\*%. Further, the Articles of Association of CFSE authorizes the President of the Board of Directors to exercise control over the day-to-day operations of the company since the president is the legal representative of the company. The Articles of Association (Article 27 to Article 30) of the company has been enclosed with the Supplementary Questionnaire Response. CFSE is therefore not a state owned company.
- vii. As regards our only non-individual major shareholder i.e., Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership), it is reiterated that government holding is only \*\*\*%. It may also be noted that the Partnership agreement clearly mentions that Wuxi Guolian Industrial Investment Co., Ltd is the only general partner of Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) and has complete control over its day-to-day operations. It is submitted that all shareholders of Wuxi Guolian Industrial Investment Co., Ltd are private persons. Accordingly, it is clear that Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) is not a state owned company.

- viii. The applicant has without any basis alleged that CFSE is indirectly controlled by the Government and there is substantial interference of Government in CFSE. In order to substantiate our claim attention of the Authority is invited to the definition of control as per the Indian Companies Act, 2013.

***“Section 2(27) of the Companies Act, 2013***

(27) “control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner;”

- ix. From the above, it is clear that in order to exercise control, the shareholder shall have the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly. It is reiterated that in CFSE, the government indirectly holds only \*\*\*% of the total shares. Therefore, it is clear that neither the government has indirect control over CFSE nor is there any interference of Government in the management of CFSE.
- x. Further, it is submitted that the decisions relating to the day-to-day operations is taken by the Board of Directors of CFSE. It is the executive organ of the company. The President is the legal representative of the Company. The President is elected by 2/3 of directors.
- xi. There are three directors of CFSE. Two directors represent the private shareholders of CFSE and the third director is nominated by the non-individual shareholder of the company i.e., Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership).
- xii. The only major non-individual shareholder of CFSE i.e., Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) is not a state-owned company. It is a limited partnership company. It is submitted that limited partnership is different from a general partnership on account of the following two main reasons
- a. Management of a limited partnership rests with the ‘general partner’;
  - b. Limited partners are ‘silent partners’ since they can make investments in the company but have no voting power or control over its day-to-day operations.
- xiii. The applicant has claimed that Wuxi Guolian Industrial Investment Co., Ltd (referred to as “Wuxi Guolian Venture Investment Co., Ltd”, which seems to be a typo error) holds 20% shares in our major shareholder namely Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership). In this context, it is submitted that Wuxi Guolian Industrial Investment Co., Ltd is a limited partner of Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) and has no role to play in its day-to-day operations. A copy of the partnership agreement of Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) is enclosed with the submissions. This partnership agreement also contains the details regarding the contribution of partners in the capital.
- xiv. The Authority’s attention is invited to the following para’s from the partnership agreement, which will prove beyond doubt that Wuxi Junyuan Capital Management Center (Limited Partnership) is the only general partner of Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) and has complete control over its day-to-day operations.

*“1.13 General Partner and Executive Partner refer to Wuxi Junyuan Capital Management Center (Limited Partnership).”*

*“2.7.1 The only general partner of the partnership is Wuxi Junyuan Capital Management Center (Limited Partnership)....”*

*“5.1.1 Limited partnership shall be carried out by general partners in partnership affairs. The management, control, operation and decision-making powers of the partnership, its investment business and other activities are entirely vested in the general partner and exercised directly or through the representatives appointed by the general partner.”*

*“5.1.2 All the partners agreed to entrust the general partner, Wuxi Junyuan Capital Management Center (Limited Partnership), as the partner of the partnership in the execution of partnership affairs.”*

There is no direct or indirect shareholding of the government in Wuxi Junyuan Capital Management Center (Limited Partnership). All shareholders of this company are private shareholders. Therefore, there is no state interference of government in the day-to-day operations of Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership), which is a shareholder of CFSE. In such case, it is also clear that there is no state inference of the government in the day-to-day operations of CFSE.

- xv. Neither any of our shareholders nor our company is a state owned company or controlled by the Government. Accordingly, the decisions of CFSE regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply & demand and without any State interference.
- xvi. The Authority should consider to grant MET status to CFSE and determine the normal value based on our actual domestic prices as done for exporters from other market economy countries.

43. **Submissions by Domestic industry**

- i. None of the parties barring one i.e. Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co. Ltd. have filed the MET Questionnaire response.
- ii. Secondly, market economy status cannot be granted unless the responding exporters satisfy each & every of the following conditions:
  - a. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity. In the present case, four of the exporters and producers namely Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd, Shanghai 3F and Inner Mongolia 3F are indirectly controlled by the Government of China with a relatively substantial amount of State interference. The relevant evidence have already been placed on record.
  - b. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values.
  - c. Market economy treatment must be rejected in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS). The requirement on insisting compliance with International Accounting Standards is to ensure accuracy and adequacy of revenues and expenses, assets and liabilities expressed in the annual report.
  - d. Market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules. While one parameter is sufficient to establish existence of injury, failure to pass one single parameter is sufficient to reject the claim of market economy status.
  - e. It is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
  - f. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected. In the present case, as per the petitioners understanding Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd (“DCC”) and its related entity Mitsubishi has not filed the questionnaire response. But since all the exporters and producers have kept the shareholding information confidential, plausibility of other related entity being involved in the product under consideration cannot be ruled out.
  - g. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.

- iii. None of the exporters including Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd who has filed the market economy treatment questionnaire satisfy each and every condition developed from jurisprudence to qualify for grant of market economy status. Thus, the Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
- iv. According to the European Commission's Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations dated 20th December, 2017; in China's state-run economy, the government – as a player of multiple roles controlling factors of production – has the capacity to fully manage these factors in order to achieve its industry policy goals. As such, the government indirectly or directly affect supply, demand and prices, through limits or incentives to produce certain chemicals or to relocate activity to other sub-markets, through relieving the production costs of certain companies, or through supporting the acquisition of new production capacities abroad. All these measures significantly affect or impede the free functioning of the market as well as company decisions, which are no longer genuinely market-driven.
- v. The United States Department of Commerce ("Department") in its Memorandum China's Status as a Non-Market Economy dated 26th October, 2017 concluded that China is a non-market economy country because it does not operate sufficiently on market principles to permit the use of Chinese prices and costs for purposes of the Departments antidumping analysis. The basis for the Department's conclusion is that the state's role in the economy and its relationship with markets and the private sector results in fundamental distortions in China's economy.
- vi. The normal value for China in such a case can be determined only in accordance with the provisions of para 7 of the Annexure I to Anti-dumping Rules in view of the aforementioned facts and circumstances.
- vii. While Art. 15(a)(ii) of China's Accession Protocol expired on December 11, 2016, the Authority must treat China PR as a non-market economy (NME) in the present investigation for the reason that a major part of the POI was till to December, 2016 as the situation prevailing during the POI becomes the relevant consideration.
- viii. According to these Rules, the normal value in China can be determined on any of the following basis:
  - a. The price in a market economy third country,
  - b. Constructed value in a market economy third country,
  - c. The price from such a third country to other country, including India.
- ix. The petitioner has made submissions and claims on normal value as per the best available information available to it. The Authority may appropriately adopt the methodology to determine normal value.
- x. Normal value in China of the product under consideration could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available and thus, the petitioner resorted to the last option. The interested parties also had sufficient time and opportunity since initiation of investigation to suggest an appropriate market economy third country and produce appropriate evidence for the same.
- xi. Moreover, the respondents have themselves admitted that the understanding, "China must be treated in the same way as to any other WTO Member for the purpose of anti-dumping investigations" is no longer shared by the U.S. and the EU when they stated in Page 18 of their written submissions- "Until recently this understanding had been also shared by both the US and the EU". The petitioner here focused on the usage of the word "had been" which clearly does not reflect the present position.
- xii. Respondent's further reference to the U.S.'s 1999 White House statement on US-China bilateral agreement and the EU's 2001 Explanatory Memorandum attached to Council Decision Accession Protocol is irrelevant and misleading because they predate the Accession Protocol, and do not

reflect the recent positions of U.S. and EU on the interpretation of Section 15(d) which has changed substantially and henceforth are not legally binding.

- xiii. Most significantly, respondent's reference to *EC-Fasteners* case is misleading because the Appellate Body has itself clarified that "[...] China's claim before the Panel concerned the determination of individual and country-wide dumping margins and duties, not the possibility of resorting to alternative methodologies in the calculation of normal value in anti-dumping investigations involving China" and in addition, the quoted passage does not support Respondent's argument to bar the use of "surrogate country" practice or makes it compulsory to treat China as "market economy country". The matter of interpretation of Section 15 and China's status is *sub judice* in WTO.
- xiv. The domestic industry has provided export price to the best of its abilities, has made adjustments as per best available information and in a manner prescribed and consistent with the practice of the Designated Authority. The domestic industry is not privy to the actual evidence and therefore cannot be expected to provide the same. In any case, the exporter from China should respond with complete and credible information in order to demand dumping margin based on its own questionnaire response. The Authority may, after verification, adopt the prices relevant for the present purpose, if the questionnaire response is complete in all respects.
- xv. For the reasons mentioned above, none of the Chinese producers/exporters including Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd should be given the market economy treatment. Also, almost each and every information was claimed confidential in the MET QR which hampers the petitioner's right to make effective comments.
- xvi. The very fact that the exporters have resorted to dumping gets established by their tacit admission in not denying existence of dumping.
- xvii. The domestic industry has identified the import data to the best of their abilities. What now appears to the domestic industry is that the exporters are now trying to show their higher value product as a low value product and have created stories to suppress such misdeeds at their end. The petitioner requests the Designated Authority to kindly consider the questionnaire response and corroborate the same with the Indian import data. Unless the questionnaire response corroborates with the Indian customs data, the questionnaire response should not be accepted.
- xviii. The dumping margin is positive and above de minimis limit.
- xix. The Authority has been rejecting the request for price undertaking made by exporters in the past in earlier cases as the Authority felt that it creates lot of practical difficulties to monitor such price undertakings. Further, since the product under consideration is produced and supplied in different forms, it would further add to practical difficulties in implementation of undertaking.
- xx. The response of the respondents should not be accepted given the fact that they have failed to disclose vital information, such as name of their related parties, details of their related party producing product under consideration, suppression of facts regarding benefits & incentives received by them.
- xxi. The domestic industry requests the Designated Authority to consider weighted average individual one dumping and injury margin for these related/group companies. Apart from the related companies, there are also unique set of Chinese producers who have responded in the present investigation.

#### **Examination by the Authority**

44. 'Normal Value' under Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975 in relation to an article means: -

*comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low*

*volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

45. The Authority notes the following relevant provisions related to Normal value computation under the AD Rules as well.

46. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to AD Rules are as under:

*“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

*8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3).*

*(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).*

*(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.*

(4) *Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization."*

47. The Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's of the date of accession. **In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession.** In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

48. The Authority notes that provisions of Article 15 (a) (ii) of the China's Accession Protocol has expired on 11/12/2016. However provision in 15(a) (i) still obligates the producers/exporters of China to establish their claim for market economy treatment. Para 7 and Para 8 of the AD Rules stipulates methodology/methodologies regarding Normal Value and also requirements for establishing market economy claims.

49. Authority notes that following exporters/producers have responded and filed questionnaire response.

- a. Solvay (Shanghai) Co., Ltd, China PR
- b. M/s. Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co, China PR
- c. Uni-Alliance Limited, China PR

- d. Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd, China PR
  - e. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd, China PR
  - f. Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR
  - g. Shanghai 3F, China PR
  - h. Inner Mongolia 3F, China PR
50. Only M/s Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR, has claimed MET. The other producers/exporters who have though not claimed MET by filing the stipulated questionnaire but have made submissions regarding China to be treated as Market Economy and also appropriate methodology to determine the Normal Value in case of Non-Market Economy.

**Evaluation of MET status of CFSE and Computation of its Normal Value**

51. The Authority notes submissions made by M/s Chenguang Fluoro And Silicone Elastomers Co. Ltd. (CFSE) regarding claim of market economy status, questionnaire filed with domestic sales, export sales and cost of production along with supplementary questionnaire regarding claim of market economy status and supplemented with additional submissions with regard to the claim of market economy status.
52. The Authority notes that M/s CFSE produces only one type of PUC i.e pre compounds (copolymer and terpolymer) and not the raw gum, which is the foundation to prepare pre compounds of FKM. Raw Gum accounts for almost 70-75% of the total cost of sales and more than 75% of the total raw material cost. This cost proportion also corroborates with the cost of production composition of domestic industry wherein the raw material cost mainly raw gum is more than 95% of cost of sales. The submissions on claim of market economy status by M/s CFSE are only with reference to their limited operation on the value addition part of only one type of PUC and with no detailed information and evidences on raw gum production (which is also a PUC) by its suppliers who also need to establish that they are also operating under the market economy conditions. CFSE's questionnaire does not include the questionnaire responses of the producers/suppliers of the raw gum. The limited and incomplete information can not enable comprehensive examination and establishment of the claim of market economy status to M/s CFSE for the subject goods.
53. The Authority has nevertheless examined the cost of production provided by the producer/exporter for pre compounds only wherein also certain discrepancies were noted. These include name of the owner of assets being erroneous, unjustified and unsubstantiated differential procurement prices of raw materials and discrepancies in power bills filed by the producer. As regards the state inference, the producer/exporter has provided its share holding pattern wherein one of its shareholders i.e M/s Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre limited partnership who holds \*\*\*\*% of share of the producer/exporter infact has Government shareholding to an extent of \*\*\*\*%. This \*\*\*\*% shareholding is comprised of M/s Wuxi Guolian Industrial Investment Co. Ltd. (\*\*\*\*%), M/s Wuxi Newspaper Developer Co. Ltd. (\*\*\*\*%), and M/s Wuxi New District Science and Technology Financial Venture Capital Group Co. Ltd. (\*\*\*\*%), who further have 100% government shareholding. The investment trail of the producers/exporters investment portfolio therefore shows significant investment by the state enterprises both directly/indirectly. The Authority also notes the submissions by CFSE that M/s Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre (\*\*\*\*%) has M/s Wuxi Junyuan Capital Management Centre (Limited Partnership) (\*\*\*\*% Private) as a General partner who unlike other limited partners is authorised to take day to day management decisions and that there is no government interference in decision making. The Authority notes that the para 8(3) of Annexure 1 of AD rules states “the designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:
- (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and **investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard**, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;



(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in Anti-Dumping Rules, 1995 in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.”

54. In the instant case, the provision under of 6.4 of the partnership agreement of M/s Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre, the major shareholder in CFSE stipulates the role of all Shareholders in investment decision making which appropriately clarifies State interference in investment decision making in CFSE. Therefore with decision making for investment by producer/exporter having interference of the state entities, the condition under para 8 (3) (a) is not met to claim MET status. Also the Authority notes that exchange rate as regards foreign currency transactions the producer/exporter has stated that exchange rate's reflected in their financial accounts are based on rate published by people's bank of China. However there are no submissions on the aspect as to whether the exchange rate is controlled by the Government. The Authority recalls its earlier finding no.14/14/2014-DGAD dated 8/4/2017 wherein in para 108 the continued control of exchange rate by Government was underscored. The issues on cost of production, shareholding pattern and claim of market economy treatment being limited only to value added component of PUC and further with no participation of raw material suppliers/producers do not qualify and justify grant of market economy status to the producer/exporter i.e. M/s CFSE.
55. The post disclosure comments on MET claim have also been further appropriately examined by the Authority in the later paras. Therefore, the Authority has adopted the methodology for normal value for CFSE as stated for the other four cooperating producers/exporters including the residual category of producers/exporters.

**Computation of 'NV' for producers/exporters not claiming MET status**

56. The Authority notes the hierarchy to determine 'NV' as prescribed in Para 7 of Annexure-I to AD Rules; and the following submissions made by various producers/exporters and Domestic Industry on appropriate methodology to determine the NV.
57. M/s TPM representing the domestic industry have stated the following:
- (i) For determination of normal value for non-market economy the following three options are available as per Para 7 of Annexure I to the Rules:
    - a) Price or constructed value in the market economy third country; or
    - b) Price from such a third country to other countries, including India; or
    - c) Price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include a reasonable profit margin.
  - (ii) Efforts were made by the domestic industry to collect information with regard to price or constructed value in market economy third country but could not get relevant information in this regard. Thus, the normal value has been determined on the basis of price from following third countries into India, as the same passes the test of Annexure-1, Para 7:
    - USA (Share of imports into India is 28.15%)
    - Japan (Share of imports into India is 15.70%- however, all forms of the PUC have not been imported into India)
    - Italy (Share of imports into India is 2.13%)- however, all forms of the PUC have not been imported into India, and the volume of imports is de-minimus.

- (iii) Full information with regard to price from these countries to India have been provided in the petition. Since these prices are CIF prices, and the export price is ex-factory export price, the price has been adjusted for expenses such as freight, insurance, bank charges and inland freight etc. This should be considered as the normal value for the product under consideration.

58. M/s World Trade Consultants and Advocates representing Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd. have stated the following:

- (i) The exporters Questionnaire response has been filed with the understanding that after 11<sup>th</sup> December, 2016 the Director General Trade Remedies will follow the protocol on China's accession to the WTO.
- (ii) As per Section 15(a) (ii) of the protocol on the Accession of the People's Republic of China to the World Trade Organization expired on December 11, 2016, India no longer has a legal basis under the agreements of the World Trade Organisation to calculate normal value in anti-dumping investigation of Chinese products using the non-market economy methodology. Any such action by India would be inconsistent with the requirements of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (the "Anti-dumping Agreement") and other covered agreements. We believe that it is the Ministry of Commerce and Industry's obligation as the Investigating Authority to solicit the information that it requires for calculating the dumping margin in accordance with the WTO Rules.
- (iii) In case the Director General Trade Remedies does not agree with our submissions and still considers China as a Non-Market Economy country, it is required that DGTR must follow given guidelines in Para 7 of the Annexure-I of the Anti-Dumping rules which read as under:
- "7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin"***
- (iv) Under the Anti-dumping Rules, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country or price from such a third country to other countries. In view of the above, it is suggested that normal value may be constructed by adopting the following parameters:
- Raw material consumption norms to construct the cost shall be adopted for the respective participating producers/exporters.
  - International price of raw material may be considered.
  - Utilities cost may be worked out based on the prevailing prices in China PR.
  - Interest rate as prevailing in international market including China PR may be considered.

59. M/s Dua Associates representing M/s Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemicals Co. Ltd. ("**Inner Mongolia 3F**") and M/s Shanghai Huayi 3F New Materials Sales Co. Ltd ("**Shanghai 3F**") have stated the following:

- (i) The Paragraph of Annexure-1 provides the chronology for determination of Normal Value for non-market economy countries as follows:
- I<sup>st</sup> methodology:** *On the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries,*
  - II<sup>nd</sup> methodology:** *Where the determination of Normal Value is possible as per I<sup>st</sup> methodology, Normal Value to be computed based on price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.*
- (ii) For the determination of Normal Value as per the aforesaid methodology, the Authority is requested to adopt the price of subject goods in Italy or USA. To gather the said information,

we request your good self to seek information from Italy or USA through Embassy of India in the respective countries. We also wish to highlight that the product under consideration is divided into PCN's therefore, the Authority should seek information as per the product category.

- (iii) Since the aforesaid methodology is practically difficult, as an alternate to the above, the Authority may also compute the Normal Value of subject goods in Italy and USA based on landed value of subject goods in India. For the said purpose, the Authority may take import value of subject goods from Italy and USA to India and make necessary adjustments such as deduction of tax and duty levied by Government of India, international freight and insurance paid by exporter/importer, domestic inland freight and other charges and taxes paid in surrogate country.
- (iv) The aforesaid methodology is best suited for computation of Normal Value due to following reasons:
  - a. The Authority possess transaction wise import data of the goods imported from surrogate country. The said import data can be segregated on a PCN basis as per the same methodology adopted for segregating import from subject country.
  - b. The cost/ sale price arrived on the basis of the aforesaid methodology will be at ex-factory level and therefore, the same is best suited for comparison with the ex-factory export price. Moreover, Para 6 of Annexure I of Anti-dumping Rules mandate that the normal value and the export price should be compared at same level and the Authority prefers to compare the same at ex-factory level.
  - c. The domestic industry constitutes nascent producers who have commenced commercial production since June 2015 (as admitted in the application). Therefore, Indian producers and Indian market is not representative of the price for an established industry. In this respect, Para 7 also mandates that the Authority while selecting surrogate country should keep in view the level of development of the country concerned and the product in question.
  - d. The aforesaid methodology would be the most suitable methodology because the computed normal value will be based on reliable information.
  - e. Computation of Normal Value on the aforesaid methodology will avoid any unnecessary delays.
  - f. The domestic industry has provided post factory expenses for China PR to arrive at ex-factory export price. Therefore, the Authority may adjust the said data (concerning post factory expenses) to arrive at cost/price of subject goods in surrogate country.

#### **Examination by Authority**

- 60. The Authority notes the submissions by M/s WTC on China's Accession protocol provisions and holds that claim of MET requires satisfying the provisions of 15(a) (i) of the Accession Protocol. On 11.12.2016 the provisions of 15 (a) (ii) have though expired, the provision of Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure 1 of India's AD Rules to be satisfied through the information/data provided in the supplementary questionnaire on MET status. Only one of the producers/exporters i.e. M/s Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co. Ltd. has provided the requisite information which has been examined in the earlier para. . Therefore for producers/exporters who have not lodged claim for grant of MET the normal value computation is required to be dealt as per provisions of para 7 of Annexure-1 of AD Rules. The Authority notes the hierarchy of options for normal value computation in case of a non-market economy country and various submissions on adopting an appropriate methodology as per the provisions of this para.
- 61. The Authority in the disclosure statement had noted that the first proviso to consider domestic prices in a surrogate third market economy country for NV is not feasible as the product under consideration has many PCN's for which information of domestic sales in a third market economy country is not available in public domain. Further none of the interested parties has filed any such an

information before the Authority. The Authority noted that the 2<sup>nd</sup> proviso of para 7, stipulates that price of PUC from such a Market economy third country to other countries including India can be considered. In view of the significant imports of PUC from USA, a market economy and the technical nature of PUC, a specialised rubber with applications in sophisticated Auto sector, space and water purification systems, the Authority had proposed USA as a surrogate Market economy country for referencing its export prices to India in accordance with the 2<sup>nd</sup> proviso of para 7.

62. However the Authority notes that the above approach at Normal Value proposed by it in the disclosure for the subject goods in China referencing import price from USA in accordance with Para7 of Annexure 1 has been contested by various interested parties. The Authority in this context recalls that submissions made by various interested parties regarding issues of considering import prices from USA as a surrogate country to India were exchanged amongst various interested parties through the public file. The Authority notes that though this approach has been justified by the domestic industry and one of the producers/exporters, the other interested parties have stated that this approach is not appropriate as export prices of raw gum from USA to India are more than Precompound prices which is anomalous and not justified. The Authority keeping in view various submissions regarding the computation of 'Normal Value', has in this finding adopted the Constructed 'Normal Value' approach on the basis of cost of production of the Indian Industry by appropriately normating various elements of cost as per best practices/norms and by allowing a reasonable return on the Cost of production of subject goods. The Authority notes that this approach has been consistently adopted by it in past cases as well and takes care of the various concerns raised on the approach suggested in the disclosure statement.
63. The Authority in this regard notes that certain interested parties have requested that while computing the Normal Value, international prices of raw material and power cost in China be adopted. The Authority notes that as per its consistent practice, it endeavours to reference international prices. In the instant case two main raw materials VF2 and GX902 have been imported in POI by the domestic industry which have been referenced as a cost element for 'CNV'. Another major raw material is 'TFC' which is captively manufactured and is not tradable. Under such circumstances, the normated cost of domestic industry with best practices/norms has been considered to evaluate the Normal Value for producers/exporters of China. Further the two raw materials i.e. VF2 and GX902 as per the WTA database are imported either in very insignificant quantities or nil respectively into China and therefore the import price of these raw materials into India can be considered as representative of international prices for the Asia region and is justified to be adopted for 'CNV' purpose.
64. The Authority has therefore constructed the 'NV' on the basis of the above methodology:

Grades	CNV (\$/kg)
Co polymer Raw gum	***
Co polymer Pre compound	***
Terpolymer –Bisphenol cured Raw gum	***
Terpolymer – Peroxide cured Raw gum	***
Terpolymer Bisphenol precompound	***

#### **G. Determination of Export Price**

65. The following producers/exporters filed exporter's questionnaire (EQ) response in the present investigation
- Solvay (Shanghai) Co., Ltd, China PR
  - M/s. Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co, China PR

- c. Uni-Alliance Limited, China PR
- d. Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd, China PR
- e. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd, China PR
- f. Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR
- g. Shanghai 3F, China PR
- h. Inner Mongolia 3F, China PR

**Determination of Export Price of Solvay (Shanghai) Co., Ltd and M/s. Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co**

- 66. The producer/exporter has sold 136.51 MT of Subject goods i.e. FKM (Co Polymer Pre Compound) on CIF basis during POI to India to its related entity i.e. M/s Solvay Specialities India Private Limited (SSIPL). The related importer has sold these goods on ex work basis to end customers but has incurred losses during POI to an extent of Rs. \*\*\*. The Authority has appropriately adjusted these losses to determine the Ex-factory Export Price.
- 67. The Authority appropriately considered adjustments on logistics expenses (ocean freight, ocean insurance, inland transportation, and port handling) to an extent of \*\*\* \$/MT, Bank Charges to an extent of \*\*\* \$/MT and Credit Cost to an extent of \*\*\* \$/MT, on the basis of actual incidence of expenses on these elements. Further, adjustment on loss on sales made by the related importer has also been considered to an extent of \*\*\* \$/MT. The Ex-factory Export Price is proposed at \*\*\* \$/MT. The landed value after adding relevant duties and charges comes to \*\*\* \$/MT.

**Export price of Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd**

- 68. The producer/exporter has exported subject goods to an extent of 131 MT in POI (only Co polymer Raw Gum) at a total invoice value of \*\*\* USD. (both with ex-works and CIF terms). The equivalent CIF value for all transactions during POI on the basis of various expenses on account of Port charges and handling, Inland transportation, Overseas transportation, Insurance and Bank Charge is computed as \*\*\* USD. The per unit CIF price comes to \*\*\* \$/MT. After allowing adjustments on Port charges and handling, Inland transportation, overseas transportation, insurance and bank charges and VAT to an extent of \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* \*\* and \*\*\* \$/MT respectively, the ex-factory export price comes to \*\*\* \$/MT.
- 69. The authority notes that the producer/exporter has stated that their Joint venture of M/s Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd. i.e. M/s Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd. has not exported subject goods directly during POI. The Authority has validated the same with transaction wise DG systems data also. The Authority however notes that the dumping margin is being computed for direct export by the participating producer/exporter only.
- 70. The Authority also notes that response for \*\*\* MT of imports has been filed by M/s Eastcorp International, an importer whose CIF also gets broadly correlated with the producer's response.

**Export price of Uni-Alliance Limited and Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd**

- 71. M/s Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd. has exported the subject goods i.e Fluoroelastomers to an extent of 112.32 MT of Fluoroelastomers during POI to India through 2 channels i.e. M/s Mitsubishi ( 23.80 MT) and M/s Uni alliance ( 88.52 MT). M/s Mitsubishi has not filed the Exporter Questionnaire Response. The exports by M/s Uni-Alliance includes 4.02 MT of Fluoroelastomers (compound) which is not part of PUC and the same is proposed to be excluded. Therefore the PUC to an extent of 84.50 MT of 3 grades i.e. Terpolymer Bisphenol Pre-Compound, Co Polymer Pre-Compound, Terpolymer Peroxide Curable Raw Gum have been exported by M/s Uni Alliance to an extent of \*\*\* MT, \*\*\* MT, \*\*\* MT at a total invoice value of \*\*\* US\$, \*\*\* US\$, \*\*\* US\$ respectively.

72. In case of **Terpolymer Bisphenol Pre Compound**, after allowing the adjustment on Inland Freight, Handling Charge, Ocean Insurance, Overseas Freight, Bank Charges, Credit Cost and VAT to an extent of \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* and \*\*\* US\$/MT respectively, the Ex-factory export price comes to \*\*\* \$/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to \*\*\* \$/MT.
73. In case of **Co Polymer Pre Compound**, after allowing the adjustment on Inland Freight, Handling Charge, Ocean Insurance, Overseas Freight, Bank Charges, Credit Cost and VAT to an extent of \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* and \*\*\* US\$/MT respectively, the Ex-factory export price comes to \*\*\* \$/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to \*\*\* \$/MT.
74. In case of **Terpolymer Peroxide Curable Raw Gum**, after allowing the adjustment on Inland Freight, Handling Charge, Ocean Insurance, Overseas Freight, Bank Charges, Credit Cost and VAT to an extent of \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* and \*\*\* US\$/MT respectively, the Ex-factory export price comes to \*\*\* \$/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to \*\*\* \$/MT.

**Export price of Shanghai 3F (Exporter) and Inner Mongolia 3F (Producer)**

75. During the POI, the following three related entities were involved in production, domestic sales and exports:
- (i) Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd. (“IM 3F”) engaged in domestic sales and also sales to countries other than India,
  - (ii) Inner Mongolia All Top Fluorine Chemistry New Materials Development Co., Ltd. (“All Top”) engaged in production and domestic sales, and
  - (iii) Shanghai Huayi 3F New Materials Sales Co., Ltd. (“SH 3F”) engaged in domestic sales and export of countries including India.
76. Post POI of the present investigation, M/s All Top was merged in IM 3F with notification in January 2018. Documents in support of merger of All Top were filed along with questionnaire response filed by IM 3F. Since All Top is already merged with IM 3F, the Authority has considered the combined response of IM 3F and All Top containing relevant information in prescribed format. A separate exporter’s questionnaire response was also filed by SH 3F the exporter.
77. The Authority has undertaken desk verification of data filed by IM 3F (including data of All Top) and SH 3F. Since closure of All top has been notified after its merger with IM 3F, the Authority considers IM 3F as the producer and SH 3F as the exporter of goods for determining dumping and injury margins.
78. The Authority notes that during POI, All Top was engaged in production and domestic sales of subject goods. IM 3F was undertaking domestic sales in China and export of subject goods to third countries. SH 3F was engaged in domestic sales, exports to India as well as other countries. SH 3F as an exporter of subject goods has exported one type of FKM i.e. Terpolymer Bisphenol Curable Raw gum grade of subject goods. The Authority notes that SH 3F has exported 2000 kg of Terpolymer Bisphenol Curable Raw gum grade of subject goods to India.
79. The Authority notes that subject goods produced by All Top (now IM 3F) has been physically supplied to SH 3F. SH 3F has further undertaken exports of subject goods to India with a significant mark up. The export price is exclusive of VAT. The Ex-factory export price for IM 3F (the producer) has been computed on the basis of sales price from IM 3F to SH 3F as \*\*\* US\$/kg after making adjustment on inland freight charges to the extent of \*\*\* USD/kg.

**LANDED VALUE:**

The landed values of subject goods exported by SH 3F have been computed by applying applicable basic customs duty and cess on the assessable value which is considered as CIF import price plus landing charges. Transactions on FOB have been converted to CIF by adding appropriate expenses

on insurance/ocean freight as applicable. The Landed Value of goods exported by SH 3F is determined as \*\*\* INR/Kg (\*\*\* USD/kg).

**Ex-factory export price of Subject goods exported by CFSE**

- 80(a) The Authority notes that as per the Questionnaire response, the producer/exporter has exported two grades of FKM i.e. FKM copolymer Pre compound and FKM Terpolymer Pre Compound to an extent of 31.375 MT with breakup of \*\*\* kg and \*\*\* kg respectively during POI. The Copolymer Pre Compound has been exported both to end users (\*\*\* kg) and to trader (\*\*\* kg) and Terpolymer to trader(\*\*\* kg). The Authority has computed ex-factory export price and landed value for 2 grades separately for an Apple to Apple comparison with NV and NIP on grade basis irrespective of the customer type.

**a. Copolymer Pre Compound**

The Authority notes that producer/exporter has exported the above type of PUC to an end user at an invoice price of \*\*\* CNY/kg (CIF) and to trader in India at \*\*\* CNY/kg (FOB).

- i. The adjustments have been claimed by the producer/exporter on exports to end user on account of discount/commission, packing, Inland freight, Overseas freight, Overseas Insurance, Bank charges, Credit Cost and VAT refund to an extent of \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* (CNY/kg) respectively. The Authority on the basis of desk study has verified the adjustments on sample evidence and system reports and has allowed the same. As regards VAT refund the producer/exporter has claimed enhancement in export price to an extent of 13% on FOB. However, it is noted that out of the applicable VAT, the producer/exporter gets a 13% refund with 4 % VAT becoming cost incidence and therefore needs to be adjusted further beyond above mentioned adjustments to arrive at ex-factory export price. The VAT refund rather than \*\*\* CNY/kg as a roll back is considered as \*\*\* CNY/kg as a deductible expense for arriving at Ex- factory export price. The ex-factory export price is considered as \*\*\* CNY/kg (\*\*\* \$/kg)
- ii. As regards the export sales to trader, the adjustments have been claimed on account of discount/commission, packing, Inland freight, Bank charges and VAT refund to an extent of \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* (CNY/kg) respectively. The Vat refund as per methodology stated above is considered as \*\*\* CNY/kg. The exfactory export price comes to \*\*\* CNY/kg (\*\*\* \$/kg). The weighted average Ex-factory export price for Copolymer pre compound for both sales channel comes to \*\*\* \$/kg. The weighted average Landed Value comes to \*\*\* \$/kg.

**b. Terpolymer Pre Compound**

The Authority notes that producer/exporter has exported the above type of PUC only to a trader at an invoice price of \*\*\* CNY/kg.

- i. The adjustments have been claimed by the exporter/producer on exports to trader on account of discount/commission, packing, Inland freight, Bank charges and VAT refund to an extent of \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* (CNY/kg) respectively. The Vat refund as per methodology stated above is considered as \*\*\* CNY/kg. The exfactory export price comes to \*\*\* CNY/kg (\*\*\* \$/kg). The Landed value comes to \*\*\* \$/kg.

The Authority notes the submission on VAT adjustment by the producer/exporter and holds that VAT refund to the extent VAT is borne as an expense is deductible.

**Determination of Dumping Margin**

The export price to India (net of all the adjustments claimed by the exporter and accepted by the Authority) have been compared with the normal value to determine dumping margin. The weighted average dumping margin of all goods during the POI for all exporters/producers from subject country has been determined and the same have been indicated in the table below. For residual category, the Authority has considered the highest dumping margin evidenced amongst the cooperating producers/exporters.

SN	Producer	Exporter	Dumping Margin - US\$/Kgs	Dumping Margin - %	Dumping Margin Range- %
1	M/s. Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co, China PR	Solvay (Shanghai) Co., Ltd, China PR	***	***	40-50
2	Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd, China PR	Uni-Alliance Limited, China PR	***	***	20-30
3	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd, China PR	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd, China PR	***	***	30-40
4	Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR	Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR	***	***	30-40
5	Inner Mongolia 3F, China PR	Shanghai 3F, China PR	***	***	100-110
6	Residual Others		***	***	100-110

## **H. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**

### **81. Submissions by exporter, importer and other interested parties**

- i. The domestic industry is already in existence for three years, started commercial production from July 2015. Accordingly, it cannot be concluded that the purported dumping has materially retarded the establishment of the Domestic Industry. Domestic Industry cannot claim material retardation as it is already established.
- ii. All three forms of injury cannot co-exist simultaneously (Korea- Anti-Dumping Duties on Imports of Polyacetal Resins from the United States refers).
- iii. Proposals on material retardation to the WTO have no legal sanctity.
- iv. No material injury or threat of material injury or material retardation suffered by domestic industry as relevant economic parameters show significant improvement.
- v. Petitioner has exaggerated the increased imports of subject goods and deliberately invented material retardation.
- vi. The petitioner has not brought any substantive evidence of dumping and/or injury to provide the condition for initiation of AD investigation while the investigating authority has not carried out appropriate scrutiny of facts.
- vii. Application does not meet the evidentiary and legal standards regarding dumping, injury and causal link between alleged dumping and injury.
- viii. Initiation of the investigation is short of factual and legal basis is baseless and thus, the same should be terminated.
- ix. The claims of petitioner appears to be, manipulated and fabricated in order to show injury.
- x. Imports from subject country have increased with the increase in demand and have compensated decline in imports from other countries. There is no volume effect caused by imports from China PR during the POI.
- xi. Petitioner has exported the subject material to other countries at prices much lower than the prices at which the goods have been imported in India from China PR and that too mainly to its subsidiary companies such as GFL America, GFL GMBH. This is one of the main reasons of purported injury to the Domestic Industry.
- xii. Price undercutting, which is most important parameter to establish causal link, is negative during the entire injury period.
- xiii. There might be some other factors which are causing injury to the domestic industry that needs to be



- examined by the DA. The petition deliberately fails to address a number of crucial issues which had an impact on the domestic industry independently from the subject imports.
- xiv. Capacity, production and capacity utilization have been at the highest-level during POI and there is no reduction in these parameters.
  - xv. Petitioner is selling whatever they are producing. Their focus has been exports, by choice and not by chance, and not Indian market.
  - xvi. Domestic industry is facing losses during the injury period even when imports were not causing injury. There might be some other reason for its injury and not the subject imports.
  - xvii. The productivity of domestic industry has increased.
  - xviii. There is no price effect as price depression is due to GFL's own pricing policies.
  - xix. The negative performance with relation to profitability is due to unremunerative pricing of like articles produced by domestic company.
  - xx. The domestic industry has not segregated the export profit/loss from domestic sales profit/loss in calculating return on capital employed and cash profits. Hence, the extent of deterioration is flawed as there is no separation of injury due to exports.
  - xxi. The commencement of production coincided with decline in demand, hence target anticipated in the project reports could not be achieved which were set when demand was increasing. However, the domestic industry captured a sizeable market in short span of time.
  - xxii. There is no injury with respect to employment, wages and productivity and no adverse impact on the Growth of the domestic industry.
  - xxiii. The correct way to analyze the inventories is to compare the closing inventories with the domestic sales made by the domestic industry as laid down by the Hon'ble CESTAT in the case of Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) Vs. DA 2011 (270) E.L.T. 696 (Tri. - Del.).
  - xxiv. The assertion of the petitioner that it has exported significant volume of the PUC only because of dumping of the product in the country is misleading. Both domestic and exports sales of the petitioner increased significantly in the POI as compared to 2015-16 (Year of commencement of the production by the petitioner). The respondent has not resorted to any dumping.
  - xxv. In a short span of two years of operation, the petitioner's domestic sales have increased by five times, market share increased by four times, capacity utilisation increased by two times etc. In such case, it is baseless and wrong to say that the dumped imports are inhibiting the growth of the domestic industry. The petitioner has suffered injury, if any, on account of its inefficiencies and poor quality of the product. It may also be noted that it is on account of these other reasons that the petitioner has incurred losses not only in the domestic market but also in the export market.
  - xxvi. It is requested that 2014-15 data should be ignored. Further, 2015-16 should be considered as base year for injury analysis. Also, the investigation should be terminated since this investigation has been initiated based on wrong analysis of the data and information provided by the petitioner.
  - xxvii. The Domestic Industry's contention that dumping by Chinese producers and exporters at low prices are restraining the Domestic Industry from capturing the desired market share and thereby, are inhibiting growth is false and deceptive for the simple reason that the Domestic Industry has been selling the subject goods produced by it at prices that were lower than the landed value of imports from China. A situation of inability to capture market share due to cheap dumped imports may only arise when the Domestic Industry prices its goods higher than that of the alleged dumped imports. The only reason for which users of the subject goods would not source the same from the Domestic Industry would be due to quality issues as evidently, the prices at which the Domestic Industry is offering the subject goods is far more attractive, being much lower than the prices of imports.
  - xxviii. Data prior to July 2015 is relevant to the extent of analyzing the trends prevalent of the subject goods in the domestic market of India. As there was no production of the subject goods prior to July 2015, the trends of demand and consumption, prices of subject goods etc. are necessary to ascertain whether the claims of the Domestic Industry such as lowering of prices, changes in patterns of consumption and demand in the domestic market etc., are correct.

- xxix. Such a trend comparison by taking data prior to July 2015 is especially necessary in the facts and circumstances of the present case as it can be seen that the demand of the subject goods in the domestic market had sharply declined in 2015 when compared to the preceding year. Furthermore, landed value of imports from China increased by approximately 9% in 2015. This clearly contradicts the misleading claim of the Domestic Industry that China lowered its prices to India when the Domestic Industry commenced production in 2015 when in fact, Chinese imports had become more expensive.
- xxx. The claims of Domestic Industry regarding co-existence of two forms of injury is entirely misplaced as the forms of injury specified in Section 9B(1)(b)(ii) have been separated by the words “or” which has been used in its disjunctive sense which indicates that the same are mutually exclusive. It is a settled position of law that needs no reiteration that the word “or” has to be used in its ordinary sense unless reading it as disjunctive would result in an unintelligible or absurd meaning. Reliance is place on Supreme Court Judgment in *Municipal Corpn. Of Delhi v. Tek Chand Bhatia* [1980] 1 SCC 158 wherein it was stated that or has to be read in its ordinary disjunctive sense unless the context indicates.
- xxxi. There is no provision in the AD Rules 1995 which indicates that if one form of injury is not found, the other form may be examined. Neither does Section 9B(1)(b)(ii), nor does Rule 11 or Annexure II provide either explicitly or through necessary implication that the DA ought to check for other forms of injury if the injury in the nature of the initial claim by the Domestic Industry is not made out.
- xxxii. Although the decision in *Korea - Anti-Dumping Duties on Imports of Polyacetal Resins from the United States* (ADP/92, and Corr.1) was issued before the present ADA came into existence, the relevant provision regarding the term “injury” under the erstwhile Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (“Tokyo Round Anti-dumping Code”) are *pari materia* with the ADA. A bare perusal of footnote 9 of the ADA and footnote 3 of the Tokyo Round Anti-dumping Code makes it clear that the understanding of the terms ‘material injury’, ‘threat of material injury’ and ‘material retardation’, as they were provided for under the Tokyo Round Anti-dumping Code, have not undergone any change under the present ADA either.
- xxxiii. It is also no longer *res integra*, as per the decision of the Hon’ble Supreme Court in *Commissioner of Customs, Bangalore v. G.M. Exports & Ors* [(2016) 1 SCC 91] that while interpreting a provision in a municipal law that has been enacted by the legislature as a consequence of the obligations incurred by India as a result of being a signatory to an international treaty, the interpretation of such a statute should be construed on broad principles of general acceptance rather than earlier domestic precedents, being intended to carry out treaty obligations, and not to be inconsistent with them.
- xxxiv. The Indian provisions regarding establishment of injury are based on the provisions contained in the ADA. Therefore, in view of the GATT Panel Report in *Korea - Anti-Dumping Duties on Imports of Polyacetal Resins from the United States* (Supra), it is established that all three forms of ‘injury’ cannot co-exist for the same Domestic Industry.
- xxxv. The domestic industry placed reliance on EU Commission Regulation (EEC) No 165/90 dated 23rd January 1990, wherein the EC found both material injury and material retardation to substantiate its claim. However, it is no longer good law in view of the later GATT Panel decision in *Korea - Anti-Dumping Duties on Imports of Polyacetal Resins from the United States* (Supra) which has expressly ruled to the contrary.
- xxxvi. The Domestic Industry’s reliance upon the final findings dated July 12, 2017 of the DA in the case of SBR 1500-1700 series and the CESTAT appeal thereto is also misplaced as the Domestic Industry in the aforesaid case consisted of two domestic producers- one which suffered material injury on the factum that it was an established domestic producer, the other was examined for material retardation due to the reason that it was not considered as established as it had not commenced. Therefore, the facts and circumstances of that case are inapplicable to the present case inasmuch as the Domestic Industry in the present case consists of only one domestic producer.
- xxxvii. The DA and the Hon’ble CESTAT did not have the advantage of the GATT Panel report in *Korea - Anti-Dumping Duties on Imports of Polyacetal Resins from the United States*, which is to be considered as the authoritative pronouncement on the issue as per the law laid down by the Hon’ble

Supreme Court in G.M. Exports while deciding the case of SBR and as such, the aforesaid decisions were passed in ignoratium of the settled legal principle that all three form of injury cannot co-exist.

- xxxviii. The Designated Authority's final finding in anti-dumping investigation concerning PHPG Dane Salt originating in or exported from China PR and Singapore cannot be relied upon as it's determination were arrived at without taking the arguments of the parties into consideration and without assigning any reasons whatsoever on how both forms of injury could co-exist for the same Domestic Industry. Such an unreasoned finding on the said issue of injury has to be treated as sub-silentio and therefore, is not a binding on the DA while deciding the present case. Reliance is placed upon the Supreme Court judgment in State of U.P. & Anr. v. Synthetics and Chemicals Ltd. & Anr. [(1991) 4 SCC 139].
- xxxix. The Domestic Industry has again sought to rely upon the discussions and proposals of the WTO member countries for the purpose of establishing how material retardation is to be ascertained, especially the proposed amendment to the ADA by way of insertion of an Article 3.9. Even though the proposal may not have been incorporated into the substantive provisions of the treaty, the same can be relied upon if there is a subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the interpretation of its provisions in terms of Article 31(3)(a) of the VCLT. Unfortunately, the Domestic Industry has not been able to provide any material regarding the existence of any such agreement either.
- xl. The domestic industry tried to mis-guide the investigating authority vide its pre-hearing submission (letter dated 17<sup>th</sup> May 2018) showcasing an excellent export performance and growth. They purposely used indexed data to put its point as per their benefit. As soon as the Chinese producers and AIRIA mentioned, during the oral hearing, that their material has failed in International market due to poor quality in spite of offering the same at very low prices.
- xli. We request the designated authority to take cognizance that how this has suddenly become "Make for India" plant to disguise their dismissal export performance. Perhaps, even the respected authorities will find it strange that a so called global company has set up a plant with the intention to cater domestic market only, while they believe their product quality and cost of production is comparable to International standard. The Designated Authority is requested to critically examine the same.
- xl.ii. Zhonghao Chenguang has done detailed R&D and patented many grades which are exclusively produced by them only, thus, there is no need to sell those products at lower prices or causing injury to the Domestic Industry. The prices at which Zhonghao Chenguang is selling are completely market driven.
- xl.iii. It is submitted that Trade Notice No. 5/2018 dated 28<sup>th</sup> February 2018 is applicable to the investigations initiated after the issuance of trade notice. Since the present investigation was initiated on 2<sup>nd</sup> January 2018, the same trade notice is not applicable to the participating exporters/importers. However, if the Authority so desires, we are willing to provide all information.

## 82. Submissions by Domestic industry

- i. The imports from the subject country have increased over the injury period in absolute terms and in POI by 50% as compared to the base year as compared to the base year against 13% increase in demand
- ii. The share of subject imports in total imports entering India has increased throughout the injury period and is 49.50% during the POI, while that of other countries have decreased throughout during the corresponding period.
- iii. The share of imports from the subject country in domestic demand/consumption has also increased over the injury period and is 42.67% during the POI.
- iv. There is a decline by Rs.28/Kg in import price over the injury period and is much below the average CIF import price and that from the other countries.
- v. The import price from subject country declined very steeply after 2015-2016, the year in which the domestic industry started its commercial production. It decreased by Rs.113/Kg i.e 11% in POI as compared to 2015-16 when the domestic industry came into existence.

- vi. Price undercutting from China is negative because the domestic industry is compelled to keep low prices in order to compete with cheap import prices from the subject country.
- vii. The subject country imports are depressing domestic industry's prices.
- viii. The market share of the domestic industry in Indian demand has increased over the injury period but continues to be abysmally low, despite the demand of the product in the country has increased.
- ix. The domestic industry has been prevented by the presence of dumped imports from increasing its production, sales, capacity utilization and market share despite existence of significant demand and capacities in the Country.
- x. Inventories with the domestic industry are increasing constantly, despite low production.
- xi. The petitioner is suffering significant financial losses, cash losses, and negative ROI.
- xii. The growth of the domestic industry is negative in terms of a number of price parameters.
- xiii. The injury margin is positive and significant.
- xiv. Dumping of the product under consideration is not allowing the domestic industry to fully establish itself. The domestic industry had commenced the commercial production in July, 2015 and the period of investigation in the present investigation is July, 2016 to June, 2017. The Designated Authority may consider (a) actual performance so far to establish effect of dumping, (b) potential situation in order to establish threat of injury and (c) whether dumping of the product under consideration is materially retarding the establishment of the domestic industry in India.
- xv. The petitioner fails to understand that how an industry cannot claim retardation within one year from the date of its commencement of commercial production.
- xvi. The Rules do not state that the retardation should be claimed only when the company has not commenced commercial production. If a new industry is facing injury, it follows that it is getting materially retarded. Decision of the Designated Authority in the matter of SBR is referred to and relied upon, which has since been affirmed by the Supreme Court as well. It cannot be said that an industry is getting materially retarded but not suffering material injury, particularly if the domestic industry has performed for some time. In fact, absence of material injury to the extent of performance must be pre-requisite in case of retardation.
- xvii. Petitioner is at its "nascent stage of business". The rules do not specify that authority records this form of injury only if the domestic industry has performance of less than one year. In fact, the WTO guidelines on the investigation period suggest that if the domestic industry performance is below 3 years, it shall fall in the category of nascent stage. The law has recognized only three forms – retardation to establishment, material injury and threat of material injury. Thus, there cannot be more than two stages of a domestic industry – in the process of development or developed.
- xviii. In the present case; Imports are leading to material retardation. The petitioner has so far suffered a loss of Rs. 12.74 crores as of now on an investment of 30 crores. The performance of the domestic industry so far clearly shows that during the short period of operation, the performance of the domestic industry has deteriorated.
- xix. Three forms of injury i.e. material injury, material retardation and threat of material injury can co-exist. The Rules imply that if one form of injury is not found, the other form of injury must be examined. "Or" has to be read as "and", if more than one form of injury exists.
- xx. The domestic industry has essentially claimed injury on the basis of material retardation to establishment of the domestic industry to the extent the petitioner has been prevented from utilising its capacities and is facing significant sub-optimal utilisation and significant financial losses. Further, petitioner has claimed material injury in as much as petitioner's performance as exists and the same shows significant financial and cash losses.
- xxi. The Authority has time and again found the co-existence of material injury and material retardation as has been done in the investigations concerning Induction Hardened Forged Steel Roll from Russia, Ukraine and Korea RP, PVC Flex Films originating in or exported from China PR, 1,1,1,2,-

Tetrafluoroethane or R-134a of all types originating in or exported from China PR and Japan and O-Acid originating in or exported from China PR.

- xxii. In the anti-dumping investigations concerning D(-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt originating in or exported from China PR and Singapore and D(-) Para Hydroxyl Phenyl Glycine Base originating in or exported from China PR and Singapore, the Authority found the existence of all three forms of injury i.e. material retardation, material injury and threat of injury. Reliance is also placed on finding in EU Japanese Dynamic Random Access Memory (DRAMs) case (Regulation (EEC) 165/90, OJ L20, 25.1.90).
- xxiii. Respondents' reference to Korea- Anti-Dumping Duties on Imports of Polyacetal Resins from the United States case is irrelevant because of two foremost reasons. Firstly, the above decision was before the Anti-dumping Agreement came into existence and secondly in view of the case of Styrene Butadiene Rubber, where the Authority in its final finding dated 12th July, 2017 has examined both material retardation and material injury simultaneously. The Authority held that:
- “x. The Anti-Dumping Rules do not prevent simultaneous examination of both these forms. It cannot be held that the 3 forms of injury are mutually exclusive.”*
- The findings of the authority were challenged in CESTAT contending the finding issued by the Designated Authority in SBR on the ground that both type of injury can-not be examined together. The CESTAT upheld the findings of the Designated Authority.
- xxiv. The Designated Authority even in the matter of Veneered Engineered Wooden Flooring originating in or exported from China PR, dated 13th Feb, 2018 held the coexistence of the material injury and material retardation. Going by the above analysis of the Designated Authority under various cases it is held again and again that all the forms of injury are not “mutually exclusive” and may co-exist together for the purpose of determination of different kinds of injury being suffered by the Domestic Industry.
- xxv. The authority may kindly consider the present case as a case where establishment of domestic industry was getting materially retarded and the same is established by considering the existing performance on one hand and comparison of existing performance with the projected/targeted performance. However, should the interested parties insist that the domestic industry is already established and both material retardation and material injury cannot co-exist, in that event the authority may kindly consider the present case for the purpose the determination of material injury as the petitioner has already commenced commercial production in July 2015. In such event, the authority may kindly apply Annexure-III for the purpose of determination of NIP and injury margin and consider that the capacity utilization in POI was at its optimum level and in that event, NIP is required to be determined by considering the capacity utilization achieved during the POI. Should the Designated Authority examine the present case as a case of material injury, as the capacity utilization in the POI was optimum, no normation may kindly be done for determination of the NIP.
- xxvi. The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry. The law doesn't say that the economic parameters necessarily show decline. The word “evaluation” doesn't mean “demonstration” and “existence”. Such evaluation will definitely be different for each case as per the situation of the concerned industry. Reliance is placed on decision in EC — Bed Linen (Article 21.5 — India).
- xxvii. The sales volume of the domestic industry could not increase in tandem with increase in capacity and production due to availability of dumped imports in the market. The domestic industry could utilise its capacities only to the extent of 36.10% during the POI and up to 54.76% in 2017-18. Further, having produced 238 MT in POI, the domestic industry was not able to sell to the extent of its production and was forced to export the product out of India.
- xxviii. The fact that some criteria do not show injury will not discredit an affirmative finding.
- xxix. The subject imports have increased by 50% over the injury period. The subject imports are causing material injury and materially retarding the establishment of the domestic industry.

- xxx. The opposite party has miserably failed to point out as to how this precondition of Rule 5 has not been met with.
- xxxi. The information filed by the domestic industry has already been duly verified by the Authority. The Authority had initiated the present investigations on the basis of sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury. The applicant has provided all relevant information in support of its claim of dumping, injury and causal link and the Authority have found it appropriate to initiate the investigations.
- xxxii. Exporting the subject goods was not the domestic industry's choice but its compulsion. GFL was forced to sell in US market at a low price only because of the sale of Chinese product at low prices in US market.
- xxxiii. As regards exports at a low price to affiliated party, while the issue is irrelevant to the present investigations, should the Authority still consider relevant, the domestic industry can provide information on resale price of the exported product to show that there is no material difference in the export price of the petitioner and sales price of the US affiliated (after adjusting for their expenses).
- xxxiv. As regards no volume effect caused by imports from China PR; the subject imports have increased by 50% in the period of investigation as compared to the base year, the demand has increased by 112 MT by 13%.
- xxxv. The non-subject countries imports have declined but their import price has increased while that of subject country has decreased.
- xxxvi. There were no DI sales in 2014-15 as DI started its commercial production in July, 2015. The same has increased from 26 MT in 2015-16 to 132 MT in POI. The DI is not able to utilize its capacities and is running at a very low capacity utilization rate. The subject imports are 68% more than the sales of the domestic industry in POI even after having the demand increased in the market. The subject imports have always put pressure as can be seen from the sales figure of domestic industry. Even after the increase in demand, the domestic industry could not sell what it produced. Thus, it cannot be said that there is no volume effect caused by imports from China PR during POI.
- xxxvii. Price undercutting is the most important parameter under the law. The rules refer to price undercutting and price suppression/depression and place these with "OR", which means alternatives. Thus, contrary to the claim, price undercutting, price suppression and price depression are at equal footing.
- xxxviii. The price undercutting in present case is negative for a very valid reason. The petitioner being a new player has given favorable prices to the consumers to switch them from the imported product. However, the exporters reduced their prices further.
- xxxix. The initial prices offered by the petitioner itself were injurious, when considered with optimum costs and NIP (the petitioner is not even claiming injury based on actual cost, price, profits). Secondly, being a retardation case, there is no data for the longer four years period and therefore, the suppression/depression is getting determined based on the data for a much shorter period. The relevant benchmark therefore is optimum costs and NIP.
- xl. Regarding the contention of existence of others factors causing injury; the respondent has failed to justify its claim or to show existence of any other factor which might have caused injury to the domestic industry. The respondent has not pointed out any "crucial issues" which had an impact on the DI independently from the subject imports.
- xli. As regards the argument that domestic industry is facing losses during the injury period even when the imports were not causing injury; the factuality clearly proves that the domestic industry is facing injury since the time of its commencement of commercial production and the same is due to the presence of dumped imports throughout.
- xl.ii. The domestic industry's plant was running at meager 36.10% capacity utilization during the POI, which in no prudent manner could be considered as a barometer for concluding that the domestic industry is not suffering injury. Production has increased throughout the injury period. However, the increase in sales was far lower than the increase in production.

- xliii. The domestic industry acknowledges that the productivity per day and per employee has increased throughout the injury period. Thus, the possible decline in productivity could not a reason for the injury to the domestic industry.
- xliv. As regards the argument that price depression is due to GFL's own pricing policy; the same is incorrect as landed price of imports from the subject country is significantly below the cost of production of the domestic industry.
- xlv. As, the domestic industry has started offering the product under consideration in the market from July, 2015, the prices fixed by the domestic industry were benchmarked to the import prices.
- xlvi. The only factor responsible for the low domestic industry prices are the import prices of the product from the subject country and the cost of production of the domestic industry.
- xlvii. Regarding the contention of unremunerative pricing; it is the intensified dumping with the commencement of production by domestic industry which has forced the petitioner to reduce the prices.
- xlvi. The reduction in cost was not due to decline in input cost but due to increase in production and decrease in per unit fixed costs.
- xlix. As regards the argument that extent of deterioration is flawed as there is no separation of injury due to exports; the domestic industry submitted that the injury submissions made by the petitioner are on the basis of domestic sales and not exports.
  - i. The domestic industry needs to be seen as it exists and not in the ideal situation as has been held by the Tribunal in the matter of Nippon Zeon Co. Ltd., Japan & Others v. Designated Authority [1997 (96) E.L.T. 126 (T)].
  - ii. The position of domestic industry, in the base year in comparison to the following years, is not truly indicative of the prevalent situation of the domestic industry; as GFL has recently commenced its production of the subject goods and is a new player in the market.

#### **Examination by the Authority**

- 83. The Authority notes various relevant post disclosure submissions by the interested parties which have been dealt later in this section. The Authority notes that domestic industry had filed application on grounds of both material injury and material retardation as has been mentioned in the initiation notification.
- 84. The Authority notes that establishing injury on account of material retardation to the domestic industry due to dumped imports has been an aspect of discussion under WTO's Negotiating group of rules from time to time. However consensus has not been arrived at in codification of appropriate parameters to establish material retardation. The Authority notes that in following documents certain suggestions emanated in meetings in WTO:
  - (i) **In document no. TN/TL/W/213 dated 30 November, 2007- Draft Consolidated Chair Texts of the AD and SCM Agreements, it was proposed to amend the Agreement by way of insertion of Article 3.9 as follows:**

*"3.9 A determination of material retardation of the establishment of a domestic industry shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. An industry may be considered to be in establishment where a genuine and substantial commitment of resources has been made to domestic production of a like product not previously produced in the territory of the importing Member, but production has not yet begun or has not yet been achieved in commercial volumes.<sup>3</sup> In making a determination whether an industry is in establishment, and in examining the impact of dumped imports on the establishment of that industry, the authorities may take into account*

<sup>3</sup> *The authorities may however consider that an industry is in establishment notwithstanding the existence of established producers of the domestic like product, if those established producers are not able to satisfy domestic demand for the product in question to any substantial degree; provided that under no circumstances shall an industry be considered to be in establishment if the collective production capacity of established producers exceeds 10 per cent of domestic demand for the product in question.*

*evidence concerning, inter alia, installed capacity, investments made and financing obtained, and feasibility studies, investment plans or market studies.*<sup>4</sup>”

**(ii) In document no. TN/RL/GEN/40 dated 13 May 2005, no. TN/RL/E/105 and no. TN/RL/W/175 dated 31 March 2005 Egypt, one of the WTO member countries proposed that:**

*“Definition: .....it is proposed to clarify the current text of footnote 9 to Article 3 to clarify that the concept of "material retardation" is not limited to industries which are established from zero, but should apply to all domestic industries which are characterized by a limited level of development and/or a new organization.*

*It is crucial not to limit the "material retardation" test to industries which are newly established; hence particular concern should be paid to embryonic, restructuring and newly privatized industries which should also be regarded as industries in the process of establishment. This matter is of specific concern to developing country Members since their domestic industries are rarely developed.....*

*Test: ..... Footnote 9 to Article 3 specifies that injury which shall also mean material retardation shall be interpreted in accordance with the provisions of Article 3 of the Agreement. Therefore, Egypt understands that investigating authorities should consider and evaluate the factors listed in Article 3.4 also in case of material retardation. This seems supported by the Panel's findings in Mexico – HFCS. In that case, the Panel explained that Article 3.7 sets out additional factors that must be considered in a threat case, but does not eliminate the obligation to consider the impact of dumped imports on the domestic industry in accordance with the requirements of Article 3.4. In other words, according to the Panel, investigating authorities should consider both the factors listed in Article 3.7 as well as the factors listed in Article 3.4 in a threat case. The Panel explained that this conclusion is mandated by the text of Article 3 which, as a whole deals with the determination of injury which is defined as material injury, threat of material injury, or material retardation of the establishment of a domestic industry.....”*

**(iii) In document no. G/ADP/AHG/W/168- Note by the Secretariat, Korea, one of the WTO member countries discussed that:**

*“1.22. (Korea) Criteria in determining "material" in both "material" injury and "material" retardation under footnote 9*

*Authorities shall consider, under Article 3.2, the 'significance' of the increase in dumped imports, the price undercutting by the dumped imports, and the degree of the depressive effect by the dumped imports, respectively.....*

*Article 3.4 exemplifies four groups of relevant economic factors and indices to be evaluated by authorities in examining the impact on the domestic industry of the dumped imports. An objective methodology should be established for the same reason as agenda item 3. For instance, it can be considered whether each indices of the same group have varied collectively, or whether the weighted average of the group can function as a general index.”*

The Authority notes that out of the various suggested parameters of evaluation, the level of development of the domestic industry requires appropriate analysis against listed parameters under Article 3.4 for evaluating the existence and extent of material retardation.

85. The Authority in past has in a few cases analyzed injury on account of material retardation to the domestic industry. The analysis of this form of injury has been an integral part of overall injury. These cases include Veneered Engineered Wooden Flooring from China PR, Malaysia, Indonesia and the European Union dated the 13th February, 2018, O- Acid originating in or exported from China PR Dated the 19th December, 2017, Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 series and 1700 series from European Union, Korea RP and Thailand dated the 12th July, 2017, ‘Resin or other organic substances bonded wood or ligneous fibre boards of thickness below 6mm, except insulation boards,

<sup>4</sup> *Members recognize that an examination of possible material retardation relates to the impact of dumped imports on the efforts of the industry to become established, and that this type of impact may not be reflected in actual or potential declines in performance. Nonetheless, the authorities shall evaluate, to the extent that data exists, available information with respect to all economic factors and indices relevant to an examination of material retardation of the establishment of the domestic industry in question.*



laminated fibre boards and boards which are not bonded either by resin or other organic substances' originating in or exported from China PR, Indonesia, Malaysia and Sri Lanka Dated 10th May 2013, PVC Flex Films originating in or exported from China PR Dated the 29th July, 2011, Induction Hardened Forged Steel Roll from Russia, Ukraine and Korea RP dated the 2nd July, 2003, D(-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt originating in or exported from China PR and Singapore and D(-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base originating in or exported from China PR and Singapore.

86. The parameters of analysis have been broadly capacity utilization, sales and profitability which are also the parameters considered for material injury. However after establishing material retardation, the Authority has examined these parameters in context of extent of growth and level of development of industry. The Authority in certain cases has also recommended measures below the normal tenure of even 5 years. The post disclosure submissions on injury and causal link have been dealt later by the Authority in this finding.
87. The Authority has evaluated and analyzed various volume and price parameters related to injury to domestic industry (material and as well as material retardation) as tabulated below.

**a) Demand and Market Share**

88. The demand or consumption of the product under consideration in India has been determined as the sum of domestic sales of the Indian producer and imports from all sources as depicted in table 1 below.

**Table 1: Demand and Market Share**

Particular	Units	2014-15	2015-16	2016-17	POI
<b>Demand (MT)</b>					
Sales of Domestic Industry	(Actual) MT	-	26	108	131
Sales of Domestic Industry	Indexed	-	100	310	376
Imports from China	MT	271	300	352	407
Import from Other Countries	MT	570	402	421	415
<b>Total Demand</b>	<b>Indexed</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>105</b>	<b>113</b>
<b>Market share in demand %</b>					
Sales of Domestic Industry	Indexed	-	100	341	383
Sales of Other Indian Producers	%	-	-	-	-
Subject Country - China	Indexed	100	128	124	132
Share of Other Countries	Indexed	100	81	70	64

89. The Authority notes that the demand for the product under consideration has increased over the injury period from base year 2014-15 (\*\* MT) to \*\* MT in POI showing 13% growth i.e. around 3% per annum. In 2015-16 there is a slight decrease in demand which is also reflected in decreased imports from countries other than China.
90. The share of imports from the subject country in domestic demand/consumption has increased over the injury period from \*\*\*% in 2014-15 to \*\*\*% in POI. Since there was no production of the subject goods in India in the past, the entire demand was being met by imports. The petitioner commenced commercial production of the subject goods in July, 2015 and their market share increased from \*\*\*% in 2015-16 to \*\*\*% in POI.

**b) Import volumes and share of subject country**

91. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India in terms of Annexure II (ii) of the Rules. The volume of imports and market share in total imports entering India are depicted in table 2 below:

**Table 2: The Import profile**

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
<b>Import Volume</b>					
Subject Country - China	MT	271	300	352	407
Other Countries	MT	570	402	421	415
<b>Total import volume</b>	<b>MT</b>	<b>841</b>	<b>702</b>	<b>773</b>	<b>822</b>
<b>Market Share in Imports</b>					
China	%	32.25	42.75	45.56	49.50
Other Countries	%	67.75	57.25	54.44	50.50
<b>Total Share in total import volume</b>	<b>%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>China Imports in relation to</b>					
Petitioner Production	Indexed	-	100	50	50
Consumption	Indexed	100	128	124	132
Total Imports	%	32.25	42.75	45.56	49.50
Petitioner Sales	Indexed	-	100	28	27

- i. The Share of Domestic Industry increased with a matching displacement of imports from non-dumped sources.
- ii. The volume of imports from subject country has increased in absolute and also relative to total imports and consumption over the injury period.
- iii. Imports from other countries have decreased both in absolute and relative terms during the injury period.

**c) Trends of Import Price**

92. The tables 3(a), 3(b) and 3(c) below shows import price trend over the injury period, on an overall, PCN basis and quarterly basis respectively.

**Table 3(a): Trend in Import Price**

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI*
Subject Country- China	Rs./Kg	951	1,037	922	923
Other Countries	Rs./Kg	1,595	1,647	1,740	1,757
Chinese prices as % of third countries prices	%	60%	63%	53%	53%

**Table 3(b): PCN wise Imports during injury period.**

Particular	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI*
<b>Copolymer Pre-Compound</b>	Rs./Kg	1,138	1,117	1,097	1,114
China - Subject Country	Rs./Kg	959	974	908	934
Other Countries (Share => 3%)	Rs./Kg	1,295	1,298	1,504	1,647
Other Countries (Share < 3%)	Rs./Kg	967	1,476	954	1,151
<b>Copolymer Raw Gum</b>	Rs./Kg	1,307	1,661	1,782	1,359

Particular	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI*
China - Subject Country	Rs./Kg	621	-	-	666
Other Countries (Share => 3%)	Rs./Kg	1,510	1,661	1,782	1,732
Other Countries (Share < 3%)	Rs./Kg	-	-	-	-
<b>Terpolymer Bisphenol Cured Raw Gum</b>	Rs./Kg	1,689	1,741	1,724	1,663
China - Subject Country	Rs./Kg	-	-	-	-
Other Countries (Share => 3%)	Rs./Kg	1,741	1,847	1,775	1,704
Other Countries (Share < 3%)	Rs./Kg	1,225	1,074	1,187	1,183
<b>Terpolymer Peroxide Cured Raw Gum</b>	Rs./Kg	1,990	2,450	2,051	1,940
China - Subject Country	Rs./Kg	-	-	-	-
Other Countries (Share => 3%)	Rs./Kg	1,995	2,449	2,048	1,952
Other Countries (Share < 3%)	Rs./Kg	1,650	3,651	2,099	1,796
<b>Terpolymer Bisphenol Cured Pre-compound</b>	Rs./Kg	1,754	2,066	1,699	1,747
China - Subject Country	Rs./Kg	-	2,066	-	-
Other Countries (Share => 3%)	Rs./Kg	1,754	2,064	1,699	1,747
Other Countries (Share < 3%)	Rs./Kg	-	-	-	-
<b>Unidentified Grades/ Types</b>	Rs./Kg	1,245	1,461	1,424	1,411
China - Subject Country	Rs./Kg	948	1,103	963	897
Other Countries (Share => 3%)	Rs./Kg	1,686	1,800	1,855	1,828
Other Countries (Share < 3%)	Rs./Kg	842	1,028	1,316	1,558
<b>Grand Total</b>	Rs./Kg	1,388	1,386	1,367	1,344
China - Subject Country	Rs./Kg	951	1,037	922	923
Other Countries (Share => 3%)	Rs./Kg	1,615	1,669	1,754	1,772
Other Countries (Share < 3%)	Rs./Kg	1,146	1,082	1,384	1,428

Table 3(c): Quarterly Trend of import prices post commencement of production by DI

Particulars	CIF Price Subject Country- China	CIF Price Other Countries	Chinese prices as % of third countries prices
Unit	Rs./Kg	Rs./Kg	%
2015-16 Q2	882	1,649	53%
2015-16 Q3	1,030	1,784	58%
2015-16 Q4	1,025	1,694	61%
2016-17 Q1	931	1,591	59%
2016-17 Q2	900	1,835	49%
2016-17 Q3	938	1,899	49%
2016-17 Q4	909	1,691	54%
2017-18 Q1	930	1,646	57%

The tables above indicate that;

- (i) The import price for China has remained in the range of 50-60% of the import price from other countries. Further in 2016-17, the import price from China dropped by 11% after domestic industry commenced production in July, 2015. This price behavior is contrary to the price behavior from other countries.
- (ii) Import prices from countries with share less than 3% are also significantly higher than import prices from China.

**I. Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry**

93. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry are analyzed herein below:

**a) Production, Capacity, Capacity utilization and Sales**

94. The performance of the domestic industry with respect to production, capacity, capacity utilization and sales is as depicted in table 5(a) and 5(b) below:

**Table 5(a): production and sales parameters**

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Capacity	(Actual) MT	-	495	660	660
Capacity	Indexed	-	100	100	100
Production	(Actual) MT	-	86	200	235
Production	Indexed	-	100	175	205
Capacity Utilisation	(Actual) %	-	17.31	30.36	35.53
Capacity Utilization	Indexed	-	100	175	205
Domestic Sales	(Actual) MT	-	26	108	131
Domestic Sales	Indexed	-	100	310	376

**Table 5(b): Quarter wise Production and Sales Parameters**

Particulars	Capacity (MT)	Production (MT)	Capacity Utilization (%)	Sales (MT)	
				Domestic	Export
Period	Indexed	Indexed	Indexed	Indexed	Indexed
2015-16 Q2	100	100	100	100	100

2015-16 Q3	100	50	50	263	244
2015-16 Q4	100	84	84	349	906
2016-17 Q1	100	73	73	595	250
2016-17 Q2	100	141	141	763	355
2016-17 Q3	100	181	181	555	2791
2016-17 Q4	100	153	153	1031	5561
2017-18 Q1	100	166	166	1228	3013

(i) The production and capacity trends (annual/quarterly) indicate that both production and capacity are generally on a rise but subdued with the best quarterly capacity utilization being at \*\*\*% even though the gap in the country provided opportunity to domestic industry to operate at almost double the present capacity utilization.

(ii) The Authority notes that domestic sales of DI were of repeat nature to customers and that they have even undertaken significant exports. Therefore quality issues does not appear to be a constraining factor for low sales.

**b) Market Share in demand**

95. As stated above, the share of imports from the subject country in domestic demand/consumption has increased over the injury period from \*\*\*% to \*\*\*%. Since there was no production of the subject goods in India in the past, the entire demand was being met by imports. The petitioner commenced commercial production of the subject goods in July, 2015 and their market share increased from \*\*\*% in 2015-16 to \*\*\*% in POI.

**c) Inventories**

96. The performance of the domestic industry with respect to the inventories is depicted in table 6(a) and 6(b) below:

**Table 6(a): Inventory trend**

Particular (Unit in MT)	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Opening	Indexed	-	-	100	107
Closing	Indexed	-	100	203	210
Average	Indexed	-	100	303	317

**Table 6(b): Quarterly Trend of Inventory**

Particulars	Opening Stock (MT)	Closing Stock (MT)
	Indexed	Indexed
2015-16 Q2	-	100
2015-16 Q3	100	123
2015-16 Q4	123	166
2016-17 Q1	166	178
2016-17 Q2	178	246
2016-17 Q3	246	352
2016-17 Q4	352	337
2017-18 Q1	337	349

The closing stock both annual and quarterly depicts progress of stock piling with average inventories being of about 5 month of sales.

**J. Price Effect of dumped imports and impact on domestic industry**

97. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country. The price depression effect has been analyzed with regard to its manifestations in the form of price retardation thereby preventing production to ramp up to an optimum level post commencement of commercial production by domestic industry.

**CHAPTER I Price suppression and depression effects of the dumped imports**

98. In order to analyze whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices which prevents price increases which otherwise would have occurred fairly and reasonably, the Authority notes the changes in the cost, prices and landed value of imports over the injury period as shown in tables 4(a) to 4(d) below:

**Table 4(a): Cost/price Trend**

Particular (Unit in Rs/Kg)	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI*
Cost of sales (Actual)	Indexed	-	100	83	81
Cost of sales (Optimum)	Indexed	-	100	86	85
Selling price	Indexed	-	100	88	87
Landed value	Rs./Kg	1,035	1,128	1,003	1,004
Selling prices as % of Cost of Sales (Actual)	Indexed	-	100	105	106
Selling prices as % of Cost of Sales (Optimum)	Indexed	-	100	101	101
Selling prices as % of landed value	Indexed	-	100	99	98

\*using best Capacity utilization of \*\*\*% on the basis of exporters data

**Table 4(b): Price Undercutting over Injury Period**

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI*
Import Volume	MT	271	300	352	407
Landed price of imports	Rs./Kg	1,035	1,128	1,003	1,004
Net Sales Realisation (Rs/Kg)	Indexed	-	100	88	87
Price Undercutting (Rs/Kg)	Indexed	-	100	97	110
Price Undercutting (%)	Range	-	Negative	Negative	Negative

**Table 4(c): Quarterly Trend of Price Undercutting**

Period	Selling Price (Rs/Kg)	Landed Value	Price Undercutting	
UOM	Indexed	Rs./ Kg	Indexed	Range
2015-16 Q2	100	960	100	10-20
2015-16 Q3	90	1,121	-44	Negative
2015-16 Q4	83	1,116	-89	Negative
2016-17 Q1	83	1,013	-29	Negative
2016-17 Q2	75	979	-65	Negative
2016-17 Q3	76	1,020	-81	Negative
2016-17 Q4	77	989	-57	Negative
2017-18 Q1	77	1,012	-70	Negative

Particulars	Rs/Kg	US\$/Kg
		67.40
Non-Injurious Price (NIP)	***	***
Landed Value	1,004.22	14.90
Price Underselling	***	***
Price Underselling (% Range)	10-20	10-20

**Table 4(d): Price Underselling during POI.**

- (i) It is seen that cost, selling price of the domestic industry and also the landed value of imports from China have decreased in the injury period.
- (ii) In the first quarter of injury period when the domestic industry commenced production, the introductory selling price of domestic industry is noted to be above the landed value of imports from China. The Price Undercutting in the first quarter is later observed to have manifested into a price suppression phenomenon with all subsequent quarterly selling price of DI in the injury period being lower than the landed value from China. The domestic industry progressively enhanced its production to enhance its presence in terms of supply in the domestic market, however this is noted to be happening along with a corresponding price depression trend.
- (iii) The price undercutting therefore barring the first quarter of injury period became negative subsequently throughout the injury period evidencing a significant price retardation. The price suppression is also indicated by the DI's realization of selling price covering only \*\*\*% of the normated cost and being \*\*\*-\*\*\*% of the landed value of imports from China.

**d) Profits, PBIT, return on investment and cash flow**

99. Performance of the domestic industry with regard to profit, return on investment and cash flow have been analyzed for injury period on annual and Quarterly basis in the following tables 7(a) to 7(d) below:

**Table 7(a): Profitability Parameters (Annual)**

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Cost of sales (Actual) - Rs/Kg	Indexed	-	100	83	81
Selling price - Rs/Kg	Indexed	-	100	88	87
Profit/(Loss) per unit - Rs/Kg	Indexed	-	(100)	(74)	(70)
Profit/(Loss) - Rs.Lacs	Indexed	-	(100)	(230)	(263)
Cash Profit - Rs.Lacs	Indexed	-	(100)	(162)	(270)
PBIT - Rs.Lacs	Indexed	-	(100)	(233)	(266)
ROCE - Domestic - %	Indexed	-	(100)	(200)	(235)

**Table 7(b): Profitability Parameters (Quarterly)**

Period	Cost of sales (Actual) (Rs/Kg)	Selling Price (Rs/Kg)	Profit/ Loss (Rs/Kg)	Profit/ (Loss) (Rs/Lacs)	ROI (%)
UOM	Indexed	Indexed	Indexed	Indexed	Indexed
2015-16 Q2	100	100	-100	-100	-100
2015-16 Q3	100	90	-127	-335	-347
2015-16 Q4	100	83	-149	-519	-540
2016-17 Q1	83	83	-82	-490	-440
2016-17 Q2	83	75	-106	-812	-731
2016-17 Q3	83	75	-104	-578	-520
2016-17 Q4	83	77	-101	-1,040	-937
2017-18 Q1	81	77	-92	-1,130	-1,045

\* The Cost of Sales evaluated for the entire year is also referenced for Quarterly periods within the same year.

**Table 7(c): Return on Capital Employed (Annual)**

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Cost of sales (Optimum) - Rs/Kg	Indexed	-	100	87	85
Selling price - Rs/Kg	Indexed	-	100	88	87
Profit/(Loss) per unit - Rs/Kg	Indexed	-	(100)	-82	-80
Profit/(Loss) - Rs.Lacs	Indexed	-	(100)	(255)	(301)
Cash Profit - Rs.Lacs	Indexed	-	(100)	(140)	(318)
PBIT - Rs.Lacs	Indexed	-	(100)	(260)	(307)
ROCE - Domestic - %	Indexed	-	(100)	(298)	(360)



**Table 7(d): Return on Capital Employed (Quarterly)**

Period	Cost of sales (Rs/Kg)	Selling Price (Rs/Kg)	Profit/Loss (Rs/Kg)	Profit/(Loss) (Rs/Lacs)	ROI (%)
UOM	Indexed	Indexed	Indexed	Indexed	Indexed
2015-16 Q2	100	100	-100	-100	-100
2015-16 Q3	100	90	-156	-412	-448
2015-16 Q4	100	83	-201	-702	-771
2016-17 Q1	87	83	-105	-624	-592
2016-17 Q2	87	75	-155	-1,184	-1,127
2016-17 Q3	87	75	-151	-836	-794
2016-17 Q4	87	77	-144	-1,481	-1,412
2017-18 Q1	85	77	-133	-1,631	-1,597

The two key profitability indices i.e. per unit losses and ROCE evaluated on the basis of both actual cost of sales and also normated cost of sales depict losses and negative ROCE respectively. The extent of losses/negative ROCE is much higher when actual COS is considered. If the start up problems are appropriately discounted by considering \*\*\*% capacity utilization, even then these 2 parameters remain significantly adverse. The price depression is noted with price undercutting becoming negative for DI to sustain a reasonable capacity utilization which is manifested in erosion of profitability indicating price retardation.

**e) Employment, Wages and Productivity**

100. It is seen from the table 8 below that production per day and per employee have been increasing over the injury period.

**Table 8: Productivity Parameters**

Parameters	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
No of Employees - Nos	Indexed	-	100	200	222
Wages - Rs.Lacs	Indexed	-	100	155	171
Productivity per day (MT/Day)	Indexed	-	100	156	182
Productivity per Employee (MT/Nos)	Indexed	-	100	117	123

**f) Growth**

101. It is seen that the growth of the domestic industry has been positive in terms of production, sales volume, market share and capacity utilization. However, the domestic industry has always been facing financial losses and its growth in respect of profits, profit before interest, cash profits and ROI has been negative.

Particulars in %	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Net Production	Indexed	-	-	100	25
Domestic Sales Volume	Indexed	-	-	100	23

Particulars in %	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Cost of sales domestic	Indexed	-	-	(100)	(15)
Selling price domestic	Indexed	-	-	(100)	(12)
Average stock	Indexed	-	-	100	7

**g) Ability to raise Capital Investment**

102. The Authority holds that negative profitability, cash flows, returns, increased losses are likely to impair the ability of the domestic industry to raise capital investment.

**h) Level of dumping & dumping margin (DM)**

103. It is seen that subject country imports are entering the country at dumped prices and the dumping margin from the subject country is quite high.

**i) Factors affecting domestic Prices**

104. The examination of the import prices from the subject country, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that landed price of imports from the subject country is significantly below the cost of production of the domestic industry. The domestic industry has started offering the product under consideration in the market from July, 2015; and the prices fixed by the domestic industry were to be benchmarked to the import prices. Demand for the product has shown increase and could not have been a factor responsible for price depression faced by the domestic industry in the POI. There is no inter-se competition as domestic industry is the Sole producer. It is thus noticed that the only factor responsible for the low domestic industry prices are the import prices of the product from the subject country.

**j) Magnitude of Injury and Injury Margin**

105. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules is compared with the landed value of the imports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

SN	Producer	Exporter	Injury Margin - US\$/Kgs	Injury Margin – %	Injury Margin Range- %
1	M/s. Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co, China PR	Solvay (Shanghai) Co., Ltd, China PR	***	***	30-40
2	Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd, China PR	Uni-Alliance Limited, China PR	***	***	0-10
3	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd, China PR	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd, China PR	***	***	30-40
4	Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR	Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR	***	***	20-30
5	Inner Mongolia 3F, China PR	Shanghai 3F, China PR	***	***	20-30

SN	Producer	Exporter	Injury Margin - US\$/Kgs	Injury Margin - %	Injury Margin Range- %
6	Residual / Other Non-cooperating exporters/producers		***	***	50-60

For residual category, the Authority has considered the highest Injury margin evaluated amongst the cooperating producers/exporters, considering lowest landed value and NIP of an appropriate PCN for this purpose.

**k) Post POI- Economic parameters**

Particular	Units	Post POI (Jul'17-Dec'17)	Annualised (Post POI)
<b>Import Volume</b>	<b>MT</b>	<b>417</b>	<b>834</b>
Subject Country - China	MT	238	476
Other Countries	MT	179	359
<b>CIF Import Price</b>			
Subject Country - China	Rs./Kg	950	950
Other Countries	Rs./Kg	1640	1640
Chinese prices as % of third countries prices	%	58%	58%
<b>Market share in import volume</b>			
Subject Country - China	%	57.02%	57.02%
Other Countries	%	42.98%	42.98%
<b>Demand/Consumption in India (MT)</b>	<b>Indexed</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
Sales of Domestic Industry (MT)	Indexed	681	681
Sales of Other Indian Producers (MT)	Indexed	-	-
Imports from China	MT	238	476
Import from Other Countries	MT	179	359
<b>Market share in demand in %</b>			
Share of Domestic Industry	Indexed	490%	490%
Share of Other Indian Producers	%	-	-
Share of Subject Country - China	Indexed	146%	146%
Share of Other Countries	Indexed	52%	52%
<b>Landed Import Price</b>			
Subject Country - China	Rs./Kg	1033	1033
Other Countries	Rs./Kg	1784	1784

*DI Parameters Indexed from 2015-16 and Other Parameters from base year 2014-15*

Particular	Units	Post POI (Jul-Dec'17)	Annualised (Post POI)
Capacity	(Actual) MT	330	660
Capacity	Indexed	100	100
Production	(Actual) MT	164	329
Production	Indexed	384	384

Capacity Utilisation	(Actual) %	49.79	49.79
Capacity Utilization	Indexed	288	288
Domestic Sales	(Actual) MT	89	178
Domestic Sales	Indexed	681	681
Closing Stock (MT)	Indexed	307	307
Selling price domestic (Rs/Kg)	Indexed	92	92

*DI parameters Indexed from 2015-16*

It is noted that post POI the domestic industry has attained capacity utilisation of \*\*\*% with continued price suppression.

106. In regard to various submissions pertaining to claimed injury by domestic industry, the Authority notes that the notice of initiation refers to material injury as well as material retardation. The interested parties have contended that the present case is not a case of material retardation to establishment of domestic industry and that both form of injury cannot co-exist. In this regard, the Authority notes that the domestic industry commenced its production of the subject goods in July, 2015 only and the capacity utilization of the domestic industry is low. Information filed by the foreign producers showed capacity utilization in the range of \*\*\*%, whereas the capacity utilisation of the domestic industry was only \*\*\*% in POI. The petitioner is not able to achieve production capacity to the extent the petitioner had envisaged while setting up the plant. The Authority considers this to draw attention to the examination in similar cases investigated earlier.
107. As regards the contention that the imports increased because of increase in demand, the Authority notes that the imports have increased when the domestic industry has started production and holding capacities beyond the domestic demand and have produced and sold the product.
108. As regards the contention of the other interested parties that the economic parameters of the domestic industry have improved during the POI as compared to previous period; the Authority holds that the injury to domestic industry has on account of volume and price parameters remaining below the desired performance levels. The Authority has also examined the post POI capacity utilization and price realization to evaluate if the claimed material retardation is also evident in post POI.
109. The Authority holds that the factors relevant in this case are price suppression/depression and low capacity utilization which evidence boot strapping phenomenon when examined on a quarterly time period.
110. The Authority notes that there are no specific rules on the methodology to be adopted for evaluation of material retardation to the establishment of a domestic industry. Noting the arguments of the interested parties in this regard, the authority has considered its past determinations, various judicial decisions and the available information with regard to the practices of other investigating authorities as made available by interested parties. The authority notes that in a situation where domestic industry does not have performance over a longer period, it is not possible to analyse injury to the domestic industry by considering an injury analysis as is normally done by authority in a material injury case. The authority notes in this regard that WTO Committee on Anti-dumping practices has prescribed that the period of data analysis for injury purposes should be at the least three years unless the domestic industry concerned does not have existence for a three-year period. This clearly implies that the authority may examine injury to the domestic industry even in those situations where the domestic industry does not have data for three or longer period. Further, the purpose of considering three or more years is to consider the performance of the domestic industry in the POI and compare the same with the earlier periods in order to ascertain whether the performance of the domestic industry during POI could be described as injurious, having regard to the performance in previous years. Considering the methodology that is normally applied in analysing data over the longer period, the authority considers that in a case like the present where performance of the domestic industry is

not available for three-year period, it would be appropriate to divide the performance of the domestic industry within the investigating period. The domestic industry in the present case has its operation from July'2015. The authority has analysed the performance of the domestic industry over this period by undertaking a quarterly analysis of the various injury parameters.

111. As regards the contention that material retardation and materials injury cannot co-exist, the Authority notes that there is no bar under the law for examination of more than one form of injury. The authority has been examining both material injury and material retardation to establishment of the domestic industry in those cases where the domestic industry does not have performance over a longer period and the domestic industry has set up production facilities in recent period. The authority has been examining performance of the domestic industry to the extent of its existence and comparing the performance of the domestic industry with the expected performance. The authority notes in this regard that the past decisions made by the authority in this manner have been upheld by the CESTAT. Thus, considering the fact of this case, the injury to the domestic industry has been examined by undertaking all possible evaluations – actual performance to the extent of domestic industry's existence/operations, potential performance by considering the actual performance till POI, comparison of actual performance with the performance planned or considered by the petitioner while deciding to set up the plant and performance of the domestic industry in respect of macro-economic parameters in the post POI period. The authority has also considered post POI data for the purpose of examining whether the performance of the domestic industry was adverse even in the post POI period.
112. The Authority also notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration; while some may show improvement. The Authority has therefore considered all relevant injury parameters to evaluate whether the domestic industry has suffered material retardation due to dumping or not.

#### **K. Other Known Factors & Causal Link**

113. The Authority has examined other factors listed under the Antidumping Rules which could have contributed to injury to the domestic industry for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry.

##### **(a) Volume and prices of imports from third countries:**

114. The Authority has examined the imports data of the subject goods from DGCI&S. It is noted that even though the imports from third countries are substantial, the import price of subject goods from non-subject countries is materially higher than the import price from China and hence these imports are not a cause of the assessed injury to the domestic industry as may be seen in the table below:

<b>CIF Import Price</b>	<b>Unit</b>	<b>2014-15</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>	<b>POI*</b>
Subject Country- China	Rs./Kg	951	1,036	921	923
Other Countries	Rs./Kg	1,595	1,647	1,740	1,757

##### **(b) Contraction in demand**

115. There has been rise in demand of the product concerned over the injury period and therefore decline in demand is not a reason for injury to the domestic industry.

##### **(c) Changes in the patterns of consumption**

116. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any material change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry.

(d) **Developments in technology**

117. No different technology for production of the product has been claimed or contested to have undergone a change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.

(e) **Conditions of competition and trade restrictive practices**

118. The Authority notes that the subject goods are not subjected to any trade restrictive practices in India. Petitioner is the sole producer of the product under consideration in the Country and therefore while inter-se competition between the domestic producers could not have been a cause of injury to the domestic industry.

(f) **Export performance of the domestic industry**

119. The Authority notes that the performance of the domestic industry and injury there to has been examined with respect to the performance of domestic industry's domestic operation to the extent possible. Possible deterioration in the export performance of the domestic industry is, therefore, not a possible cause of injury to the domestic industry.

(g) **Performance of the domestic industry with respect to other products**

120. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.
121. It is thus seen that none of the listed other factors of injury are responsible for the injury to the domestic industry.

**Factors establishing causal link**

122. The Authority has examined whether injury to the domestic industry is due to dumped imports on account of following factors:
- a) The dumped imports have entered the Indian market throughout the injury period and the volume has increased in absolute terms which have resulted in price depression.
  - b) Since the domestic industry started selling the product under consideration from July, 2015, the prices fixed by the domestic industry were required to be benchmarked to the import prices.
  - c) Presence of dumped imports is preventing the domestic industry to fully utilize its capacity and maximize its production and sales. The domestic industry has been prevented from increasing its production, sales, capacity utilization and market share despite existence of significant demand supply gap in the Country.
  - d) Price depression being suffered by the domestic industry is due to dumping in the Country.
  - e) The domestic industry has suffered significant financial losses which have led to deterioration in return on capital employed and cash profits.
  - f) The growth of the domestic industry is negative in terms of a number of price parameters like ROCE and cash profits.
  - g) The subject imports are also resulting in underselling in the market, when compared with the non-injurious price.
  - h) Dumping of the product under consideration is not allowing the domestic industry to fully establish itself and is unable to increase its production and sales to the extent of optimum level of capacity utilisation despite significant demand for the subject goods in the Country.

**L. Post Disclosure Comments**

123. Pursuant to the Disclosure statement, following submissions are made by the Domestic Industry, Exporters, Importers and User Industries:

**a. Submissions by M/s TPM representing Domestic Industry**

- i. Rejoinder submissions, communications with other interested parties, dumping margin, verification report of exporters/producers should be disclosed.
- ii. The NIP determined by the Designated Authority is unduly low as the Authority has normated the cost of the domestic industry considering the best achieved capacity utilization. Even while it is appreciated that the petitioner has not produced to the extent of optimum levels, it would not be appropriate to consider the expenses charged to PUC in the POI and normate the same on the basis of notational production. This is for the simple reason that a number of these expenses have been charged to the product by following an apportionment methodology linked to production/sales/ turnover.
- iii. It is requested to kindly consider the following approach: (A) Format C-II be redrawn by considering optimum level of production, (b) Apportion fixed expenses between PUC and other product in the ratio of revised turnover.
- iv. Existence of dumping has not been disputed by the producers/exporters in China PR.
- v. Much of the submissions made by user industry have become known to the petitioner domestic industry for the first time through the disclosure statement. The petitioner has not got a chance to rebut the issues raised by user industries so far. The petitioner requests to make available the non-confidential version of the same.
- vi. As per the decision of Hon'ble Supreme Court in Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. and others [(2005) 3 SCC 39] and Gauhati High Court in Century Plyboards Ltd. vs Union of India, the export price of USA to India is to be preferred for normal value determination as compared to constructed normal value.
- vii. The anti-dumping duty may be imposed as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed in US\$/kg.

**b. Submissions by various Exporters and Importers**

- i. The petitioner has not manufactured Terpolymer Pre-compound during the POI and thus should be excluded from the scope of PUC. Also, Petitioner has only included Terpolymer Raw Gum and not Pre-compound within the scope of the product under consideration. No PCN has been suggested by the petitioner for Terpolymer Pre-compound (Referred to decision in Plain Gypsum Plaster Board, Gypsum Ceiling Board with Aluminium Edges Sealed in White Film and Saturated Fatty Alcohols).
- ii. Information regarding export sales of exporter, not available in public domain, is disclosed while the confidentiality claims of DI regarding its volumetric parameters are accepted. The respondents stand on an equal footing as that of the Domestic Industry regarding the volume parameters. The DA ought to have extended the same benefit to the respondents and other interested parties on the ground of parity.
- iii. The data filed in the petition doesn't matches with data in pre hearing written submissions. Similarly, there is a huge difference in data in pre hearing written submissions and verified data.
- iv. Value addition is not a criterion in an anti-dumping investigation to grant or reject individual dumping or injury margin and MET. CFSE purchases raw gum from unrelated suppliers.
- v. High quality grade of raw gum is purchased from The Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co., Ltd., and therefore, the cost is high.
- vi. It is requested to take into consideration all the element of costing provided by the respondent into consideration except power cost, average cost per Kwh as per the power invoices provided by the respondent and best ratio of power consumption of the petitioner (Kwh / KG) to produce pre-compound from raw gum for determining its normal value in line with Para 3 of Annex II ADA.
- vii. The decisions of CFSE regarding prices, costs and inputs, output, sales and investment are made in response to market signals and without significant State interference
  - a. Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) is not a state owned company, and therefore, there is no State interference in investment decision making in CFSE

As per the law, a company can be termed as state owned & controlled only in the following two situations:

- a) Direct or indirect shares held by government departments, organization, institutions, single state-owned or state-controlled enterprises is more than 50%, or;
- b) Shareholder agreements, articles of association, board resolutions or other agreements authorize the government to exercise control.

Government holding is only 34% in Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) (Wuxi Investment). It may also be noted that the Partnership agreement clearly mentions that Wuxi Junyuan Capital Management Centre (Limited Partnership) (Wuxi Capital) is the only general partner of Wuxi Investment and has complete control over its day-to-day operations. All shareholders of Wuxi Capital are private persons. Accordingly, it is clear that Wuxi Investment is not a state owned company.

- b. Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) is not state controlled, and therefore, no State interference in investment decision making in CFSE.

The shareholders of Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) with government shareholding are limited partners and have no role to play in its day-to-day operations.

Partnership agreement makes it amply clear that Wuxi Capital is the only general partner of Wuxi Investment and has complete control over its day-to-day operations.

The decisions of the investment committee are taken as per the professional ethics and in line with the company law, securities investment fund law and other laws and administrative regulations.

- viii. Exchange rate in China is determined based on the market forces and the government has no control over it. Also, it is a macro economic issue and the market economy status of the company cannot be decided on the basis of this issue alone as per Tiles Case.
- ix. International price of raw material and power cost in China may be considered for the determination of the normal value.
- x. The price to Trader will always be lower than the price to the End Consumer (varies by 6%). Thus, the export price, landed value, dumping and injury margin should be calculated for each customer type.
- xi. The respondent requests the Authority to apply 0.4/1.04 formula to the FOB export price of CFSE to calculate the VAT adjustment of 4% assuming that export price is inclusive of 4% VAT for the calculation of the ex-factory export price of different PCN's.
- xii. Post POI data is not relevant in the case of injury or material retardation investigation.
- xiii. Export performance is the cause of injury, if any, to the petitioner.
- xiv. Injury, if any, to the petitioner is because of other reasons like inferior quality of its product, internal inefficiencies, mismanagement, pricing / predatory pricing strategy etc.
- xv. The Authority in the Disclosure Statement has considered USA as an appropriate market economy third country for determination of Normal Value. However, despite the same, the Authority has computed Normal Value based on the normated cost of production of Domestic Industry. This methodology has been adopted merely because 10 percent of the overall import entities from USA do not specify the grade / PCN as per the present investigation. Even though the Authority has recognised that the Indian laws provide a chain to be followed while computing normal value in case of a non-market economy country, the Authority has erred in adopting the second methodology (i.e. on any other reasonable basis) and discarding 90 percent of import data from USA to India. It is also relevant to highlight that similar to the import data of subject goods from USA to India, a large number of import transactions from China to India also do not specify the grades. However, the Authority has accepted the import data of subject goods from China to India and while rejecting that of USA to India. It is submitted that the Authority should base its determination of 'Normal Value' on the basis of export price from USA to India instead of adopting any other basis.



- xvi. The Authority has erred in determination of ex-factory price of goods exported by Shanghai 3F.
- xvii. The Authority should not base its determination based on Post POI data. Also, Average inventory has been evaluated incorrectly.
- xviii. The Authority should mandatorily examine all 15 economic parameters listed in Article 3.4 of AD Agreement to evaluate material retardation or material injury as per WTO Panel Report in *Morocco – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey*
- xix. There is absence of causal link between subject imports and injury to domestic industry
- xx. Price Depression to Domestic Industry is self-inflicted.
- xxi. USA is a developed country while China is developing. Prices of subject goods from USA to India cannot be taken as NV for China.
- xxii. USA has exported a nominal quantity of co-polymer raw gum (around 3 MT) to India during the POI, which is negligible quantity and the same is of specialty grades. This small volume of Imports cannot be termed as represented quantity to arrive at normal value for China PR.
- xxiii. It is requested that the normal value may be constructed by adopting raw material consumption norms, international price of raw material, utilities cost as per prices in China PR and interest rate as prevailing in international market.
- xxiv. The export price of USA cannot be considered for the purpose of determining normal value in the present investigation as it is not an appropriate surrogate market economy third country for China PR owing to difference in the level of development of the two countries.
- xxv. Information regarding export sales of exporter, not available in public domain, is disclosed while the confidentiality claims of DI regarding its volumetric parameters are accepted. The respondents stand on an equal footing as that of the Domestic Industry regarding the volume parameters. The DA ought to have extended the same benefit to the respondents and other interested parties on the ground of parity.
- xxvi. All three forms of injury cannot co-exist. The DA has brushed aside the submissions of respondents in this regard and hasn't addressed.
- xxvii. The DA has not mentioned as to why Korea Panel Report is not applicable in the facts and circumstances of the present case.
- xxviii. The Final Findings and CESTAT order in SBR is not applicable for it having different set of facts as compared to the present investigation.
- xxix. GFL is an established Domestic Industry of the like article. Since the DA did not have a standard test for determining whether an industry was already established or under establishment, the test applied by anti-dumping authorities in other jurisdictions may be adopted.
- xxx. The UISTC examines (i) length of domestic operations; (ii) characteristics of domestic production; (iii) the size of domestic operations; (iv) whether the Domestic Industry has reached a reasonable financial 'break-even' point and (v) whether the start-up is more in the nature of the introduction of a new product line by an already established business- GFL is already a well-established business, being the 4th largest manufacturer of PTFE globally of which, fluoroelastomers is only a further downstream product. As per GFL's Annual Report, adding capability for manufacturing fluoroelastomers required minimal capital expenditure and that it would be sweating the assets already set up.
- xxxi. Proposal to the WTO cannot be relied upon to gauge material retardation. As per the Vienna Convention on the Law of Treaties, the proposals made by the various countries do not fall within the ambit of any of the legitimate aids to construction.
- xxxii. The DA is also required to consider the fact that imports have actually decreased in relation to domestic production. The increase in imports from China PR has only been at the cost of reducing imports from non-subject countries. Therefore, imports from China PR have not had a volume effect.

- xxxiii. The DA has compared the import prices from China PR with that of non-subject countries and has thereby observed that import prices from China PR have been at 50-60% of import prices from other countries. Such an analysis is unprecedented and has no relevance as far as the analysis under Para (ii) of Annexure II is concerned.
- xxxiv. The DA has stated that ‘the price depression effect has been analyzed with regard to its manifestations in the form of price retardation thereby preventing production to ramp up to an optimum level post commencement of commercial production by domestic industry’. This prescription for such an analysis is not to be found under any of the provisions in Annexure II of the AD Rules 1995. The term ‘price retardation’ does not have any foundational basis in any provision governing the levy of anti-dumping duty or any past determinations of the DA. Therefore, the DA is requested to clarify the nature of analysis involved while examining ‘price retardation’ or what the same entails so that the interested parties can offer meaningful comments.
- xxxv. The data regarding quarterly trends of price undercutting clearly shows that prices between the five quarters from 2016-17 Q1 to 2017-18 Q1 have largely remained the same with minimal variations. The post-POI data of the two quarters of July to December 2017 shows that import prices have increased further.
- xxxvi. DA has stated that though the prices of the DI were being undercut by imports from China PR in the first quarter, later the price undercutting turned negative which resulted in price suppression. The requirement under Para (ii) of Annexure II of the AD Rules 1995 is whether imports have been significantly undercutting the prices of the like product in India. Therefore, the reasons stated by the DA for arriving at a conclusion of price suppression is contrary to the settled position that it is the existence of price undercutting that is considered responsible for price suppression and depression and not its absence.
- xxxvii. Prices from China PR were above the prices of the DI clearly indicate that their prices were not under pressure from imports. The margin of negative price undercutting actually increased during the POI when compared to the previous year. Despite having enough leeway to increase its selling price further, at least to the same level as that of imports from China, the Domestic Industry instead chose to lower its price.
- xxxviii. Referred to the Panel Report in China – Definitive Anti-Dumping Duties on X-Ray Security Inspection Equipment from the European Union [DS425]- price undercutting was negative as the Domestic Industry was selling below landed value of imports, price suppression or depression could not be attributed to imports in the absence of cogent reasons explaining why the Domestic Industry could not raise its prices, at least to the level of the imports.
- xxxix. The volumetric parameters have shown a massive improvement and yet the DA has observed that the said parameters are subdued. The said observation of the DA is misplaced as FKM is a product with highly specialized application and therefore, the Domestic Industry cannot be expected to capture the entire market overnight. The steady improvements made by the Domestic Industry cannot be negated by suggesting that better performance could have been achieved.
- xl. When viewed as a percentage of sales of the Domestic Industry, inventories have actually decreased in the POI when compared to the base year {as per the decision of CESTAT in Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) v. Designated Authority [(2011) 270 ELT 696]}.
- xli. DI has not suffered injury with respect to employment, productivity or wages.
- xl. Imports from China PR have had no effect on the prices of the subject goods sold by the Domestic Industry by virtue of being much above the selling price.
- xl. The DA has proposed to hold that the losses would impair the ability of the Domestic Industry to raise capital investment. The DA is requested to take into consideration the fact that the Domestic Industry has itself admitted in its Annual Report 2015-16 that it “has the ability to comfortably raise more capital at any time should the need arise.”
- xliv. The DA has attributed the declining profitability of the Domestic Industry to price depression as a result of price undercutting becoming negative. However, the said observation suffers from an

inherent contradiction inasmuch as it is positive price undercutting that is responsible for price suppression and depression whereas negative price undercutting implies that selling price of the Domestic Industry is not under any pressure. Rather, on prices of imports being higher, the Domestic Industry can also afford to raise its prices, at least to a price comparable to that of imports.

- xlv. Post POI data has only been supplied for the two quarters between July 2017 and December 2017 (6 months) and therefore, annualization of the data has been adopted to gauge the various economic parameters. Only data till December, 2017 was furnished despite the fact that the information was filed by the Domestic Industry on the 7th of November, 2018. Not only is the Annual Report for FY 2017-18 available on GFL's website but also its financial results for the quarter and half year ending September 30, 2018.

#### **Causal Link**

- xlvi. An absolute increase in the volume of imports in isolation cannot be reconciled with price depression. The relevant criterion for assessing price depression is to examine whether the prices of imports are undercutting the prices of the Domestic Industry. The only situation in which an increase in volume of imports can result in price depression is if it is coupled with price undercutting which is not the case in the present investigation.
- xlvi. Domestic Industry has made commendable improvement in volumetric parameters and Domestic Industry cannot be expected to capture the entire domestic market overnight. Fluoroelastomers are used in highly specialized applications, users have to assess the goods sourced from different manufacturers through product trials in order to gauge compatibility and performance which takes time.
- xlvi. In a situation where price undercutting is negative, dumping cannot be the reason for price depression. The prices of imports are required to be compared with the prices of the Domestic Industry to examine whether the former is dictating the latter and thereby, depressing it
- xlix. Financial losses suffered by the Domestic Industry is due to selling the subject goods produced by it at unremunerative prices that are not comparable to prices of imports which have consistently been higher throughout the injury analysis period.
- i. Dumping by itself does not prevent the Domestic Industry from increasing its sales, production or capacity utilisation. It must be coupled with other factors such as price undercutting which make it more lucrative for the users of the product to switch to the lower priced imports. However, the DA must explain how dumping has restrained the Domestic Industry from achieving optimum capacity utilisation when the Domestic Industry has consistently priced the subject goods produced by it below the prices of the Domestic Industry. Therefore, this factor does not establish a causal link between dumping of the subject goods and injury to the Domestic Industry either.
  - ii. Referred to previous Findings (Caustic Soda, N butanol, PBR and Belting Fabric) where investigations have been terminated because absence of causal link between dumped imports and injury to the Domestic industry in cases where a majority of the economic factors have shown improvement despite a decrease in profitability.

#### **c. Submissions by User Industries (M/S Hi-Tech Arai Private Limited and M/s Devashish Polymers Pvt. Ltd)**

- i. Referring to the calculation of the copolymer gum price to be USD 24.60 and co-polymer precompound price to be USD 22.25. It is submitted that this value in itself is factually and theoretically totally in-correct. The price of Copolymer gum has to be atleast 20-25% lower than the price Co-polymer gum is mixed with expensive curatives to make pre-compounds. Process in itself is unique and involves precaution to be taken. Therefore even after addition of very expensive curatives and underdoing a strict manufacturing procedure the price of pre-compound will cheaper than the price of gum. Further there is a flaw in calculation of raw gum price strangely the price of co-polymer raw gum is calculated to be even more expensive than ter-polymer raw gum. Ter-polymer consists of 3 monomers whereas co-polymers consists of 2 monomers. The addition of the 3<sup>rd</sup> monomer is done under controlled environment, makes the terpolymer raw gum much expensive than co-polymer raw gum, and thus is used in only very high demanding applications. Hence, the views of DGTR for

calculating such a high price of co-polymer raw gum, even over and above co-polymer precompund is factually and theoretically in-correct.

- ii. Non-injurious price (NIP) considered by the DGTR is almost 30% higher than what has been claimed by the domestic industry in its petition. This is one of a kind case wherein the DGTR wants to allow the DI a higher selling price (in terms of higher level of protection) than what the DI had demanded as a fair price thus overlooking interest of medium and small industries. DGTR has strangely calculated the fair prices based on prevailing prices in USA. We donot understand the rationale behind using USA which is the most developed economy of the world, and calculate fair price to be prevailing developing economies such as China and India. USA has one of highest prevailing labour cast, overheads and other related expenditures.
- iii. An increase in cost by way of additional duties would affect the entire Indian Automobile parts manufacturing units who are making progress in the world market.
- iv. It is submitted that DGTR has failed to address the quality issues associated with the DI product. The product had huge consistency issues. It was informed to DI several times but they have failed to address it from their end. In a high performance product like FKM, this is totally unacceptable.
- v. It is submitted that fluoroelastomer as a category of material is divided into several types and are available in several grades; the applicant claiming injury currently does not produce materials of such types and do not intend to do so at this point of time. There are certain products even belonging to the same category of product being imported from China, do not provide similar or better results that a buyer may choose to procure the material for its functional requirement. It is clear with the applicant claiming injury if the intention of the Company lies to offer the materials in form of Raw Gums or Pre Compounds, and in case of a single interest the antidumping duty should be added categorically and not both to safeguard its interests in all manners.
- vi. It is submitted that the department should consider a fair pattern in which the selective category of the materials be placed within in order to offer ease to the Industry in continuing to import, manufacture and sell its final products. Rubber Industry have largely been hit with several Trade Agreements between India and other Nations where in the finished Rubber parts are being imported at Duties much lower than even the Basic Customs Duty of the Base Raw Material, enabling the OEM's to take advantage from Countries other than India itself. Increase in unjustified costs on the raw materials which are not even produced in India will incur immense pressure on the Manufacturers of Rubber Components in India and shall force them to give up the business and loose them against others.

#### **M. Examination by Authority**

124. The Authority notes that interested parties have also raised concerns on quality of goods produced by the Domestic Industry mainly consistency of product. The Authority notes that the petitioner has attained capacity utilisation of almost 50% in the post POI period, which indicates that quality concerns are being overcome by the domestic industry. 'Price Correction' of unfair imports through AD measure is only to ensure a level playing field. The Imports can come in at corrected fair price. M/s Seetharaman and Associates representing M/s Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co Ltd., M/s Solvay (Shanghai) Co Ltd. and M/s Solvay Specialities India Private Limited have stated that while total export sales of the Cooperating exporters have been disclosed but for the Domestic Industry it has been kept Confidential. The Authority after considering these submissions to ensure equity have also disclosed the total domestic sales of the Domestic Industry in this Finding.
125. The Authority notes that M/s Dua Associates representing M/s Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd. ("IM 3F"), M/s Inner Mongolia All Top Fluorine Chemistry New Materials Development Co., Ltd. ("All Top") and M/s Shanghai Huayi 3F New Materials Sales Co., Ltd. ("SH 3F") has mentioned that Ex-factory Export price be determined by working backwards from CIF price of exporter to India to producer in China. The Authority notes that in the instant case as the exporter has made exports at a profit, the relevant value chain link between producer in China i.e. IM3F and the linked exporter i.e. SH3F has been considered to evaluate the Ex-factory Export price at the producer level. Since the profits made by the exporter cannot become part of the Ex-factory export prices, the approach suggested by the exporter is trivial. The Ex-factory export price as determined and disclosed on confidential basis to exporters in the disclosure is confirmed. Further the export price is net of VAT.

126. The Authority notes that submissions have been made by various interested Parties on injury and causal link analysis mainly related to not using the post POI data, that too only of 6 months, evaluating all parameters of article 3.4, Price depression to domestic industry is self-inflicted with causal link missing, all three forms of injury cannot coexist and proposal to WTO cannot be relied upon to gauge Material retardation.
  127. The Authority notes that it has been submitted by the interested parties that even terpolymer pre compound be excluded along with compound and FFKM as domestic industry has not produced terpolymer Pre compound during the period of Investigation. The Authority notes that the Domestic industry has produced terpolymer Pre compound during the post POI. However for compounds and FFKM for while DI has no capability terpolymer precompound is a grade of precompound which is within the scope of PUC. The Authority has considered raw gum and Pre Compound (Copolymers and terpolymers) as the two main types of Product under consideration which further has different variants. All variants have been considered as part of the product under consideration. As the injury claim is of material retardation, the variants not produced in POI but DI having capability need to be included in the scope of PUC.
  128. Therefore, the Authority noting submissions and citation of earlier Anti-dumping cases on excluding a product not manufactured during period of investigation holds that since injury to domestic industry has been evaluated on material retardation and as well as material injury, only those product types i.e. compounds and FFKM for which Domestic industry has no capability to product are excluded from the scope of PUC.
  129. The Authority further holds that for terpolymer Precompound, the Non-injurious price evaluation has been done on the basis of actual data of cost of domestic industry during POI with value addition included Raw Gum to precompound. The dumping margin and injury margin are compared on an apple to apple basis only.
  130. The Authority notes the submission that domestic industry had filed different sets of data during the course of initiation and that initiation is bad. The Authority holds that data filed by any interested party is verified either on site or on desk study. The Authority considers the verified data for the purpose of final finding. If discrepancies in data are corrected and shared with all interested parties, no prejudice is caused and no natural justice right is violated.
  131. The Authority notes the submissions of M/s CFSE on determination of Normal Value for determination of domestic prices as per Accession protocol of China. The producers/exporters had filed Questionnaire to illustrate the prevalence of market economy conditions in the industry.
- Page 11 of rejoinder submissions of M/s CFSE draws attention to Section 15(a)(i) *“if the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;...”*
132. The Authority has evaluated the information filed by the producer/exporter comprehensively. The Authority notes the submissions of the producer/exporter stating that value addition is not a criteria for granting dumping margin, injury margin or Market economy treatment. The Authority observes that in the instant case the producer/exporter is sourcing raw materials which itself is a Product under consideration type and a major cost of the PUC type manufactured by the producer/exporter and in this context ‘MET’ status for raw gum’s manufacture is extremely vital to consider grant of MET to its value added product type i.e. pre compound. The sourcing of this raw material whether from related or unrelated is trivial as the issue to be settled is whether raw gum manufacture meets the MET requirements. Non-filing of response for this significant part of product does not enable grant of MET to the goods exported by the Producer/exporter. The Authority further notes that the producer/exporter has clarified sourcing of raw material from some suppliers at a higher price as quality is better. The price variations in the main raw material across suppliers also indicate that even the cost variations of suppliers of this PUC and whether they being operating under market economy conditions requires close examination for which concerned suppliers should file questionnaire responses. Under such circumstances, the Authority has not granted the MET to the producer/exporter.

133. The Authority also notes that producer/exporter has stated that there are discrepancies in purchase document and power bills which are of typo/clerical nature.

134. The Authority in the para 53 and 54 of the disclosure statement had held that

*“.....As regards the state inference, the producer/exporter has provided its share holding pattern wherein one of its shareholders i.e M/s Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre limited partnership who holds \*\*\*% of share of the producer/exporter infact has Government shareholding to an extent of \*\*\*%. This \*\*\*% shareholding is comprised of M/s Wuxi Guolian Industrial Investment Co. Ltd. (\*\*\*%), M/s Wuxi Newspaper Developer Co. Ltd. (\*\*\*%), and M/s Wuxi New District Science and Technology Financial Venture Capital Group Co. Ltd. (\*\*\*%), who further have 100% government shareholding. The investment trail of the producers/exporters investment portfolio therefore shows significant investment by the state enterprises both directly/indirectly. The Authority also notes the submissions by CFSE that M/s Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre (\*\*\*%) has M/s Wuxi Junyuan Capital Management Centre (Limited Partnership) (\*\*\*% Private) as a General partner who unlike other limited partners is authorised to take day to day management decisions and that there is no government interference in decision making. The Authority notes that the para 8(3) of Annexure 1 of AD rules states “the designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:*

*(a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;*

*(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;*

*(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and*

*(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in Anti-Dumping Rules, 1995 in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.”*

*In the instant case, the provision under of 6.4 of the partnership agreement of M/s Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre, the major shareholder in CFSE stipulates the role of all Shareholders in investment decision making which appropriately clarifies State interference in investment decision making in CFSE. Therefore with decision making for investment by producer/exporter having interference of the state entities, the condition under para 8 (3) (a) is not met to claim MET status. Also the Authority notes that exchange rate as regards foreign currency transactions the producer/exporter has stated that exchange rate's reflected in their financial accounts are based on rate published by people's bank of China. However there are no submissions on the aspect as to whether the exchange rate is controlled by the Government. The Authority recalls its earlier finding no.14/14/2014-DGAD dated 8/4/2017 wherein in para 108 the continued control of exchange rate by Government was underscored. The issues on cost of production, shareholding pattern and claim of market economy treatment being limited only to value added component of PUC and further with no participation of raw material suppliers/producers do not qualify and justify grant of market economy status to the producer/exporter i.e. M/s CFSE.”*

135. The Authority notes that M/s CFSE has reiterated the earlier submissions to justify that there is no state interference in investment decision making, or day to day control. The Authority recalls its observations in the disclosure statement as also reproduced above and holds that the producers/exporters claim for MET falls short of establishing no significant state interference in decision making process of investment. Further with sourcing of significant proportion of PUC i.e. raw gum for which no questionnaire being filed by suppliers for claiming MET and deficiencies of technical mismatches in cost of production records as stated above, the Authority does not grant MET status to M/s CFSE for the subject goods under consideration.

136. As regards submissions on the injury parameter, the Authority notes that the volume of imports from China have increased in absolute terms and also relative to consumption/demand. However with reference to production there has been a decline in imports.
137. The Authority has also noted that though fact of price of subject goods from China being about 60% of the prices from non-subject countries may seem trivial but manifestation of this aspect is observed in increase of imports from China which the Authority has underscored in analysis.
138. The domestic industry has been able to increase its market share from 2015 to POI by displacing the market share of non-subject countries whose prices are almost 70% higher than China. The low prices level of imports from China on one hand led to increase in market share of subject goods from China and at the same time led to a price depression effect on selling prices of domestic industry. It is noted that only in the first quarter of injury period, the price undercutting by imports from China was positive which later led to a retarding effect on selling prices of domestic industry which continued over the injury period. The volume parameters of domestic industry i.e. production, sales, market share, capacity utilization though increased over injury period, the volume growth is at the expense of price depression.
139. The Authority notes the submissions of interested parties that it is the positive price undercutting that is responsible for price suppression and depression whereas negative price undercutting implies that selling price of the Domestic Industry is not under any pressure. The Authority in this regard holds that although price undercutting is negative since the domestic industry had to succumb to the pressure of import prices from China PR.
140. The Authority notes that it has been submitted by one of the interested party that the PUC is a highly specialized product and that the domestic industry would take time to increase its market share and that its present performance on volume parameters is quite satisfactory. The Authority in this regard notes that the domestic industry has no doubt increased its market share but it has made its place by displacing imports from non-subject countries, and that growth of dumped imports from China remain unabated. The price retardation effect stated earlier cannot get arrested if unfair imports from subject country remain unaddressed. The Authority therefore holds that both phenomenon of material retardation and material injury are witnessed in this case. As has been submitted by one of the interested party that in the recent WTO Panel report in matter titled *Morocco – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey*, it has been held that all parameters of article 3.4 need to be examined. The Authority has examined all parameters under Article 3.4 in this finding.

The Authority holds that it is also pertinent to note that it is not mandatory that all factors show negative trend or decline as has been held by WTO in the Panel Report **EC- Bed Linen case**. Rather, the analysis and conclusions must consider each factor; determine the relevance of each factor in the context of the particular industry at issue, to make a reasoned conclusion as to the state of the domestic industry.

As far as relevance of SBR case is concerned, the Authority notes that the concept of domestic industry has to be seen as domestic producers as a whole as per Rule 2(b) of the Rules. While it may happen that in a case there are two units of domestic industry but altogether they form the domestic industry. In SBR case, the Authority has recommended that one of the units of the domestic industry has suffered from material injury and the other unit has suffered from material retardation. In essence, the domestic industry has suffered from both material injury and material retardation. The same has been upheld by CESTAT and Supreme Court. Thus, it cannot be the case that SBR case is not relevant here.

141. After examining all parameters under Article 3.4 there is no bar for authority to also look at post POI data to validate whether the retardation in domestic industry's performance noted in injury period is still continuing or has undergone a change. In this regard, the Authority notes the submission made by one of the interested parties that post POI is not relevant and that designated authority has only considered 6 months post POI when a larger duration data was available. The Authority holds that a post POI of 6 months is normally considered for different types of anti-dumping investigation i.e. Sunset review, examining threat of injury or material retardation. In this case also the Authority has not departed from this practice, and has taken note of 6 months post POI data as indicative only.

142. The Authority notes the submissions regarding US not treating an industry with 2-3 years of existence eligible for Material retardation case. However, the circumstances under which such a consideration is done may be different in different countries. The criteria of an established industry would also therefore vary from country to country. In the instant case, the domestic industry filed a petition in December, 2017, alleging dumping with POI considered as July, 2016 – June, 2017. Therefore the domestic industry has claimed injury especially material retardation after one year of its starting the commercial production in July 2015. The authority therefore holds that in the present case circumstances, the domestic industry's claim for material retardation seems justified and has appropriately analyzed in this finding.
143. The Authority notes that it has been submitted by one of the interested party that the domestic industry in its annual report has reported that it has the ability to comfortably raise more capital at any time as per the need as and thus, its ability to raise capital investment has not been jeopardized. The Authority in this regard notes that GFL is a multi-product company and the annual report of a multi-product company reflects the performance of all the products and segments and about the overall operations of the company and is not limited to one segment. The information related to product under consideration is only relevant for the purpose of present investigation.

**N. Conclusions**

144. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:
- i. The product under consideration has been exported to India from the subject country below its normal value, resulting in dumping.
  - ii. The Domestic Industry has suffered material injury and material retardation due to dumping of the product under consideration from the subject country.
  - iii. The aforesaid injury has been caused by the dumped imports from the subject country.

**O. Recommendations**

145. The Authority notes that the producers/exporters from the Subject Country have been found to be dumping the subject goods during POI and that there has been a price injury due to retarding effect caused by dumping on the domestic selling price of domestic industry. The performance of domestic industry on price parameters in context of material injury and material retardation has been subdued resulting in financial losses.
146. The Authority further notes that domestic industry's establishment has got retarded in terms of price but it has been able to enhance its capacity utilisation, and domestic sales. The analysis of injury in the case has been limited to only 24 months of injury period. Further 6 months of post POI has also been examined which is only intended to capture whether the domestic industry has been able to overcome the retarding effect. The price depression continues in post POI. The Authority holds that on the basis of 2 years injury period if may not be justified to recommend levy of AD measure for a 5 year tenure. The Authority therefore considers it appropriate to recommend AD measure only for a period of 18 months from the date of notification. The Authority holds that by that time the performance data of domestic industry for almost 5 years would be available which can enable the domestic industry to file a petition if they so desire. The Authority at that time would be in a position to examine the complete injury period data for evaluating injury to domestic industry.
147. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of Definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country for 18 months in the form and manner described hereunder :



**DUTY TABLE**

No.	Heading/ Sub-heading**	Description of goods *	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	39046990, 39049000 & 39046910	Fluoro elastomers (FKM)	China	China	Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd.	Shanghai Huayi 3F New Materials Sales Co., Ltd.	3.85	Kg	US\$
2.	39046990, 39049000 & 39046910	Fluoro elastomers (FKM)	China	China	M/s Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co Ltd.	M/s Solvay (Shanghai) Co. Ltd.	4.24	Kg	US\$
3.	39046990, 39049000 & 39046910	Fluoro elastomers (FKM)	China	China	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	3.6	Kg	US\$
4.	39046990, 39049000 & 39046910	Fluoro elastomers (FKM)	China	China	Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd.	Uni Alliance Limited	0.078	Kg	US\$
5.	39046990, 39049000 & 39046910	Fluoro elastomers (FKM)	China	China	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd.	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd.	3.56	Kg	US\$
6.	39046990, 39049000 & 39046910	Fluoro elastomers (FKM)	China	China	Any Combination other than mentioned in S.No. 1 to 5 above		7.31	Kg	US\$
7.	39046990, 39049000 & 39046910	Fluoro elastomers (FKM)	China	Any country other than China PR	Any	Any	7.31	Kg	US\$
8.	39046990, 39049000 & 39046910	Fluoro elastomers (FKM)	Any country other than China PR	China	Any	Any	7.31	Kg	US\$

\*FKM compound and Perfluoroelastomer (FFKM) are excluded from the scope of the subject goods.

\*\*The imports also happen under ITC head 39045090.

**P. Further procedure:**

148. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority